गजलों के महासूर्य बन चमक रहे हैं दुष्यन्त

-ललित गर्ग

दुष्यन्त कुमार जयन्ती- 1 सितम्बर, 2024

दुष्यंत कुमार ऐसे गजलकार एवं फनकार हैं जो निराशा में आशा, अंधेरों में उजाले एवं मुर्दों में जान भर देते हैं। हिंदी कविता और हिन्दी गजल के क्षेत्र में जो लोकप्रियता उनको मिली, वैसी लोकप्रियता सदियों में किसी कवि एवं शायर को नसीब होती है। दुष्यंत एक कालजयी कवि हैं और ऐसे कवि समय काल में परिवर्तन हो जाने के बाद भी प्रासंगिक रहते हैं। इस सृजनधर्मी बहुआयामी लेखक एवं कवि ने कविता, गीत, गजल, काव्य, नाटक, कथा आदि सभी विधाओं में लेखन किया लेकिन गजलों के वे महासूर्य बन चमके। वे हिंदी गजल के लिए विख्यात है किंतु उन्हें यह ख्याति हिंदी गजलों के लिए नहीं, हिंदुस्तानी गजलों के लिए मिली। वे क्रांतिकारी विचारों वाले शायर हैं, उनकी शायरी को सामाजिक धारणाओं, आदर्श-व्यवस्थाओं एवं मजबूत राष्ट्रीय सोच का सूत्रपात कहा जा सकता है। जो सोयी शक्तियों को जगाता है, जो समय के साथ चलने की समाज एवं व्यक्ति को सूझ देता है। उन्होंने राष्ट्रीय-भावना, कुछ अनूठा करने के जज्बे को जीवंतता देते हुए समाज में क्रांति घटित करने का प्रयत्न किया।

जब भी बात गजलों की होती है तो उर्दू जुबान ही याद आती है लेकिन दुष्यंत कुमार एक ऐसा चमकता-दमकता नाम हैं जिन्होंने हिन्दी में गजलें लिखीं और उन्हें मुकाम तक भी पहुंचाया, उनकी गजलों में आम जनमानस का दर्द नजर आता है। शायद दुष्यंत कुमार अकेले ऐसे शायर हैं, जिनके शेर सबसे ज्यादा बार सार्वजनिक मंचों से सुनाए जाते हैं। सभाओं में नेताओं से लेकर वक्ताओं ने उनके शेर सुनाकर व्यवस्था पर चोट की हैं एवं सरकार को जगाने और जनचेतना का कार्य किया है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। हममें से कितने ही लोग अपनी जिंदगी में इन कालजयी पंक्तियों का इस्तेमाल करते रहे हैं। उनके कई शेर हैं जो व्यक्ति में ही नहीं बल्कि पूरे समाज में क्रांति की अलख जगा देने की ताकत रखते हैं। उनकी कई रचनाओं को स्कूल के साथ ही बी.ए. और एम.ए. के पाठ्यक्रम में विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता हैं। वहीं बहुत से शोधार्थियों ने उनके साहित्य पर पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है।

दुष्यंत कुमार का जन्म 01 सितंबर 1933 को उत्तर-प्रदेश के बिजनौर जिले के राजपुर नवादा गांव में हुआ था। उनका मूल नाम दुष्यंत कुमार त्यागी था लेकिन वह साहित्य जगत में दुष्यंत कुमार के नाम से जाने गए। उनके पिता का नाम श्री भगवत सहाय और माता का नाम श्रीमती राम किशोरी था। दुष्यंत का अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान ही राजेश्वरीजी से विवाह हुआ था। इसके बाद दोनों ने प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी, दर्शनशास्त्र व इतिहास विषय में विवाहोपरांत साथ मिलकर बी.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से ही द्वितीय श्रेणी में एम.ए. की परीक्षा पास की। वहीं से उनके साहित्यिक जीवन का आरंभ हुआ और उनके लेखन को एक नया आयाम मिला। अपने दांपत्य जीवन में उन्होंने तीन संतानों को जन्म दिया। उनके दो पुत्र और एक पुत्री थी।

अपने अध्ययन के दौरान दुष्यंत कुमार साहित्यिक संस्था ह्यपरिमलह्न की गोष्ठियों में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे और ह्यनए पत्तेह्न जैसे महत्वपूर्ण पत्र से भी जुड़े रहे। इस समय उन्हें मार्गदर्शन के रूप में डॉ.रामकुमार वर्मा, डॉ. धीरेंद्र कुमार शास्त्री व डॉ. रसाल मिले तो सहपाठी के रूप में कमलेश्वर, मार्कंडेय और रवींद्रनाथ त्यागी का सान्निध्य प्राप्त हुआ। लेकिन जिंदगी का काफी हिस्सा मध्य प्रदेश में बीता। मध्य प्रदेश सरकार ने उनके नाम पर दुष्यंत कुमार पुरस्कार भी देती चली आ रही है। दुष्यंत आपातकाल के दौर में अपनी बागी रचनाओं के लिए भी चर्चित हुए थे। दुष्यंत कुमार ने केवल 42 वर्ष का जीवन पाया था लेकिन उन्होंने जिस भी विधा में साहित्य का सृजन किया वह कालजयी हो गई। उनकी रचनाएं सार्वदेशिक, सार्वकालिक एवं सार्वभौमिक हैं, जो आधुनिक हिंदी साहित्य में आज भी ह्यमील का पत्थरह्न मानी जाती हैं। हिंदी अल्फाज की ऐसी रवानी, ऐसी ताजगी, ऐसी ऊर्जा और किसी शायर में मुश्किल से ही देखने को मिलती है। दुष्यंत की गजलों एवं शायरी में हिंदी-उर्दू अल्फाज का प्रयोग एक नई ताजगी के साथ जाहिर होता है और यह दुष्यंत की बड़ी खूबी मानी जा सकती है। दुष्यंत ने इंसानी कशमकश, जज्बात, उदासी, महरूमी को भी बहुत फनकारी के साथ बयान किया गया है, जो उन्हें एक न भूलने वाला शायर बनाता है। इसके अलावा जबान की सादगी और जबान का हिंदुस्तानीपन दुष्यंत को अपने दौर के सबसे अनोखे और अलबेले शायर के रूप में भी स्थापित करता है। दुष्यंत नई गजल के माध्यम से सच बोलने एवं सच रचने का साहस किया एवं अनोखे शायर कहलाये। जिनकी शायरी तब तक जिंदा रहेगी जब तक गरीबों, लाचारों और बेबसों के लिए कोई न कोई आवाज उठती रहेगी। दुष्यंत के बारे में अच्छी और बुरी बातें हर नए दौर में कही जाती रहेंगी, लेकिन दुष्यंत ही अकेले ऐसे शायर हैं जिन्होंने उम्र भर सियासत को मुंह चढ़ाया, मगर कमाल यह है कि दुष्यंत के बाद सियासतदानों ने संसद में या संसद के बाहर, विधानसभाओं में या विधानसभाओं के बाहर अपनी बात को मनवाने और अपनी बात में ज्यादा वजन पैदा करने के लिए दुष्यंत को ही बार-बार कोट किया है, उनकी ही गजलों एवं शायरी का सहारा लिया है। दुष्यंत का आदर्श कोरा दिखावा न होकर संकल्प की उच्चता एवं पुरुषार्थ की प्रबलता है। व्यक्ति एवं समाज क्रांति के रूप में विकृत सोच एवं आधे-अधूरे संकल्पों को बदलने के लिये दुष्यन्त ने जिजीविषा एवं रचनात्मकता के उपाय निर्दिष्ट किये हैं। दुष्यंत कुमार की संपूर्ण साहित्यिक रचनाओं एवं रचना संसार में अनेक कृतियां हैं। उनके गजल-संग्रह में साये में धूप है तो उपन्यासों में शामिल है छोटे-छोटे सवाल, आँगन में एक वृक्ष, दुहरी जिंदगी। उनके काव्य-संग्रह में सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत हैं। गीति नाट्य है एक कंठ विषपायी। प्रमुख नाटक है और मसीहा मर गया। कहानी-संग्रह है मन के कोण। हिंदी गजल विधा के पुरोधा दुष्यंत कुमार के सम्मान में भारतीय डाक विभाग ने एक डाक टिकट जारी किया था। इसके साथ ही ह्यदुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालयह्न में उनकी धरोहरों को संभालने का प्रयास किया गया है। दुष्यंत कुमार की कविता ह्यहो गई है पीर पर्वत सी, अब पिघलनी चाहिएह्न के कुछ अंशों का इस्तेमाल 2017 की लोकप्रिय फिल्म इरादा में किये गये हैं एवं भारत में हर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान अक्सर इसका उपयोग होता रहा है। दुष्यंत मायूसी के काले बादलों को तार-तार करने की ताकत रखते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने पर उकसाते हैं।

दुष्यन्त हिंदी साहित्य के आकाश में सूर्य की तरह चमकते हैं और चमकते रहेंगे। आम से दिखने वाले दुष्यंत को इतनी शोहरत इसलिये मिली कि उन्होंने कभी भी शायरी अपने लिए नहीं की बल्कि जब भी कलम उठायी, अपने लोगों, अपने समाज एवं अपने राष्ट्र के लिए उठायी। जब भी दुख जाहिर किया उन लोगों का किया जिनका दुख दुनिया के लिए कोई मायने नहीं रखता था। ऐसे लोग जो अपने दुख अपने सीनों में लिए जीते रहते हैं और ऐसे ही मर जाते हैं, उन लोगों के दर्द को आवाज देने वाला दुष्यन्त महान् रचनाकार है। उनकी शख्सियत अब इतनी बड़ी हो गई हैं कि किताबों की कैद से बाहर निकल कर जन-जन की आवाज बन गयी हैं और इतने तेज रफ्तार भी हो गई हैं कि सरहदों को मुंह चिढ़ाते हुए शायरी समझने वाले देश एवं दुनिया के लोगों के दिलों में बस गयी है। दुष्यंत को सिर्फ सियासत को आइना दिखाने वाले शायर ही समझ लेना उनकी शायरी की अनदेखी करना है, जो कि हम लोग वर्षों से करते आ रहे हैं। दुष्यंत अपने हाथों में अंगारे लिए नजर आते हैं, मगर दूसरी तरफ उनके सीने में वह महकते हुए फूल भी हैं जो जवां दिलों को महकाते हैं और प्रेम की एक अनदेखी और अनजानी फिजा भी कायम करते हैं। दुष्यंत की रूमानी शायरी में भी उनका खुरदुरापन उसी तरह मौजूद है, मगर यह खुरदुराहट दिल पर खराशें नहीं डालती बल्कि एक मीठे से दर्द का एहसास कराती चली जाती है।

भाजपा में हिंदुत्व की राह पर चलने की मुख्यमंत्रियों की होड़

अशोक भाटिया

2024 लोकसभा चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी में बहुत कुछ बदला है। लोकसभा चुनावों में शिकस्त मिलने के बाद केंद्र में सरकार तो बन गई पर फैसले लेने में सरकार पहले जैसी कॉन्फिडेंट नहीं दिख रही है। यही कारण है कि लगातार कई मौकों पर सरकार को यू टर्न लेना पड़ा है पार्टी के अंदर संघर्ष भी शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने मोर्चा खोल रखा है पर अभी शांति है। इस बीच पार्टी में मुख्यमंत्रियों के बीच उग्र हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बनने की होड़ लगी हुई है।

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पिछले दिनों ऐसे फैसले लिए हैं और ऐसे बयान दिए हैं कि योगी आदित्यनाथ भी फीके पड़ जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि दोनों मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व से आगे निकलना चाहते हैं यही नहीं योगी आदित्यनाथ भी इधर कुछ दिनों से लगातार उग्र हिंदुत्व की राह पर है इस तरह पर तीन मुख्यमंत्रियों के बीच उग्र हिंदुत्व का झंडाबरदार बनने की होड़ लगी हुई है। हिमंता बिस्वा सरमा के मुसलमानों के खिलाफ लगातार बयान, इसके साथ ही चाइल्ड मैरिज के नाम पर मुस्लिम शादियों में रुकावट डालने तथा जुम्मे की नमाज को लेकर जो फैसले हुए हैं, उसे साफ तौर पर पता चलता है कि हिमंता हिंदुत्व की राह पर तेजी से दौड़ रहे हैं। अब असम विधानसभा मुस्लिम विधायकों को शुक्रवार को नमाज अदा करने के लिए दिए जाने वाले दो घंटे के अवकाश को खत्म करेगी। हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट किया कि 2 घंटे की जुम्मा छुट्टी को खत्म करके, असम विधानसभा ने उत्पादकता को प्राथमिकता दी है और औपनिवेशिक बोझ के एक और अवशेष को हटा दिया है। उन्होंने आगे लिखा कि यह प्रथा 1937 में मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्ला द्वारा शुरू की गई थी। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए स्पीकर बिस्वजीत दैमारी और हमारे विधायकों को मेरा आभार।

हिमंता बिस्वा सरमा ने बृहस्पतिवार को विपक्ष पर निशाना साधते हुए दावा किया कि उनमें मूलतः राज्य के निवासी हिंदू विधायकों को विधानसभा में अपनी बात नहीं रखने देने की प्रवृत्ति विकसित हो गई है। असम भूमि एवं राजस्व विनियमन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 पर चर्चा के दौरान, शर्मा ने अपनी पार्टी के विधायक भुवन पेगु के भाषण को बाधित करने के लिए भी विपक्षी सदस्यों की कड़ी आलोचना की। शर्मा ने पेगु का बचाव करते हुए कहा, मूलतः राज्य के निवासी हिंदू विधायकों को सदन में नहीं बोलने देने की एक नयी प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई है। यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है। कृपया इतने आक्रामक न हों। हमारी जमीन के बाद अब विधानसभा पर कब्जा करने की कोशिश न करें। पेगू तत्कालीन पूर्वी बंगाल से असम में लोगों के कथित प्रवास और आक्रामकता के बारे में पुराने विधानसभा रिकॉर्ड का उल्लेख करते हुए एक बयान दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा, आप हिंदू-मुस्लिम मुद्दों पर बात करना बंद नहीं कर सकते। ये जीवन की कठोर वास्तविकताएं हैं। हाल ही में राज्य विधानसभा में बोलते हुए, असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि झ मैं असम को मियां लोगों की भूमि नहीं बनने दूंगा।

हिमंता के लिए हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बनने की धुन आज की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जॉइन करने के बाद से ही उन्होंने हार्डकोर हिंदुत्व की राह पकड़ ली थी। मुस्लिम आबादी को लेकर लगातार बयान,चाइल्ड मैरेज के नाम पर मुस्लिम शादियों में रुकावट डालने की कोशिश या सीएए और एनआरसी की बात रही हो, कांग्रेस से भाजपा में आए हिमंता मुस्लिम समुदाय के खिलाफ इस तरह से आग उगलते हैं जिसका मुकाबला जन्मजात भाजपाई भी नहीं कर सकते। अभी पिछले हफ्ते की बात है हिमंता ने निजी स्वामित्व वाले विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेघालय (यूएसटीएम) से पढ़ाई करने वाले छात्रों को असम सरकार की नौकरियों में रोक लगाने की बात कही एनआईआरएफ के तहत शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में से एक है। यह संस्थान असम के एक बंगाली-मुस्लिम महबुबुल हक के स्वामित्व वाले फाउंडेशन द्वारा संचालित है, जो संस्थान के चांसलर भी है। हिमंता का मानना है कि इस विश्वविद्यालय परिसर के निर्माण के लिए वनों और पहाड़ियों की कटाई का ही नतीजा है कि गुवाहाटी को अचानक बाढ़ का सामना करना पड़ा। सरमा का कहना है ये सब असम के खिलाफ बाढ़ जिहाद के कारण हुआ है।

सरमा ने इससे पहले बंगाली-मुस्लिम किसानों पर उर्वरक जिहाद का भी आरोप लगाया था। कहा था कि सब्जियां उगाने में उर्वरक के अनियंत्रित उपयोग के कारण लोगों में बीमारियां फैल रही हैं। उन्होंने राज्य में मुसलमानों पर भूमि जिहाद का आरोप लगाते हुए उन्हें जमीन की बिक्री पर अंकुश लगाने के फैसले की भी घोषणा की और कहा है कि सरकार लव जिहाद के लिए आजीवन कारावास की सजा वाला एक कानून लाएगी यही सब कारण है कि असम में उनकी लोकप्रियता में लगातार इजाफा हो रहा है।

योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के फायरब्रांड लीडर रहे हैं। पर मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके तेवरों में थोड़ी नरमी आ गई थी। पर पिछले महीने से ही अचानक उन्होंने अपना पुराना चोला फिर से ओढ लिया है वो फिर से उग्र हिंदुत्व की अपनी जानी पहचानी शैली में वापस आ गए हैं हाल ही में बांग्लादेश स्थिति को लेकर उन्होंने जब-जब मुंह खोला, आग ही उगला है। अभी 2 दिन पहले ही आगरा में उन्होंने हिंदुओं से सावधान रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर बंटेंगे तो कटेंगे बांग्लादेश वाली गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे।

योगी के कट्टर हिंदुत्व का यह रूप पिछले महीने से ही दिखने लगा था जुलाई महीने के अंत में, राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया, जिससे उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 को और अधिक सख्त बना दिया गया। यूपी विधानसभा ने 30 जुलाई को संशोधन विधेयक पारित किया, जिसमें लव जिहाद को खत्म करने के अपने इरादे को फिर से रेखांकित किया गया। कांवड़ यात्रा मार्ग पर सड़क किनारे विक्रेताओं और दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठानों के बाहर अपना नाम लिखने के आदेश पर पूरे देश में उनके समर्थन और विरोध हुआ है। अयोध्या रेप केस में आरोपी के मुसलमान होने पर काफी हिंदू-मुसलमान यूपी में हुआ है। योगी ने इस मामले को खुद संज्ञान लेते हुए आरोपी का घर और प्रतिष्ठानों पर बुलडोजर कार्रवाई का एक्शन लिया। राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सफलता को देखते हुए अन्य मुख्यमंत्री जब उनकी राह के तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं तो योगी भला क्यों पीछे हटे। योगी आदित्यनाथ को भी हिंदू हृदय सम्राट की पदवी बरकरार रखनी है इसलिए उन्हें भी अपने पुराने रूप में आना ही फायदेमंद दिख रहा है।

बात करें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की तो जन्माष्टमी के दिन एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि भारत में जो रहना चाहते हैं, उन्हें हिंदू, भगवान राम और कृष्ण की जय कहना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस देश के नागरिक अपने-अपने धर्मों के पालन के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन वह देशभक्त रहेंगे। इसके साथ यह भी कह गए कि खाता कहीं और का बजाता कहीं और का यह नहीं चलेगा। हालांकि मोहन यादव ने यह भी कहा कि देश हिंदू और मुसलमानों के बीच अंतर नहीं करता है, लेकिन उसे ऐसे लोगों की जरूरत है जो ईश्वर, उसकी रचना, ब्रह्मांड को समझें। उन्होंने कहा कि रहीम और रसखान का जन्म यहीं हुआ था। बीते दिनों छतरपुर में पुलिस पर पत्थरबाजी के आरोपियों के करोड़ों के घर सरकार ने तोड़ दिए। इस घर में रखी करोड़ों की गाड़ियों को भी बुलडोजर कर दिया गया। पत्थरबाजी का आरोपी चूंकि मुसलमान था इसलिए कुछ लोगों को इस कार्रवाई में धार्मिक एंगल भी दिखा। सिर्फ छतरपुर ही नहीं, इंदौर में भी एक अतिक्रमणकारी ने प्रशासन पर गोली चलवाई थी, उसकी कोठी को भी प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। इसका सीधा मतलब है कि कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोहन यादव ने मध्यप्रदेश के सीएम पद की शपथ लेने के साथ ही अपने इरादे जता दिए थे। उनके शुरूआती एक्शन में ही योगी की छाप दिखी थी शपथ लेते ही उन्होंने खुले में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना और लाउडस्पीकर पर बैन का फैसला लिया था। उसके बाद लगातार उन्होंने ऐसे फैसले लिए जो उन्हें हिंदू पोस्टर बॉय बनने की उनकी इच्छाशक्ति को दिखाता है।

इतना ही नहीं मोहन यादव ने एमपी में भगवान राम और कृष्ण से जुड़े तीर्थ स्थलों की तरह विकसित करने का काम करने का बीड़ा उठाया है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के 7 मंदिरों को जोड़े जाने का एक्शन प्लान बनाया जा रहा है। संघ के विचारकों और प्रमुख पदाधिकारियों की किताबें मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ाने का भी फैसला लिया गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों की धार्मिक शिक्षा देने पर रोक लगाया जा रहा है। एक और बात यह है कि भाजपा को यह बात समझ में आ गई है कि मुस्लिम समाज का उन्हें वोट बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है हिंदुत्व का ध्रुवीकरण होने पर विपक्ष के सारे तीरों से निपटने की भाजपा को ताकत मिल जाएगी।

भारत की सनातनी एवं संस्कृतिक सत्ता के वैश्विक स्थापना का समय

संजीव ठाकुर

यह तय है कि हमारी आध्यात्मिक,सनातनी विचारधारा ही देश को विश्व में अग्रणी बनाएगी। मुझे बहुत आश्चर्य होता है की क्यों नहीं हम अपनी सनातनी सत्ता और संस्कृति के साथ आध्यात्मिक स्थापना को विश्व में प्रचारित प्रसारित करते हैं। ऐतिहासिक तौर पर प्रमाणित है कि जब- जब विदेशी हमारी धरती पर आए हमने उनकी संस्कृति को अपनाया उन्होंने हमारी संस्कृति को नहीं? अब यह समय एवं कालखंड की आवश्यकता है कि भारतीय पूरे विश्व में अपने कर्म के संबल पर अपनी पहचान तथा स्थापना को मूर्त रूप दे रहे हैं ऐसे में हमें अपनी सनातनी सत्ता एवं संस्कृति को वहां पूरी क्षमता,ताकत तथा ऊर्जा के साथ प्रचारित प्रसारित कर उसकी स्थापना की जानी चाहिए। भारत का सांस्कृतिक, आध्यात्मिक वैदिक इतिहास सदैव प्रबुद्ध तथा गौरवशाली रहा है। वेदों, शास्त्रों ,पुराणों और सनातन संस्कृति एवं संस्कार में इतनी शक्ति है कि भारतीय संस्कृति अनंत काल तक कभी नष्ट नहीं हो सकती है। भारतीय संस्कृति का लचीलापन एवं व्यापक ग्राह्यता इतनी विशाल है कि इस सभ्यता ने कई सभ्यताओं को अपने में समाहित कर एक विशाल धर्मनिरपेक्ष वातावरण निरूपित कर वृहद वट वृक्ष की तरह अपनी शाखाएं वैश्विक स्तर पर प्रचारित, प्रसारित की है। यह वैदिक अध्यात्म योग और संस्कृति का ही प्रतिफल है कि भारत के नागरिक विश्व में चहुंओर निवास कर रहे हैं और अब समय आ गया है कि भारत को अपनी संस्कृति आध्यात्मिक तथा संस्कारों के आत्म बल के दम पर विश्व का नेतृत्व करना होगा एवं विश्व गुरु बनने की प्रक्रिया में नए नए सोपान निर्मित करने होंगे। प्रारंभ से ही शांति तथा मानवता को लेकर भारत में अपनी विकास यात्रा प्रारंभ की है आध्यात्मिक चिंतन और सनातनी इतिहास इस बात का गवाह है कि भारत विश्व शांति की बहाली के लिए विश्व को मार्गदर्शन देने का हौसला तथा क्षमता दोनों रखता है। अब यह समय आ चुका है कि भारत को विश्व का मार्गदर्शी प्रणेता बन जाना चाहिए।

जिंदगी का कैनवास जन्म से लेकर मृत्यु तक समुद्र की तरह विराट और गहराई लिए हुए होता है। जीवन में वयक्तिक, पारिवारिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक विकास की संभावनाओं के साथ मनुष्य अपना जीवन प्रारंभ कर विकास प्रगति तथा ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है,बशर्ते उसके व्यक्तित्व में जीवन के प्रति जीजिविषा, संघर्ष करने की क्षमता, अनंत आत्म विश्वास और संयम के घटक मौजूद हो। ऐतिहासिक तौर पर भारतीय विकास सांस्कृतिक संरचना एवं संस्कार के मूलभूत तत्वों को लेकर दुनिया में अभूतपूर्व रहा है। वैसे भी भारतवर्ष सभ्यता से लेकर संस्कृति की प्रकृति के मामले में वैभवशाली इतिहास को समेटे हुए हैं। विकास और प्रगति के सोपान को कोई एक दिन वर्ष अथवा दशक में रेखांकित नहीं किया जा सकता, यह एक निरंतर, सतत एवं समय के साथ चलने वाली क्रिया की प्रतिक्रिया है। और प्रकृति सभ्यता तथा मानव जीवन में परिवर्तन एक अकाट्य सत्य और शाश्वत अभिक्रिया है। व्यक्ति के जीवन तथा समाज या देश में विकास के संदर्भ में एवं घटकों को प्रारंभ से आदमी का धन उपार्जन, गरीबी भुखमरी से लड़ाई भूतकाल की कुरीतियों की विडंबना से संघर्ष का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन सब से समाज की प्रगति और विकास में राजाओं, सम्राटों की कूटनीति ,राजनीति सर्वोपरि रही है इतिहास से लेकर अब तक मनुष्य देश और विश्व के विकास में राजनैतिक नीति निर्देशक तत्व ही देश को बलवान,शक्तिहीन,भौगोलिक रूप से बड़ा या छोटा बनाते आए हैं। किसी भी राष्ट्र के राजा, सम्राट या राष्ट्र प्रमुख की अपनी क्षमता ,शक्ति, ऊर्जा और उसके विवेक से उस राष्ट्र की प्रगति विशाल या न्यूनतम होती देखी गई है। भूतकाल में कई संघर्षशील एवं उत्साह से लबरेज यात्रियों के वृतांत हमारी नजरों में आए हैं यथा कोलंबस और वास्कोडिगामा जैसे अत्यंत ऊर्जावान संघर्षशील और साहसिक यात्रियों द्वारा लगभग नामुमकिन रास्तों की खोज कर एक मिसाल कायम की है। नेपोलियन का एक बड़ा सूत्र वाक्य था कुछ भी असंभव नहीं है। बिस्मार्क जर्मनी के एक ऐसे सम्राट रहे हैं जिनके बारे में कहा जाता है की उनके हाथों में दो गेंद तथा 3 गेंदें हवा में होती थी, यूरोप का जादूगर भी कहलाता था, पूर्व से ही समुद्रगुप्त ,कनिष्क, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, शेरशाह सूरी जैसे शासकों का अदम्य आत्मविश्वास एवं संघर्ष करने की क्षमता के फल स्वरुप भी भारत आज इस स्वरूप में विद्यमान है। अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से भी किसी भी राष्ट्र में सदैव विकास वैभव और आर्थिक तंत्र को मजबूत करने की संभावनाएं अवस्थित रहती हैं। भारत की विशाल जनसंख्या को देखते हुए भारत में गरीबी, भुखमरी ,बाढ़ तथा अन्य विभीषिका सदैव आती जाती रहती हैं। विशाल जनसंख्या के होने के कारण भारत में ही भारत की बड़ी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है और केवल भारत के कुछ नागरिकों को ही सारी जीवन की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, बाकी लोग इन सुविधाओं से वंचित भी हैं। हमारा देश स्वतंत्रता के बाद से ही आवाज की कमी भूख गरीबी भ्रष्टाचार काला धन हवाला कुपोषण बेरोजगारी की बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है। भारत की विशाल जनसंख्या के बावजूद ऐतिहासिक तौर पर देश सांस्कृतिक वैचारिक और संस्कारी ग्रुप से सदैव समृद्ध रहा है और धार्मिक रूप से भी देश में ज्ञान की जड़े बहुत गहराई तक हैं। भारत को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करने के लिए वेद, पुराण, उपनिषद, गीता ,रामायण ,महाभारत महा ग्रंथों की पृष्ठभूमि बड़ी ही शक्तिशाली है। देश में अनेक साधु संत ज्ञानी जिनमें मोहम्मद मूसा कबीर, रैदास, नामदेव, तुकाराम चैतन्य, तुलसीदास शंकरदेव जैसे महापुरुषों ने देश के सांस्कृतिक आध्यात्मिक विकास मैं अभूतपूर्व योगदान दिया है। भारत में अनेक विदेशी आक्रमणों को झेल कर उन्हें आत्मसात किया है किंतु हमारी संस्कृत पाली एवं प्राकृत भाषा अन्य भाषाओं के साथ आज भी समृद्ध है। भारत में अनेक भाषा क्षेत्र एवं बोलियां हैं किंतु हिंदी, पंजाबी, गुजराती, बांग्ला, मराठी ,असमिया भाषाएं उसी तरह पल्लवित पुष्पित हो रही हैं जैसे की संस्कृत और प्राकृत पाली भाषा होती रही है। भारत में स्वाधीनता के बाद विकास के प्रगति के पथ पर वैज्ञानिक क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास किया और पृथ्वी से लेकर नभ तक हर क्षेत्र में मानव की अतीव उत्कंठा ,जीजिविषा के कारण हमने चांद पर भी अपने वायुयान भेजें हैं। देश के नागरिकों की भौतिकवादी सुविधा के लिए भी हमने वतानुकुलित यंत्र ,वायुयान तेज चलने वाली ट्रेनें और वायुमंडल में अनेक ऐसे तथ्यों को जो आज तक छुपे हुए थे उजागर कर अपने महत्व के लिए इसका उपयोग करना शुरू किया है। यह कहावत आशाओं पर आकाश टिका हुआ है और आकाश का कोई अंत नहीं यानी मनुष्य की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है मनुष्य पर सही प्रतीत होती है इसी तरह प्रगति और विकास का भी कोई अंत या अनंत नहीं है। भारत देश में वैश्विक स्तर पर राजनैतिक सामाजिक वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक स्तर पर काफी प्रगति की एवं विश्व में योग अध्यात्म दर्शन का लोहा भी मनवाया है। मनुष्य की अभिलाषा का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है, मनुष्य मूल रूप से अत्यंत महत्वकांक्षी,लोलुप एवं इच्छाओं का दास हुआ करता है, ऐसे में पूर्व में किए गए कार्यों को निरंतर सुधार कर उसे नए रूप में प्राप्त करना मनुष्य की अभिलाषा हो सकती है,पर इसके लिए अथक मेहनत संघर्ष आत्मविश्वास एवं संयम की आवश्यकता होगी तभी जाकर हम अपने नए-नए लक्ष्यों को विकास तथा प्रगति के पैमाने पर टटोलकर आगे बढ़ा सकते हैं। पर लक्ष्य की प्राप्ति के साधन जरूर सच्चे ,पवित्र और मानव कल्याण की ओर अग्रेषित होने चाहिए, तब ही विकास प्रगति चाहे वह आध्यात्मिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक अथवा वैज्ञानिक ही क्यों ना हो सफल हो सकती है।

मानसिक स्वास्थ्य की नींव होती है नींद

-डॉ. राजेंद्र कुमावत चिराना

प्रतिस्पर्धा की इस दौड़ में भागते हुए हम स्वस्थ रहने के नियम कायदे मानो भूलते से जा रहे हैं। न खाने का सही सलीका व समय रहा और न की शयन का वक्त, बस कुछ हासिल करने के चक्कर में हम दैनिक चर्या के नियम भी नही मान रहें हैं।सच कहे तो इस भागती दौड़ती जिंदगी में हमारा जीवन भी मशीन की मानिंद बन गया है। व्यसन व इलेक्ट्रिक उपकरणों का सहारा हमारे जीवन को संक्षिप्त करने में है,तो वही इस आपाधापी के चलते खानपान भी बदल सा गया है। जिंदगी इतनी व्यस्त हो गई है की न सोने का समय मुहैया और न ही आहार विहार का समुचित ध्यान। जिंदगी से जुड़े यह तमाम शगल इस बात के भी परिचायक है कि जब व्यक्ति इन सब सदगुणों की नियमित पालना नहीं कर पायेगा तो भला स्वस्थ कैसे रहेगा। उचित समय पर भूख नहीं लगना और बिस्तरों में जाने के बाद काफी समय तक नींद का नही आना ये दोयम दुविधा हमे यह दशार्ती है की कमोबेश स्वास्थ्य का पाया कमजोर हो रहा है।शरीर को बनाए रखने में जहां अच्छी भूख का होना जरूरी है। वहीं मन मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में अच्छी नींद का महत्व अहम होता है और जब यह दोनो सेहत कारक जीवन की दैनिक चर्या में शामिल न बन पा रहें है तो समझ लेना चाहिए की अब काया पर मानसिक परेशानी का दौर आने वाला है। इस वैचारिक खुजली के अतिरिक्त दुःख इस बात का भी है की इस दुनिया में अपना मुकाम तलाशने में लगा आज का इंसान न खाने की परवाह कर रहा है और न ही शगुन भरी नींद लेने का प्रयास। इस मिलावटी युग में शुद्ध खाना मिलेगा यह सोचने का समय भी खो चुका होता है। इंसान को जब कहीं कुछ खाने की सामग्री नजर आती है तो मौके पर मिली उस खाद्य वस्तु से ही उदर पूर्ति कर लेता है, वो तनिक नही सोचता है की यह हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी मुफीद और कितनी नुकसानदायक रहेगी, ऐसे ही जब निंद्रा आने लगती है तो उसको भी अधूरा रह रहा काम पूरा करने की सोच जहन में पाले चाय पीकर ही काफुर करने का प्रयास करता है। ऐसे में कैसे कहे की पहला सुख निरोगी काया को हम मान रहे है

सेहत के मूलमंत्र का पालन कर रहे है ,आयुर्वेद में बताए गए स्वस्थ रहने के नियमों का हम ताक में रख कर उनका पालन नहीं कर रहे हैं। देखने में तो यह भी आया है की आज का युवा सरपट चाल चलते हुए अपने निज कार्यों को शीघ्र ही निपटाने में उतावला ही नजर आ रहा है। दूसरी ओर देखे तो दुनिया की खैर खबर से जुड़े रहने के लिए चौकने रहते हुए हर तहरीर पर पकड़ बनाए हुए है तथा अपने मोबाइल में मिलने वाली पल पल की खबरों व मैसेज से अपडेट रहने के लिए बार बार मोबाइल को देखते हैं। हारा थका शरीर व चिंता में डूबा मन जब खाने के लिए तैयार होता है तो वहां भी समय न होने के बहाने के कारण टीवी देखते हुए खाना खाते हैं। जो सेहत की दृष्टि से ठीक नही है।समय पर जब नींद नहीं आती है तो उसकी आगोस में जाने के लिए भी कई उपाय करते हैं। इसके अतिरिक्त इस कड़ी में रही सही खसर मैं और मेरा मोबाइल की संस्कृति ने छीन ली है जिसके चलते लगता है अब भूख और नींद से अधिक महत्व कहीं मोबाइल का हो गया है। जिंदगी से जुड़े उपरोक्त तमाम कारण व्यस्त जीवन के कारण जरूर नजर आ रहें हैं पर जिंदगी के झमेलों में यूंही उलझे रहे और नींद व अच्छी भूख से दूर रहे तो निरोग बने रहने की नींव कैसे व कोन भरेगा। कहां से लाओगे वो अच्छी आदत जो सेहत के लिए वरदान का काम करती है। वो माए भी नही रही जो लोरी गाकर हमे सुला देवे। सेहत पाने के लिए हमें खुद को ही समय के साथ बदलते हुए निरोग रहने का ढांचा तैयार करते हुए,कंपीटिसन दौर में पनप रही सेल्स मैन संस्कृति से बचना होगा और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहते हुए योग,मेडिटेशन,निरोग रहने के नियम कायदे व सही समय पर खाने पीने का ध्यान रखकर ही सेहत की बुनियादी नीव रख पाएंगे। आपको बता देवे - आरोग्य आहार के अधीन है तो मानसिक स्वास्थ्य नींद पूरी होने पर मिलता है इन दोनो बातों को जानकर व आयुर्वेद की मानकर सेहत के सारथी खुद बने। समय रहते ऐसा नहीं किया गया तो संतुलित आहार और सुहानी नींद जिंदगी के स्लोगन ही बनकर रह जाएंगे।

लेखक- वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी,
अध्यक्ष महावीर इंटरनेशनल,
वीर बहुजन सेवा केंद्र चिराना।

सेबी का शिकंजा, 39 स्टॉक ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन रद्द, 22 डिपॉजिटरी पर कार्रवाई

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शुक्रवार को 39 शेयर ब्रोकर और सात जिंस ब्रोकर का पंजीकरण रद्द कर दिया। पंजीकरण अनिवार्यताएं पूरी करने में विफल रहने पर इन ब्रोकर का पंजीकरण रद्द किया गया है। इसके अतिरिक्त, नियामक ने उन 22 डिपॉजिटरी' प्रतिभागियों का पंजीकरण भी रद्द कर दिया, जो अब किसी भी डिपॉजिटरी' से संबद्ध नहीं हैं। सेबी ने तीन अलग-अलग आदेशों में कहा, इन इकाइयों के पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द करने का मुख्य कारण उन्हें ह्यडिपॉजिटरी' का सक्रिय भागीदार या मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज का सदस्य बने बिना अपने सेबी पंजीकरण का दुरुपयोग करने से रोकना है, जिससे ह्यअनजान' निवेशकों की सुरक्षा हो सके। पंजीकरण रद्द होने के बावजूद, ये इकाइयां शेयर ब्रोकर या जिंस ब्रोकर या ह्यडिपॉजिटरी' प्रतिभागियों के रूप में की गई किसी भी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हैं। वे सेबी को देय किसी भी बकाया शुल्क, बकाया तथा ब्याज का भुगतान करने के लिए भी जिम्मेदार हैं। सेबी ने अपने आदेश में कहा कि 39 शेयर ब्रोकर और सात जिंस ब्रोकर को कुछ शर्तों के तहत पंजीकरण प्रदान किया गया था। इसमें यह शर्त भी शामिल थी कि वे किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य बने रहेंगे। जिन 39 शेयर ब्रोकर का पंजीकरण रद्द किया गया है उनमें बेजल स्टॉक ब्रोकर्स, रिफ्लेक्शन इन्वेस्टमेंट्स, सम्पूर्ण पोर्टफोलियो, विनीत सिक्योरिटीज, क्वॉन्टम ग्लोबल सिक्योरिटीज, वेलिंडिया सिक्योरिटीज, व्राइज सिक्योरिटीज, क्रेडेंशियल स्टॉक ब्रोकर्स, आन्या कमोडिटीज, एम्बर सॉल्यूशंस, आर्केडिया शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स और सी.एम. गोयनका स्टॉक ब्रोकर्स, डेस्टिनी सिक्योरिटीज शामिल हैं। वेल्थ मंत्रा कमोडिटीज, सम्पूर्ण कॉमट्रेड, चैतन्य कमोडिटीज, बीवीके पल्सेस ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी, इन्फोनिक इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल लीडर्स कमोडिटीज और वेलिंडिया कमोडिटीज वे सात जिंस ब्रोकर हैं जिनके पंजीकरण रद्द किए गए। इंटिग्रेटेड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज, मूंगिपा इन्वेस्टमेंट्स, एएसएल कैपिटल होल्डिंग्स, अटलांटा शेयर शॉपी, वेल्थ मंत्रा, पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक, मैक्स प्लानवेल्थ सिक्योरिटीज, ब्राइट शेयर्स एंड स्टॉक उन 22 संस्थाओं में शामिल हैं जिनका ह्यडिपॉजिटरी' प्रतिभागियों के रूप में पंजीकरण रद्द कर दिया गया है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

सम्पादकीय

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे नासा के अंतरिक्ष यात्री- स्टारलाइनर मिशन की विफलता आगामी चुनौतियां और इसरो के लिए सबक

अंतरिक्ष यात्रियों सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर के फरवरी 2025 तक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन) में फंसे रहने की खबर उन चुनौतियों को सामने लाती है जो मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियानों में सामने आ सकती हैं। अंतरिक्ष यात्रियों का यह अनुभवी जोड़ा जून के आरंभ में बोइंग स्टारलाइनर पर सवार होकर आईएसएस पहुंचा था। यह मिशन आठ दिन का था। स्टारलाइन पहले ही दो लॉन्च कर चुका था लेकिन यह उसका पहला मानवयुक्त मिशन था। इसके थर्स्टर्स में समस्या के कारण आईएसएस के साथ इसके जुड़ाव में दिक्कत आई और हीलियम के लीक होने के कारण जोखिम और बढ़ गया। स्टारलाइनर को यात्रियों के बिना धरती पर लाना संभव है लेकिन इसे इंसानों को लाने की दृष्टि से असुरक्षित माना जा रहा है। नासा नहीं चाहता कि दो स्पेस शटल दुर्घटनाओं का इतिहास फिर से दोहराया जाए। अतीत में हुई ऐसी ही दुर्घटनाओं में कल्पना चावला सहित कई अंतरिक्ष यात्री जान गंवा चुके हैं। ऐसे में इस बार यात्रियों को अभी आईएसएस में ही रहना होगा और वे फरवरी 2025 में स्पेसएक्स के विमान से लौट सकेंगे। नासा ने जब आईएसएस पर वस्तुओं और मनुष्यों को ले जाने में सक्षम जीवन रक्षक कैप्सूल के साथ चल सकने वाले यानों के लिए निविदा जारी की तो उसने दूरदर्शिता का परिचय दिया। उसने दो डिजाइनों के लिए अनुबंध चुने। एक बोइंग से तो दूसरा स्पेसएक्स से। स्पेसएक्स ने जहां बार-बार इस्तेमाल किए जाने वाला डिजाइन तैयार किया वही बोइंग इसके लिए संघर्ष करती रही।

दशकों के तकनीक और वैमानिकी में गहरे अनुभव के बावजूद बोइंग की परियोजना की लागत स्पेसएक्स के करीब तीन गुना रही और इसमें अनुमान से बहुत अधिक समय और पैसा खर्च हुए। स्टारलाइन में अभी भी खामियां हैं। उसका थर्स्टर अभी भी कमजोर प्रदर्शन कर रहा है। यह आईएसएस के साथ जुड़ पाने में भी मुश्किलों से जूझता रहा है। अब वापसी की यात्रा के लिए स्पेस स्टेशन से अलग होने के लिए उसे सॉफ्टवेयर अपग्रेड की आवश्यकता है। बहरहाल, इसमें अतिरिक्त क्षमता मौजूद है और पृथ्वी पर वापस आने के लिए पर्याप्त गतिशीलता मौजूद है। हालांकि, गैस लीक के मामले गंभीर होते हैं क्योंकि ये अपने आप में जानलेवा साबित हो सकते हैं। अगर स्पेसएक्स का विकल्प नहीं होता तो आईएसएस पर सभी लोग फंसे रह जाते। एक भयंकर विस्फोट या अनियंत्रित ढंग से क्रैश हो जाने के बजाय उनके सामने खाने और ऑक्सीजन की कमी की स्थिति पैदा हो जाएगी। मानवयुक्त अभियानों में ऐसे जोखिम होते हैं और नासा के मानवयुक्त मिशन तथा ऐसे सोवियत कार्यक्रम दोनों को त्रासदियों का सामना करना पड़ा। यह अंतरिक्ष में लोगों को स्वस्थ रखने की चुनौतियों से एकदम अलग है। स्पेस फ्लाइट को तय अवधि तक गति की आवश्यकता होती है। इसके चलते शरीर पर गुरुत्वाकर्षण का भार सामान्य से 9-10 गुना तक अधिक रहता है। शून्य गुरुत्व वाली लंबी अवधि भी होती है जिसके कारण मांसपेशियों में समस्या पैदा हो सकती है या स्वास्थ्य संबंधी अन्य दिक्कतें हो सकती हैं। अंतरिक्ष में हवा नहीं है और वहां बहुत अधिक गर्मी और ठंड पड़ती है।

भाजपा में हिंदुत्व की राह पर चलने की मुख्यमंत्रियों की होड़

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पिछले दिनों ऐसे फैसले लिए हैं और ऐसे बयान दिए हैं कि योगी आदित्यनाथ भी फीके पड़ जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि दोनों मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व से आगे निकलना चाहते हैं। यही नहीं योगी आदित्यनाथ भी इधर कुछ दिनों से लगातार उग्र हिंदुत्व की राह पर है। इस तरह पर तीन मुख्यमंत्रियों के बीच उग्र हिंदुत्व का झंडाबरदार बनने की होड़ लगी हुई है।

अशोक भाटिया

2024 लोकसभा चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी में बहुत कुछ बदला है। लोकसभा चुनावों में शिकस्त मिलने के बाद केंद्र में सरकार तो बन गई पर फैसले लेने में सरकार पहले जैसी कॉन्फिडेंट नहीं दिख रही है। यही कारण है कि लगातार कई मौकों पर सरकार को यू टर्न लेना पड़ा है।पार्टी के अंदर संघर्ष भी शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने मोर्चा खोल रखा है पर अभी शांति है। इस बीच पार्टी में मुख्यमंत्रियों के बीच उग्र हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बनने की होड़ लगी हुई है। हिमंता बिस्वा सरमा के मुसलमानों के खिलाफ लगातार बयान, इसके साथ ही चाइल्ड मैरिज के नाम पर मुस्लिम शादियों में रुकावट डालने तथा जुम्मे की नमाज को लेकर जो फैसले हुए हैं, उसे साफ तौर पर पता चलता है कि हिमंता हिंदुत्व की राह पर तेजी से दौड़ रहे हैं। अब असम विधानसभा मुस्लिम विधायकों को शुक्रवार को नमाज अदा करने के लिए दिए जाने वाले दो घंटे के अवकाश को खत्म करेगी। हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट किया कि 2 घंटे की जुम्मा छुट्टी को खत्म करके, असम विधानसभा ने उत्पादकता को प्राथमिकता दी है और औपनिवेशिक बोझ के एक और अवशेष को हटा दिया है। उन्होंने आगे लिखा कि यह प्रथा 1937 में मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्ला द्वारा शुरू की गई थी। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए स्पीकर बिस्वजीत दैमारी और हमारे विधायकों को मेरा आभार। हिमंता बिस्वा सरमा ने बृहस्पतिवार को विपक्ष पर निशाना साधते हुए दावा किया कि उनमें ''मूलत- राज्य के निवासी हिंदू विधायकों'' को विधानसभा में अपनी बात नहीं रखने देने की प्रवृत्ति विकसित हो गई है। असम भूमि एवं राजस्व विनियमन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 पर चर्चा के दौरान, शर्मा ने अपनी पार्टी के विधायक भुवन पेगू के भाषण को बाधित करने के लिए भी विपक्षी सदस्यों की कड़ी आलोचना की। शर्मा ने पेगू का बचाव करते हुए कहा, मूलत- राज्य के निवासी हिंदू विधायकों को सदन में नहीं बोलने देने की एक नयी प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई है। यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है। कृपया इतने आक्रामक न हों। हमारी जमीन के बाद अब विधानसभा पर कब्जा करने की कोशिश न करें। पेगू तत्कालीन पूर्वी बंगाल से असम में लोगों के कथित प्रवासन और आक्रामकता के बारे में पुराने विधानसभा रिकॉर्ड का उल्लेख करते हुए एक बयान दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा, आप हिंदू-मुस्लिम मुद्दों पर बात करना बंद नहीं कर सकते। ये जीवन की कठोर वास्तविकताएं हैं। हाल ही में राज्य विधानसभा में बोलते हुए, असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि - मैं असम को मियां लोगों की भूमि नहीं बनने दूंगा।

हिमंता के लिए हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बनने की धुन आज की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जॉइन करने के बाद से ही उन्होंने हार्डकोर हिंदुत्व की राह पकड़ ली थी। मुस्लिम आबादी को लेकर लगातार बयान,चाइल्ड मैरेज के नाम पर मुस्लिम शादियों में रुकावट डालने की कोशिश या सीएए और एनआरसी की बात रही हो, कांग्रेस से भाजपा में आए हिमंता मुस्लिम समुदाय के खिलाफ इस तरह से आग उगलते हैं जिसका मुकाबला जन्मजात भाजपाई भी नहीं कर सकते। अभी पिछले हफ्ते की ही बात है हिमंता ने निजी स्वामित्व वाले विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेघालय (यूएसटीएम) से पढ़ाई करने वाले छात्रों को असम सरकार की नौकरियों में रोक लगाने की बात कही। एनआईआरएफ के तहत शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में से एक है। यह संस्थान असम के एक बंगाली-मुस्लिम महबुबुल हक के स्वामित्व वाले फाउंडेशन द्वारा संचालित है, जो संस्थान के चांसलर भी हैं। हिमंता का मानना है कि इस विश्वविद्यालय परिसर के निर्माण के लिए वनों और पहाड़ियों की कटाई का ही नतीजा है कि गुवाहाटी को अचानक बाढ़ का सामना करना पड़ा। सरमा का कहना है ये सब असम के खिलाफ बाढ़ जिहाद के कारण हुआ है। सरमा ने इससे पहले बंगाली-मुस्लिम किसानों पर उर्वरक जिहाद का भी आरोप लगाया था। कहा था कि सब्जियां उगाने में उर्वरक के अनियंत्रित उपयोग के कारण लोगों में बीमारियां फैल रही हैं।

उन्होंने राज्य में मुसलमानों पर भूमि जिहाद का आरोप लगाते हुए उन्हें जमीन की बिक्री पर अंकुश लगाने के फैसले की भी घोषणा की और कहा है कि सरकार लव जिहाद के लिए आजीवन कारावास की सजा वाला एक कानून लाएगी।यही सब कारण है कि असम में उनकी लोकप्रियता में लगातार इजाफा हो रहा है। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के फायरब्रांड लीडर रहे हैं। पर मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके तेवरों में थोड़ी नरमी आ गई थी। पर पिछले महीने से ही अचानक उन्होंने अपना पुराना चोला फिर से ओढ लिया है।वो फिर से उग्र हिंदुत्व की अपनी जानी पहचानी शैली में वापस आ गए हैं।हाल ही में बांग्लादेश स्थिति को लेकर उन्होंने जब-जब मुंह खोला , आग ही उगला है। अभी 2 दिन पहले ही आगरा में उन्होंने हिंदुओं से सावधान रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर बंटेंगे तो कटेंगे।बांग्लादेश वाली गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे । योगी के कट्टर हिंदुत्व का यह रूप पिछले महीने से ही दिखने लगा था।जुलाई महीने के अंत में, राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया, जिससे उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 को और अधिक सख्त बना दिया गया। यूपी विधानसभा ने 30 जुलाई को संशोधन विधेयक पारित किया, जिसमें लव जिहाद को खत्म करने के अपने इरादे को फिर से रेखांकित किया गया।कांवड़ यात्रा मार्ग पर सड़क किनारे विक्रेताओं और दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठानों के बाहर अपना नाम लिखने के आदेश पर पूरे देश में उनके समर्थन और विरोध हुआ है।अयोध्या रेप केस में आरोपी के मुसलमान होने पर काफी हिंदू-मुसलमान यूपी में हुआ है। योगी ने इस मामले को खुद संज्ञान लेते हुए आरोपी का घर और प्रतिष्ठानों पर बुलडोजर कार्रवाई का एक्शन लिया।राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सफलता को देखते हुए अन्य मुख्यमंत्री जब उनकी राह के राही बनने की कोशिश कर रहे हैं तो योगी भला क्यों पीछे हटे। योगी आदित्यनाथ को भी हिंदू हृदय सम्राट की पदवी बरकरार रखनी है इसलिए उन्हें भी अपने पुराने रूप में आना ही फायदेमंद दिख रहा है। बात करें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की तो जन्माष्टमी के दिन एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि भारत में जो रहना चाहते हैं, उन्हें हिंदू , भगवान राम और कृष्ण की जय कहना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस देश के नागरिक अपने-अपने धर्मों के पालन के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन वह देशभक्त रहें। इसके साथ यह भी कह गए कि खाता कहीं और का बजाता कहीं और का यह नहीं चलेगा।हालांकि मोहन यादव ने यह भी कहा कि देश हिंदू और मुसलमानों के बीच अंतर नहीं करता है, लेकिन उसे ऐसे लोगों की जरूरत है जो ईश्वर, उसकी रचना, ब्रह्मांड को समझें। उन्होंने कहा कि रहीम और रसखान का जन्म यहीं हुआ था। बीते दिनों छतरपुर में पुलिस पर पत्थरबाजी के आरोपियों के करोड़ों के घर सरकार ने तोड़ दिए। इस घर में रखी करोड़ों की गाड़ियों को भी बुलडोज कर दिया गया। पत्थरबाजी का आरोपी चूंकि मुसलमान था इसलिए कुछ लोगों को इस कार्रवाई में धार्मिक एंगल भी दिखा। सिर्फ छतरपुर ही नहीं, इंदौर में भी एक अतिक्रमणकारी ने प्रशासन पर गोली चलवाई थी, उसकी कोठी को भी प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई विविध लक्ष्यों को पूरा करेंगे। क्या आप यह जानना चाहते है कि आपके जीवन के ऐसे कौनसे क्षेत्र है, जहां आपके सितारे बुलंद रहेंगे और दूसरी तरफ, आपको किस बातों से सावधान रहना चाहिए। हम न सिर्फ हमारे काम में और जटिल मुद्दों को सुलझाते वक्त सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेंगे, बल्कि पारम्परिक संबंधों में भी, जहां यह स्थानान्तरण हमें संताप और बातचीत में लाभ प्रदान करेगा

मेष
स्वजनों एवं परिजनों के साथ विवाद हो सकता है। आय की अपेक्षा खर्च अधिक होगा और ज्यादा परिश्रम के बाद ही सफलता मिलेगी। दुर्घटना हो सकती है, सावधान रहें। आज आपका दिन बहुत लाभदायी है।

वृष
बाहर जाना हो सकता है। माता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। सरकारी लाभ होगा एवं स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आप का दिन मध्यम फलदायी रहेगा। पहले से निर्धारित काम के लिए आपका प्रयास ज्यादा रहेगा।

मिथुन
मित्र एवं प्रियजन आपके प्रवास को आनंद से भर देंगे। नए वस्त्रों की खरीदी के योग हैं। तन-मन की तंदुरस्ती अच्छी रहेगी। अच्छे भोजन एवं वैवाहिक सुख की अनुभूति होगी। आज आप के घर में सुख शांति और आनंद का माहौल रहेगा।

कर्क
नौकरी में आपके अधिकारी खुश रहेंगे। आपकी पदोन्नति के योग हैं। अधिकारियों के साथ किसी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा होगा। परिजनों के साथ खुले मन से बातचीत होगी। घर के डेकोरेशन पर कुछ खर्च हो सकता है। आपका व्यवहार न्यायपूर्ण रहेगा।

सिंह
हेल्थ का ध्यान रखने और खासकर बाहर के खाने-पीने से परहेज करने की सलाह आपको दी जाती है। आज आपमें क्रोध की मात्रा अधिक रहेगी, इसलिए वाणी में गुस्सा ना रखें। परिजनों से उग्र चर्चा के कारण मनमुटाव न हो।

कन्या
अविवाहितों को योग्य जीवनसाथी मिलने के योग हैं। धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। मित्रों से अचानक हुई मुलाकात आनंददायी रहेगी। मित्रों से लाभ होगा। आज आपको अच्छा खाना नसीब होगा। मित्रों से लाभ होगा। महिलाओं के मायके से समाचार आने के योग हैं।

तुला
संतान पक्ष से अच्छे समाचार मिलेंगे। नौकरीपेशा लोगों से आपको लाभ होगा। आय में वृद्धि होगी। वैवाहिक सुख की अनुभूति होगी। आज का दिन आपके लिए अनुकूल है। आप आज हर काम सरलता से पूरे कर पाएंगे।

वृश्चिक
आज धन का व्यय अधिक होगा। आज नियम विरुद्ध कामों से दूर रहें। आज आपका दिन आनंद-प्रमोद में गुजरेगा। रोमांस के लिए आज का दिन अच्छा है और किसी खास व्यक्ति का साथ आपको आनंद देगा।

धनु
आपका शारीरिक एवं मानसिक आरोग्य अच्छा रहेगा। जरूरी कामों पर धन खर्च होगा। बीमार व्यक्तियों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। दफ्तर में सहकर्मियों का अच्छा साथ मिलेगा। मित्रों से मुलाकात होगी।

मकर
आप तन-मन से स्वस्थ होकर कई तरह के काम आसानी से पूरे कर पाएंगे। सफलता मिलने से आपके उत्साह में वृद्धि होगी। आज भाग्य आपका साथ देगा। इनकम बढ़ेगी। परिजनों के साथ आनंद एवं उल्लास से समय गुजरेगा।

कुंभ
माता से लाभ होने के संकेत आपको मिल रहे हैं। मित्र और संबंधियों से घर का वातावरण अच्छा रहेगा। आज अचानक होने वाली घटनाओं से आप चिंतित रहेंगे। स्वास्थ्य खराब होने और आंखों में दर्द होने की आशंका बनी रहेगी।

मीन
आज आपके धार्मिक एवं मांगलिक कामों में व्यस्त रहने की संभावना ज्यादा रहेगी। आप में आज क्रोध की मात्रा अधिक रहेगी, इसलिए आप सावधान ही रहें। संतान एवं व्यापार की परेशानियों के कारण आपका मन अशांत रहेगा। धन लाभ होगा।

शख्सियत

पी.एल.चौधरी
जिला कमान्डेंट, होमगार्ड

नमस्कार दोस्तों हमारी आज की शख्सियत कॉलम के स्टार हैं श्री पीएल चौधरी जो कि इस समय गृह रक्षा विभाग में उच्च अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस समय जिला कमांडेंट झुंझुनू, जिला कमांडेंट अलवर व जिला कमांडेंट भिवाड़ी के पद को सुशोभित कर रहे हैं । तीन बड़े जिलों की कमान संभाल रहे हैं। 10 जुलाई सन 1981 को झुंझुनू के समीप गांव कालियासर में जन्मे प्यारेलाल चौधरी ग्रामीण परिवेश में पले बड़े हुए हैं। उनकी स्कूली शिक्षा सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से हुई और बीएससी की डिग्री इन्होंने महाराजा कॉलेज जयपुर से ली। 2003 में लेफ्टिनेंट के पद पर आर्मी में चयन हुआ 6 साल आर्मी में देश की सेवा की और 2009 में आर्मी में मेजर बने । 2009 के लास्ट में आर्मी से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। 2012 में आरपीएससी के द्वारा गृह रक्षा विभाग में ऑफिसर के पद पर चयन हुआ। बहुत बेहतरीन अधिकारी के रूप में इन्हें जाना जाता है । हमेशा अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए सेवा करना इनकी परवरिश का बखान करता है। अपने नीचे के अधिकारियो के लिए बहुत संवेदनशील भाव बनाए रखते हैं। पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सेवा देने वाले होमगार्ड कर्मियों के लिए यह वरदान साबित हुए हैं । उनकी समस्या और उनकी महती परेशानी को बखूबी समझकर उनके निस्तारण में एक बेहतरीन भूमिका निभाई है। युवाओं में अपने कर्तव्य के प्रति किस तरीके का जज्बा पैदा हो इसके लिए समय-समय पर व्याख्यान के रूप में होमगार्ड कर्मियों को प्रेरित करते रहते हैं। ट्रेनिंग के दौरान भी लगातार युवाओं को जागरुक करते रहते हैं । सरल और सहज अधिकारी के रूप में इन्हें जाना जाता है। तीन जिलों की कमान अकेले संभाल रहे हैं यही बात इनके व्यक्तित्व को बयां कर रही है। दैनिक बढ़ता राजस्थान की टीम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है।

जय हिंद

आज का इतिहास

1 सितंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- पीसा काउंसिल 1511 में खुला।
- अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति आरोन बर्र 1807 को राजद्रोह के मामले में निर्दोष पाये गये।
- एम्मा एम नट्ट अमेरिका में 1878 को पहली महिला टेलीफोन ऑपरेटर बनी।
- ग्रेट कैंटो भूकंप ने 1923 में जापान के टोक्यो और योकोहामा में भयंकर तबाही मचायी।
- जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करने के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हुई।
- भारतीय मानक समय को 1947 में अपनाया गया।
- भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की स्थापना 1956 में हुई।
- राज्यों के पुनर्गठन के बाद 1956 को त्रिपुरा केन्द्रशासित प्रदेश बना।
- महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 1962 को शिवाजी विश्वविद्यालय की स्थापना।
- इंडियन ऑयल रिफाइनरी और इंडियन ऑयल कम्पनी को 1964 में विलय करके इंडियन ऑयल कॉपरेशन बनाई गयी।
- मिस्र और लीबिया ने 1972 में फेडरेशन बनाया।
- उत्तरी आयरलैंड में आयरिन रिपब्लिकन आर्मी ने 1994 में युद्ध विराम लागू किया।
- साहित्यकार महाश्वेता देवी तथा पर्यावरणविद एम सी मेहता को 1997 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया।
- विक्टर चेर्नोमीर्दिन पुनः रूस के नये प्रधानमंत्री 1998 को नियुक्त।
- चीन ने 2000 में तिब्बत होते हुए नेपाल जाने वाले अपने एकमात्र रास्ते को बंद किया।
- लीबिया और फ्रांस के बीच यूटीए विमान पर 1989 में हुई बमबारी में मारे गये लोगों के निकट सम्बन्धियों को मुआवजा देने को लेकर 2003 में समझौता हुआ।
- पाकिस्तान के एक मानवाधिकार विशेषज्ञ मेहर खान विलियम्स को 2004 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने उप उच्चायुक्त नियुक्त किया।
- सद्दाम हुसैन ने 2005 में सशर्त रिहाई की अमेरिकी पेशकश ठुकराई।
- फिजी के अपदस्थ प्रधानमंत्री लाइसेनिया करासे 2007 को नौ महीने बाद राजधानी सुवा लौटे।
- तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने डी. सुब्बाराव की भारतीय रिजर्व बैंक के 22वें गर्वनर के रूप में नियुक्ति की घोषणा 2008 में की।
- यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया ने 2008 में अपना लोगो बदला।
- वायस एडमिरल निर्मल कुमार वर्मा को 2009 में भारतीय नौसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया।
- सर्वोच्च न्यायालय में जसवंत सिंह की किताब पर गुजरात में प्रतिबंध लगाए जाने के मामले में राज्य सरकार को 2009 में नोटिस दिया।

1 सितंबर को जन्मे व्यक्ति

- भारतीय संगीतकार चेमबइ वैद्यनाथ भगवतार का जन्म 1895 को हुआ था।
- प्रसिद्ध गौड़ीय वैष्णव गुरु तथा धर्मप्रचारक भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपाद का जन्म 1896 को हुआ था।
- जानेमाने भूगोलवेत्ता लक्ष्मी नारायण उपाध्याय का जन्म 1901 को हुआ था।
- भारतीय सिनेमा के खलनायक अभिनेता के. एन. सिंह का जन्म 1908 को हुआ था।
- प्रसिद्ध साहित्यकार फादर कामिल बुल्के का जन्म 1909 को हुआ था।
- भारतीय क्रिकेटर माधव मंत्री का जन्म 1921 को हुआ था।

विशेष आलेख

दुष्यन्त कुमार जयन्ती

गज़लों के महासूर्य बन चमक रहे हैं दुष्यन्त

ललित गर्ग

दुष्यंत कुमार ऐसे ग़ज़लकार एवं फनकार हैं जो निराशा में आशा, अंधेरों में उजाले एवं मुर्दों में जान भर देते हैं। हिंदी कविता और हिन्दी गजल के क्षेत्र में जो लोकप्रियता उनको मिली, वैसी लोकप्रियता सदियों में किसी कवि एवं शायर को नसीब होती है। दुष्यंत एक कालजयी कवि हैं और ऐसे कवि समय काल में परिवर्तन हो जाने के बाद भी प्रासंगिक रहते हैं। उनके लिखे स्वर सड़क से संसद तक गूंजते रहे हैं। इस सृजनधर्मी बहुआयामी लेखक एवं कवि ने कविता, गीत, गजल, काव्य, नाटक, कथा आदि सभी विधाओं में लेखन किया लेकिन गज़लों के वे महासूर्य बन चमके। वे हिंदी गजल के लिए विख्यात है किंतु उन्हें यह ख्याति हिंदी गजलों के लिए नहीं, हिंदुस्तानी गजलों के लिए मिली। वे क्रांतिकारी विचारों वाले शायर हैं, उनकी शायरी को सामाजिक धारणाओं, आदर्श-व्यवस्थाओं एवं मजबूत राष्ट्रीय सोच का सूत्रपात कहा जा सकता है। जो सोयी शक्तियों को जगाता है, जो समय के साथ चलने की समाज एवं व्यक्ति को सूझ देता है। उन्होंने राष्ट्रीय-भावना, कुछ अनूठा करने के जज्बे को जीवंतता देते हुए समाज में क्रांति घटित करने का प्रयत्न किया। जब भी बात ग़ज़लों की होती है तो उर्दू जुबान ही याद आती है लेकिन दुष्यंत कुमार एक ऐसा चमकता-दमकता नाम हैं जिन्होंने हिन्दी में ग़ज़लें लिखीं और उन्हें मुकाम तक भी पहुंचाया, उनकी ग़ज़लों में आम जनमानस का दर्द नज़र आता है। शायद दुष्यंत कुमार अकेले ऐसे शायर हैं, जिनके शेर सबसे ज्यादा बार सार्वजनिक मंचों ही नहीं, संसद में पढ़े गए हैं। सभाओं में नेताओं से लेकर वक्ताओं ने उनके शेर सुनाकर व्यवस्था पर चोट की हैं एवं सरकार को जगाने और जनचेतना का कार्य किया है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। हममें से कितने ही लोग अपनी ज़िंदगी में इन कालजयी पंक्तियां का इस्तेमाल करते रहे हैं। उनके कई शेर हैं जो व्यक्ति में ही नहीं बल्कि पूरे समाज में क्रांति की अलख जगा देने की ताकत रखते हैं। उनकी कई रचनाओं को स्कूल के साथ ही बी.ए. और एम.ए. के पाठ्यक्रम में विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता हैं। वहीं बहुत से शोधार्थियों ने उनके साहित्य पर पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है। दुष्यंत कुमार का जन्म 01 सितंबर 1933 को उत्तर-प्रदेश के बिजनौर जिले के राजपुर नवादा गांव में हुआ था। उनका मूल नाम दुष्यंत कुमार त्यागी था लेकिन वह साहित्य जगत में दुष्यंत कुमार के नाम से जाने गए। उनके पिता का नाम श्री भगवत सहाय और माता का नाम श्रीमती राम किशोरी था। दुष्यंत का अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान ही राजेश्वरीजी से विवाह हुआ था। इसके बाद दोनों ने प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी, दर्शनशास्त्र व इतिहास विषय में विवाहोपरांत साथ मिलकर बी.ए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से ही द्वितीय श्रेणी में एम.ए की परीक्षा पास की। यहीं से उनके साहित्यिक जीवन का आरंभ हुआ और उनके लेखन को एक नया आयाम मिला। अपने दांपत्य जीवन में उन्होंने तीन संतानों को जन्म दिया। उनके दो पुत्र और एक पुत्री थी।

अपने अध्ययन के दौरान दुष्यंत कुमार साहित्यिक संस्था 'परिमल' की गोष्ठियों में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे और 'नए पत्ते' जैसे महत्वपूर्ण पत्र से भी जुड़े रहे। इस समय उन्हें मार्गदर्शक के रूप में डॉ.रामकुमार वर्मा, डॉ. धीरेंद्र कुमार शास्त्री व डॉ. रसाल मिले तो सहपाठी के रूप में कमलेश्वर, मार्कंडय और रवींद्रनाथ त्यागी का सान्निध्य प्राप्त हुआ। लेकिन जिंदगी का काफी हिस्सा मध्य प्रदेश में बीता। मध्य प्रदेश सरकार उनके नाम पर दुष्यंत कुमार पुरस्कार भी देती चली आ रही है। दुष्यंत आपातकाल के दौर में अपनी बागी रचनाओं के लिए भी चर्चित हुए थे। दुष्यंत कुमार ने केवल 42 वर्ष का जीवन पाया था लेकिन उन्होंने जिस भी विधा में साहित्य का सृजन किया वह कालजयी हो गई। उनकी रचनाएं सार्वदैशिक, सार्वकालिक एवं सार्वभौमिक हैं, जो आधुनिक हिंदी साहित्य में आज भी 'मील का पत्थर' मानी जाती हैं। हिंदी अल्फाज़ की ऐसी रवानी, ऐसी ताजगी, ऐसी ऊर्जा और किसी शायर में मुश्किल से ही देखने को मिलती है। दुष्यंत की गजलों एवं शायरी में हिंदी-उर्दू अल्फाज़ का प्रयोग एक नई ताज़गी के साथ ज़ाहिर हुआ है और यह दुष्यंत की बड़ी खूबी मानी जा सकती है। दुष्यंत ने इंसानी कशमकश, जज़्बात, उदासी, महरूमी को भी बहुत फनकारी के साथ बयान किया गया है, जो उन्हें एक न भूलने वाला शायर बनाता है। इसके अलावा ज़बान की सादगी और ज़बान का हिंदुस्तानीपन दुष्यंत को अपने ढंग के सबसे अनोखे और अलबेले शायर के रूप में भी स्थापित करता है। दुष्यंत नई ग़ज़ल के माध्यम से सच बोलने एवं सच रचने का साहस किया एवं अनोखे शायर कहलाये। जिनकी शायरी तब तक ज़िंदा रहेगी जब तक गरीबों, लाचारों और बेबसों के लिए कोई न कोई आवाज़ उठती रहेगी। दुष्यंत के बारे में अच्छी और बुरी बातें हर नए दौर में कही जाती रहेंगी, लेकिन दुष्यंत ही अकेले ऐसे शायर हैं जिन्होंने उम्र भर सियासत को मुंह चढ़ाया, मगर कमाल यह है कि दुष्यंत के बाद सियासतदानों ने संसद में या संसद के बाहर, विधानसभाओं में या विधानसभाओं के बाहर अपनी बात को मनवाने और अपनी बात में ज्यादा वजन पैदा करने के लिए दुष्यंत को ही बार-बार कोट किया है, उनकी ही गजलों एवं शायरी का सहारा लिया है। दुष्यंत का आदर्श कोरा दिखावा न होकर संकल्प की उच्चता एवं पुरुषार्थ की प्रबलता है। व्यक्ति एवं समाज क्रांति के रूप में विकृत सोच एवं आधे-अधूरे संकल्पों को बदलने के लिये दुष्यन्त ने जिजीविषा एवं रचनात्मकता के उपाय निर्दिष्ट किये हैं। दुष्यंत कुमार की संपूर्ण साहित्यिक रचनाओं एवं रचना संसार में अनेक कृतियां हैं। उनके गजल-संग्रह में साये में धूप है तो उपन्यासों में शामिल है छोटे-छोटे सवाल, आँगन में एक वृक्ष, दुहरी ज़िंदगी। उनके काव्य-संग्रह में सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत हैं। गीति नाट्य है एक कंठ विषपायी। प्रमुख नाटक है और मसीहा मर गया। कहानी-संग्रह है मन के कोण। हिंदी गजल विधा के पुरोधा दुष्यंत कुमार के सम्मान में भारतीय डाक विभाग ने एक डाक टिकट जारी किया था। इसके साथ ही 'दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय' में उनकी धरोहरों को संभालने का प्रयास किया गया है। दुष्यंत कुमार की कविता 'हो गई है पीर पर्वत सी, अब पिघलनी चाहिए' के कुछ अंशों का इस्तेमाल 2017 की लोकप्रिय फ़िल्म इरादा में किये गये हैं एवं भारत में हर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान अक्सर इसका उपयोग होता रहा है। दुष्यंत मायूसी के काले बादलों को तार-तार करने की ताक़त रखते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने पर उकसाते हैं। दुष्यन्त हिंदी साहित्य के आकाश में सूर्य की तरह चमकते हैं और चमकते रहेंगे। आम से दिखने वाले दुष्यंत को इतनी शोहरत इसलिये मिली कि उन्होंने कभी भी शायरी अपने लिए नहीं की बल्कि जब भी कलम उठायी, अपने लोगों, अपने समाज एवं अपने राष्ट्र के लिए उठायी। जब भी दुख ज़ाहिर किया उन लोगों का किया जिनका दुख दुनिया के लिए कोई मायने नहीं रखता था। ऐसे लोग जो अपने दुख अपने सीनों में लिए जीते रहते हैं और ऐसे ही मर जाते हैं, उन लोगों के दर्द को आवाज देने वाला दुष्यन्त महान् रचनाकार है।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कमलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,हमीदपुरा रोड खण्डवा,निवाई टोंक (राज.) से मुद्रित एवं 185/ 116 ''प्रतीक्षा'' सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-तनुजा पठान*। प्रधान संपादक-राम बिलास विजयवर्गीय मो. 9414242258, 9214048888,जयपुर फोन नं.0141-2796794,795 टोंक कार्यालय-बाईपास निवाई, टोंक फोन नं.01432-244881 निवाई 01438-222201,202,203 अलवर कार्यालय-मेहताब सिंह का नोहरा,अलवर मो. 7733000123,कोटा कार्यालय-छावनी मेन रोड,कोटा मो.9414823448 । ई मेल-badhatarajasthan@yahoo.com *पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार

https://t.me/AllNewsPaperPaid

संपादकीय

प्रदूषण से जंग

यह खबर उत्साहवर्धक है कि भारत में सूक्ष्म कणों से पैदा होने वाले जानलेवा प्रदूषण में गिरावट आई है। लेकिन अभी जीवन प्रत्याशा घटाने वाले प्रदूषण को लेकर जारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की हालिया वार्षिक रिपोर्ट 'वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक-2024' बताती है कि भारत में साल 2021 की तुलना में 2022 के वायु प्रदूषण में 19.3 फीसदी की कमी आई है। हालांकि, यह उपलब्धि मौजूदा हालात में बहुत बड़ी तो नहीं कही जा सकती है, लेकिन यह बात उत्साहवर्धक है कि प्रत्येक भारतीय की जीवन प्रत्याशा में इक्यावन दिन की वृद्धि हुई है। हालांकि, हम अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों की कसौटी पर खरे नहीं उतरे हैं,लेकिन एक विश्वास जगा है कि युद्ध स्तर पर प्रयासों से भयावह प्रदूषण के खिलाफ किसी हद तक जंग जीती भी जा सकती है। लेकिन इसके साथ ही 'वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक-2024' में यह भी चेताया गया है कि यदि भारत में डब्ल्यूएचओ के वार्षिक पीएम 2.5 के सांद्रता मानक के लक्ष्य पूरे नहीं होते तो भारतीयों की जीवन प्रत्याशा में करीब साढ़े तीन साल की कमी आने की आशंका पैदा हो सकती है। दरअसल, पीएम-2.5 हवा में विद्यमान ऐसे सूक्ष्म कण होते हैं जो हमारे श्वसनतंत्र पर घातक प्रभाव डालते हैं। उल्लेखनीय है कि एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेखित प्रदूषण में आई गिरावट की वजह अनुकूल मौसम संबंधी परिस्थितियां बतायी गई हैं। हालांकि, हकीकत यह भी है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिये चलायी जा रही कई योजनाओं के सकारात्मक परिणामों का भी इसमें योगदान रहा है। खासकर भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत जिन शहरों को शामिल किया गया था, वहां भी पीएम-2.5 सांद्रता में गिरावट देखी गई है। वहीं स्वच्छ ईंधन कार्यक्रम का सकारात्मक प्रभाव प्रदूषण नियंत्रण पर नजर आया है। इससे भारत के रिहाइशी इलाकों में कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिली है। ऐसी योजनाओं को पूरे देश में लागू करने का सुझाव भी दिया गया है।

बहरहाल, हमें वर्ष 2022 के उत्साहजनक परिणामों के सामने आने के बाद व्यापक लक्ष्यों के प्रति उदासीन नहीं होना है। यह एक लंबी लड़ाई है और इसमें सरकार व समाज की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि सरकारों के भरोसे ही लगातार गहराते पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकता है। राष्ट्रीय राजधानी में हर साल ठंड की दस्तक के बाद पराली जलाने और दिवाली पर पटाखे फोड़ने के बाद जो प्रदूषण का बड़ा संकट खड़ा होता है, उसमें हम अपनी जिद व लापरवाही की भूमिका को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम न भूलें कि देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की गिनती लगातार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानियों में होती रही है। दरअसल, पीएम-2.5 कणों की सांद्रता बढ़ाने में हमारी लापरवाही की बड़ी भूमिका होती है, जिसमें सड़कों पर बढ़ते वाहनों का दबाव भी शामिल है। जिसके मूल में हमारी लचर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था भी है। हालांकि, राजधानी समेत कई अन्य राज्यों में मेट्रो ट्रेन शुरू होने के बाद प्रदूषण में काफी कमी आई है। इस दिशा में हमें दीर्घकालीन नीतियों के बारे में सोचना होगा। हमारी कोशिश हो कि घनी आबादी के बीच चलायी जा रही औद्योगिक इकाइयों को शहरों से दूर स्थापित किया जाए। हमारे उद्यमियों को भी जिम्मेदार नागरिक के रूप में प्रदूषण नियंत्रण में योगदान देना चाहिए। नीति-नियंताओं को सोचना चाहिए कि प्रदूषण में अप्रत्याशित वृद्धि के बाद दिल्ली आदि शहरों में चलाये जाने वाले ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रेप जैसी व्यवस्था को नियमित रूप से लागू क्यों नहीं किया जा सकता। हालिया कुछ अध्ययनों में बताया गया है कि बढ़ता प्रदूषण नवजात शिशुओं तथा बच्चों की जीवन प्रत्याशा पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। निस्संदेह, लगातार जहरीली होती हवा से मुक्ति नीति-नियंताओं की प्राथमिकता में शामिल होनी चाहिए। ऐसे में हमें पराली के निस्तारण, औद्योगिक कचरे के नियमन तथा कार्बन उत्सर्जन करने वाले ईंधन पर रोक लगाने जैसे फौरी उपाय तुरंत करने चाहिए।

बेहतर आर्थिक उपलब्धियों की आधी सदी

भारत का अंतर्राष्ट्रीय उल्लेख अब 'गरीबों का देश' की बजाय एक उभरती हुई शक्ति के रूप में किया जाता है। फिर भी, भारत अपने मानव विकास सूचकांक में केवल 'मध्यम विकास' वाला देश गिना जाता है, जबकि वियतनाम जैसे देशों ने 'उच्च विकास' का दर्जा प्राप्त कर लिया है।

आज हमें लगता नहीं कि हुआ होगा, लेकिन 50 साल पहले भारत एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया था। उस समय आर्थिक संकट और राजनीतिक उथल-पुथल थी। एक साल बाद निर्णायक कार्रवाई के रूप में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू कर दिया था। लेकिन दो साल से भी कम समय में इस फैसले को वापस ले लिया। जो चीज अधिक दीर्घकालिक साबित हुई व जिस पर उस समय मुश्किल से गौर किया जाता था - इंदिरा गांधी के साफतौर पर झलकते वामपंथी झुकाव वाले चरण से इतर आर्थिक नीति में एक नई दिशा की जरूरत थी। इसके बाद वाले समय में, भारत द्वारा लंबे समय तक आर्थिक मोर्चे पर कमजोर प्रदर्शन करने वाले युग का अंत हुआ और आगे जाकर एक नई 'भारतीय गाथा' का जन्म हुआ। वर्ष 1970 के दशक के मध्य तक, विश्व अर्थव्यवस्था की तुलना में भारत की प्रगति काफी धीमी थी। 1970 के दशक का उत्तरार्ध संक्रमण काल था, जिसमें युद्ध, कमजोर खेती और यहां तक कि अकाल, भारतीय रुपये का असहनीय अवमूल्यन और तेल पर मिले दो झटकों के रूप में लगभग 15 साल तक संकटकाल बना रहा। जवाहर लाल नेहरू के शुरुआती आशावाद के बाद इनमें से कई घटनाओं ने राष्ट्रीय आत्मविश्वास खोने में योगदान किया था। लेकिन एक बार जब अर्थव्यवस्था स्थिर हो गई, तो उसके बाद लगातार आधी सदी तक बेहतर प्रदर्शन हुआ। विकास दर के मामले में, निम्न-आय और मध्यम-आय वाले देशों के अलावा, कई विकसित अर्थव्यवस्थाओं को भी पीछे छोड़ दिया गया है। परिणामस्वरूप, देश के पास आज एक अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव है, जो इससे पहले कभी नहीं था। फिर भी, निरंतर खराब सामाजिक-आर्थिक मापदंडों और बढ़ती असमानता के कारण यह एक 'चमकदार' रिकॉर्ड नहीं रहा है।

संक्रमण काल से पहले, वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी कम ही रही–इससे पहले की गिरावट धीमी पड़ी, स्थिर हुई और आखिर में सुधरने लगी। वर्ष 1960 में यह 2.7 प्रतिशत से घटकर 1975 में 1.9 फीसदी रही। यहां तक कि 2013 में भी, विश्व जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 1960 की तुलना में मामूली कम थी। अब, 2024 में, यह वैश्विक जीडीपी का 3.5 प्रतिशत है। और चूंकि अर्थव्यवस्था वैश्विक औसत से दोगुनी गति से बढ़ रही है, इसलिए वैश्विक आर्थिक विकास में भारत तीसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। प्रति व्यक्ति आय में भी इसी तरह सुधार हुआ है। प्रति व्यक्ति आय के वैश्विक औसत में, 1960 में यह 8.4 प्रतिशत से घटकर 1974 में 6.4 फीसदी रह गई। 2011 में यह मात्रा बढ़कर 13.5 प्रतिशत हो गई और 2023 में यह 18.1 प्रतिशत रही। पिछले पांच दशकों में यह वृद्धि लगभग तीन गुना है। फिर भी अधिकांश देशों में लोग काफी अच्छे जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं। वास्तव में, अफ्रीका और भारत के पड़ोसी दक्षिण एशियाई देशों के अलावा शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां प्रति व्यक्ति आय वैश्विक औसत से कम हो। अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है।

भारत की गाथा को बदलने वाला मुख्य कारक इसकी जनसंख्या का आकार है। हालांकि, प्रति व्यक्ति आय मामूली है, लेकिन जब इसे 140 करोड़ से गुणा किया जाता है, तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देती है। वर्तमान में, भारत मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल-स्कूटर के लिए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। शायद विमानन सेवा और कारों के लिए तीसरे या चौथे स्थान पर। उत्पाद और सेवा बाजार में हुई उल्लेखनीय वृद्धि मध्यम आय वर्ग के आकार में हो रहे विस्तार की बदौलत है। इस वर्ग को सेवा मुहैया करने वाले काम-धंधों से निवेशकों ने बहुत अधिक धन बनाया, जिससे भारत के डॉलर-खरबपतियों की गिनती में बढ़ोतरी हुई (200 की संख्या के साथ भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है) जबकि शेयर बाजार पूंजीकरण के हिसाब से इसकी स्टॉक मार्केट चौथे स्थान पर आती है। वर्ष 1970 के दशक के मध्य तक, लगभग आधी से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी। आज, 10 प्रतिशत से भी कम लोग आधिकारिक तौर पर गरीब हैं। भारत का अंतर्राष्ट्रीय उल्लेख अब 'गरीबों का देश' की बजाय एक उभरती हुई शक्ति के रूप में किया जाता है। फिर भी, भारत अपने मानव विकास सूचकांक में केवल 'मध्यम विकास' वाला देश गिना जाता है, जबकि वियतनाम जैसे देशों ने 'उच्च विकास' का दर्जा प्राप्त कर लिया है। अगले एक दशक या उससे अधिक समय तक भारत की 'उच्च विकास' श्रेणी में शामिल होने की संभावना नहीं है–इसके ऊपर विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाली 'बहुत उच्च विकास' श्रेणी है, जिसमें जगह बनाने की आकांक्षा हमारा देश रखता है। हालांकि, यहां भी आंकड़े में सुधार हो रहा है। स्कूली शिक्षा में बिताई औसत अवधि, वर्ष 2010 में 4.4 वर्ष से बढ़कर अब 6.57 वर्ष हो गई है। भारत में प्रति 1,000 व्यक्ति पर एक डॉक्टर है जोकि डब्ल्यूएचओ द्वारा सुझाए अनुपात से अधिक है, और औसत जीवनकाल अंततः 70 वर्ष की सीमा पार कर चुका है। अधिक आय का मतलब है ज्यादा विविधतापूर्ण और समृद्ध खुराक। दूध की खपत 10 गुना बढ़ गई है। इसी तरह मछली का उपभोग भी बढ़ा है, जबकि अंडों की खपत 20 गुना से अधिक बढ़ गई है। इसमें बागवानी–फल और सब्जियों के मामले में तेजी से हुई वृद्धि भी शामिल है। इस बीच, आय के हिस्से के रूप में घरेलू बचत 70 प्रतिशत बढ़ गई है।

इन सबसे भी, शायद अधिक महत्वपूर्ण है मानसिकता में आया बदलाव। वर्ष 1970 के दशक के मध्य तक भारत समाजवाद के फलसफे के लिए प्रतिबद्ध था। बड़े पैमाने पर कई उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किए जाने के अलावा, कागज से लेकर स्टील, चीनी, सीमेंट, यहां तक कि नहाने के साबुन और कारों तक, हर चीज़ पर मूल्य एवं उत्पादन नियंत्रण का निज़ाम था! औद्योगिक विवादों में राज्य सरकारें नियमित रूप से ट्रेड यूनियनों का पक्ष लेती थीं। लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। भारतीय राजनीति अब समाजवादी से ज़्यादा लोकलुभावन है, वामपंथी दल पराभव अवस्था में हैं। सरकारें व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए श्रम कानूनों में बदलाव करना चाहती हैं। भारतीय लोग उत्साही शेयर-बाज़ार पूंजीपति बनने लगे हैं। 1974 में, शेयरों का सबसे बड़ा पब्लिक इश्यू कुल 12 करोड़ रुपये का था (आज के पैसे में लगभग 350 करोड़ रुपये)। इसकी तुलना में, पिछले कुछ वर्षों में, कई निजी कंपनियों ने ही 15,000-21,000 करोड़ रुपये के पब्लिक इश्यू जारी किए हैं (एलआईसी, अडाणी, वोडाफोन, आदि)। एक दशक पहले तक, म्यूचुअल फंड कंपनियां बैंकों में जमा कुल रकम के आठवें हिस्से जितना ही जुटा पाती थीं, अब इसका अंश दोगुना होकर एक-चौथाई से अधिक हो गया है।

आज का इतिहास

- पीसा काउंसिल 1511 में खुला।
- अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति आरोन बर्र 1807 को राजद्रोह के मामले में निर्दोष पाये गये।
- एम्मा एम नट्ट अमेरिका में 1878 को पहली महिला टेलीफोन ऑपरेटर बनी।
- ग्रेट कैंटो भूकंप ने 1923 में जापान के टोक्यो और योकोहामा में भयंकर तबाही मचायी।
- जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करने के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हुई।
- भारतीय मानक समय को 1947 में अपनाया गया।
- भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की स्थापना 1956 में हुई।
- राज्यों के पुनर्गठन के बाद 1956 को त्रिपुरा केन्द्रशासित प्रदेश बना।
- महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 1962 को शिवाजी विश्वविद्यालय की स्थापना।
- इंडियन ऑयल रिफ़ाइनरी और इंडियन ऑयल कम्पनी को 1964 में विलय करके इंडियन ऑयल कॉपरेशन बनाई गयी।
- मिस्र और लीबिया ने 1972 में फेडरेशन बनाया।
- उत्तरी आयरलैंड में आयरिन रिपब्लिकन आर्मी ने 1994 में युद्ध विराम लागू किया।
- साहित्यकार महाश्वेता देवी तथा पर्यावरणविद एम सी मेहता को 1997 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया।
- विक्टर चेर्नोमीर्दिन पुन- रूस के नये प्रधानमंत्री 1998 को नियुक्त।
- चीन ने 2000 में तिब्बत होते हुए नेपाल जाने वाले अपने एकमात्र रास्ते को बंद किया।
- लीबिया और फ्रांस के बीच यूटीए विमान पर 1989 में हुई बमबारी में मारे गये लोगों के निकट सम्बन्धियों को मुआवजा देने को लेकर 2003 में समझौता हुआ।
- पाकिस्तान के एक मानवाधिकार विशेषज्ञ मेहर खान विलियम्स को 2004 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने उप उच्चायुक्त नियुक्त किया।
- सद्दाम हुसैन ने 2005 में सशर्त रिहाई की अमेरिकी पेशकश ठुकराई।
- फिजी के अपदस्थ प्रधानमंत्री लाइसेनिया करासे 2007 को नौ महीने बाद राजधानी सुवा लौटे।
- तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने डी. सुब्बाराव की भारतीय रिजर्व बैंक के 22वें गर्वनर के रूप में नियुक्ति की घोषणा 2008 में की।
- यूनियन बैंक ऑफ़ इण्डिया ने 2008 में अपना लोगो बदला।
- वायस एडमिरल निर्मल कुमार वर्मा को 2009 में भारतीय नौसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया।
- सर्वोच्च न्यायालय में जसवंत सिंह की किताब पर गुजरात में प्रतिबंध लगाए जाने के मामले में राज्य सरकार को 2009 में नोटिस दिया।
- भारतीय संगीतकार चेमबइ वैद्यनाथ भगवतार का जन्म 1895 को हुआ था।
- प्रसिद्ध गौड़ीय वैष्णव गुरु तथा धर्मप्रचारक भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपाद का जन्म 1896 को हुआ था।

अराजक राजनीति से अपराध के दलदल में भद्रलोक

बंकिम चंद्र की शस्य-श्यामला माटी वाला पश्चिम बंगाल एक शक्ति-पूजक समाज है। शरद ऋतु के स्वागत के साथ बंगाल की धरती हर साल मां दुर्गा के स्वागत में विभोर हो जाती है। बंगाल में महिलाओं का सम्मान किस प्रकार की परंपरा का हिस्सा रहा है, इसे समझने के लिए दुर्गा पूजा के विधान को समझना चाहिए। मूर्तियों को बनाने के लिए सबसे पहले उन वेश्याओं के घर से मिट्टी लाई जाती है, जिन्हें समाज आम तौर पर त्याज्य और गंदा मानता है। इस प्रकार बंगाल की धरती कितनी नारी-पूजक रही है, यह स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में भी देखने को मिलता है, जो अन्य राज्यों में कम ही मिलता है।

स्वाधीनता संग्राम में जिन तीन महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई और अपने ज्ञान व संघर्ष से भारत को आलोकित किया, वे तीनों बंगाल की बेटियां थीं। पहली थीं अरुणा गांगुली, जिन्होंने बाद में अरुणा आसफ अली का नाम अपनाया। दूसरी थीं सुचेता मजूमदार, जो सुचेता कृपलानी के नाम से प्रसिद्ध हुईं। तीसरी थीं सरोजिनी चट्टोपाध्याय, जिन्होंने बाद में भारत कोकिला सरोजिनी नायडू का नाम पाया।

बंगाल की माटी ने महिलाओं को कितना सम्मान दिया, इसका एक और उदाहरण कमला देवी चट्टोपाध्याय हैं। जब भारत के अन्य इलाकों की महिलाएं घूंघट के पीछे सिर्फ परिवार के काम में व्यस्त थीं, तब बंगाल ने अपनी बेटियों को वाजिब सम्मान और अवसर दिए। बंगाल में कभी महिलाओं के साथ बदसलूकी की कल्पना तक नहीं की जाती थी।

अब स्थिति बदल गई है। इसका एक उदाहरण हाल ही में राधागोविंद कर अस्पताल में हुई घटना है। स्वतंत्रता की 77वीं सालगिरह की रात, जब पूरा देश उत्सव में था, कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर की बर्बरतापूर्वक बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। बंगाल में देर रात तक दफ्तर से लौटने वाली लड़कियों की कभी चिंता नहीं होती थी, लेकिन अब लोग अपनी बच्चियों के लिए चिंतित हो गए हैं। यह बंगाल में महिला के खिलाफ ऐसी बर्बरता की शायद पहली घटना है। इससे बंगाली समाज का क्रोध और क्षोभ स्वाभाविक है।

दिलचस्प यह है कि पश्चिम बंगाल इकलौता ऐसा राज्य है, जिसे महिला मुख्यमंत्री का गौरव प्राप्त है। एक महिला के शासन में इस प्रकार का दुराचार लोगों के लिए असहनीय है। इसलिए बंगाल इन दिनों बहुत उबाल पर है। बंगाल का बौद्धिक समाज सड़कों पर उतर आया है। पश्चिम बंगाल में हाल ही में संदेशखाली से महिलाओं के बलात्कार की खबरें आई थीं। वहां की घटनाओं की परतें खुलने पर पता चला कि बलात्कार की घटनाएं अपराध और राजनीति के नापाक गठजोड़ का नतीजा थीं। संदेशखाली की पीड़िताओं की खबरें भले ही उबाल ला पाई, लेकिन आरजी कर अस्पताल की घटना ने कहीं अधिक ध्यान खींचा। इसका कारण यह हो सकता है कि संदेशखाली की पीड़िताएं ग्रामीण इलाकों से थीं, जबकि आरजी कर की घटना कोलकाता शहर में हुई, जिसे भद्रलोक समाज के लिए जाना जाता है।

पश्चिम बंगाल की कड़वी सच्चाई बांग्लादेश से हो रही अवैध घुसपैठ है। 34 वर्षों के वामपंथी शासन के दौरान इस घुसपैठ को वैधता मिली। वामपंथी शासन व्यवस्था के दौरान पार्टी कैडर के नाम पर बड़े झुंड उभरे। पश्चिम बंगाल के वासी इस संस्थागत व्यवस्था से इतने परेशान हो गए कि उन्हें ममता बनर्जी में नई उम्मीद दिखी। बंगाली समाज को लगा कि ममता एक नई बयार बनकर पश्चिम बंगाल की व्यवस्था में जमी काई को साफ करेंगी। लेकिन अफसोस, ऐसा नहीं हुआ। ममता भी उसी दिशा में चल पड़ीं, जिस दिशा में वामपंथी कैडर चलते थे।

प्रशासन लगातार या तो पंगु होता गया या फिर सत्ताधारी तंत्र का चारण बनता गया। प्रशासन का यह चारण रूप 16 अगस्त को भी दिखा, जब आरजी कर की पीड़िता की रिपोर्ट साढ़े ग्यारह बजे रात को दर्ज की गई, जबकि बलात्कार और हत्या पंद्रह अगस्त की रात दो से ढाई बजे के बीच हो चुकी थी। इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस किया और कोलकाता पुलिस को फटकार भी लगाई। ममता की अगुआई में कोलकाता में बलात्कार और हत्या के विरोध में धरना दिया गया। यह धरना ऐसा था, जो सरकार के खिलाफ सरकार द्वारा ही दिया गया था। ऐसा किसी भी लोकतांत्रिक समाज में कम से कम अब तक नहीं देखा गया है। ममता ने प्रशासन में कोई गुणात्मक बदलाव नहीं किया, बल्कि वामपंथ जैसी कैडर व्यवस्था को अपना लिया। इससे राज्य में अपराध बढ़ा और पुलिस का इकबाल कम हुआ। पुलिस की लाचारगी आरजी कर बलात्कार में भी नजर आई।

बंगाल के बारे में कहा जाता रहा है कि 'बंगाल जो आज सोचता है, वैसी सोच भविष्य में अन्य राज्यों की होती है।' इस उम्मीद को कायम रखते हुए भद्रलोक समाज को चाहिए कि वह इस दिशा में भी सोचे। उसका गुस्सा एक ऐसे बंगाल की रचना करे, जहां रवींद्र संगीत गूंजता रहे, बंकिम के गीत गाए जाएं और नारियां स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। जहां सिंदूर खेला होगा, घुंघुंची नृत्य होगा और दुर्गा देवी की पूजा होगी।

नई जल प्रहरी 'अरिघात'

अरिहंत और अरिघात में 83 मेगावाट के लाइट वाटर रिएक्टर हैं जिनसे इनका संचालन किया जाता है। परमाणु रिएक्टरों के कारण यह पनडुब्बी परम्परागत पनडुब्बियों की तुलना में महीनों तक पानी में रह सकती है।

भारत में शास्त्र और शस्त्र का बहुत महत्व है। शास्त्र और शस्त्र से बुद्धि और बल का आपसी समन्वय होता है। शास्त्र जीवन का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करते हैं और शस्त्र दुष्टों से रक्षा करते हैं। ऋ?षियों-मुनियों की तप साधना को बचाने के लिए और उनके यज्ञ में कोई विघ्न न डाले इसलिए भगवान श्रीराम ने शस्त्रों से ही राक्षसों का संहार किया था। सिख गुरुओं ने भी धर्म और शास्त्रों की रक्षा के लिए शस्त्र उठाए थे। कोई भी राष्ट्र तब तक शक्तिशाली नहीं होता जब तक उसकी सेना मजबूत नहीं होती। हमें इस बात पर गर्व है कि भारत की तीनों सेनाएं थल, वायु और जल सेना हर तरफ से देश की सुरक्षा के लिए तैयार हैं। थल और वायुसेना के साथ-साथ अब भारतीय नौसेना भी बहुत ताकतवर बन चुकी है। भारतीय नौसेना 1612 में अस्तित्व में आई थी तब अंग्रेजों के शासन में इसे रॉयल इंडियन नेवी का नाम दिया था।

स्वतंत्रत?ा के बाद 1950 में इसे भारतीय नौसेना के तौर पर पुनर्गठित किया था। भारतीय नौसेना अब अपने युद्ध पोतों और पनडुब्बियों के बेड़े का विस्तार करने पर ध्यान केन्द्रित कर रही है ताकि 2035 तक जंगी जहाजों की संख्या 175 हो सके। अंडरवाटर लड़ाकू वाहकों को बढ़ाने के लिए भारत अब स्वदेशी उत्पादन पर निर्भर है। हिन्द महासागर क्षेत्र में दुश्मनों को रोकने के ?लिए भारतीय नौसेना के संचालन का क्षेत्र विस्तार ले रहा है और इसके लिए जरूरी है कि भारतीय नौसेना को लगातार मजबूत बनाया जाए। गुरुवार को रक्षामंत्री राजनाथ की उपस्थिति में भारतीय नौसेना में स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघात को शामिल ?किया गया है। यह दूसरी परमाणु पनडुब्बी होगी जो ?हिन्द महासागर में देश की नई प्रहरी होगी। अरिघात का अर्थ शत्रु का नाश करने से है और यह शब्द संस्कृत से ?लिया गया है। इस तरह की पनडुब्बी अब तक सिर्फ पांच देशों के पास है या?न फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, रूस और अमेरिका। भारत अब ऐसी पनडुब्बी हासिल करने वाला छठा देश बन गया है। यह पनडुब्बी देश की परमाणु तिकड़ी परमाणु ट्रायडेट को और मजबूत करेगी। परमाणु प्रतिरोध को बढ़ाएगी। क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन स्थापित करने में मदद देगी और देश की सुरक्षा में निर्णायक भूमिका निभाएगी।

अरिहंत श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी अरिघात अरिहंत का उन्नत स्वरूप है और यह अत्याधुनिक हथियार प्रणाली तथा उपकरणों से लैस है। इसे कठिन तथा निरंतर परीक्षणों की सफलता के बाद नौसेना को सौंपा गया है। अरिघात की लंबाई 112 मीटर, चौड़ाई 11 मीटर तथा इसका वजन 6 हजार टन है। पनडुब्बी में घातक 15 मिसाइलें लगी हैं जो 750 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम हैं। इसकी विशेषता यह है कि यह दुश्मन को चकमा देकर उसकी पकड़ में आये बिना हमला करने में सक्षम है। पनडुब्बी डेढ़ हजार फुट से भी अधिक गहराई तक पानी में जा सकती है। देश में तीसरी परमाणु पनडुब्बी अरिदमन भी बनायी जा रही है और कुछ वर्षों में यह भी नौसेना के बेड़े में शामिल हो जायेगी।

अरिहंत और अरिघात में 83 मेगावाट के लाइट वाटर रिएक्टर हैं जिनसे इनका संचालन किया जाता है। परमाणु रिएक्टरों के कारण यह पनडुब्बी परम्परागत पनडुब्बियों की तुलना में महीनों तक पानी में रह सकती है।

पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में भारत परमाणु शक्ति बना था। पोखरण में परमाणु विस्फोट परीक्षण कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। वर्ष 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब भारत ने फिर परमाणु परीक्षण किए थे। 11 मई, 1998 को पोखरण में एक के बाद एक तीन सफल परीक्षण?के बाद भारत परमाणु राष्ट्र बन गया था। यह अटल बिहारी वाजपेयी की सोच का परिणाम था कि उस समय की केन्द्र सरकार देश की परमाणु नीति का और परमाणु अस्त्रों को तैनात करने के विकल्प का पुनर्मूल्यांकन करने को तैयार हो गई थी। तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल वी.पी. मलिक ने भी यह मांग रखी थी कि दुश्मन देशों के परमाणु अस्त्रों और मिसाइलों की बढ़ती चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार सेना की रणनीतिक प्रतिरोध क्षमता विकसित करे।

चीन तुम कब सुधरोगे

इसने तिब्बत को चीन का स्वायत्तशासी अंग स्वीकार कर लिया और बदले में चीन ने सिक्किम को भारत का हिस्सा मंजूर कर लिया। परन्तु इसके बाद से चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करने लगा और वह अभी भी जारी है। चीन को सैनिक मोर्चे पर नियन्त्रित रखना जरूरी है उतना ही कूटनीतिक मोर्चे पर भी उसे काबू में रखना महत्वपूर्ण है।

भारत और चीन के बीच नियन्त्रण रेखा पर तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के बीच सैनिक व कूटनीतिक स्तर की जो बातचीत जून 2020 के बाद से जारी है उसका अभी तक का नतीजा सन्तोषप्रद नहीं कहा जा सकता। इसका मुख्य कारण चीन की विस्तारवादी सोच है जिसके चलते इस देश की सेनाएं यदा-कदा नियन्त्रण रेखा को पार कर जाती हैं और बाद में बहाना बनाती हैं कि यह उनकी अवधारणा के चलते होता है। भारत के सन्दर्भ में चीन एक आक्रमणकारी देश है जिसने 1962 में भारत पर हमला उस समय किया था जब भारत उसकी दोस्ती की तरफ से आशवस्त था। उस समय उसकी सेनाएं असम के तेजपुर तक पहुंच गई थीं। चीन ने तब भारत की पीठ में छुरा घोंपते हुए भारत को यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि चीन का अपने पड़ोसी के बारे में नजरिया सैनिक शक्ति से बंधा हुआ है। वह अपनी सेना की ताकत पर भारतीय जमीन हड़पना चाहता है। उस समय पूरा देश सकते में आ गया था क्योंकि केवल तीन वर्ष पहले ही भारत में तत्कालीन चीनी प्रधानमन्त्री चाऊ-एन-लाई के आने पर 'हिन्दी-चीनी भाई-भाई' के नारे लगे थे। तब चीन ने भारत की पंचशील सिद्धान्त पर आधारित विदेश नीति के परखचे उड़ाकर ऐलान कर दिया था कि वह अपनी भौगोलिक सीमाओं का निर्धारण स्वयं करेगा। उस समय देश के प्रधानमन्त्री पं. जवाहर लाल नेहरू जैसे दूरदर्शी राजनेता थे। उस समय दुनिया के लगभग सभी लोकतान्त्रिक देशों ने भारत का समर्थन किया था और अन्तर्राष्ट्रीय दबाव में मजबूर होकर चीन की सेनाओं को वापस लौटना पड़ा था मगर इसके बावजूद उसने भारत के बड़े भू-भाग को अपने कब्जे में ले लिया था। तब से दोनों देशों के बीच नियन्त्रण रेखा की अवधारणा जमीन पर उतरी क्योंकि 1914 में भारत-चीन-तिब्बत के बीच खिंची मैकमोहन रेखा को चीन ने मानने से इन्कार इस वजह से कर दिया था क्योंकि वह तिब्बत को एक स्वतन्त्र देश नहीं मानता था। चीन ने 1949 में आजाद होते ही तिब्बत पर आक्रमण शुरू कर दिये थे और 1959 में इसका पूरा अधिग्रहण कर लिया था जिसकी वजह से तिब्बत के धार्मिक व राजनैतिक मुखिया दलाई लामा भारत में शरण लेने आ गये थे। पं. नेहरू ने दलाई लामा को भारत में अपनी निर्वासित सरकार बनाने की इजाजत दे दी थी। मगर 2003 में भारत के रुख में आमूलचूल परिवर्तन तब आया जब देश में भाजपा नीत वाजपेयी सरकार थी। इसने तिब्बत को चीन का स्वायत्तशासी अंग स्वीकार कर लिया और बदले में चीन ने सिक्किम को भारत का हिस्सा मंजूर कर लिया। परन्तु इसके बाद से चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करने लगा और वह अभी भी जारी है। चीन को सैनिक मोर्चे पर नियन्त्रित रखना जरूरी है उतना ही कूटनीतिक मोर्चे पर भी उसे काबू में रखना महत्वपूर्ण है। इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए कि जून 2020 में जब चीन की सेनाओं ने पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी पर अतिक्रमण किया था तो भारत के प्रति उसके नजरिये में ज्यादा बदलाव नहीं था और वह मानता था कि उसकी सैन्य शक्ति के आगे भारत झुक जायेगा परन्तु हमारे बीस वीर सैनिकों ने अपनी शहादत देकर चीनी सेना को गलवान घाटी में ही सबक सिखाया। मगर चीन ने इसके साथ अपनी सैनिक रणनीति में आधारभूत परिवर्तन किया लद्दाख व अरुणाचल इलाके में छिटपुट तरीके से घुसपैठ करने की रणनीति अपनाई, जिसकी वजह से चीन की सेनाओं का मुकाबला करने के लिए सीमा पर भारत ने भी 50 हजार सैनिकों को तैनात कर रखा है। इसके बावजूद चीन नियन्त्रण रेखा पर अपनी छिट-पुट घुसपैठ करके भारतीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर कब्जा किये हुए है। इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए भारत की सेनाएं पूरी मुस्तैदी के साथ डटी हुई हैं और सन्देश दे रही हैं कि आज का भारत 1962 का भारत नहीं है। यह भी सनद रहे कि भारत-चीन सीमा विवाद को हल करने के लिए दोनों देशों ने एक उच्च स्तरीय वार्ता दल बनाया हुआ है जिसकी दो दर्जन से अधिक बैठकें हो चुकी हैं।

https://t.me/AIRNewsArchive

सामाजिक दायरे में कई लोग रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, जिन्हें हम पंसद नहीं करते। लेकिन इसके बावजूद हमें उनकी मेजबानी करनी पड़ती है। क्योंकि इनकी मेजबानी करना जरूरी हो जाता है या हम 'ना' नहीं कह पाते, इसलिए हमें इसकी मेजबानी करनी पड़ती है. चाणक्य ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं, इनका बहुत अधिक मान-सम्मान या सत्कार करने से बचना चाहिए।

चाणक्य

सन्मार्ग
पटना, रविवार 01 सितंबर 2024
www.live7tv.com

पेंशन की भांति किसान को सुनिश्चित कीमत क्यों नहीं

देविंदर शर्मा

इसे पेंशन सुधार बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है। उन्होंने कहा हमें उन सभी सरकारी कर्मचारियों की कड़ी मेहनत पर गर्व है जो राष्ट्रीय प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वास्तव में, यूपीएस, जो प्राप्त अंतिम वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन का आश्वासन देता है, स्वीकारोक्ति है कि पहले वाली और बाजार नीत महंगाई से जुड़ी न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) सरकारी कर्मचारियों के लिए कारगर नहीं रही। सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित लाभ सुनिश्चित करने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेंशन योजना में बदलाव किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बाजार नीत अत्याचार (महंगाई) का सामना न करना पड़े। हालांकि, प्रधानमंत्री ने कई मौकों पर देश के किसानों की सराहना की है और अकसर कृषक समुदाय द्वारा प्रदर्शित लचीलेपन की प्रशंसा की है, लेकिन लंबे वक्त से चली आ रही गारंटीशुदा कीमत की मांग पर विचार करने में कोई भी इच्छुक नहीं है। अगर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बाजार नीत महंगाई से निपटना मुश्किल हो रहा है, तो स्पष्ट कर दें कि बाजार नीत महंगाई किसान के लिए भी उतनी ही बड़ी समस्या है। अगर कर्मचारियों को एक सुनिश्चित पेंशन की जरूरत पड़ती है, तो किसान को भी सुनिश्चित कीमत की जरूरत है। दुनिया में कहीं भी बाजार ने किसानों के लिए उच्च आय सुनिश्चित नहीं की है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में, या तो सब्सिडी देकर आय में घाटे की भरपाई की जाती है (चीन कृषि सब्सिडी प्रदान करने में शीर्ष पर उभरा है) या फिर कृषि को अपनी सुविधानुसार बाजार की ताकतों के रहमो-करम पर छोड़ दिया जाता है, मसलन, भारत में। जैसा कि कुछ अध्ययनों से पता चला है, निष्कर्ष केवल यह है कि भारतीय किसान आय पिरामिड के निचले स्तर पर है, बल्कि पिछले लगभग 25 वर्षों से वे हर साल घाटा उठा रहे हैं। किसानों को कभी खत्म न होने वाली गरीबी से बाहर निकालने का एकमात्र कारगर ढंग है कृषि कीमतों की गारंटी कानूनी रूप से बाध्यकारी तंत्र बनाकर सुनिश्चित करना। परंतु इसकी परवाह न करते हुए,

एनडीए सरकार ने कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट में पेश एक शपथपत्र में कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) गारंटी देने वाला कानून बाजार में बिगाड़ ला देगा। अजीब बात यह है कि जब किसानों की बात आती है, तो नीति निर्माता बाजार में बिगाड़ का वास्ता देकर और सुनिश्चित कृषि कीमतों से महंगाई पर आगे असर का हौवा खड़ा कर देते हैं। कर्मचारियों के मामले में सुनिश्चित पेंशन से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, उनके मामले में, बाजार में बिगाड़ का डर अचानक गायब हो जाता है। जब मुख्यधारा के अर्थशास्त्री मानते हैं कि कानूनन एमएसपी से उपभोक्ता कीमतें बढ़ेंगी और इस तरह बाजार में बिगाड़ होगा, तो वास्तव में, यह कॉर्पोरेट मुनाफे को कम करता है और इसीलिए हो-हल्ला मचता है। अजीब बात यह है कि मुक्त बाजार के हामी इन अर्थशास्त्रियों की यही नस्ल तब चुप रहती है जब अमेरिका में कॉर्पोरेट अपने उत्पाद की मूल्य वृद्धि करते हैं, उपभोक्ताओं को नोच खाने के लिए कीमतों में बेजा बढ़ोतरी करते हैं। वास्तव में यह मूल्य विकृति है। अमेरिका में पहले से ही, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क सहित 38 राज्यों ने ऐसे कानून बनाए हैं जो इस चलन को प्रतिबंधित करते हैं। उदाहरणार्थ, न्यूयॉर्क राज्य ने उन कंपनियों के खिलाफ कदम उठाया जिन्होंने महामारी के दौरान हैंड सैनिटाइजर की कीमतों में 400 प्रतिशत की वृद्धि की थी। और फिर भी, कई बाजार अर्थशास्त्री साफ नजर आने वाली ऐसी बाजार विकृतियों पर अंकुश लगाने के उपायों को सोवियत शैली के मूल्य नियंत्रण की ओर वापसी करार देते हैं। बाजार के पक्ष में यह पूर्वाग्रह तब पैदा होता है जब किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की बारी आए, लेकिन तब नहीं जब कॉर्पोरेट ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए कीमतें बढ़ाते हैं। बाजार विकृति पर यह दोगलापन किसानों को जीवनयापन की आय प्रदान करने की राह में अड़चन है। निःसंदेह, किसानों को देय सुनिश्चित कीमत के अनुसार बाजार अपने आप समायोजित हो जाएंगे। यह केवल खास किस्म की विचारधारा ही है, जो अड़ंगा लगा रही है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कॉर्पोरेट द्वारा अनाप-शनाप मूल्यवृद्धि पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है, जो कोविड महामारी के बाद खाद्य और किराना वस्तुओं की कीमतों में आई 53 प्रतिशत वृद्धि के लिए अकेले जिम्मेदार है। रिपब्लिकनों ने उनके इस रुख को कम्युनिस्ट ठहराया है। दक्षिणपंथी चाहे जो भी कहें, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, जैसा कि कुछ अर्थशास्त्री भी स्वीकारते हैं कि बेजा मूल्यवृद्धि पर अंकुश अच्छी अर्थव्यवस्था के साथ-साथ अच्छी राजनीति भी है। हैरिस ने उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया है जो खाद्य कीमतों को कृत्रिम रूप से ऊंचा रख रही हैं। वापस कर्मचारियों की पेंशन पर लौटते हुए, यह देखना दिलचस्प है कि व्यय विभाग इस निर्णय को सही ठहराने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है, इसे राजकोषीय रूप से विवेकपूर्ण करार देते हुए दावा किया जा रहा है कि यह नागरिकों की भावी पीढ़ियों को वित्तीय कठिनाई से बचाएगा। निश्चित रूप से, कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित पेंशन के खिलाफ कोई नहीं है। लेकिन यदि कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का आश्वासन दिया जा सकता है, तो कोई वजह नहीं है कि किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा का भरोसा न दिया जा सके। वे राष्ट्रीय प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और उनकी अथक मेहनत की बदौलत ही देश में खाद्य सुरक्षा बनी हुई है। मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के किसान कमलेश पाटीदार ने जब 10 एकड़ में खड़ी अपनी सोयाबीन की फसल को खुद ही रौंद दिया, तो उन्हें यह अहसास नहीं था कि इससे एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। घटना का वीडियो वायरल होने के कुछ ही दिनों बाद, कई अन्य दुखी किसानों द्वारा फसल उखाड़ने की खबरें आने लगीं। सोयाबीन की कीमतों में गिरावट- और वह भी कटाई के मौसम से डेढ़ महीने पहले- अर्थशास्त्रियों की एक और धारणा को नकारती है जो यह कहती है कि किसानों को कटाई तब तक रोक कर रखनी चाहिए जब तक कि उन्हें मंडी में फसल का भाव चढ़ा हुआ नजर न आने लगे। लेकिन यह जुगत भी कारगर न रही। सोयाबीन की मौजूदा कीमतें 12 साल पहले के स्तर पर आ गई हैं, लेकिन कृषि पर निर्भर आजीविका के विनाश ने लाखों सोयाबीन किसानों को गुस्से से भर दिया है। कीमतें, जो एमएसपी से बहुत कम हैं, उत्पादन लागत तक निकालने के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं। हैरानी की बात है कि हमारे पास किसानों के लिए एक सुनिश्चित मूल्य नीति कब होगी जो न केवल किसानों की भावी बल्कि वर्तमान पीढ़ी के लिए भी वित्तीय कठिनाइयों को रोकेगी। इसके तुरंत बाद, टमाटर की कीमतों में 60 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25 किलोग्राम वाले क्रेट का भाव 300 रुपये के निचले स्तर पर आने की खबरें आईं। और फिर बासमती की कीमतों में 28 प्रतिशत की गिरावट के साथ 2,500 रुपये प्रति क्विंटल आने की खबरें भी आईं। यह केवल इसी साल होने वाली कोई अनोखी बात नहीं है, बल्कि यह चलन एक दर्दनाक सालाना प्रवृत्ति बन चुका है, जिसको लेकर देश में चिंता नहीं है। किसान चाहे वह हो जिसके पास विपणन योग्य अतिरिक्त उत्पाद है या फिर हाशिए पर आता कृषक, जिसको प्रत्यक्ष आर्थिक मदद दी जाती है, उन्हें कानूनन गारंटीकृत एमएसपी प्रदान करना, वह बड़ा सुधार है जिसका इंतजार कृषि को शिद्दत से है।

हिंसक तत्वों पर लगाम लगे

कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु अगर निराश हैं, तो समझ सकते हैं कि हालात कितने बुरे हैं। राष्ट्रपति का कहना है कि देश के लोगों का गुस्सा जायज है और वह भी गुस्से में हैं। लेकिन इस गुस्से को जाहिर करने के लिए पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन के दौरान जिस तरह की हिंसक घटनाएं हुईं, वे कम निराशाजनक या चिंताजनक नहीं। बीजेपी ने 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया था। इस दौरान कई जगह से बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबरें आईं, एक बीजेपी नेता पर हमले का आरोप है। तमाम लोगों को हिरासत में लेना पड़ा। स्थिति यह थी कि सरकारी बस ड्राइवर हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाते दिखे। पिछले कुछ दिनों से जो बंगाल भीतर ही भीतर सुलग रहा था, वह अचानक से फट पड़ा। राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस हो या विपक्ष की बीजेपी, दोनों ही पार्टियां महिलाओं की सुरक्षा चाहती हैं। फिर टकराव की स्थिति कैसे बन गई? इसका सीधा-सा जवाब है पॉलिटिक्स। महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को राजनीति का मुद्दा न बनाने की अपील करने वाले नेता भी अपनी जरूरत के मुताबिक बड़े आराम से इसे राजनीति का रंग दे देते हैं। बंगाल में यही हो रहा है। टीएमसी प्रमुख और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने लगभग चेतावनी वाले अंदाज में कहा है कि अगर आग बंगाल में लगेगी तो यूपी, बिहार, असम और दिल्ली भी जलेंगे। इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया आ रही है, जो लाजिमी है। लेकिन, सोचने वाली बात है कि क्यों बंगाल बार-बार ऐसे हालात में फंसता है, जहां आग लगने की नौबत आ जाए। राज्य से थोड़े-थोड़े समय पर हिंसा की एक-जैसी तस्वीरें आती रहती हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति जितनी आक्रामक है, उतनी ही हिंसक भी। शायद इसकी वजह वहां के राजनीतिक इतिहास में है। 1970 और बाद के दशकों में राज्य ने नक्सलवादियों और सीपीएम कार्यकर्ताओं के बीच के हिंसक टकरावों को देखा। आरोप लगते रहे हैं कि कम्युनिस्ट दलों ने विपक्ष को पनपने नहीं दिया। बदलाव की उम्मीदें जगाकर आई टीएमसी भी हिंसा के उसी चक्रव्यूह में फंस गई। ऐसा लगता है कि जो असामाजिक तत्व पहले सक्रिय थे, वे अब भी अपना खेल दिखा रहे हैं, बस पार्टी बदल चुकी है। पश्चिम बंगाल बेहद संवेदनशील राज्य है। वहां हुई कोई भी घटना पूरे देश पर असर डालती है। ऐसे में पक्ष हो या विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है कि जनमत को प्रभावित करने की प्रक्रिया में इस बात का खास ख्याल रखें कि हिंसक तत्वों को बढ़ावा न मिले।

अंतरिक्ष में फजीता फिर भी डटी सुनीता

अरुण नैथानी

दुनिया भर के भारतीय एक बार फिर भारतवंशी बेटी सुनीता विलियम्स के लिये फिक्रमंद हैं। दरअसल, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में शोध-अनुसंधान के लिये गई सुनीता के लिए अपने एक सहयोगी के साथ निर्धारित समय पर लौट पाना मुश्किल हो रहा है। वे बोइंग के जिस अंतरिक्ष विमान स्टारलाइनर से गए थे, उसमें कई तरह की तकनीकी खामियां आ गई हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष संगठन नासा अपने अंतरिक्ष यात्रियों की जान को लेकर कोई जोखिम नहीं उठाना चाह रहा है। दो बेहद अनुभवी व प्रशिक्षित अंतरिक्ष यात्रियों की बेशकीमती जिंदगियों का प्रश्न तो है ही, लेकिन मिशन की असफलता से सुपरपावर की साख को जो झटका लगेगा, उसकी बड़ी कीमत होगी। वह भी तब जब उसके नंबर वन के ओहदे को चुनौती देने वाला चीन अंतरिक्ष अभियान में नित नई सफलताएं हासिल करता ही जा रहा है। मगर भारतीयों के लिये अपनी बेटी की सुरक्षा की चिंता है। उसके दिल में भारत की एक होनहार बेटी कल्पना चावला को खोने के जख्म अभी तक हरे हैं। हरियाणा की इस लाडली को खोने का गम देश अभी तक नहीं भुला पाया है।

बहरहाल, अब अमेरिका से छनकर आ रही खबरें बताती हैं कि जो सुनीता विलियम्स आठ दिन के लिये अंतरिक्ष मिशन पर गयी थीं, उसे अब आठ महीने अंतरिक्ष में गुजारने होंगे। निस्संदेह, किसी व्यक्ति के अंतरिक्ष में इस तरह की अनिश्चितताओं में फंसना एक बड़ी चिंता का सबब होता है। लेकिन सुनीता बड़ी दिलेर अंतरिक्ष यात्री हैं। एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर की चालक रही सुनीता की उपलब्धियों ने ही उसे अंतरिक्ष मिशन तक पहुंचाया है। यह उसका तीसरा अंतरिक्ष मिशन है। पूरी दुनिया ने उस वीडियो क्लिप को देखा था, जिसमें वह स्टारलाइनर

अंतरिक्ष विमान से निकलकर बहुत ही गर्मजोशी से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपने सहयोगियों से मिली थीं। नये उत्साह व उमंग के साथ। निश्चित रूप से अंतरिक्ष यात्री कड़े प्रशिक्षण व मजबूत मानसिक तैयारी के बाद ही अंतरिक्ष मिशन में जुड़ते हैं। यूं तो जोखिम सड़क पर पैदल चलने वाले व्यक्ति के जीवन में भी कम नहीं होते हैं, लेकिन अंतरिक्ष यात्री के जीवन के जोखिम हर पल नजर आते हैं। दरअसल, बोइंग का स्टारलाइनर अंतरिक्ष विमान जब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के करीब पहुंचा तो उसमें बड़ी तकनीकी खामियां आ गई थी। उसके वे पांच थ्रस्टर्श बंद हो गए थे, जो यान की दिशा निर्धारित करते हैं। कालांतर में उसकी हीलियम गैस भी खत्म हो गई। फलतः उसे वैकल्पिक ईंधन पर निर्भर होना पड़ा। नासा ने अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने वाली व्यावसायिक उड़ानों के लिये बोइंग व स्पेस एक्स के साथ अरबों डॉलर के करार किये हैं। अब तक नौ मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियानों को अंजाम देने वाले स्पेस एक्स को सुनीता विलियम्स व बैरी बुच विल्मोर को वापस धरती पर लाने का जिम्मा सौंपा गया है। नासा ने अंतरिक्ष अभियान के तमाम जोखिमों का अध्ययन करने के बाद यह फैसला लिया है। बहरहाल, नासा ने फैसला किया है कि सुनीता व विल्मोर को फरवरी, 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में ही रहना पड़ेगा। इसके बाद वे स्पेस-एक्स क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से वापस लौट सकेंगे। जिसमें दो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाएंगे और वापसी में सुनीता और विल्मोर उससे लौटेंगे। इन परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए 58 वर्षीय सुनीता के हौसले बुलंद हैं। अगले छह माह तक का उनका कार्यक्रम निर्धारित हो गया है। इस बीच वह स्टेशन पर वैज्ञानिक कार्यों के अलावा यान की मरम्मत तथा स्पेस वॉक भी करेंगी। इस घटनाक्रम से बोइंग के अभियान को लेकर भी सवाल उठे हैं। कहा जा रहा है कि शुरूआती दौर में हीलियम रिसाव के संकेत मिले थे। विगत में भी बोइंग के कई अंतरिक्ष मिशनों का प्रदर्शन आशा के अनुरूप नहीं रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर बोइंग की प्रतिद्वंद्वी एलन मस्क की स्पेसएक्स ने पिछले कुछ वर्षों में खासी उपलब्धियां हासिल की हैं। चार साल पहले ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचा चुका है और अंतरिक्ष यात्रियों व सामान को ले जाने व लाने का काम करता रहा है। सुनीता विलियम्स पिछले दो माह से धरती के ऊपर अंतरिक्ष में तैर रही हैं। एक प्रायोगिक अभियान के तहत वह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन गई थीं। लेकिन अब जब उनको अगले छह माह अंतरिक्ष में रहना पड़ेगा, तो कहा जा रहा है कि सुनीता क्रिसमस व नया साल भी अंतरिक्ष में ही मनाएंगी। उल्लेखनीय है कि सुनीता विलियम्स की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यह तीसरी यात्रा है। वह एक अनुभवी अंतरिक्ष यात्री हैं जो नौसेना हैलीकॉप्टर पायलट की भूमिका निभाने के बाद नासा के अंतरिक्ष अभियानों से जुड़ी हैं। हाल ही में उन्होंने उत्साहपूर्वक कहा था कि वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में अपने दायित्वों के निर्वहन में खासी व्यस्त हैं। वे अंतरिक्ष स्टेशन में गुरुत्वाकर्षण मुक्त परिवेश में तैरना अच्छा महसूस करती हैं। इसे वे अपने अंतरिक्ष के घर में वापसी मानती हैं। टीम के साथ शोध-अनुसंधान करने का यह अनुभव सुखद है। निश्चित रूप से हर अंतरिक्ष यात्री अपने मिशन में उत्पन्न होनी वाली चुनौती और विकट स्थितियों के लिये मानसिक व शारीरिक रूप से तैयार ही होता है। लेकिन भारहीनता की स्थिति, बाधित नींद, आंखों पर पड़ने वाला अतिरिक्त दबाव, समाज से कटकर नितांत एकांत व भावनाशून्य स्थितियां संवेदनशील मनुष्य को अखरती तो हैं ही। वहीं मांसपेशियों का वजन कम होने से कई तरह की व्यावहारिक दिक्कतें भी आती हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि सुनीता सकुशल घर लौटे।

मोदी सरकार तीसरा कार्यकाल: नदी का रुख क्या बदला सब तैराक हो गए

मोहन सिंह

सत्रहवीं लोकसभा के नतीजे आने के बाद नरेन्द्र मोदी की तीसरी बार सरकार बन गई है, पर विपक्षी दलों को खासकर कांग्रेस को ऐसा लगता है कि मोदी को हराने, झुकाने और सरकार का रुख बदलने का सूत्र उनके हाथ लग गया है। चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, संविधान रक्षा का सवाल हों अथवा हाल ही में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के आरक्षण में क्रीमी लेयर वर्ग को अलग करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मामला हो, ये कुछ ऐसे संवेदनशील मामले हैं, जिन पर किसी भी सरकार को भविष्य में भी रक्षात्मक रुख अख्तियार करना ही पड़ेगा। इसके बरक्स मोदी सरकार का गरीब तबके के किसान, नौजवान और नारी सशक्तिकरण का मुद्दा जैसे कुछ फीका नजर आ रहा है। सवाल है कि जातीय जनगणना में अंतर्निहित जातीय पहचान की राजनीति और आरक्षण का सवाल क्या सचमुच ऐसे सवाल हैं; जिसके आधार पर भविष्य की राजनीतिक दिशा तय होनी है? फिलहाल राजनीतिक परिदृश्य से तो कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। दिख तो यह भी रहा कि धार्मिक पहचान की चमक पहले की अपेक्षा अब फीकी पड़ती जा रही है। ऐसा इसलिए लगता है कि बात जब मिस इंडिया ब्यूटी कांटेस्ट में आरक्षण किए जाने की होने लगी है; तो अगला निशाना भारत में क्रिकेट जैसे मशहूर खेल और ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियाई खेलों में खिलाड़ियों के चयन में आरक्षण का प्रावधान किए जाने की होने लगे, तो इसमें कौन अचरज की बात है? लेकिन जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया उस पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के अलावा सपा की खामोशी का क्या मतलब है? अनुसूचित जाति- जनजाति मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बसपा को जैसे संजीवनी प्रदान कर दिया है।

इधर, एक अरसे बाद बीएसपी कार्यकर्ता नीले झंडे और बैनर तले सड़कों पर नजर आए। आमतौर पर बसपा की राजनीतिक यात्रा में ऐसे अवसर कम ही दिखते हैं। बसपा अब इंडिया गठबन्धन के संविधान रक्षा की शपथ खाने और क्रीमी लेयर के सवाल पर कांग्रेस और यूपी। में सपा को कठघरे खड़ा कर रही है, और भाजपा पर यह आरोप लगा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आड़ में भाजपा सरकार दलित आदिवासियों को मिले संवैधानिक अधिकार को समाप्त करना चाहती है। उत्तर प्रदेश में यह मानकर चलना चाहिए कि बसपा का पुनर्जीवन किसी भी अर्थ में राजग और इंडिया गठबन्धन के लिए बड़ी चुनौती तो पेश कर ही सकता है। पर यह भी उतना ही सच है कि बहन मायावती के राजनीतिक फैसले का पूर्वानुमान लगना कम जोखिम भरा नहीं है। मायावती को कम से कम उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को रिलॉन्च करने और अपने भतीजे आकाश आनन्द को राजनीतिक कमान सौंपना भर देना काफी नहीं होगा। बसपा के कैडर को यह ठीक से समझना और साफ सन्देश देना होगा कि बसपा, भाजपा की बी टीम नहीं है और किसी भी चुनाव में उनके पार्टी के उम्मीदवारों का चयन भाजपा के मनमुताबिक नहीं होगा- जैसा कि इस बार लोकसभा चुनाव और इसके पहले सन- 2022 के उत्तर प्रदेश के राज्य विधान सभा के चुनावों में

हुआ। फिलवक्त भाजपा हर मुद्दे पर जैसे बचाव की मुद्रा में दिखती है। कई दफा तो उसकी स्थिति दयनीय नजर आने लगती है। खासकर लोकसभा में विपक्ष के अक्रामक तेवर के समय। कई बार तो लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री के बजाय गृहमंत्री अमित शाह को मोर्चा संभालना पड़ता है। भाजपा के लोकसभा सदस्य जैसे सदन के नियम- कायदों से तो अंजान दिखते ही हैं, सोलहवीं लोकसभा में जैसे हर मुद्दे पर मोदी सरकार की रक्षा में खड़े होने वाले सांसदों का रुख भी इस बार कुछ बदला-बदला नजर आता हैं। सवाल है कि क्या वे मोदी सरकार के कुछ फैसलों से नाराज हैं ? और इस वजह से विपक्षी दलों के हमलावर रुख के सामने बेबस और लाचार नजर आते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा को अन्दर से ब्रांड मोदी की चमक फीकी पड़ने का अंदेशा होने लगा है, और अब मोदी सरकार विकसित भारत के संकल्प के लिए बड़े फैसले लेने के बजाय छोटे-छोटे फैसले पर यूटर्न लेने लगी है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति का सवाल हो, चाहे ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर पर लेटरल इंट्री का मामला मोदी सरकार के हालिया रुख से तो कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं में भी ऐसा सन्देश जा रहा है। तो क्या यह मान लेना चाहिए कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का आशियाना ऐसे नाजुक साख पर खड़ा है, जिसकी जड़े हिलाने और फिर उखाड़ने का हथियार विपक्षी दलों के हाथ लग गया हैं? अभी बहुत ज्यादा दिन तो नहीं बीते जब मोदी सरकार की हर गारंटी भाजपा को भी भरोसा होता था और देश की जनता भी कुछ फैसलों को छोड़ कर आमतौर मोदी सरकार का साथ देती थी। ऐसा क्या घटित हो गया कि मोदी सरकार इस बार कुछ सहमी-सहमी नजर आ रही है। इस देश में दसवीं लोकसभा के चुनावों के बाद नरसिम्हा राव की अल्पमत की सरकार भी पांच साल तो काट ही ले गई थी। उस सरकार में बड़े आर्थिक सुधार के फैसले लेने पीछे नहीं रही। आम सहमति के आधार वह सरकार चल रही थी और देश डावाडोल आर्थिक हालत का सामना करने के लिए कमोवेश विपक्ष का भी साथ मिल ही जाता था। तब विपक्ष में अटल बिहारी वाजपेई, लालकृष्ण आडवाणी, जसवंत सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चन्द्रशेखर, इंद्रजीत गुप्ता, सोमनाथ चटर्जी और जार्ज फर्नांडीस जैसे कद्दावर नेता मौजूद थे। पर नरसिम्हा राव सरकार ने बड़े और कठोर फैसले लेने में न हिचकिचाई न पीछे हटी। यह अलग बात है कि उस सरकार के मंत्रियों और खुद प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगे। बाबरी मस्जिद का विध्वंस उस सरकार के ढुलमुल रवैए की वजह से हुआ। इन आरोपों के कारण एक अरसे तक कांग्रेस अलग - थलग पड़ गई। आज कांग्रेस हाल हाल तक मजबूत दिख रही मोदी सरकार पर नए जोश और आरक्षण, संविधान की रक्षा, जातीय जनगणना, किसानों के सवाल घेरती है, तो इन राजनीतिक मुद्दों के अलावा कांग्रेस इस रणनीति पर भी काम करती नजर आती हैं कि इस सरकार को हर उस सवाल घेरा जाए और बदनाम किया जाए, जो आज के जवलंत मुद्दे हैं, मसलन महंगाई, बेरोजगारी, दलित-आदिवासी और अल्पसंख्यकों के मामले। फिर यह साबित किया जाए कि यह सरकार चंद पूजीपति घरानों की ही हितैषी है। इस सरकार में जानबूझकर आमजन को उसके वाजिब हक महरूम किया जा रहा है। इस रणनीति को कामयाब करने के लिए अगर झूठ - फरेब का भी सहारा लेना पड़े, तो कोई हर्ज नहीं। क्यों कि उत्तर आधुनिक राजनीति के इस दौर में राजनीति में किसी सरकार अथवा किसी व्यक्ति को असफल साबित करने के लिए इतना ही काफी है कि उस सरकार अथवा व्यक्ति विशेष पर तमाम उलजलूल आरोप लगाकर बदनाम कर दिया जाए, इतना ही किसी सरकार को पराजित करने के लिए काफी है। इस दौर की राजनीति को एक छोटी कहानी के जरिये भी समझा जा सकता है। वह यह कि जब जनता में झूठ सुनने की योग्यता बढ़ जाती है। तब झूठ बोलने के दावे भी बढ़ जाते हैं। आचार्य रजनीश अपने प्रवचनों में अकसर मुल्ला नसरुद्दीन के हवाले से अपनी बात करते है। मुल्ला नसरुद्दीन अपने भतीजे को एक कहानी सुना रहे थे कि एक जंगल में यात्रा के समय उन पर दस शेरों ने एक साथ हमला किया। मैंने पांच शेरों को मार गिराया। उनके भतीजे ने उनके दावे पर आपत्ति जताई। कहा कि कुछ महीने पहले तो आप पांच ही शेरों के हमले किए जाने की बात बता रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन ठहरे एक होशियार आदमी। उन्होंने भतीजे को बताया कि तब तुम्हारी उम्र कुछ कम थी, इस नाते तुममें झूठ सुनने की उतनी योग्यता उस वक्त नहीं थी। अब तू कुछ बड़ा हो गए हो और बड़े झूठ सुनने के योग्य भी हो गए हो। इस लिए मैं कुछ बढ़ाचढ़ा कर झूठे दावे कर सकता हूं। आज कहीं विपक्ष भी कुछ मामले में उतने ही बड़े झूठे दावे तो नहीं कर रहा, और आमजन उनके झूठे झांसे में तो नहीं आ रही हैं।

(यह लेखक के निजी विचार हैं।)

https://t.me/AINewsPaperPdf

पर्यावरण संरक्षण के उपाय

पर्यावरण शब्द का निर्माण दो शब्दो से मिलकर बना है – "परि" और "आवरण" अर्थात वह आवरण जो हमें चारों और से घेरे हुआ है उसे पर्यावरण कहते है। हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वाराराजनैतिकऔर सामाजिक जाग्रति लाने के लिये घोषित किया गया है। सबसे पहला पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को मनाया गया था।पर्यावरण मेजैविक जैसे कि जीवाणु, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधों से लेकर हमसभी इंसान शामिल है। जबकि अजैविक तत्वों में निर्जीव तत्व जैसे पर्वत, चट्टानें नदी आदि शामिल हैं।मनुष्य द्वारा की जाने वाली सारी क्रियाएँ पर्यावरण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं।विज्ञान के क्षेत्र मे असीमित प्रगति का असर पर्यावरण पर पड़ा है। आज मानव विज्ञान के क्षेत्र में नये-नये आविष्कार कर रहा है। लेकिन इन आविष्कारों के कारण वह प्रकृति पर पूर्णतया विजय प्राप्त करना चाहता है। इस कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। धरती पर जनसंख्या वृद्धि का असर भी पर्यावरण पर रहा है।औद्योगीकरण तथा शहरीकरण की तीवृ गतिप्रकृति के हरे भरे क्षेत्रों को समाप्त कर रही है। हमारी प्रथ्वी पर पेड़-पौधे, हवा, पानी है तो हम है।आज इंसान प्रथ्वी पर बहुत ज्यादा अन्याय कर रहा है। दुनिया कंक्रीट की होती जा रही है। पेड़-पौधे काटे जा रहें हैं। जिसके कारणवर्षा कम हो गयी है, सूखा पड़ रहा है। आजधरती पर सबसे बड़ी समस्या जल की है। आज हमें बारिश के पानी को संग्रहित करने की आवश्यकता है। इसके लिये हमें बड़े स्तर पर तालाब, पोखर बनाने की जरुरत है। आजकल वाटर मेंनेजमेंट को लेकर कई संस्थान बहुत सारे कोर्सेस चला रहें हैं। जिसमे वाटर साइंटिस्ट, वाटर मेंनेजर, हाइड्रो जियोलाजिस्ट, बायोलाजिस्ट, वाटर कंजरबेशनिस्ट आदि बनाने के मौके बढ़ गए हैं।आज प्रदूषण के कारण सारी धरती प्रदूषित हो रही है और ऐसा ही रहा तो मानव सभ्यता का अंत निश्चित है। पर्यावरण प्रदूषण के बहुत से दुष्प्रभाव है जो अत्यंत घातक है; जैसे परमाणु विस्फोटो से वायुमंडल का तापमान बढ़ना, ओज़ोन परत का क्षतिज होना, मृदा क्षरण आदि। पर्यावरण सरंक्षण को ध्यान में रखते हुए 1992 मे ब्राज़ील में एक 'पृथ्वी सम्मेलन' आयोजित किया गया जिसमे विश्व के 174 देशों ने हिस्सा लिया।

सस्ती एवं नकारात्मक राजनीति है लेटरल एंट्री का विरोध

आरती कुमारी

भारतीय नौकरशाही संरचना के प्रभावी एवं परिणामकारी प्रदर्शन को निश्चित रूप से लेटरल एंट्री प्रक्रिया के साथ पूरक किया जा सकता है। लेटरल एंट्री नई बाहरी प्रतिभाओं को लाकर, सरकारी अधिकारियों को सार्वजनिक कल्याण के लिए और अधिक काम एवं प्रभावी काम करने के लिए प्रेरित करके नियमित सरकारी अधिकारियों को पूरक कर सकते हैं, लेकिन लेटरल एंट्री की प्रणाली को अधिक समावेशी, पारदर्शी और असरदार बनाने के लिए एक निश्चित नीति के साथ आगे बढ़ने एवं इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सकारात्मक रवैया अपनाना देश विकास के लिये जरूरी प्रतीत होता है। इसके लिये वर्तमान नरेन्द्र मोदी सरकार ने जो कदम उठाया है, उस पर राजनीति करने करने की बजाय उसमें देशहित को सामने रखा जाना चाहिए। वैश्वीकरण ने शासन के काम को अत्यंत जटिल बना दिया है और यही वजह है कि इस क्षेत्र में विशेषज्ञता और कौशल की मांग पहले से बहुत अधिक बढ़ गई है। अर्थव्यवस्था और अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में थिंक-टैंकों की आवश्यकता के मद्देनजर तथा अन्य ऐसे विभागों में जहाँ विशिष्ट प्रकार की सेवाओं की आवश्यकता होती है, लेटरल एंट्री से संयुक्त सचिवों की नियुक्ति की जानी प्रांसगिक एवं उपयोगी कदम है। संघ लोकसेवा आयोग ने केंद्र सरकार के 24 मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव की भूमिकाओं के लिए प्रतिभाशाली, कार्यक्षम और दक्ष भारतीय नागरिकों से 45 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करके सिविल सेवाओं में लेटरल एंट्री (सीधी भर्ती) का स्वागतयोग्य एवं सराहनीय प्रयोग कर रहा है। भले ही इस मुद्दे को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों में विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं। वैसे भी ऐसे राजनीतिक लोगों एवं दलों की आंखों में किरणें आंज दी जाये तो भी वे यथार्थ को नहीं देख सकते। क्योंकि उन्हें उजाले के नाम से एलर्जी है। विपक्षी दलों विशेषतः कांग्रेस ने एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के आरक्षण की उपेक्षा के लिए सिविल सेवाओं में लेटरल एंट्री नीति की आलोचना की है। जबकि भारत में सिविल सेवाओं में लेटरल एंट्री का तात्पर्य सरकार के मध्य और वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर पेशेवरों एवं प्रतिभाशाली कर्मियों की भर्ती से है। जिसमें प्रतिभाशाली एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य विशिष्ट कौशल और विशेषज्ञता लाना है जो पारंपरिक नौकरशाही ढांचे में उतनी प्रभावी प्रतीत नहीं हो रही है। कई संभावित और अच्छे प्रशासक हैं जो अपनी कम उम्र के दौरान सरकार द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भाग नहीं लेते हैं। लेटरल एंट्री उन्हें शासन तंत्र का हिस्सा बनने और राष्ट्र निर्माण में योगदान करने का अवसर प्रदान करता है। नया भारत, सशक्त भारत, विकसित भारत निर्मित करने में इन प्रतिभाओं का उपयोग होना राष्ट्र में एक नयी रोशनी का अवतरण हो सकता है। देखा यह गया है कि जब भी ब्यूरोक्रेसी में सुधार की चर्चा होती है, तो इसका विरोध होने लगता है, जो विरोधाभासी एवं विडम्बनापूर्ण होने के साथ-साथ संकीर्ण राजनीति का द्योतक हैं। कांग्रेस और कुछ अन्य दलों की ओर से जिस तरह लेटरल एंट्री पर आपत्ति जताई जा रही है, वह यही बताती है कि नकारात्मक राजनीति की जा रही है। यह आश्चर्जनक है कि ऐसे देश-विकास एवं राष्ट्र-निर्माण के निर्णयों एवं मुद्दों का विरोध करने की राजनीति की कमान राहुल गांधी अपने हाथ में लेते हुए दिख रहे हैं। कम से कम उन्हें तो इससे बचना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी को यह नहीं भूलना चाहिए कि वित्त सचिव के रूप में मनमोहन सिंह की नियुक्ति लेटरल एंट्री ही थी और वह भी बिना किसी निर्धारित प्रक्रिया के। भारत में लेटरल एंट्री कोई नई बात नहीं है। पहले भी भारत में इसका फायदा उठाया जा चुका है। मुख्य आर्थिक सलाहकार की नियुक्ति लेटरल एंट्री से ही की जाती रही है। पूर्व आर्थिक सलाहकार मोंटेक सिंह अहलूवालिया, आधार की नींव रखने वाले नंदन नीलेकणि जैसी बड़ी हस्तियां इसी के जरिए प्रशासन में शामिल हुईं। यह व्यवस्था तदर्थ आधार पर की गई है, यह संस्थागत नहीं है। लेटरल एंट्री की व्यवस्था सिर्फ भारत में ही है। ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और बेल्जियम जैसे पश्चिमी देशों में पहले से ही सभी क्षेत्रों के योग्य कर्मियों के लिए विशिष्ट सरकारी पदों को खोल दिया है। यह नौकरी के लिए बेहतरीन प्रतिभाओं को आकर्षित करने का एक बेहतर तरीका पाया गया है। स्पष्ट है कि कांग्रेस एक बार फिर अपने शासन के समय सुधार की दिशा में उठाए गए कदम का विरोध कर रही है। इसके विपरीत वर्तमान सरकार एक तय प्रक्रिया के तहत लेटरल एंट्री कर रही है। इसी कारण इसकी जिम्मेदारी संघ लोक सेवा आयोग को दी गई है। कांग्रेस एवं विपक्षी दलों को यह भी पता होना चाहिए कि लेटरल एंट्री के जरिये जो नियुक्तियां की जा रही हैं, वे अस्थायी हैं। ये नियुक्तियां केवल तीन वर्ष के लिए हैं और उनमें अधिकतम दो वर्ष की वृद्धि की जा सकती है। प्रशासन में सुधार की हर पहल को आरक्षण से जोड़ना केवल यही नहीं बताता कि वोट बैंक की सस्ती राजनीति अनियंत्रित हो रही है, बल्कि यह भी इंगित करता है कि आरक्षण को हर मर्ज की दवा मान लिया गया है। यह ठीक नहीं कि होनी को अनहोनी बनाने का प्रयत्न हो। वैसे लेटरल एंट्री राष्ट्रहित का मुद्दा है। जिस पर 2002 की संविधान समीक्षा आयोग ने भी सिफ़ारिश वकालत की। मनमोहन सिंह के समय 2005 की द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर लेटरल एंट्री के लिए एक संस्थागत और पारदर्शी प्रक्रिया की सिफारिश की। स्पष्ट है कि कांग्रेस एक बार फिर अपने शासन के समय सुधार की दिशा में उठाए गए कदम का विरोध कर रही है। नीति आयोग ने अपने तीन-वर्षीय कार्य एजेंडा में लेटरल एंट्री के विचार का समर्थन किया। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि लेटरल एंट्री से विशेष ज्ञान और प्रशासनिक कौशल को शामिल करके शासन में सुधार की क्षमता को विकसित किया जा सकता है। शासन में सचिवों का क्षेत्रीय समूह ने भी लेटरल एंट्री प्रणाली का समर्थन किया। यह तर्क दिया गया कि लेटरल एंट्री प्रासंगिक विशेषज्ञता वाले पेशेवरों को पेश करके सार्वजनिक सेवाओं की प्रभावशीलता को बढ़ाया सकता है और उसे उच्च परिणामकारी बनाया जा सकता है। विरोध के लिये विरोध करने की सोच एवं उद्देश्यहीन, उच्छृंखल, विध्वंसात्मक नीति के द्वारा किसी का भी हित सधता हो, ऐसा प्रतीत नहीं होती। राहुल गांधी और कुछ अन्य विपक्षी नेताओं की ओर से यह जो माहौल बनाया जा रहा है कि लेटरल एंट्री के जरिये विभिन्न मंत्रालयों में विशेषज्ञों की नियुक्तियों से आरक्षित वर्गों के हितों को नुकसान होगा, उसका इसलिए कोई औचित्य नहीं, क्योंकि यह कहीं नहीं कहा गया है कि इन वर्गों के लोग आवेदन नहीं कर सकते। राहुल गांधी किस तरह अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए एक झूठा विमर्श खड़ा रहे हैं, इसका पता इससे भी चलता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के समय स्वयं उन्होंने पूर्व सैन्य अधिकारियों को लेटरल एंट्री के जरिये सिविल सेवाओं में शामिल करने का वादा किया था। लेटरल एंट्री का उद्देश्य है कि जहां कहीं भी कुशल और जानकार लोग हों, उनकी प्रशासन के संचालन में सेवाएं ली जाएं, ताकि सरकारी नीतियों और योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। इसमें कोई दो राय नहीं कि ब्यूरोक्रेसी में सुधार की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा करने से पहले इसे राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करने की भी आवश्यकता है। राजनीतिक रूप से मजबूत और स्थिर नरेंद्र मोदी की सरकार ने कंपनियों के दिवालिया होने से जुड़े विवादों के निपटारे, जीएसटी लागू करने, नोटबंदी और कृषि क्षेत्र जैसे कई अहम सुधार किए हैं। मोदी सरकार ने श्रम कानूनों को भी सरल बनाया है। लेकिन, इन सुधारों को लेकर उन्हें उस वक्त के मुकाबले कड़े विरोध का सामना करना पड़ा है, जब पहले पहल इन सुधारों का प्रस्ताव रखा गया था। लेटरल एंट्री जैसे मुद्दे पर भारी विरोध के बादल मंडरा सकते हैं, इसके लिये भाजपा और साथ ही मोदी सरकार को इसके प्रति सतर्क रहना होगा कि विपक्षी दल उसके खिलाफ झूठा नरेटिव खड़ा कर जनता को गुमराह न करने पाएं।

भाजपा में हिंदुत्व की राह पर चलने की मुख्यमंत्रियों की होड़

अशोक भाटिया , मुंबई

2024 लोकसभा चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी में बहुत कुछ बदला है। लोकसभा चुनावों में शिकस्त मिलने के बाद केंद्र में सरकार तो बन गई पर फैसले लेने में सरकार पहले जैसी कॉन्फिडेंट नहीं दिख रही है। यही कारण है कि लगातार कई मौकों पर सरकार को यू टर्न लेना पड़ा है।पार्टी के अंदर संघर्ष भी शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने मोर्चा खोल रखा है पर अभी शांति है। इस बीच पार्टी में मुख्यमंत्रियों के बीच उग्र हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बनने की होड़ लगी हुई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पिछले दिनों ऐसे फैसले लिए हैं और ऐसे बयान दिए हैं कि योगी आदित्यनाथ भी फीके पड़ जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि दोनों मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व से आगे निकलना चाहते हैं।यही नहीं योगी आदित्यनाथ भी इधर कुछ दिनों से लगातार उग्र हिंदुत्व की राह पर है।इस तरह पर तीन मुख्यमंत्रियों के बीच उग्र हिंदुत्व का झंडाबरदार बनने की होड़ लगी हुई है। हिमंता बिस्वा सरमा के मुसलमानों के खिलाफ लगातार बयान, इसके साथ ही चाइल्ड मैरिज के नाम पर मुस्लिम शादियों में रुकावट डालने तथा जुम्मे की नमाज को लेकर जो फैसले हुए हैं, उसे साफ तौर पर पता चलता है कि हिमंता हिंदुत्व की राह पर तेजी से दौड़ रहे हैं। अब असम विधानसभा मुस्लिम विधायकों को शुक्रवार को नमाज अदा करने के लिए दिए जाने वाले दो घंटे के अवकाश को खत्म करेगी। हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट किया कि 2 घंटे की जुम्मा छुट्टी को खत्म करके, असम विधानसभा ने उत्पादकता को प्राथमिकता दी है और औपनिवेशिक बोझ के एक और अवशेष को हटा दिया है। उन्होंने आगे लिखा कि यह प्रथा 1937 में मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्ला द्वारा शुरू की गई थी। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए स्पीकर बिस्वजीत दैमारी और हमारे विधायकों को मेरा आभार। हिमंता बिस्वा सरमा ने बृहस्पतिवार को विपक्ष पर निशाना साधते हुए दावा किया कि उनमें ''मूलतः राज्य के निवासी हिंदू विधायकों'' को विधानसभा में अपनी बात नहीं रखने देने की प्रवृत्ति विकसित हो गई है। असम भूमि एवं राजस्व विनियमन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 पर चर्चा के दौरान, शर्मा ने अपनी पार्टी के विधायक भुवन पेगू के भाषण को बाधित करने के लिए भी विपक्षी सदस्यों की कड़ी आलोचना की। शर्मा ने पेगू का बचाव करते हुए कहा, मूलतः राज्य के निवासी हिंदू विधायकों को सदन में नहीं बोलने देने की एक नयी प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई है। यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है। कृपया इतने आक्रामक न हों। हमारी जमीन के बाद अब विधानसभा पर कब्जा करने की कोशिश न करें। पेगू तत्कालीन पूर्वी बंगाल से असम में लोगों के कथित प्रवासन और आक्रामकता के बारे में पुराने विधानसभा रिकॉर्ड का उल्लेख करते हुए एक बयान दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा, आप हिंदू-मुस्लिम मुद्दों पर बात करना बंद नहीं कर सकते। ये जीवन की कठोर वास्तविकताएं हैं। हाल ही में राज्य विधानसभा में बोलते हुए, असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि – मैं असम को मियां लोगों की भूमि नहीं बनने दूंगा। हिमंता के लिए हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बनने की धुन आज की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जॉइन करने के बाद से ही उन्होंने हार्डकोर हिंदुत्व की राह पकड़ ली थी। मुस्लिम आबादी को लेकर लगातार बयान,चाइल्ड मैरेज के नाम पर मुस्लिम शादियों में रुकावट डालने की कोशिश या सीएए और एनआरसी की बात रही हो, कांग्रेस से भाजपा में आए हिमंता मुस्लिम समुदाय के खिलाफ इस तरह से आग उगलते हैं जिसका मुकाबला जन्मजात भाजपाई भी नहीं कर सकते। अभी पिछले हफ्ते की ही बात है हिमंता ने निजी स्वामित्व वाले विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेघालय (यूएसटीएम) से पढ़ाई करने वाले छात्रों को असम सरकार की नौकरियों में रोक लगाने की बात कही।एनआईआरएफ के तहत शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में से एक है। यह संस्थान असम के एक बंगाली-मुस्लिम महबुबुल हक के स्वामित्व वाले फाउंडेशन द्वारा संचालित है, जो संस्थान के चांसलर भी हैं। हिमंता का मानना है कि इस विश्वविद्यालय परिसर के निर्माण के लिए वनों और पहाड़ियों की कटाई का ही नतीजा है कि गुवाहाटी को अचानक बाढ़ का सामना करना पड़ा। सरमा का कहना है ये सब असम के खिलाफ बाढ़ जिहाद के कारण हुआ है। सरमा ने इससे पहले बंगाली-मुस्लिम किसानों पर उर्वरक जिहाद का भी आरोप लगाया था। कहा था कि सब्जियां उगाने में उर्वरक के अनियंत्रित उपयोग के कारण लोगों में बीमारियां फैल रही हैं। उन्होंने राज्य में मुसलमानों पर भूमि जिहाद का आरोप लगाते हुए उन्हें जमीन की बिक्री पर अंकुश लगाने के फैसले की भी घोषणा की और कहा है कि सरकार लव जिहाद के लिए आजीवन कारावास की सजा वाला एक कानून लाएगी।यही सब कारण है कि असम में उनकी लोकप्रियता में लगातार इजाफा हो रहा है। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के फायरब्रांड लीडर रहे हैं। पर मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके तेवरों में थोड़ी नरमी आ गई थी। पर पिछले महीने से ही अचानक उन्होंने अपना पुराना चोला फिर से ओढ लिया है।वो फिर से उग्र हिंदुत्व की अपनी जानी पहचानी शैली में वापस आ गए हैं।हाल ही में बांग्लादेश स्थिति को लेकर उन्होंने जब-जब मुंह खोला , आग ही उगला है। अभी 2 दिन पहले ही आगरा में उन्होंने हिंदुओं से सावधान रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर बंटेंगे तो कटेंगे।बांग्लादेश वाली गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे । योगी के कट्टर हिंदुत्व का यह रूप पिछले महीने से ही दिखने लगा था।जुलाई महीने के अंत में, राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया, जिससे उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 को और अधिक सख्त बना दिया गया। यूपी विधानसभा ने 30 जुलाई को संशोधन विधेयक पारित किया, जिसमें लव जिहाद को खत्म करने के अपने इरादे को फिर से रेखांकित किया गया।कांवड़ यात्रा मार्ग पर सड़क किनारे विक्रेताओं और दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठानों के बाहर अपना नाम लिखने के आदेश पर पूरे देश में उनके समर्थन और विरोध हुआ है।अयोध्या रेप केस में आरोपी के मुसलमान होने पर काफी हिंदू-मुसलमान यूपी में हुआ है। योगी ने इस मामले को खुद संज्ञान लेते हुए आरोपी का घर और प्रतिष्ठानों पर बुलडोजर कार्रवाई का एक्शन लिया।राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सफलता को देखते हुए अन्य मुख्यमंत्री जब उनकी राह के राही बनने की कोशिश कर रहे हैं तो योगी भला क्यों पीछे हटे। योगी आदित्यनाथ को भी हिंदू हृदय सम्राट की पदवी बरकरार रखनी है इसलिए उन्हें भी अपने पुराने रूप में आना ही फायदेमंद दिख रहा है। बात करें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की तो जन्माष्टमी के दिन एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि भारत में जो रहना चाहते हैं, उन्हें हिंदू , भगवान राम और कृष्ण की जय कहना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस देश के नागरिक अपने-अपने धर्मों के पालन के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन वह देशभक्त रहें। इसके साथ यह भी कह गए कि खाता कहीं और का बजाता कहीं और का यह नहीं चलेगा।हालांकि मोहन यादव ने यह भी कहा कि देश हिंदू और मुसलमानों के बीच अंतर नहीं करता है, लेकिन उसे ऐसे लोगों की जरूरत है जो ईश्वर, उसकी रचना, ब्रह्मांड को समझें। उन्होंने कहा कि रहीम और रसखान का जन्म यहीं हुआ था। बीते दिनों छतरपुर में पुलिस पर पत्थरबाजी के आरोपियों के करोड़ों के घर सरकार ने तोड़ दिए। इस घर में रखी करोड़ों की गाड़ियों को भी बुलडोज कर दिया गया। पत्थरबाजी का आरोपी चूंकि मुसलमान था इसलिए कुछ लोगों को इस कार्रवाई में धार्मिक एंगल भी दिखा। सिर्फ छतरपुर ही नहीं, इंदौर में भी एक अतिक्रमणकारी ने प्रशासन पर गोली चलवाई थी, उसकी कोठी को भी प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। इसका सीधा मतलब है कि कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।मोहन यादव ने ने मध्यप्रदेश के सीएम पद की शपथ लेने के साथ ही अपने इरादे जता दिए थे। उनके शुरूआती एक्शन में ही योगी की छाप दिखी थी।शपथ लेते ही उन्होंने खुले में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना और लाउडस्पीकर पर बैन का फैसला लिया था। उसके बाद लगातार उन्होंने ऐसे फैसले लिए जो उन्हें हिंदू पोस्टर बॉय बनने की उनकी इच्छाशक्ति को दिखाता है। इतना ही नहीं मोहन यादव ने एमपी में भगवान राम और कृष्ण से जुड़े तीर्थ स्थलों की तरह विकसित करने का काम करने का बीड़ा उठाया है।उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के 7 मंदिरों को जोड़े जाने का एक्शन प्लान बनाया जा रहा है। संघ के विचारकों और प्रमुख पदाधिकारियों की किताबें मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ाने का भी फैसला लिया गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों की धार्मिक शिक्षा देने पर रोक लगाया जा रहा है। एक और बात यह है कि भाजपा को यह बात समझ में आ गई है कि मुस्लिम समाज का उन्हें वोट बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है।हिंदुत्व का ध्रुवीकरण होने पर विपक्ष के सारे तीरों से निपटने की भाजपा को ताकत मिल जाएगी।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

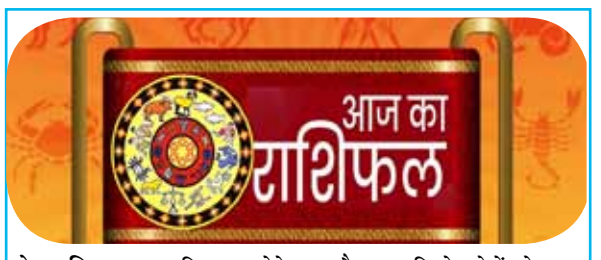

मेष राशि–आज का दिन लाभ देने वाला है। इस राशि के लोगों को आज धन लाभ होने से परिवार में सुख-शांति का माहौल बना रहेगा। इस राशि वाली महिलाओं के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है। उन्हें अपने ननिहाल या मायके की तरफ से खुशखबरी मिल सकते हैं। आज आपके विचारों को ऑफिस में सीनीयर्स की तरफ से पॉजीटिव रिसपॉन्स मिलेगा। इस राशि के लोग आज भविष्य के लिए कोई खास निर्णय ले सकते हैं।

वृष राशि–आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। आज कार्यस्थल की व्यवस्था में कुछ परिवर्तन लाने की भी जरूरत है। टूर एंड ट्रेवल्स तथा मीडिया संबंधी व्यवसाय में सुधार आएगा। आज कार्यभार अधिक होने की वजह से ओवरटाइम करना पड़ेगा। पति-पत्नी का आपसी सहयोगात्मक व्यवहार आपसी नज़दीकियां बढ़ाएगा। आज अपने मनोबल को मजबूत बनाने के लिए मेडिटेशन का सहारा लेंगे।

मिथुन राशि–आज का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहने वाला है। आज बिजनेस में बहुत संजीदगी और गंभीरता से काम करने की जरूरत है। व्यापार बढ़ाने की योजनाओं पर एक बार फिर से विचार करेंगे। कोई भी छोटा बड़ा फैसला लेते समय किसी एक्सपर्ट की सलाह से आपको मुनाफा होगा। आज पारिवारिक माहौल व्यवस्थित रखने में आपकी मदद कारगर साबित होगी, आज किसी को दिए पैसे की वापसी भी हो सकती है।

कर्क राशि–लेखकों के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज इन्हें अपने लेखन शैली से जीवन में सफलता मिलने के अवसर प्राप्त होंगे। इस राशि के लोगों को आज अपने परिवार के किसी सदस्यों से नये वस्त्रों की मिल सकते हैं। आज का दिन आपके अनुकूल रहने वाला है, साथ ही जो भी काम करना चाहेंगे वो पूरे हो जाएंगे। किसी भी कामों को पूरा करने के लिए आज आपको अपने मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा।

सिंह राशि–आज व्यस्तता के साथ गुजरेगा फिर भी आपको यह सोचकर अच्छा लगेगा कि आज आपने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है। इसके साथ ही आप घर वापस आकर अगले दिन के लिए टारगेट सेट करेंगे साथ ही आप अगर घरों में कोई परिवर्तन संबंधी कोई निर्णय लेना चाहते है तो आपके लिए अच्छा दिन है। बिजनेसमैन के लिए भी आज का दिन शुभ है। इस राशि के लोगों का झुकाव आज अपने परिवारजनों के प्रति होगा।

कन्या राशि–आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। घर में सुखद और अच्छा माहौल रहेगा, शाम का समय बड़े बुजुर्गों के साथ बिताएंगे ।यदि किसी कारण से कुछ खोने का डर है तो आप निश्चिन्त हो जाएँ, ऐसा कुछ नही होने वाला क्युकी आज आपका दिन आपके फेवर में है। आज जीवनसाथी का आपके प्रति पूर्ण सहयोग रहेगा। लवमेट के साथ घूमने-फिरने का भी प्रोग्राम बनेगा।

तुला राशि–आज आपका दिन रोज से अच्छा रहेगा।आप अपने कामकाजी जीवन से थोड़ा ब्रेक लेकर जीवन साथी के साथ किसी ट्रिप पर जाने का प्लान बनाएंगे। यह आपके अपने रिश्ते को संजोए रखने के लिए आवश्यक कदम होगा। पारिवारिक जीवन खुशहाल रखने के लिए कम्युनिकेशन गैप न होनें दें। सबसे बातचीत अवश्य करें। व्यापारिक जीवन में मनचाहा परिणाम मिलेगा व्यवसाय के संबंध में आपके लिए साझेदारी लाभकारी सिद्ध होगी।

वृश्चिक राशि–आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। काम करने के तरीकों में बदलाव करेंगे और व्यवस्थित रहेंगे तो इससे आपके काम जल्दी निपटेंगे। आज आपको कोई नयी जानकारी मिलेगी आपके लिए यह जानकारी भविष्य के लिये फायदेमंद साबित होगी। आज आलस्य व सुस्ती छोड़कर काम में मन लगाने की जरूरत है, आज आप मार्किट से कोई मनपसंद सामान खरीदेंगे। आज लम्बी यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है।

धनु राशि–आज का दिन आपके लिए खुशहाल रहने वाला है। आज दोस्तों और संबंधियों से पूरी मदद मिलेगी। खास काम के सिलसिले में बातचीत भी होगा। किसी महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले घर के सदस्यों की सलाह लेना आपके लिए बहुत ही लाभदायक भी रहेगा। आज कोई सुखद समाचार मिलने से भावनात्मक रूप से आप अपने आपको बढ़िया महसूस करेंगे। आज कुछ समय एकांत अथवा आध्यात्मिक स्थल पर बिताएंगे। आज किसी करीबी व्यक्ति से काम संबंधी नाराजगी दूर होगी।

मकर राशि–आज दिन की शुरूआत अच्छी होगी। इससे परिवार में सामांजस्य बना रहेगा। छात्रों को आज कोई शुभ सूचना मिलने वाली है। जिससे करियर में बदलाव आयेगा। पुराने समय को भूलकर आगे बढ़ेंगे तो सफल हो जाएंगे। आपकी सोच में बदलाव आयेगा । यह बदलाव आपके लिए शुभ फल देने वाला होगा। इस राशि की महिलाओं के लिये आज का दिन अच्छा रहने वाला है।

कुंभ राशि–आज का दिन आपके लिए बहुत सामान्य रहेगा। आज पैसों से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे। आज पारिवारिक तथा व्यवसायिक गतिविधियों में संतुलन बना कर रखने से उचित व्यवस्था बनी रहेगी। स्टूडेंट को अपने अध्ययन और करियर में एकाग्रता रखने से उचित परिणाम मिलेंगे। बच्चों की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए कुछ समय उनके साथ जरूर बिताएं।

मीन राशि–आज का दिन आपको सफलता दिलाने वाला रहेगा। आज बच्चों का परिणाम देखकर मन में तसल्ली रहेगी। आज अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए ध्यान केंद्रित करेंगे। आज आपको यह ध्यान रखन होगा कि नकारात्मक विचार आपके मनोबल को कमजोर कर सकते हैं। आपकी मेहनत से आय में इजाफा होगा ।

शब्द पहेली - 8237

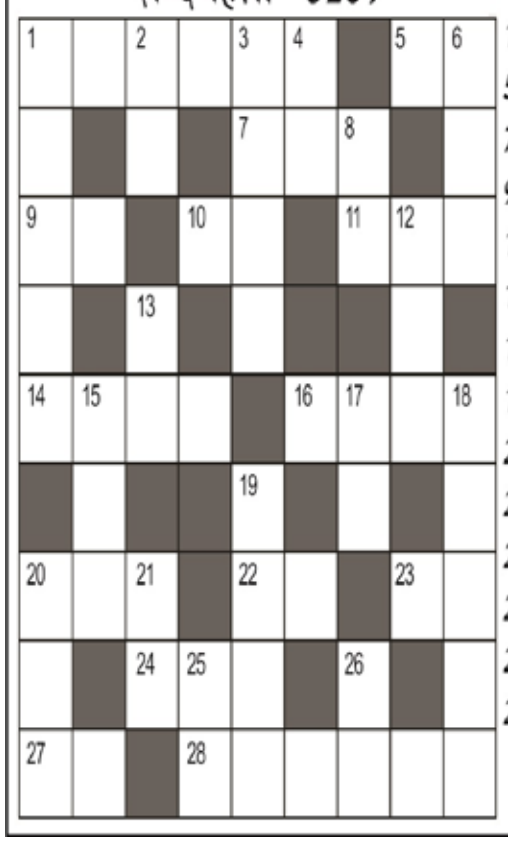

बाएँ से दाएँ

1. परिचय, जानना-2,4
5. वायु रोग-2
7. उत्साह, जिज्ञासा
9. कांटा, शूल
10. पिता, साधू-2
11. योद्धा जाति, राजपूत-3
14. थकान-4
16. मिसाल के तौर पर-4
20. ध्वजा, पताका-3
22. सीमा, बार्डर-2
23. बुरी आदत-2
24. समस्या, मुद्दा-3
27. जोर, दम, ताकत-2
28. दिखावटीपन, आडंबर, -3,3

ऊपर से नीचे

1. सीतापति, रामचंद्र-5
2. लम्हा, क्षण-2
3. धोखेबाज, दगाबाज-4
4. नलका, टोंटी-2
6. पुत्र, लड़का-3
8. कमरा, रूम-2
12. तीनों काल-3
13. पार्थिव शरीर, लाश-2
15. कजरा, अंजन-3
17. सच्चाई, सच-2
18. सेंधमार-5
19. पुचकारना, हाथ फेरना-4
20. धोखा, दगा-3
21. जरा, थोड़ा-2
25. सभी, संपूर्ण-2
26. राजेश खन्ना व मुमताज की बेहतरीन फिल्म-2

शब्द पहेली -8236 का हल

Jagrutidaur.com, Bangalore

सूडोकु नवताल- 7175

मध्यम

4			9		6	1		8
6	8							
	1	7	3	8		4		
3	4		6		7			9
5		1	8			2		7
2			5		1		8	4
		3		7	5	8	6	
							9	5
7		6	2		8			1

Jagrutidaur.com, Bangalore

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -7174 का हल

2	9	8	3	5	6	1	7	4
4	5	3	2	1	7	9	8	6
7	1	6	4	8	9	2	5	3
8	2	5	6	9	1	3	4	7
3	6	4	7	2	5	8	1	9
1	7	9	8	3	4	5	6	2
5	4	1	9	7	2	6	3	8
6	3	2	1	4	8	7	9	5
9	8	7	5	6	3	4	2	1

अब निर्णायक कदम जरूरी

इस्लामाबादमें इसी वर्ष अक्तूबरमें होनेवाले शंघाई सहयोग संघटन (एससीओ) की शिखर बैठकमें प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीको पाकिस्तानसे मिले आमंत्रणके बाद इस बातपर चर्चा होना स्वाभाविक है कि क्या दोनों देशोंके बीच खराब हो चुके रिश्तोंको फिरसे सुधारनेकी कोशिश हो सकती है। ऐसेमें परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकरका दो-टूक यह कहना अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तानके साथ निर्बाध बातचीतका युग अब खत्म हो चुका है। एस. जयशंकरके इस वक्तव्यके निहितार्थको समझनेकी जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तानमें आजादीके बाद स्वतंत्र रूपसे न कभी लोकतांत्रिक सत्ता थी और न है। कहनेको वहां जनताकी सरकार है लेकिन सत्ताकी ड्राइविंग सीटपर सेना, वहांकी खुफिया एजेंसी आईएसआई और कट्टरपंथी आतंकी संघटनोंकी तिकड़ी शक्ति काबिज है। ऐसी स्थितिमें सम्बन्ध सुधारनेकी वार्ता हो भी तो किससे। यदि किसी सरकारसे सार्थक समझौता होता भी है तो वह कितने दिनतक स्थिर रहेगी, कहा नहीं जा सकता है। पहले भी दोनों देशोंके बीच विवाद और तनाव कम करनेके लिए शिमला समझौते समेत अन्य कई अहम समझौते हो चुके हैं जो आज बेमानी है। किसी भी दो देशोंके बीच द्विपक्षीय समझौता मात्र औपचारिक नहीं होते, बल्कि उसकी एक अहमियत होती है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं समझता है। ऐसी स्थितिमें परराष्ट्रमंत्रीका यह कहना उचित और स्वागतयोग्य है कि अब पाकिस्तानके हर सकारात्मक या नकारात्मक कदमका जवाब उसीकी भाषामें दिया जायगा। भारत अपने इस पड़ोसी देशके साथ रिश्ते वैसे ही आगे बढ़ायेगा जैसे हालात होंगे। दुनियाके हर देशके लिए पड़ोसी एक समस्या हैं। गौर किया जाय तो हर देशकी उसके पड़ोसीके साथ कुछ न कुछ समस्याएं जरूर हैं, जिन्हें सौहार्दपूर्ण तरीकेसे हल किया जा सकता है। पड़ोसियोंके साथ अपने रिश्तोंको जयशंकरने बेबाक तरीकेसे रखते हुए कहा कि भारतकी वजहसे ही आज श्रीलंका हालातसे उबर पाया है। मालदीवने हमारे प्रयासको पहचाना है और मानता है कि भारतसे रिश्ता उनके लिए ताकत जैसा है। बंगलादेशकी आजदीके बादसे ही भारतके रिश्ते उतार-चढ़ाववाले रहे हैं। हमें बंगलादेशके साथ आपसी हितोंका आधार तलाशना होगा। भारत हमेशासे ही अपने पड़ोसी देशोंके साथ मधुर सम्बन्धोंका पक्षधर रहा है और इसमें सफलता भी मिली है लेकिन यह दुखद है कि पाकिस्तानके रिश्तोंपर जमी बर्फ अबतक नहीं पिघल सकी। इसके लिए पाकिस्तान स्वयं जिम्मेदार है। अब समय आ गया है कि उसके विरुद्ध निर्णायक कदम उठाया जाय।

अस्पतालोंकी सुरक्षा

कोलकाताके आरजीकर अस्पताल काण्डके बादसे देशभरमें महिला चिकित्सकोंकी सुरक्षाका विषय चर्चामें है। अस्पतालकी घटना इतनी वीभत्स थी कि देशभरके रेजिडेण्ट डाक्टर हड़तालपर चले गये। ऐसेमें सर्वोच्च न्यायालयने स्वत: संज्ञान लेकर कड़ी टिप्पणी करते हुए केन्द्र सरकारको चिकित्सकोंकी सुरक्षाके लिए कड़े कदम उठानेको कहा है। सर्वोच्च न्यायालयके आदेशके बाद केन्द्र सरकारने अस्पतालोंमें डाक्टरोंकी सुरक्षाके लिए राज्योंको अलग-अलग कदम उठानेको कहा है, जिनमें अस्पताल परिसरोंमें रात्रिमें गश्त और अहम जगहोंतक सिर्फ कुछ जरूरी लोगोंको जानेकी अनुमति देना शामिल है। देशके विभिन्न राज्योंमें अस्पतालों, मेडिकल कालेजोंकी सुरक्षा सख्त करनेके लिए नयी गाइडलाइन जारी की गयी है। उत्तर प्रदेश सरकारने भी अस्पतालोंमें सुरक्षा बढ़ाये जानेको लेकर कड़े निर्देश दिये है। अब अस्पताल परिसरमें बिना प्रवेश-पत्रके तीमारदार भी रात्रिमें अस्पतालमें नहीं रुक सकेंगे। प्रवेश-पत्र नीतिका सख्तीसे पालन कराया जायगा। किसी डाक्टर या चिकित्साकर्मीके साथ हिंसा होनेपर संस्थागत एफआईआर दर्ज करायी जायेगी। महिला चिकित्सकोंकी सुरक्षाके लिए रातमें दूसरे वार्ड जानेपर उन्हें गार्ड मिलेगा। खुद इंडियन मेडिकल असोसियेशनके किये एक सर्वेकी माने तो रातकी शिफ्टमें उनके एक-तिहाई डाक्टर जिनमें ज्यादातर महिला डाक्टर हैं, काफी असुरक्षित महसूस करती हैं। कुछ डाक्टरोंने यह भी कहा कि उन्हें आत्मरक्षार्थ हथियार रखनेकी जरूरत महसूस होती है। रात्रिकालीन सेवाके मद्देनजर मूलभूत बुनियादी सुविधाओंका अभाव है। यदि कानून व्यवस्थाका खौफ होता और अस्पताल प्रशासन मुस्तैद रहता तो इस तरहकी घटना न होती। कोलकाताकी घटनाका यही सन्देश है कि हमें अपने-अपने आसपासके माहौल और महिलाओंके कार्यस्थलको ऐसा बनाना होगा कि वह सुरक्षित और समावेशी हो। सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने तथा कानूनोंकी जानकारी देनेके साथ महिलाओंको उच्च पदोंपर लाना होगा, जहां पीड़ितोंकी तत्काल सुनवाई और कठोर काररवाई हो। सुरक्षा नियमोंका सख्तीसे पालन सुनिश्चित होना चाहिए।

लोक संवाद

उद्देश्यपरक छड़ी

महोदय,-जब न्यूयार्कमें बर्फबारी हो रही थी तो मैंने बाहर एक छोटी लड़कीको देखा। वह मेरे सामने फुटपाथपर चल रही थी और मैं दंग रह गया! वह ऐसी चालसे चल रही थी कि बाकी सभी लोग पीछे रह गये, क्योंकि स्थिर कदमोंके साथ, वह बाकी लोगोंसे आगे निकल गयी। लेकिन जो चीज उसे आगे बढ़नेमें मदद कर रही थी, वह थी एक छड़ी। उन आधुनिक छड़ियोंमेंसे एक जिसका उपयोग आप ट्रैकिंग या चढ़ाईके लिए करते हैं। वह एक उद्देश्यके साथ चल रही थी, अच्छी तरहसे सोची-समझी छड़ीने उसकी मदद की। मुझे यकीन नहीं है कि उसे इसकी जरूरत थी। जैसे कि लंगड़ानेका उसमें कोई संकेत नहीं था, हालांकि वह किसी चोटसे गुजरी हो सकती थी, जिसमें उसे सहारा चाहिए था लेकिन एक निश्चित लक्ष्य और दृढ़ संकल्पके साथ वह आगे बढ़ गयी और उसने दूसरोंको बहुत पीछे छोड़ दिया। जब मैंने उसे चलते हुए देखा तो मुझे कई लोगोंके बारेमें याद आया, जिनके लिए चलनेकी छड़ीकी वकालत की जाती है। मां छड़ीका उपयोग करो, ताकि तुम फिरसे न गिरो! लेकिन वास्तवमें वे छड़ीको अस्वीकार कर देते हैं। लेकिन यह केवल बूढ़े और कमजोर लोगोंके बारेमें नहीं है, हममेंसे कई लोग हैं जो तब भी समर्थनसे इनकार करते हैं जब हमें छड़ीकी आवश्यकता होती है। एक टीम बनाओ और उन्हें आपकी मदद करने दो! आपका बॉस कहता है, मुझे अकेले काम करना पसंद है। कुछ साल पहले मैंने एक वॉकिंग स्टिक प्रोजेक्ट शुरू किया था और उन लोगोंके लिए वॉकिंग स्टिक खरीदनेके लिए पैसे इकट्ठे किये थे जो झुग्गी-झोंपड़ियोंमें रहने वाले लोगोंके घरोंमें गरीब और बूढ़े थे। एक सामाजिक कार्यकर्त्ताने मुझे बताया था कि ये बूढ़े लोग दिनभर अपनी पीठके बल बैठे रहते हैं क्योंकि उनके पास चलनेके लिए कोई सहारा नहीं होता। हमने उस दिन बहुत-सी छड़ियां बांटीं और मुझे यकीन था कि अगले दिन मैं उनमेंसे बहुतोंको पार्कमें देखूंगा, जो अपनी नयी-नयी मिली आजादीका आनंद ले रहे होंगे। बहुतसे लोग नहीं आये क्योंकि वे छड़ीके साथ नहीं दिखना चाहते थे। मैंने लड़कीको फिरसे देखा, जो आगे बढ़ रही थी। हम कितने मूर्ख हैं कि अपनी छड़ियोंका उपयोग नहीं करते। हमें मुफ्त सहारा दिया गया है! सहारा, जैसे हमारे बच्चों या दोस्तोंसे मदद या इससे भी महत्वपूर्ण बात, प्रार्थना नामक एक दिव्य सहारा। **-डी. राबर्ट, वाया इमेल।**

महामहिम राष्ट्रपति मुर्मूका दर्द

आमतौरपर माना जाता है कि भारतके राष्ट्रपतिको सार्वजनिक रूपसे कुछ भी बोलनेका अधिकार नहीं है। यह भी कहा जाता है कि जो केन्द्रीय कैबिनेट पारित करके उसके पास भेज देती है उसपर वह हस्ताक्षर कर देता है। भारतका राष्ट्रपति एक तरहसे रबर स्टैम्प होता है। परन्तु इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूने इतिहास रच दिया।

❑ **विजयनारायण**

देशमें स्वतंत्रतासेनानी कांग्रेसके पूर्व अध्यक्ष और मान्यताओंपर विश्वास करनेवाले डा. राजेन्द्र प्रसाद, विश्वस्तरके चिन्तक और भारतीय दर्शनके प्रवक्ता डा. एस. राधाकृष्णन और उनके बाद डा. जाकिर हुसैन, डा. वी.वी. गिरी और डा. वेंकट राघवन जैसे शक्तिशाली व्यक्तित्ववाले लोग राष्ट्रपति रहे हैं। लेकिन आदिवासी समाजसे आनेवाली डा. द्रौपदी मुर्मूने इन सभी मान्यताओंको भी नहीं ऐसी सभी सीमाओंको तोड़ दिया है और उन्होंने सीधे देशकी आम जनताकी भावनाओंसे अपना रिश्ता जोड़ लिया है। करीब छह महीना पूर्व राष्ट्रपतिने देशकी जेलोंमें बिना किसी मुकदमे और जांच पड़तालके १० से १५ सालसे सड़ रहे गरीब बच्चों और असहायोंका सवाल उठाया था। देशके सुप्रीम कोर्टने उनकी इस बातपर तत्काल संज्ञान लिया और केन्द्र सरकार कभी राज्य सरकारोंको नोटिस जारी कर दस साल या उससे अधिक समयसे बिना मुकदमा चलाये और बिना सजायाफ्ता जैसे व्यक्तिका जीवन काट रहे लोगोंके बारेमें पूरी जानकारी मांगी। लेकिन विडम्बना यह देखिये कि देशकी केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारोंने इसपर पूरी चुप्पी साध ली और जेलोंमें बंद ऐसे असहाय लोगों विशेषकर बच्चोंकी कोई भी जानकारी लेने या जानकारी जुटानेकी कोई कोशिश नहीं की। यह भारतीय राजनीतिमें विशेषकर सरकारोंमें और राजनीतिक दलोंमें संवेदनहीनताकी पराकाष्ठाको जाहिर करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूने एक बार फिर देशमें इस संवेदनहीनताके सन्नाटेको तोड़ा है। उन्होंने प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डियाको भेजे अपने एक लेखमें देशके विभिन्न भागोंमें महिलाओंके साथ हो रहे उत्पीड़न, उनके साथ बलात्कार और सरकारों और प्रशासनकी उपेक्षा और लापरवाहीको उजागर किया है। उन्होंने अपना दुख भी बहुत गम्भीरताके साथ व्यक्त किया है। राष्ट्रपतिने एक ओर जहां बंगालमें एक जूनियर महिला डाक्टरके साथ बलात्कारके बाद हत्यासे उत्पन्न जनाक्रोशका जिक्र किया है, वहीं दूसरी ओर देशके अन्य भागोंमें महाराष्ट्रा, असम और अन्य राज्योंमें ऐसी घटनाओंकी रोज-रोज हो रही पुनरावृत्तिपर अपनी चिन्ता व्यक्त की है। राष्ट्रपतिका यह लेख या उनका यह वक्तव्य बहुत ही सन्तुलित है। उन्होंने न किसी एक सरकारको कोसा है, बल्कि उन्होंने केन्द्रके साथ सभी राज्य सरकारोंकी उपेक्षापूर्ण रवैयेपर चिन्ता व्यक्त की है। उन्होंने महाराष्ट्रके ठाणेमें नाबालिग बच्चियोंके साथ ऐसी घटनाओंकी पुनरावृत्ति और पुलिसकी रिपोर्ट लिखनेमें लापरवाहीपर भी चिन्ता व्यक्त की है। कोलकाताके एक अस्पतालकी महिला जूनियर डाक्टरके साथ हुए बलात्कारकी घटनाके बादसे जनतामें जो उबाल आया है वह थमनेका नाम नहीं ले रहा। ठीक इसी तरह ठाणे जिलेके लोगोंको कई दिनोंतक रेलवे लाइनपर बैठना पड़ा, उनपर पुलिसने लाठियां भांजी, लोगोंको गिरफ्तार किया और जब यह मामला राष्ट्रीय स्तरपर सुर्खियोंमें आया तब जाकर गिरफ्तारियां की गयीं। महामहिमने एक गम्भीर सवाल देशकी केन्द्रीय और राज्य सरकारोंके अलावा जनताके सामने भी उठाया है कि क्या ऐसी घटनाएं थमेगी नहीं? उन्होंने यह भी पूछा है कि क्या यह घटना आखिरी होगी। ऐसा लगता है राष्ट्रपतिने महिलाओंके दर्दको अच्छी तरह शायद इसलिए समझा है कि वह एक महिला हैं। यह भी कहा जा सकता है उनकी जगह कोई पुरुष राष्ट्रपति होता तो शायद इतनी गहरी संवेदनाके साथ इन बातोंको नहीं रखता। महामहिमने छह महीनेके अन्दर दो घटनाओंको जिस तरहसे उजागर किया है और बड़ी हिम्मतके साथ देशके सामने रखा है वह उनको देशकी महान महिलाओंकी श्रेणीमें ही नहीं, महान लोगोंकी श्रेणीमें स्थापित करता है। अब एक बार फिर देखनेकी बात यह है कि महामहिमकी इन बातोंका सरकारें संज्ञान लेती हैं या नहीं। महामहिमने इस सवालोंको उठानेके साथ विभिन्न घटनाओंपर अपनी राय रखनेके अलावा यह भी सवाल देशसे पूछा है कि आखिर ऐसी प्रवृत्ति हमारे समाजमें आयी कैसे। साथ ही उन्होंने यह भी पूछा है कि ऐसी प्रवृत्तिको बदलनेके लिए क्या हम कुछ करनेको तैयार नहीं हैं। यहां यह देखनेकी बात है कि २०१२ में जब नयी दिल्लीमें निर्भया काण्ड हुआ था तो सारे देशने सड़कोंपर प्रदर्शन हुआ लेकिन हमारे समाजमें यह बलात्कारी प्रवृत्ति कहांसे आयी और यह क्यों बढ़ती जा रही है इसपर न तो बहस हुई, न कोई खोजबीन हुई और न ही इस प्रवृत्तिको समाप्त करनेके लिए कोई काररवाईपर या कोई वैचारिक अभियान चलानेपर किसी स्तरपर कोई निर्णय हुआ। यह सच है कि समाजमें जो गिरावट आयी है वह पिछले ६०-७० वर्षोंकी देन है। पहले भारतीय सिनेमामें अश्लील दृश्य नहीं दिखाये जाते थे फिर अश्लील दृश्योंका प्रचलन बढ़ा। उसके बाद टीवी सीरियल आ गया और अब तो मोबाइलका दौर है। अब आम आदमीके सामने वह सब परोसा जा रहा है जिसे हम कानूनी रूपसे अश्लील कहते हैं और जिसपर सार्वजनिक रूपसे भी और परिवारके अन्दर भी बहस करनेके आदी नहीं हैं। जो कुछ भी अश्लील है वह सब बच्चोंतक पहुंच रहा है। एक बहस पिछले ३०-४० वर्षोंसे यह भी चल रही है कि महिलाओंको वस्तु न बनायें। लेकिन यह भी आज सच है कि महिला वस्तु बन चुकी है। महिलाएं जिस तरह वस्तु बन रही हैं। महिलाओंका उपयोग जिस तरह विज्ञापनोंमें किया जा रहा है उसपर न किसी स्तरपर कोई काररवाई होती है, न ही उसका प्रतिरोध ही होता है। यह स्थिति कितनी चिन्ताजनक है इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। विडम्बना देखिये जो महिला बलात्कार और हत्या जैसी घटनाकी शिकार हो जाती है उसको निर्भया नाम दे दिया जाता है। इस नामका आखिर मतलब क्या है। जिस समाजमें महिलाओं और लड़कियोंको निर्भय रहनेका अहसास ही नहीं हो पा रहा है उनके लिए ऐसे शब्दोंका इस्तेमाल क्या अर्थ रखता है। २०१२ की निर्भया काण्डके बाद कानून बदला गया और बलात्कारकी सजाके अलावा मृत्युदण्डकी सजाका भी प्रावधान किया गया। कहीं-कहीं ऐसा भी हुआ कि ऐसे काण्डोंसे सम्बन्धित अभियुक्तोंको एक माहके अन्दर सजा दी गयी और ऐसी खबरोंको खूब उछाला गया। लेकिन जो मूल बात रह गयी ऐसी घटनाओंकी पुनरावृत्ति रोकनेकी और ऐसी प्रवृत्तियोंको समाप्त करनेकी उस दिशामें भारतीय समाज और सरकारें भी शायद एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी हैं। जहां देशमें कोलकाता, ठाणे और असमकी घटनाओंकी चर्चा हो रही है वहीं केरलके फूल उद्योगने महिलाओंके साथ उत्पीड़नकी घटनाओंका एक जांच रिपोर्टमें बड़ा खुलासा हुआ है। इस जांच रिपोर्टमें पाया गया है कि मलयालम फिल्म उद्योगमें काम करनेवाली महिलाओं विशेषकर लड़कियोंका यौन शोषण होता रहा है। यानी अबतक महिलाओंने जितनी भी शिकायतें की हैं वह हर शिकायत जायज है। अब देखनेकी बात यह है कि जो भी फिल्म निर्माता या अभिनेता या अन्य कोई व्यक्ति ऐसे शोषणका दोषी है उसके खिलाफ मुकदमा चलता है या नहीं। मुम्बई फिल्म उद्योगमें भी ऐसी शिकायतें एक लम्बे अर्सेसे आ रही हैं। कई फिल्मी अभिनेत्रियोंने बड़ी हिम्मत करके कुछ नामीगिरामी निर्माताओं और नायकोंके खिलाफ हल्ला बोला था। कई लोगोंके नाम भी उजागर हुए थे। कुछ लोगोंके खिलाफ जांच पड़ताल भी हुई। अंग्रेजीमें 'मी टू' कहनेकी हिम्मत कई अभिनेत्रियोंने किया। लेकिन फिर यही पुरुषप्रधान समाजने इसे दबा दिया। क्योंकि फिल्म उद्योगमें निर्माताओं और पैसा लगानेवालोंका वर्चस्व है। आगे कोई हिन्दी फिल्म उद्योगकी महिला ऐसा खुलासा करनेकी हिम्मत कैसे करेगी। यह अनुत्तरित सवाल है। कहनेको पुलिसमें महिलाओंकी भर्ती अर्शतक की गयी है। महिलाएं थाने भी खुल गये हैं। अब तो महिला पुलिस अफसर, पुलिस कप्तान और कोतवाल भी बन रही हैं। लेकिन देशकी महिलाएं अपनी सुरक्षाके प्रति आश्वस्त नहीं हैं। महिलाओंका अनुपात नौकरियोंमें तेजीसे बढ़ रहा है। शिक्षाके क्षेत्रमें भी लड़कियां लड़कोंसे अच्छे नम्बर पा रही हैं। उन्हें देशके एक कोनेसे दूसरे कोनेतक अकेले ही जाना पड़ता है। आखिर उनकी सुरक्षाकी गारण्टी कैसे होगी। क्या सिर्फ कानूनमें सुधार कर देने या कानून कड़ा कर देने या महिलाओंको पुलिसकी वर्दी पहनाकर उन्हें अफसर बनानेसे होगी या फिर देश और समाजको अपनी पूरी सोच, संस्कृति और आदत भी बदलनी होगी। देशकी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मूके कहनेका अर्थ तभी सही मायनेमें हम समझ पायेंगे जब हम उनकी आशंकाओंको हमेशाके लिए दूर कर पायेंगे।

कोलकातामें महिला जूनियर डाक्टरके साथ हुए बलात्कारकी घटनाके बादसे जनतामें जो उबाल आया है वह थमनेका नाम नहीं ले रहा। महामहिमने गम्भीर सवाल देशकी केन्द्रीय और राज्य सरकारोंके अलावा जनताके सामने भी उठाया है कि क्या ऐसी घटनाएं थमेगी नहीं? ऐसा लगता है राष्ट्रपतिने महिलाओंके दर्दको अच्छी तरह शायद इसलिए समझा है कि वह भी महिला हैं। कहा जा सकता है उनकी जगह कोई पुरुष राष्ट्रपति होता तो शायद इतनी गहरी संवेदनाके साथ इन बातोंको नहीं रखता। महामहिमने हिम्मतके साथ अपनी बातको रखा है वह उन्हें महान लोगोंकी श्रेणीमें स्थापित करता है।

गणित और विज्ञानका सिरमौर भारत

अंधविश्वास बढ़ रहा है। अंधविश्वास राष्ट्रजीवनके लिए घातक है। परीक्षामें सफलताके लिए लोग ठगनेवाले बाबाओंकी शरणमें जा रहे हैं। देशको वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनानेकी जरूरत है। संसार प्रत्यक्ष है। विज्ञान कार्य कारणकी व्याख्या है।

❑ **हृदयनारायण दीक्षित**

वैज्ञानिक दृष्टिकोणका मतलब क्या है। विज्ञान कार्य कारणकी व्याख्या है। भारतीय दर्शनमें तर्क और प्रतितर्कका विशेष महत्व है। आधुनिक विज्ञान सब कुछ जाननेकी जिज्ञासा है। प्राचीन कालमें ऋषि सृष्टि रहस्योंपर विचार करते थे। सृष्टि रहस्यपूर्ण है भी। ऋग्वेदमें जिज्ञासा है कि मरुत (वायु) किस शक्ति से वर्षा करते हैं और किस देशसे आते हैं। सूर्य प्रत्यक्ष हैं। सम्पूर्ण जगतके लिए उपास्य हैं। भौतिक सत्य हैं। ऋषिकी जिज्ञासा है कि वह रात्रिमें किस क्षेत्रको प्रकाशित करते हैं। वैदिक समाजको सूर्यके दर्शनमें आनन्द मिलता था। सूर्यपर अनेक सूक्त हैं। आधुनिक विज्ञानने अनेक सौरमण्डल जान लिये हैं। ऋग्वेदमें इसीसे मिलती-जुलती जिज्ञासा है कि सूर्य हैं कितने। यहां सूर्यपर एक मजेदार प्रश्न है कि सूर्य आकाशसे क्यों नहीं गिरता। उसका आधार क्या है। ऋग्वेदमें ऐसे सैकड़ों प्रश्न हैं। क्या इन प्रश्नोंको वैज्ञानिक नहीं माना जा सकता। विज्ञानका जन्म और विकास ऐसी ही प्रश्न बेचैन जिज्ञासासे हुआ है। संसारके सर्जक एक देवताका नाम विश्वकर्मा था। ऋषिका प्रश्न है कि जब संसार नहीं था तब विश्वकर्माने कहां बैठकर संसार बनाया। वे सृष्टि निर्माणकी सामग्री कहांसे लायें। विज्ञान भौतिक जगतके अणु परमाणुओं एवं गोचर प्रपंचोंका अध्ययन है। चरक संहिता प्राचीन ज्ञानका महान ग्रंथ है। चरक संहितामें आत्माको द्रव्य बताया गया है। यही बात इसके पहले वैशेषिक दर्शनमें है। वैशेषिक दर्शनमें आत्माको द्रव्य बतानेकी घोषणा क्रांतिकारी है। प्राचीन विज्ञानकी जड़ें प्राचीन संस्कृतिमें हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञानने बड़ी उन्नति की है। परम्पराकी जड़ोंको देखना जांचना अवैज्ञानिक नहीं हो सकता। अथर्ववेदके एक ऋषिने सफेद बालोंको काला करनेकी दवा खोजी थी। इसे विज्ञान कहेंगे या अध्यात्म। कभी-कभी प्राचीनताके समर्थक भी अति उत्साहमें आधुनिक कालमें हुई खोजोंको प्राचीन बताते हैं। यह विषय विशेष शोधके लायक है। भारतीय काव्य परम्परामें आकाश मार्ग और विमानके उल्लेख हैं। विमानकी बात कल्पना हो सकती है। विमानकी कल्पनाके लिए भी वैज्ञानिक चित्त चाहिए। प्राचीन कालमें विमान थे या नहीं थे यह शोधका विषय है। इतिहास और पुरातत्वका है। वैज्ञानिक दृष्टिकोणके लिए साक्ष्य चाहिए। प्राचीन आख्यानके एक मजेदार पात्र हैं नारद। वह बिना किसी वाहनके दुनियाके किसी भी कोनेकी यात्रा कर लेते हैं। धरती और आकाशकी भी। उनके हाथमें सुंदर वाद्ययंत्र है। नारदका उल्लेख ऋग्वेदमें है। महाभारतमें है। रामायणमें है। नारद यत्र तत्र सर्वत्र भ्रमण करते हैं। वे इतिहासके पात्र हो सकते हैं और नहीं भी। दुनियाके किसी भी ग्रंथमें नारद जैसा पात्र नहीं है। वैदिक भारतमें तर्कशास्त्र और दर्शनका विकास हो रहा था। आधुनिक कालमें वैज्ञानिक दृष्टिकोणको विकसित करनेका काम यहांके विद्वानोंने किया। प्राचीन भारत अंधविश्वासी नहीं था। ऋग्वेदमें प्रकृतिके भीतर एक सारभूत नियम व्यवस्थाका उल्लेख है। डा. राधाकृष्णनके अनुसार ईश्वर भी प्राकृतिक संविधानमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। प्राचीन विज्ञानमें सृष्टिके गोचर प्रपंचोंकी गहन जिज्ञासा थी। तैत्तिरीय उपनिषद् (उत्तर वैदिक काल) में भृगुको पिताने बताया अन्न ही संपूर्णता है। अन्नसे प्राण हैं। यहां प्रत्यक्ष वैज्ञानिक भौतिकवाद है। फिर कहा प्राण ही सर्वस्व हैं। प्राणके कारण प्राणी हैं। यहां भी कोई अंधविश्वास नहीं। आगे बताया कि मन ही सब कुछ है और फिर बताया विज्ञान ही सब कुछ है। विज्ञानसे ही प्राणी जन्म लेते हैं। जीवित रहते हैं और विज्ञानमें ही समा जाते हैं। यहां विज्ञान शिखर है। विज्ञान अर्थात् प्रकृतिके अकाट्य नियम। अंतमें कहा कि लेकिन आनंद ही सर्वस्व है। अन्न, मन, प्राण या विज्ञान सबका उद्देश्य आनन्द ही है। प्रयोगसिद्धि विज्ञानकी प्रमुख कसौटी है। व्यक्तिगत अनुभूति वैज्ञानिक नहीं होती। सार्वजनिक सिद्धि जरूरी है। भारी-भरकम उपकरण या प्रयोगशालाएं ही किसी ज्ञानको विज्ञान नहीं बनाते। आईंस्टीनने लिखा है जिसने भी उन औजारों और विधियोंका व्यवहार सीख लिया है, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमें वैज्ञानिक प्रतीत होते हैं, मैं उसे वैज्ञानिक नहीं मानूंगा। मैं उन व्यक्तियोंकी बात कर रहा हूं जिनमें वैज्ञानिक मानसिकता-साइंटिफिक मेण्टालिटी जीवंत है। यहां वैज्ञानिक मानसिकतापर ही जोर है। वैज्ञानिक मानसिकता क्या है। भारत अंधविश्वास मुक्त और जिज्ञासु था। धरती, आकाश और सौरमण्डलको जानने जांचनेको बेचैन था। इसलिए प्राचीन ज्ञान विज्ञानको कोरा मिथक कहना राष्ट्रजीवनका सीधा अपमान है। वैज्ञानिक दृष्टिकोणमें ज्ञानकी कोई अवस्था अंतिम नहीं होती। ज्ञान निरन्तर विकासमान प्रक्रिया है। न प्राचीन विज्ञान पूर्ण था और न ही आधुनिक विज्ञान ही पूर्ण है।

गणित विज्ञानकी आत्मा है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिकाके अनुसार शून्यके अंकका आविष्कार संभवत: हिन्दुओंने किया। लिखा है कि एकसे दस अंकोंके प्रतीक अधिकतर भारतमें उत्पन्न हुए। अरबोंने उनका प्रयोग किया। उन्हें हिन्दू अरेबिक अंक कहा जाता है। संस्कृतमें शति दस सूचक और सौके लिए शतम् है। इसका लैटिन रूप केंतुम और जर्मनमें हुंड या हुडा है, अंग्रेजीका हंड्रेड इसीका विस्तार हो सकता है। वैदिक मंत्रोंमें दस अंगुलियोंका अनेक बार उल्लेख है। एसएन सेनने हिस्ट्री अफ साइंसेज इन इण्डियामें लिखा है, शब्दांक और दाशमिक स्थानगत मूल व्यवस्थामें व्यवहार एक अन्य अपूर्व भारतीय विकास है। गणितका विकास विश्लेषक प्रतिभाका उत्कृष्ट प्रमाण है। दशमलव पद्धति विश्वको भारतकी देन है। नीढेमने साइंस एण्ड सिविलाइजेशन इन चाइनामें लिखा, शून्यका प्रयोग १२४७ ई. में चीनमें मिलता है। धारणा है कि वह सीधे भारतसे प्राप्त किया गया है। गणित और विज्ञानका जन्म भारतमें हुआ। एकके साथ शून्य लगाकर बना दस महत्वपूर्ण अंक है। ऋग्वेदके अनुसार दस दिशाएं हैं। इन्द्रियां भी दस हैं। विराट पुरुष दस अंगुलमें विश्व घेरता है। सौ अंकका भी उल्लेख है-सौ शरद्का जीवन चाहिए। शून्यवाली संख्या मजेदार ढंगसे बढ़ती है, वरूण सौ औषधियां रखते हैं और हजार भी। पुरुष सहस्त्र शिरो वाला, सहस्त्र पैरोंवाला है। मैक्डनल और कीथने वैदिक साहित्यसे अनेक संख्याओंका उल्लेख किया है। उन्होंने समय मापके दाशमिक विभाजनका भी ब्योरा दिया है। बीज गणितका विकास यहां हुआ। हड़प्पा स्थापत्य प्राचीन रेखागणितका साक्ष्य है। जर्मन विद्वान डा. थामसके अनुसार हड़प्पा सभ्यताके मापक यंत्र गणित ज्ञानकी गवाही है। पृथ्वीकी गतिशीलता और गुरूत्व अथर्ववेदमें है। वेदोंमें हजारों वनस्पतियोंका उल्लेख है। यहां धातु उद्योग भी है। वस्त्र उद्योग भी है। भारतको प्राचीन ज्ञान, विज्ञानपर गर्व है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारा उत्तराधिकार है। भारतके वैज्ञानिकोंने उत्कृष्ट कार्य किये हैं। प्राचीन ज्ञानका स्वाभिमान और आधुनिक विज्ञानकी ग्राह्यतामें भारतका भविष्य उज्जवल है।

आत्मबोध

वराह जयंती

❑ **अनिमेश शुक्ल**

वराह जयंती भाद्रपद मासके शुक्ल पक्षकी तृतीया तिथिको मनायी जाती है। इस तिथिको भगवान विष्णुने वराह अवतार लिया था और हिरण्याक्ष नामक दैत्यका वध किया। भगवान विष्णुके इस अवतारमें श्रीहरि पापियोंका अंत करके धर्मकी रक्षा करते हैं। वराह जयंती भगवानके इसी अवतरणको प्रकट करती है। हिरण्याक्ष देवर्षि नारदके पास जाकर नारायणका पता पूछा। देवर्षि नारदने उसे बताया कि नारायण इस समय वाराहका रूप धारण कर पृथ्वीको रसातलसे निकालनेके लिए गये हैं। इसपर हिरण्याक्ष रसातलमें पहुंच गया। वहां उसने भगवान वाराहको अपनी दाढ़पर रखकर पृथ्वीको लाते हुए देखा। उस महाबली दैत्यने वाराह भगवानसे कहा, अरे जंगली पशु! तू जलमें कहांसे आ गया है। मूर्ख पशु! तू इस पृथ्वीको कहां लिये जा रहा है। इसे तो ब्रह्मा जीने हमें दे दिया है। रे अधम! तू मेरे रहते इस पृथ्वीको रसातलसे नहीं ले जा सकता। तू दैत्य और दानवोंका शत्रु है, इसलिए आज मैं तेरा वध कर डालूंगा। हिरण्याक्षके इन वचनोंको सुनकर वाराह भगवानको बहुत क्रोध आया, किन्तु पृथ्वीको वहां छोड़कर युद्ध करना उन्होंने उचित नहीं समझा और उनके कटु वचनोंको सहन करते हुए वे गजराजके समान शीघ्र ही जलके बाहर आ गये। उनका पीछा करते हुए हिरण्याक्ष भी बाहर आया और कहने लगा, रे कायर! तुझे भागनेमें लज्जा नहीं आती। आकर मुझसे युद्ध कर। पृथ्वीको उचित स्थान देकर भगवान वाराह दैत्यकी ओर मुड़े और कहा, अरे ग्राम सिंह (कुत्ते)! हम तो जंगली पशु हैं और तुम जैसे ग्राम सिंहोंको ही ढूंढ़ते रहते हैं। अब तेरी मृत्यु सिरपर नाच रही है। उनके इन व्यंग वचनोंको सुनकर हिरण्याक्ष उनपर झपट पड़ा। भगवान वाराह और हिरण्याक्षके मध्य भयंकर युद्ध हुआ और अंतमें हिरण्याक्षका भगवान वाराहके हाथों वध हो गया। भागवत पुराणके अनुसार ब्रह्माने मनु और सतरूपाका निर्माण किया और सृष्टि करनेकी आज्ञा दी। इसके लिए भूमि की आवश्यकता होती है, जिसे हिरण्याक्ष नामक दैत्य लेकर सागरके भीतर भू-देवीको अपना तकिया बनाकर सोया था तथा देवताओंके डरसे विष्ठाका घेरा बना रखा था। मनु सतरूपाको जल ही जल दिखा, जिसके बारेमें ब्रह्माको बताया। तब ब्रह्माने सोचा कि सभी देव तो विष्ठाके पासतक नहीं जाते, एक शूकर ही है जो विष्ठाके समीप जा सकता है। भगवान विष्णुका ध्यान किया और अपनी नासिकासे वाराह नारायणको जन्म दिया, पृथ्वीको ऊपर लानेकी आज्ञा दी। वाराह भगवान समुद्रमें उतरे और हिरण्याक्षका संहार कर भू-देवीको मुक्त किया।

पुलिस विभागमें परिवर्तनसे ही आतंकियोंका सफाया सम्भव

❑ **ब्रिगे.कुलदीप सिंह काहलों**

कारगिल विजय दिवसकी २५वीं वर्षगांठके अवसरपर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदीने द्रास स्थित कारगिल वार मैमोरियलमें शहीदोंको श्रद्धांजलि देते हुए पाकिस्तानको सख्त चेतावनी देते हुए कहा, उन्होंने इतिहाससे कुछ नहीं सीखा। हमारे सैनिक आतंकवादको खत्म कर मुंहतोड़ जवाब देंगे। १५ अगस्तको लाल किलेकी प्राचीरसे भी प्रधान मंत्रीने सर्जीकल स्ट्राइक २०१६ और बालाकोट एयर स्ट्राइक २०१६ की याद ताजा करवायी। अग्निपथ योजनाके बारेमें उन्होंने द्रासमें कहा कि इस स्कीमका मुख्य उद्देश्य सेनाको सदैव ही युद्धके लिए प्रतिपल तैयार रखना है और यह स्कीम सेनाकी ओरसे किये गये सुधारोंकी एक मिसाल है। इसके अतिरिक्त प्रधान मंत्रीने कुछ और मुद्दे भी उजागर किये। पाकिस्तानकी वर्ष १९४७-१८ की लड़ाईमें हुई शर्मनाक हारका बदला लेनेकी भावनाके साथ पाकिस्तानके पूर्व राष्ट्रपति जनरल आयूब खानने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) के अंदर वर्ष १९६५ के शुरूमें चार गुरिल्ला ट्रेनिंग कैंप स्थापित कर करीब ९००० प्रशिक्षण प्राप्त घुसपैठियोंको अगस्तके पहले सप्ताह इस्लामके नारेके अंतर्गत जम्मू-कश्मीरके इलाके कारगिलसे लेकर जम्मूके पश्चिमकी ओर पहाड़ियोंतक धकेल दिया जो अब भी विशेष तौरपर जम्मूके नौ जिलोंमें सरगर्म हैं। मईसे लेकर अबतक आतंकियोंके साथ मुठभेड़के दौरान घाटीमें १८ सुरक्षा कर्मचारी अपना बलिदान दे चुके हैं। इनमेंसे १४ तो जम्मू क्षेत्रमें ही शहीद हुए जिनमें दो कैप्टन, एक सीआरपीएफ इंस्पैक्टर तथा बाकी जवान शामिल थे। वास्तवमें आतंकवादका जन्मदाता तो आयूब खान ही है। जम्मू-कश्मीरके उप राज्यपाल मनोज सिन्हाने अगस्तके प्रथम सप्ताहमें पांच पुलिस कर्मियों और एक अध्यापकको देश विरोधी गतिविधियोंमें शामिल होनेके दोषमें संविधान की धारा ३११ (२) (सी) का इस्तेमाल करते हुए उन्हें नौकरीसे बर्खास्त कर दिया। ऐसे लोग फिरसे पैदा हो जाते हैं परन्तु किस तरह यह मालूम नहीं। घाटीके अंदर हैरानीजनक भेद उस समय खुला जब वर्ष २०१२ में एक पुलिस कर्मचारीको हिरासतमें लिया गया। खुफिया एजैंसियोंको करीब डेढ़ सालतक जांच करनेके उपरांत पता चला कि कुछ पुलिस स्टाफ आतंकियोंकी ओरसे सुरक्षा चौकियों और सुरक्षाबलोंपर निशाना साध रहे हैं। कश्मीर रेंजके तत्कालीन इंस्पैक्टर जनरल (आईजी) शिव मुरारी सहायके अनुसार जम्मू-कश्मीरके कांस्टेबल अब्दुल रशीद शीगानने हिजबुल मुजाहिद्दीनके एक रिहा किये गये आतंकी इम्तियाज अहमद उर्फ रशीदके साथ मिलकर १८ महीनोंमें १३ बार घातक हमले किये, जिनमेंसे एक जानलेवा हमला ११ दिसम्बर २०११ को जम्मू-कश्मीरके कानून एवं विधायी कार्यों बारे मंत्री अली मोहम्मद सागरके ऊपर भी किया गया। आईजी सहायके उस समयके बयानके अनुसार अब्दुलको जब हिरासतमें लिया गया तो उस समय वह सशस्त्र पुलिसके सुरक्षा विंगमें ड्यूटी निभा रहा था। फोर्समें भर्ती होनेसे पहले उसकी पृष्ठभूमि आतंकी गतिविधियों वाली रही है। उसे एक साल नजरबंद किया गया परन्तु अदालतके फैसलेके अनुसार वर्ष २०१२ में उसे वापस पुलिसमें शामिल कर लिया गया जो कि कई सवाल पैदा करता है। इससे पहले भी वर्ष २००२ में राज्यके गृहमंत्री मुश्ताक अहमद लोनकी हत्याके पीछे एक एसएचओ तथा एक मुंशीका हाथ था। अब सवाल पैदा यह होता है कि जम्मू-कश्मीरकी करीब १.४० लाख गिनतीवाली पुलिस फोर्समें कितने इस किस्मके अधिकारी होंगे जिनकी तारें आतंकवादियों और कुछ नेताओंके साथ जुड़ी हो सकती हैं। इसका जवाब तो जम्मू-कश्मीरके प्रशासक ही दे सकते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि वारदातें करनेवाले फिर जंगलों एवं घाटीमें ही समा जाते हैं जो कि बिना किसी स्थानीय मददके संभव नहीं है। शहादतें तो सेनाको ही देनी पड़ती हैं। पाकिस्तानको केवल बार-बार चेतावनी देनेके साथ बात नहीं बनेगी क्योंकि लातोंके भूत बातोंसे नहीं मानते। जरूरत इस बातकी है कि आतंकियोंके मददगार और कसूरवार राजनीतिक नेता, प्रशासनिक तथा पुलिस अधिकारियोंको बख्शा न जाय। जम्मू-कश्मीरके पुलिस विभागमें रद्दोबदल करनेसे ही आतंकियोंका सफाया संभव होगा। कारगिल विजय दिवसके अवसरपर प्रधान मंत्रीकी ओरसे अग्निपथ योजना या वन रैंक वन पैंशन (ओआरओपी) जैसे मुद्दोंके बारेमें राजनीति करना शोभा नहीं देता। उल्लेखनीय है कि जब दिवंगत प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयीने कारगिल युद्धके समय यह महसूस किया कि शहीदोंके परिवारों, बल्कि समस्त सैनिक वर्गके कल्याणके बारेमें कोई नीति नहीं है तो उन्होंने रक्षामंत्री दिवंगत जॉर्ज फर्नांडीजकी अध्यक्षतामें कमेटीका गठन किया। परन्तु अफसोसकी बात है कि २५ वर्ष बीतनेके बाद भी यह नीति नहीं बनी। प्रधान मंत्री मोदीको चाहिए कि उसके बारेमें जिक्र करते। इसी तरह ओआरओपीको लागू करनेमें सरकारकी ओरसे बार-बार अड़चनें डाली गयीं। आखिकार सुप्रीम कोर्टकी ओरसे सख्त फैसलेके बाद सरकारको ही झुकना पड़ा।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

सड़कों पर आंदोलन, विरोध प्रदर्शन, उपद्रव और हिंसा हर राज्य में हर पार्टी के शासन काल में होते हैं। लेकिन बंगाल में हिंसा का जो स्वरूप और व्याप्ति देश पचास साल से देख रहा है वह असाधारण और दूसरे सभी राज्यों की तुलना में अनूठा है। हिंसा बंगाली राजनीति के चरित्र का एक खूनी अविभाज्य अंग बन चुकी है। यह पूरे देश के लिए तो चिंताजनक है ही स्वयं बंगाल की प्रगति और भविष्य के लिए भी आत्मघाती है। इसका समाधान भी बंगाल के समाज को ही ढूंढ़ना पड़ेगा। इसमें जितनी देर होगी उतना नुकसान होगा।

-राहुल देव, पत्रकार @rahuldev2

जलवायु बदलाव

भारत डोगरा

पर्यावरण व समता का मिलन जरूरी

वैसे तो समतावादी विचार की जरूरत सदा थी, पर गंभीर पर्यावरण संकट के दौर में यह जरूरत और बढ़ गई है। एक बड़ी जरूरत यह है कि अर्थव्यवस्था में विषमताएं सब स्तरों पर कम की जाएं क्योंकि इसके बिना टिकाऊ तौर पर, दीर्घकालीन तौर पर सब लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना लगभग असंभव ही है। पर्यावरण के बढ़ते संकट के दौर में तो यह और भी जरूरी हो गया है। पर्यावरण के निरंतर गंभीर होते संकट के बीच सादगी के कुछ मानदंड स्वीकार करने पर ही सबकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। महात्मा गांधी ने बहुत पहले कहा था कि प्रकृति में सबकी जरूरतें पूरा करने की तो क्षमता है पर लालच पूरी करने की नहीं। लालच या विलासिता आधारित मांग प्रकृति पर बोझ डालती हैं व पर्यावरण के संकट को बहुत विकट करती हैं। अतः अर्थव्यवस्था में समता व सादगी के सिद्धान्त को अपना कर पर्यावरण की रक्षा से अर्थव्यवस्था को बुनियादी तौर पर जोड़ा जा सकता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में पर्यावरण की रक्षा पर समुचित महत्त्व देना अलग से जरूरी है।

बढ़ती प्रासंगिकता के बावजूद विश्व स्तर पर पर्यावरण के आंदोलन का जन-आधार इस कारण व्यापक नहीं हो सका है क्योंकि इसमें न्याय व समता के मुद्दों का उचित ढंग से समावेश नहीं हो पाया है। जलवायु बदलाव के संकट को नियंत्रण करने के उपायों में जनसाधारण की भागीदारी प्राप्त करने का सबसे असरदार उपाय यह है कि विश्व स्तर पर ग्रीनहाऊस गैसों के उत्सर्जन में पर्याप्त कमी उचित समय-अवधि में लाए जाने की ऐसी योजना बनाई जाए जो सभी लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने से जुड़ी हो और फिर इस योजना को कार्यान्वित करने की दिशा में तेजी से बढ़ा जाए।

यदि इस तरह की योजना बना कर कार्य होगा तो ग्रीनहाऊस गैस उत्सर्जन में कमी के जरूरी लक्ष्य के साथ-साथ करोड़ों अभावग्रस्त लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का लक्ष्य अनिवार्य तौर पर जुड़ जाएगा, व इस तरह ऐसी योजना के लिए करोड़ों लोगों का उत्साहवर्धक समर्थन प्राप्त हो सकेगा। ग्रीनहाऊस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कुछ हद तक हम फॉसिल ईंधन के स्थान पर अक्षय ऊर्जा (जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा) का उपयोग कर सकते हैं, पर केवल यह पर्याप्त नहीं है। विलासिता व गैर-जरूरी उपभोग कम करना भी जरूरी है। यह तो बहुत समय से कहा जा रहा है कि विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बहुत सावधानी से होना चाहिए व वनों, चरागाहों, कृषि भूमि व खनिज-भंडारों का उपयोग करते हुए इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि पर्यावरण की क्षति न हो या उसे न्यूनतम किया जाए। जलवायु बदलाव के दौर में अब नई बात यह जुड़ी है कि विभिन्न उत्पादन कार्यों के लिए कितना कार्बन स्थान या स्पेस उपलब्ध है, यह भी ध्यान में रखना जरूरी है। जब हम इन नई-पुरानी सीमाओं के बीच दुनिया के सब लोगों की जरूरतों को पूरा करने की योजना बनाते हैं तो स्पष्ट है कि वर्तमान अभाव की स्थिति को देखते हुए करोड़ों गरीब लोगों के लिए पौष्टिक भोजन, वस्त्र, आवास, दवाओं, कापी-किताब आदि का उत्पादन बढ़ाना होगा। इस उत्पादन को बढ़ाने में हम पूरा प्रयास कर सकते हैं कि ग्रीनहाऊस गैस के उत्सर्जन को कम करने वाली तकनीकों का उपयोग हो पर यह एक सीमा तक ही संभव होगा।

अतः यदि गरीब लोगों के लिए जरूरी उत्पादन बढ़ाना है तो उसके लिए जरूरी प्राकृतिक संसाधन व कार्बन स्पेस प्राप्त करने के लिए साथ ही यह जरूरी हो जाता है कि विलासिता की वस्तुओं व गैर-जरूरी वस्तुओं का उत्पादन कम किया जाए। यह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि गरीब लोगों के लिए जरूरी उत्पादन को प्राथमिकता देने वाला नियोजन न किया गया तो फिर विश्व स्तर पर बाजार की मांग के अनुकूल ही उत्पादन होता रहेगा। वर्तमान विषमताओं वाले समाज में विश्व के धनी व्यक्तियों के पास क्रय शक्ति बेहद अन्यायपूर्ण हद तक केंद्रित है, अतः बाजार में उनकी गैर-जरूरी व विलासिता की वस्तुओं की मांग को प्राथमिकता मिलती रहेगी। अतः इन्हीं वस्तुओं के उत्पादन को प्राथमिकता मिलेगी। सीमित प्राकृतिक संसाधनों व कार्बन स्पेस का उपयोग इन गैर-जरूरी वस्तुओं के उत्पादन के लिए होगा। गरीब लोगों की जरूरी वस्तुएं पीछे छूट जाएंगी, उनका अभाव बना रहेगा या और बढ़ जाएगा। अतः यह बहुत जरूरी है कि ग्रीनहाऊस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की योजना से विश्व के सभी लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की योजना को जोड़ दिया जाए व उपलब्ध कार्बन स्पेस में बुनियादी जरूरतों को प्राथमिकता देना एक अनिवार्यता बना दिया जाए। इस योजना के तहत जब गैर-जरूरी उत्पादों को प्राथमिकता से हटाया जाएगा तो यह जरूरी बात है कि सब तरह के हथियारों के उत्पादन में बहुत कमी लाई जाएगी। मनुष्य व अन्य जीवों की भलाई की दृष्टि से देखें तो हथियार न केवल सबसे अधिक गैर-जरूरी हैं अपितु सबसे अधिक हानिकारक हैं। इसी तरह अनेक हानिकारक उत्पाद हैं (शराब, सिगरेट, कुछ बेहद खतरनाक केमिकल्स आदि) जिनके उत्पादन को कम करना करना जरूरी है। इन हानिकारक उत्पादों व विशेषकर हथियारों के उत्पादन को कम करने में अनेक पेचीदगियां हैं, अनेक कठिनाइयां व बाधाएं हैं। पर ग्रीनहाऊस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की अनिवार्यता के दौर में इन उत्पादों को न्यूनतम करने का औचित्य पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया है। इस तरह की योजना पर्यावरण आंदोलन को न्याय व समता आन्दोलन के नजदीक लाती है व साथ ही इन दोनों आंदोलनों को शान्ति आंदोलन के नजदीक लाती है। यह तीनों सरोकार एक होंगे तो दुनिया की भलाई के कई महत्त्वपूर्ण कार्य आगे बढ़ेंगे।

पहले कहा जाता था कि संसाधन सीमित हैं, उनका सही वितरण करो पर अब तो ग्रीनहाऊस गैसों के उत्सर्जन से जुड़ी कार्बन की सीमा है। इस सीमा के बीच में ही हमें सब लोगों की जरूरतों को टिकाऊ आधार पर पूरा करना है। अतः अब विषमता को दूर करना, विलासिता व अपव्यय को दूर करना, समता व न्याय को ध्यान में रखना, भावी पीढ़ी के हितों को ध्यान में रखना पहले से भी कहीं अधिक जरूरी हो गया है। यह एक बहुत रचनात्मक कार्य और चुनौती हमारे सामने है कि सभी लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करते हुए साथ-साथ कार्बन सीमा के भीतर रहा जाए। दूसरे शब्दों में, हम ग्रीनहाऊस गैसों में तेज कमी लाते हुए भी सभी लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें। इस तरह के प्रयास से ऐसे परिणाम मिल सकते हैं जो विश्व के लिए बहुत कल्याणकारी संदेश दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, ऐसे किसी मॉडल के नियोजन से ऐसा संदेश मिलने की बहुत संभावना है कि युद्ध व हथियारों की होड़ को समाप्त किया जाए या न्यूनतम किया जाए। एक अन्य संदेश यह मिलने की संभावना है कि जो बहुत वेस्टफुल उत्पादन व उपभोग है उन्हें समाप्त किया जाए या बहुत नियंत्रित किया जाए। इस तरह से स्थिति स्पष्ट होने से युद्ध, हथियारों व वेस्टफुल उत्पादन-उपभोग पर नियंत्रण के पक्ष में बड़ा जनमत बनेगा। यह अपने आप में बहुत उपयोगी होगा व पर्यावरण संरक्षण के लिए भी। इस तरह अमन-शांति और सभी लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी करने के कार्य साथ-साथ आगे बढ़ सकेंगे।

विषमता दूर करना, विलासिता व अपव्यय को दूर करना, समता व न्याय को ध्यान में रखना, भावी पीढ़ी के हितों को ध्यान में रखना पहले से भी कहीं अधिक जरूरी हो गया है। यह बहुत रचनात्मक कार्य और चुनौती है कि सभी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करते हुए साथ-साथ कार्बन सीमा के भीतर रहा जाए। हम ग्रीनहाऊस गैसों में तेज कमी लाते हुए भी सभी की बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें। ऐसे प्रयासों से ऐसे परिणाम मिल सकते हैं जो विश्व के लिए कल्याणकारी संदेश दे सकते हैं। ऐसे किसी मॉडल के नियोजन से ऐसा संदेश मिलने की बहुत संभावना है कि युद्ध व हथियारों की होड़ को समाप्त या न्यूनतम किया जाए। एक अन्य संदेश यह मिलने की संभावना है कि जो बहुत वेस्टफुल उत्पादन व उपभोग है उन्हें समाप्त किया जाए या बहुत नियंत्रित किया जाए

सोशल मीडिया और कानून

मीडिया

सुधीश पचौरी

पिछले लोक सभा चुनावों के दौरान सोशल मीडिया के एक हिस्से ने भाजपा के ही अनुसार, भाजपा की 'आरक्षण नीति' को लेकर ऐसा 'फेक नेरेटिव' गढ़ा कि भाजपा तीसरी बार बड़े बहुमत से सत्ता में आई तो 'आरक्षण' हटा देगी...कि संविधान बदल देगी....। भाजपा के नेता लाख सफाई देते रहे कि आरक्षण को कोई नहीं हटा सकता...

यूपी सरकार ने सोशल मीडिया के आपत्तिजनक 'कंटेंट' के 'नियमन' के लिए कुछ कानूनी प्रावधान किए हैं जिन्होंने 'मीडिया की आजादी' की बहसों को गरम कर दिया है। बहुत से मानते हैं कि ये तानाशाही है। फासिज्म है। मीडिया को गुलाम बनाने साजिश है। अभिव्यक्ति की आजादी और जनतंत्र का गला घोंटना है। मूलभूत अधिकारों का हनन है...कई चैनलों ने खबर दी है कि इन प्रावधानों के अनुसार, किसी प्रकार की अश्लील व अभद्र टिप्पणी, किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाने के इरादे से की गई टिप्पणी, समाज में अशांति फैलाने के उद्देश्य से की गई टिप्पणी या सामाजिक तानाबाना बिगाड़ने के इरादे से किए गए भड़काऊ कमेंट्स, वीडियो आदि 'आपत्तिजनक' होंगे और इनके कर्ता सजा के पात्र होंगे और जो पॉजिटिव नजरिए वाले होंगे उनको सरकार इनाम देगी...चैनलों की बहसों में कानून के पक्षधरों का कहना रहा कि यह कोई नई बात नहीं, न इनाम देना नई बात है। बहुत से मीडिया को सरकारें विज्ञापन देती हैं जो प्रतिकूल होते हैं, उनको विज्ञापन नहीं मिलते। ऐसा ही इनामों के बारे में है। बहुत सी सरकारों का मानना है ऐसे 'कमेंटेटर' और 'मीडिया इन्फ्लूएंसरों' के 'नकारात्मक', 'आपत्तिजनक कमेंटों' व 'वीडियोज' के दुष्परिणामों से उन्हें निपटना पड़ता है। ऐसों को 'नियमित नियंत्रित' करने के लिए ऐसे कानून की जरूरत होती है। ऐसी व्यवस्था कई राज्यों में पहले से है। अब ऐसी व्यवस्था यूपी में कर दी गई तो आपत्ति क्यों?

जितने प्रकार के पक्ष-विपक्ष हैं, उतने ही प्रकार के तर्क हैं: कहीं 'अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकारों के हनन' के तर्क हैं तो कहीं ऐसे तर्क हैं कि 'आजादी' का 'दुरुपयोग' करने वाले बहुत से अराजकतावादी तत्व 'सोशल मीडिया प्लेटफार्मों' पर दिन-रात सक्रिय रहते हैं। इनमें से बहुत से विदेशी संस्थानों द्वारा फाइनेंस किए जाते हैं। ऐसे 'आवारा मीडिया' को अनुशासित करने के लिए ही यूपी सरकार ने यह व्यवस्था की है। हो सकता है कि कुछ लोग अदालत जाएं और वहां यह खारिज हो जाए या हो सकता है कि इनमें कुछ संशोधन की मांग हो...लेकिन यह सब तो आगे की बातें हैं। हमारा सवाल है कि क्या इस कानून के बाद 'संदिग्ध सोशल मीडिया' व 'डिजिटल मीडिया प्लेटफार्म' सुधर जाएंगे, क्या वे कानून-सम्मत कंटेंट के वाहक रहेंगे...। हमारा मानना है कि ऐसा नहीं होने वाला। इसके लिए हमारे तर्क निम्न प्रकार से हैं: -इससे पहले भी सरकारों के पास ऐसे बहुत से कानून रहे हैं जिनके जरिए वे 'आपत्तिजनक कंटेंट' व 'मीडिया' को अनुशासित करती रही हैं, लेकिन कई बार ऐसे प्लेटफार्म ऐसे हर नियमन से बच निकलते हैं क्योंकि अदालत में सारे आरोप विवाद का विषय बनकर रह जाते हैं और सत्ताएं अक्सर तय नहीं कर पातीं कि कोई संदेश आपत्तिजनक है तो क्यों है, कितना है, कैसे है? -फिर ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों में आने वाले आपत्तिजनक संदेश कहां से आ रहे हैं, कहीं उनके स्रोत कोई दूसरे देश या शत्रु देश तो नहीं है? -फिर कौन सा प्लेटफार्म, किन विदेशी 'नॉन स्टेट एक्टरों' से कंटेंट' लेता देता है। -ऐसे तथ्यों को सप्रमाण सिद्ध करना असंभव नहीं तो कई बार बेहद कठिन होता है। -फिर ऐसे 'फरेबी' अपनी जगहों को बदलते भी रहते हैं। उनको कैसे 'लोकेट' करें। 'फिक्स' करें? -फिर ऐसे कानून को कैसे लागू किया जाए कि वह अदालत को भी सही लगे...।

आज की 'तकनीकी क्रांति' के दौर में ऐसी बहुत सी समस्याएं और चुनौतियां नित्य पैदा होती रहती हैं, जिनका तुरंत इलाज नहीं किया जा सकता। फिर भी सरकारें ऐसे कानून इसलिए बनाती हैं ताकि मीडिया पर उनकी धमक बनी रहे। इतिहास गवाह है कि ऐसे कई तरह के कानून पहले से ही मौजूद हैं, बल्कि बहुत सी सरकारें उनका उपयोग भी करती रहती हैं लेकिन बहुत से अवांछित 'कंटेंट' और 'संदेश' तमाम सत्ताओं और राजनीतिक दलों को परेशान करते ही रहते हैं। पिछले लोक सभा चुनाव के दौरान सोशल मीडिया के एक हिस्से ने भाजपा के ही अनुसार, भाजपा की 'आरक्षण नीति' को लेकर ऐसा 'फेक नेरेटिव' गढ़ा कि भाजपा तीसरी बार बड़े बहुमत से सत्ता में आई तो 'आरक्षण' हटा देगी...कि संविधान बदल देगी...। भाजपा के नेता लाख सफाई देते रहे कि आरक्षण को कोई नहीं हटा सकता...और संविधान हमारी पवित्र किताब है, तो भी ऐसे 'नेरेटिव' की काट न हुई और इस 'नेरेटिव' का परिणाम भाजपा को भुगतना पड़ा। कहने की जरूरत नहीं कि ऐसे 'बिगड़ैल' सोशल मीडिया को कैसे 'नाथा' जाए? इसका जवाब अब भी किसी के पास नहीं है!

चुनाव के बीच अमेरिका में मोदी

वैश्विकी

डॉ. दिलीप चौबे

वैसे घरेलू राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी का एजेंडा ट्रंप जैसा है। मोदी 'सबसे पहले भारत' की बात करते हैं तो ट्रंप सबसे पहले अमेरिका की वकालत करते हैं। भारत में यदि एक बार फिर मोदी का नारा लगता है तो अमेरिका में एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की बात होती है

अमेरिकी चुनाव में अब करीब दो महीने बाकी हैं। चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। चुनाव व्यूह रचना अंतिम रूप ले चुकी है। चुनाव के पहले सबसे बड़ा घटनाक्रम पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का प्रयास था। इस घटना ने अमेरिकी जनमानस को झकझोर दिया। हमले के समय ट्रंप ने जैसी दिलेरी दिखाई उससे आप अमेरिकी नागरिक बहुत प्रभावित हुआ। लोगों में यह धारणा बनी कि आज की अस्थिर और संघर्ष से जूझ रही दुनिया में ट्रंप जैसे दृढ़ संकल्प वाले नेता की जरूरत है। लोग जब ट्रंप और आयुजनित ह्रास रोग का शिकार जो बाइडन की तुलना करते थे तब पूर्व राष्ट्रपति ही उपयुक्त विकल्प के रूप में सामने आते थे। इसी समय दूसरा बड़ा घटनाक्रम यह हुआ कि बाइडन चुनाव मैदान से हटे गए और उन्होंने उप राष्ट्रपति कमला हैरिस को कमान सौंप दी। कुछ समीक्षकों का तो यह भी मानना था कि वह बाइडन से भी अधिक अलोकप्रिय हैं, लेकिन अमेरिका की राजनीति में मीडिया और विभिन्न दबाव समूहों की बड़ी भूमिका रहती है। यही नेताओं की छवि बनाने और बिगाड़ने का काम करते हैं। उम्मीदवारी की घोषणा होते ही मुख्यधारा की अमेरिकी मीडिया कमला हैरिस का प्राशस्ति-गान करने लगी। विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में वह छा गईं। एक महिला और गैर-श्वेत व्यक्ति के राष्ट्रपति बनने की संभावना को अमेरिकी लोकतंत्र और समाज की बड़ी जीत के रूप में प्रचारित किया जाएगा।

चुनाव के अंतिम चरणों में एक बार फिर बदलाव आया तथा डेमोक्रेटिक पार्टी की दो बड़ी हस्तियों ने ट्रंप को समर्थन देने की घोषणा की। जाने-माने कैनेडी परिवार के सदस्य रॉबर्ट एस. कैनेडी ने जो स्वयं चुनाव में एक उम्मीदवार थे, ट्रंप के समर्थन में आ गए। जनमत-सर्वेक्षणों के अनुसार वह पांच फीसद मतदाताओं की पसंद थे। उनके पाला बदलने से ट्रंप के चुनाव अभियान को मदद मिली है तथा वह कड़ी टक्कर वाले 'स्विंग स्टेट' में निर्णायक सिद्ध हो सकते हैं। इसी तरह डेमोक्रेटिक पार्टी की एक पूर्व नेता तुलसी गबार्ड ने भी ट्रंप को समर्थन देने की घोषणा की है। तुलसी अमेरिकी सेना की नेशनल गार्ड शाखा में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। किसी समय उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी में उभरता हुआ सितारा माना जाता था। सैनिक होने के बावजूद वह युद्ध विरोधी हैं तथा हिलेरी क्लिंटन सहित डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व पर युद्धोन्मादी होने का आरोप लगाती हैं। यह विडंबना है कि रिपब्लिकन पार्टी को पूर्व में साम्राज्यवादी रुझान वाली युद्ध समर्थक पार्टी माना जाता था। इसके विपरीत डेमोक्रेटिक पार्टी की छवि शांतिवादी और उदारवादी पार्टी की थी। लेकिन अब दोनों पार्टियों की भूमिका बदल गई है।

अमेरिका ने पर्यावरणवादी और युद्धविरोधी ग्रीन पार्टी का भी एक समर्थक वर्ग है। गाजा में इस्राइल के नरसंहार से मुस्लिम मतदाता नाराज हैं। वे इस बात का आकलन कर रहे हैं कि ट्रंप और कमला हैरिस में से कौन फिलिस्तीन में युद्ध रुकवा सकता है।

चुनावी दंगल के बीच ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संयुक्त राष्ट्र में संबोधन के लिए अमेरिका जाने वाले हैं। वह 22 सितम्बर को न्यूयार्क में भारतीय समुदाय के लोगों के एक बड़े कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं जिसमें करीब 20 हजार भारतीय के शामिल होने की संभावना है। जाहिर है कि प्रधानमंत्री किसी खास प्रत्याशी के पक्ष में कोई राय व्यक्त नहीं करेंगे लेकिन ट्रंप और कमला हैरिस दोनों को यह आशा होगी कि मोदी इशारों-इशारों में उनके पक्ष में पसंद जाहिर करें। वैसे घरेलू राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी का एजेंडा ट्रंप जैसा है। मोदी 'सबसे पहले भारत' की बात करते हैं तो ट्रंप सबसे पहले अमेरिका की वकालत करते हैं। भारत में यदि एक बार फिर मोदी का नारा लगता है तो अमेरिका में एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की बात होती है। ट्रंप खुलकर इस्लामिक आतंकवाद के खतरे की बात करते हैं जबकि कमला हैरिस ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं करतीं। डेमोक्रेटिक पार्टी मानवाधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे मुद्दों को तूल देकर मोदी सरकार को निशाना बनाती रही है। भारतीय मूल की कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी के भारत विरोधी रवैये में किस हद तक बदलाव करती हैं, इससे तय होगा कि भारतीय मतदाता उन्हें कितना समर्थन देते हैं।

राष्ट्रपति की पीड़ा को समझना होगा

चिंता

डॉ. विशेष गुप्ता

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर की अस्पताल में दुष्कर्म के बाद हत्या पर राष्ट्रपति की पीड़ा ध्यान देने योग्य है। उन्होंने दर्द भरे शब्दों में कहा, 'मैं निराश और भयभीत हूं।' कहना न होगा कि नौ अगस्त को कोलकाता में घटित इस दर्दनाक घटना के बाद उनका यह पहला बयान है। उन्होंने स्पष्ट लिखा कि कोई भी सभ्य समाज बेटियों और बहनों पर इस तरह के अत्याचार की अनुमति नहीं देता। उन्होंने दिसम्बर, 2012 में दिल्ली में निर्भया के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या की चर्चा करते हुए कहा,'कुछ बच्चों ने मुझसे बड़ी मासूमियत से इस घटना के बारे में पूछा, मगर क्या उन्हें ऐसी घटना आगे घटित न होने का भरोसा दिया जा सकता है।'

राष्ट्रपति की महिला उत्पीड़न को लेकर पीड़ा अनायास नहीं है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की हालिया रिपोर्ट बताती है कि देश में हर 16 मिनट में यौन दुष्कर्म की एक घटना होती है। प्रत्येक घंटे महिलाओं के विरुद्ध 50 अपराध घटित होते हैं। इनमें 10 फीसद से भी अधिक यौन दुष्कर्म की घटनाएं 18 साल से कम उम्र के नाबालिगों के साथ घटित होती हैं। लगता है कि निर्भया यौन उत्पीड़न की घटना के बाद समाज की सोच में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। उल्लेखनीय है कि ऐसी घटनाओं का लगातार बढ़ना निश्चित ही गंभीर चिंता का विषय है।

कड़वा सच यह है कि यौन दुष्कृत्यों से जुड़ी घटनाओं के पीछे छिपा वह सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण भी है जिसे हमने अपनी खुली बाजारू अर्थव्यवस्था तथा जाति व धर्म पर आधारित सामाजिक वैमनस्य और दबंगई राजनीति से तैयार किया है। ऐसे में विषैली मानसिकता का प्रस्फुटन होना स्वाभाविक है। इसलिए हमें समय रहते उन सामाजिक-मनोवैज्ञानिक दशाओं का विश्लेषण भी करना चाहिए जो लोगों को बलात्कारी बनाती हैं। साथ ही स्त्री-पुरुष देह से जुड़ी उन सामाजिक मान्यताओं और पुलिस व कानून की कमजोर व्यवस्थाओं का भी मूल्यांकन करना पड़ेगा जो आज खुद बलात्कारी की रक्षक बन कर न्याय का गला घोंट रही हैं।

यदि असलियत में हमें यह चिंता है कि किसी भी महिला अथवा पुरुष पर बलात हिंसा व यौन आक्रमण न हो तो हमें शाब्दिक वाचालता, चपलता व यौन हिंसा की घटनाओं से जुड़ी त्वरित टिप्पणी के खोल से बाहर आकर रेप से जुड़े मूल सवालों से टकराना पड़ेगा जो इस प्रकार की घटनाओं से उभर रहे हैं। स्वस्थ व स्त्री सशक्तता से जुड़े समाज की पुनर्स्थापना भी करनी पड़ेगी। तभी महिला की देह को सुरक्षा कवच मिल पाएगा। कहना न होगा कि रेप चाहे कोलकाता में हों या देश किसी अलग हिस्से में, कानून की विफलता के कारण ही नहीं हैं। हम इस सच्चाई को अच्छी तरह जानते हैं कि आज के लगातार हिंसक हो रहे समाज में कानून की सख्ती के बिना जंगलराज होने की पूरी संभावनाएं हैं परंतु यह भी सच है कि कानून व्यवस्था हम चाहे कितनी भी दुरुस्त क्यों न कर लें, अगर उसे सभ्य समाज की संवेदनशील सामाजिक मूल्यों की संस्कृति का सहयोग व समर्थन नहीं मिलता तो ऐसे में न तो सामान्य अपराधों पर और न ही बढ़ती यौन हिंसा पर रोक लगाई जा सकती। प्रत्येक नारी के सम्मान के साथ-साथ करुणा व दया के भाव से जुड़े मूल्यों को आत्मसात करके और व्यवहार में उनका प्रदर्शन करके ऐसी यौन दुष्प्रवृत्तियों पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकती है।

अमेरिकी स्वप्न का अंत निकट तो नहीं

सामयिक

प्रह्लाद सबनानी

अमेरिका विश्व के लगभग समस्त देशों पर अपनी चौधराहट लागू करता रहा है परंतु हाल के वर्षों में अमेरिका की आंतरिक स्थिति, लगभग समस्त क्षेत्रों यथा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि में लगातार बिगड़ती जा रही है। इसे अब अमेरिकी स्वप्न के अंत की शुरुआत भी माना जाने लगा है। अमेरिका में राष्ट्रीय ऋण 35 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है जबकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था का आकार, सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर, लगभग 25 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का है। आशय यह है कि आय की तुलना में ऋण अधिक ले लिया गया है। अमेरिकी सरकार को अपने सामान्य खर्चों को चलाने के लिए भी बाजार से और अधिक ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है। यह स्थिति है विश्व के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका की। वर्ष 1776 में जब पूंजीवाद के जनक कहे जाने वाले एडम स्मिथ ने अपनी 'द वेल्थ ऑफ नेशनंस' नामक किताब जारी की थी, उस समय पूंजीवाद अपने शैशावस्था में ही था। उनका महत्त्वपूर्ण सिद्धांत था कि व्यवसायी, जो अपनी लाभप्रदता को अधिकतम करना चाहते हैं, अपने व्यवसाय को कुशलता के साथ चलाना चाहते हैं। इस तरह वे न केवल अपने आप को धनाढ़्य बनाएंगे, बल्कि देश इन धनाढ़्यों के संसाधनों को जोड़कर स्वयं भी धनी देश बन जाएगा। समूची 19वीं शताब्दी एवं 20वीं शताब्दी में अमेरिका इसी सिद्धांत पर कार्य करता रहा एवं अपने देश में धनाढ़्यों की संख्या में अपार वृद्धि करता रहा। इससे अमेरिकी नागरिकों में व्यक्तिवाद पनपा एवं वे परिवार एवं समाज के भले को भूल कर अपने बारे में ही सोचने लगे एवं अपने व्यापार को पूरे विश्व में फैलाने लगे। इससे अमेरिका में गरीबों की संख्या में लगातार वृद्धि होती रही।

अमेरिका की 1940 के दशक में पूरे विश्व के विनिर्माण क्षेत्र में 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी हो गई थी, परंतु अब घटकर 17 प्रतिशत से भी कम हो गई है। कई उद्योगों के मामले में उत्पादन का जो एकाधिकार अमेरिका के पास होता था, वह अब अन्य देशों के पास चला गया है। अमेरिकी कंपनियों ने कुशल कर्मचारियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से कर्मचारियों के स्वास्थ्य खर्चे की पूरी लागत स्वयं वहन करना प्रारंभ किया था। अमेरिका में श्रम लागत भी बहुत अधिक बढ़ चुकी थी, अन्य देशों में श्रमिक, अमेरिकी श्रम लागत की तुलना में, आधी से भी कम राशि में ही काम करने को तैयार हो रहे थे।

इस बीच, अमेरिकी सरकार ने आय कर की दरें भी बढ़ा कर 35 प्रतिशत से अधिक कर दी थीं जबकि अन्य देशों में आय कर की दरें 20/25 प्रतिशत थीं। इससे अमेरिका में विभिन्न उत्पादों की उत्पादन लागत बढ़ने लगी। इसलिए धीरे धीरे अमेरिका में विनिर्माण इकाइयां बंद होने लगीं। वर्ष 1979 में अमेरिका में 20 प्रतिशत श्रमिक विनिर्माण इकाइयों में कार्यरत थे, अब यह संख्या घटकर 10 प्रतिशत से भी कम हो गई है। अमेरिका में 2 करोड़ कर्मचारी विनिर्माण इकाइयों में कार्य कर रहे थे जो घटकर 1 करोड़ 20 लाख हो गए हैं। अमेरिका में जब प्रथम राष्ट्रपति ने शपथ ली थी उस समय 10 श्रमिकों में से 9 श्रमिक कृषि क्षेत्र में कार्यरत थे जबकि आज 2 प्रतिशत श्रमिक ही इस क्षेत्र में कार्य करते हैं। इस प्रकार अमेरिका में रोजगार की दृष्टि से कृषि एवं उद्योग क्षेत्र में बहुत अधिक संकुचन हुआ है।

इन कारणों के चलते अमेरिका में गरीबी की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गरीबी के चलते इस वर्ग के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती। अंततः वे सामाजिक अपराधी गतिविधियों में संलग्न हो जाते हैं। इनके मकानों में कम सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। अमेरिका में गरीबी रेखा का निर्धारण कृषि विभाग द्वारा प्रति वर्ष किया जाता है। वर्ष 2015 में गरीबी आकलन के लिए प्रत्येक चार व्यक्तियों के परिवार के लिए प्रति वर्ष 24,300 अमेरिकी डॉलर की आय तय की गई थी। इससे कम आय वाले परिवार गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं। इस गणना के आधार पर अमेरिका में 13.5 प्रतिशत परिवार (4.31 करोड़ अमेरिकी नागरिक) गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे। गरीब वर्ग के नागरिकों के आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के चलते अमेरिका में 22 लाख अमेरिकी गरीब नागरिक जेलों में बंद थे एवं 50 लाख गरीब नागरिक पैरोल अथवा परीक्षण पर थे एवं अन्य 10 लाख नागरिक, जो जेलों से छूट गए थे, न तो पैरोल पर थे और न ही परीक्षण पर थे, परंतु वे कभी भी पुनः जेलों में भेजे जा सकते हैं।

एक अनुमान के अनुसार, अमेरिका में तीन से साढ़े तीन करोड़ नागरिक स्थायी निम्न वर्ग की श्रेणी में आते हैं, जो अमेरिका की कुल 32.5 करोड़ जनसंख्या का 10 प्रतिशत है। प्रत्येक 5 अमेरिकी बच्चों में से एक बच्चा गरीब वर्ग का है। करोड़ों अमेरिकी नागरिकों को प्राथमिक केयर डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यह सुविधा उपलब्ध भी है तो चार में से एक नागरिक को ही डॉक्टर से उसी दिन का मिलने का समय मिल पाता है। अमेरिका एवं अन्य विकसित देशों में ऐसे हालात देख कर कई अर्थशास्त्रियों द्वारा आर्थिक विकास के पूंजीवादी मॉडल पर ही प्रश्न चिह्न लगाया जाने लगा है। कहा जा रहा है कि कहीं अमेरिकी स्वप्न का अंत निकट तो नहीं है।

अमेरिका में गरीबी रेखा का निर्धारण कृषि विभाग द्वारा प्रति वर्ष किया जाता है। 2015 में गरीबी आकलन के लिए प्रत्येक चार व्यक्तियों के परिवार के लिए प्रति वर्ष 24,300 अमेरिकी डॉलर की आय तय की गई थी। इससे कम आय वाले परिवार गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं। इस गणना के आधार पर अमेरिका में 13.5 प्रतिशत परिवार (4.31 करोड़ अमेरिकी नागरिक) गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। गरीब नागरिकों के आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के चलते अमेरिका में 22 लाख अमेरिकी जेलों में बंद हैं, एवं 50 लाख नागरिक पैरोल अथवा परीक्षण पर हैं। अन्य 10 लाख नागरिक, जो जेलों से छूट गए थे, न तो पैरोल पर थे और न ही परीक्षण पर थे

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

https://t.me/AllNewsPaperPaid

राष्ट्रीय सहारा
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
वर्ष-34, अंक 18
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

उपनिषद एक ईश्वर की अन्य सभी भगवानों पर श्रेष्ठता की शिक्षा नहीं देते क्योंकि आस्था हर सवाल से ऊपर है लेकिन सभी जीवों और ब्राह्मांड में किसी एक की उपस्थिति को हमें अंतर्मन में झांक कर जान लेना होगा।
-डॉ. डेविड फ्राउले, धर्म मर्मज्ञ @davidfrawleyved

विमर्श

डॉ. सचिन कुमार

मेरे एआई भगवान, न्याय दो

न्याय प्रणाली किसी भी सभ्य समाज के सबसे आवश्यक घटकों में से एक है जिसकी नींव स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित है। मानव अधिकारों और जीवन की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से न्याय प्रदान करना समाज की सबसे महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक है। न्याय प्रदान करने के मामले में दक्षता भी सबसे महत्त्वपूर्ण तत्व है क्योंकि न्याय में देरी का मतलब न्याय से वंचित होना है।

भारतीय न्यायिक प्रणालियों में, नागरिकों ने न्यायिक मामलों में पीढ़ी-दर-पीढ़ी शामिल होने और समाधान नहीं होने के उदाहरण देखे हैं। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के अनुसार, देश भर में 50 मिलियन से अधिक मामले लंबित हैं। उनमें से लगभग 87.4% अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित हैं, और 12.4% उच्च न्यायालयों में लंबित हैं। सरकार द्वारा लोक सभा को दी गई जानकारी के अनुसार उच्चतम न्यायालय में लगभग 80,000 मामले लंबित हैं। लगभग 1,82,000 मामले 30 वर्षों से अधिक समय से बिना किसी परिणाम के लंबित हैं। भारत में लगभग 77 प्रतिशत कैदी मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर की तुलना में यह तीन में से एक है। वर्तमान गति से भारत की गोदी साफ करने में 300 से अधिक वर्ष लगेंगे। सवाल उठता है कि क्या भारतीय न्याय प्रणाली न्याय सुनिश्चित करती है?

यह कटु वास्तविकता न्याय में देरी के कारण न्याय न मिलने का स्पष्ट मामला है। भारतीय न्याय व्यवस्था की एक बानगी लंबित मुकदमों की संख्या है। लेकिन इस अन्याय के लिए जिम्मेदार कौन है? इससे जुड़े मुद्दे क्या हैं? क्या 21वीं सदी में ऐसा कुछ किया जा सकता है? क्या प्रौद्योगिकी और ज्ञान अर्थव्यवस्था ऐसे दयनीय परिदृश्य को सकारात्मक रूप से बदल सकती है? ये कुछ प्रासंगिक प्रश्न हैं जिन्हें पूछे जाने और समाधान किए जाने की आवश्यकता है।

भारतीय न्याय प्रणाली की इस दयनीय स्थिति के लिए जिम्मेदार कुछ प्रमुख कारणों में पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की अनुपलब्धता, सहायक अदालती कर्मचारियों की कमी और भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे की खराब स्थिति शामिल हैं। भारत में जनसंख्या के मुकाबले न्यायाधीशों का अनुपात दुनिया में सबसे कम है, यहां प्रति दस लाख लोगों पर 21 लोग हैं, जबकि अमेरिका में यह लगभग 150 है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, दशकों से भारत के नेताओं और अदालतों ने प्रति मिलियन लोगों पर 50 न्यायाधीशों का लक्ष्य रखा है। लेकिन अधिक न्यायाधीशों को नियुक्त करने, अदालती सुविधाओं में सुधार करने और प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के लिए कोई बड़ी धनराशि नहीं बढ़ाई गई है क्योंकि अधिकारी अन्य प्राथमिकताओं को अधिक महत्त्वपूर्ण मानते हैं।

एआई ऐसा डोमेन है जो मानवस्तरीय बुद्धिमत्ता वाली मशीनें विकसित करने और बुद्धिमानी से निर्णय लेने को स्वचालित करने के लिए जिम्मेदार है। एआई और संबंधित प्रौद्योगिकियों में भारतीय न्यायिक प्रणालियों को बदलने की क्षमता है। न्याय प्रणाली में दो महत्त्वपूर्ण पहलू शामिल हैं : स्वयं मामला और मामले को सुलझाने और उस विशेष मामले में न्याय देने की न्यायिक प्रक्रिया। प्रत्येक मामले में एआई कुशलतापूर्वक कार्य कर सकता है और न्याय वितरण के समय को काफी कम कर सकता है। कई प्रकार के मामले होते हैं, कुछ साधारण मामले जिनमें कानून के वस्तुनिष्ठ नियम और प्रावधान शामिल होते हैं, और कुछ जटिल मामले जहां व्यक्तिपरकता और व्याख्या शामिल होती है। उदाहरण के लिए, वित्तीय धोखाधड़ी, श्रम विवाद, ई-कॉमर्स मुद्दे, डोमेन नाम विवाद, या ऑनलाइन कॉपीराइट मुद्दे आदि से संबंधित मामलों को वस्तुनिष्ठ मामलों में रखा जा सकता है, और इसमें प्रत्यक्ष नियम-आधारित दृष्टिकोण शामिल हो सकता है जिसे एआई कुशलता से कर सकता है।

एआई क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डेटा एनालिटिक्स में न्यायिक प्रणालियों में उपलब्ध विशाल डेटा से गहरी अंतर्दृष्टि और पैटर्न प्राप्त करने की बड़ी क्षमता है जो न केवल तेजी से मामलों की सुनवाई के लिए अच्छा है, बल्कि समग्र रूप से न्याय प्रणालियों में सुधार के लिए भी अच्छा है।

कंप्यूटर विजन और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण में प्रगति के साथ संयुक्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) बुद्धिमान दस्तावेज असेंबली, केस पुनर्पाप्ति, केस वर्गीकरण, विवेकाधीन निर्णय लेने के लिए समर्थन और नये के विकास में सहायता करके न्यायिक प्रक्रिया प्रशासन के सुधार में सहायता कर सकती है। न्यायिक प्रक्रिया और मामलों को समझने और मॉडलिंग करने के लिए विश्लेषणात्मक उपकरण। एआई निर्णय समर्थन उपकरण न्यायिक अभ्यास में स्थिरता और दक्षता को प्रोत्साहित करने और स्वीकार्य न्यायिक विवेक के प्रयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए अपेक्षित है। अन्य न्यायिक कार्य, जैसे न्यायिक दस्तावेज़ लिखना, लचीलेपन, दक्षता और सटीकता से बहुत लाभान्वित होंगे जो ऐसी तकनीक को बढ़ावा देंगे।

भारत चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों और अनेक प्रकार की विविधता वाला विशाल राष्ट्र है। टेली लॉ सुविधाओं के साथ एआई-संचालित ऑनलाइन विवाद समाधान प्रणाली (ओडीआरएस) में व्यापक पैमाने पर कुशलतापूर्वक न्याय दिलाने की अपार क्षमता है। ओडीआरएस में अदालत और संबंधित वादकारियों की वास्तविक उपस्थिति की आवश्यकता को समाप्त करके ग्रामीण क्षेत्रों में क्रांति लाने की क्षमता है। एआई और उससे जुड़े डोमेन के विकास और विकास पथ को निवेश रुझानों से समझा जा सकता है। गोल्डमैन सैक्स रिसर्च के एआई विकास अनुमानों के अनुसार, एआई से संबंधित निवेश यूएस में सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 से 4% और अन्य प्रमुख एआई नेता देशों में सकल घरेलू उत्पाद का 1.5 से 2.5% तक पहुंच सकता है। भारत ने इंडिया एआई मिशन के लिए 10,300 करोड़ रुपये भी मंजूर किए हैं, जो भारतीय न्याय प्रणाली और इसके कुशल प्रशासन में एआई-संचालित नवाचार को बढ़ावा दे सकता है।

एआई सिस्टम और उनके निर्णयों के बारे में कुछ आशंकाएं हैं। निर्णयों में पारदर्शिता की कमी, डेटा की समावेशिता के मुद्दे, लेखांकन और एल्गोरिदम की व्याख्या, और कोडित पूर्वाग्रहों से संबंधित मुद्दे हैं। ऐसे मामलों में एआई को न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के लिए बुद्धिमान सहायक के रूप में माना जा सकता है, न कि अंतिम निर्णय और निर्णय लेने वाले अंतिम न्यायाधीश के रूप में। न्यायाधीशों की स्वतंत्रता और विवेकाधीन निर्णय को कम किए बिना एआई का अनुप्रयोग न्यायिक प्रणाली को कुशल, किफायती, पूर्वानुमानित और समावेशी बनाने में मदद करेगा जिससे सुनिश्चित होगा कि न्याय में देरी न हो और न्याय से इनकार न हो। ■

एआई सिस्टम और उनके निर्णयों के बारे में कुछ आशंकाएं हैं। निर्णयों में पारदर्शिता की कमी, डेटा की समावेशिता के मुद्दे, लेखांकन और एल्गोरिदम की व्याख्या, और कोडित पूर्वाग्रहों से संबंधित मुद्दे हैं। ऐसे मामलों में एआई को न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के लिए बुद्धिमान सहायक के रूप में माना जा सकता है, न कि अंतिम निर्णय और निर्णय लेने वाले अंतिम न्यायाधीश के रूप में। न्यायाधीशों की स्वतंत्रता और विवेकाधीन निर्णय को कम किए बिना एआई का अनुप्रयोग न्यायिक प्रणाली को कुशल, किफायती, पूर्वानुमानित और समावेशी बनाने में मदद करेगा

व्यंग्य विनोद कुमार विक्की

प से पैसेंजर, प से पेट्रोल

'प' वर्ण से बनने वाले शब्द प्रायः पब्लिक के लिए टेंशन देने वाले होते हैं। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान, पड़ोसी, पत्नी, पदाधिकारी, पनौती, प्याज, प्यार, प्राइवेटाइजेशन, परमाणु बम आदि। आज के प्रसंग में मैं भी प से बने पैसेंजर, पेट्रोल और प्राइवेट बस की चर्चा करने वाला हूं।

आर्यावर्त में मंहगाई दर अथवा मुद्रास्फीति हो, घोटाले हों, गर्मी का पारा हो, सर्दी का तापमान हो अथवा नेताजी का मिजाज, सभी तत्व परिस्थितिवश बढ़ते हैं। लेकिन एक समय के बाद घटते भी हैं। इस परिवर्तनशील युग में एक ऐसा भौतिक तत्व भी है, जो हमेशा बढ़ता ही रहा है। कभी किसी प्राणी ने घटते हुए नहीं सुना। शर्त लगा लो मियां चालीस साल का तजुर्बा है। गलत नहीं हो सकता। दरअसल, वह अद्भुत चीज प्राइवेट बस का किराया है। जब-जब डीजल-पेट्रोल के जलवे में चवन्नी से अठन्नी पैसे की बढ़ोतरी होती है तब-तब प्राइवेट बस के किराये में अनाकोंडा की तरह वृद्धि होती है। बस किराया वृद्धि का उत्सव लगभग हर तीसरे महीने मना ही लिया जाता है। भले ही व्यस्तता की वजह से आपने टेलीविजन पर समाचार न देखा हो। न ही सुबह-सुबह अखबार पढ़ पाए हों। भले ही कोई न्यूज आपसे मिस हो गई हो लेकिन एक न्यूज ऐसी होती है जिसके संदर्भ में आप यात्रा के दौरान ही अपडेट हो जाते हैं, और वो है पेट्रोल-डीजल की कीमत में उछाल की खबरें। बहुत ही गंभीरता के साथ बस कंडक्टर उस समय आपको इस समाचार से अवगत कराता है, जब आप बस का नियमित किराया उसे थमाते हैं।

'अरे सर पांच रुपये और दीजिए...।'

'क्यों भाई रोज तो इतना ही देते हैं?'

'कहां साहब! आप भी हड़प्पा युग में पड़े हुए हैं, पता नहीं आपको रात में फिर पेट्रोल-डीजल के दाम में चालीस पैसे की वृद्धि हो गई है...आग लगा दिया है इस सरकार ने पेट्रोल-डीजल के दाम में।' कहने का आशय है कि यदि पेट्रोल-डीजल की कीमत प्रति लीटर एक रुपये के अंदर हो तो आपको गंतव्य तक पहुंचने के लिए न्यूनतम पांच रुपये एवं वृद्धि दो रुपये तक हो न्यूनतम एक दसटकिया का अतिरिक्त भार किराये के रूप में व्यय करने का नैतिक पाठ अगले ही दिन बस कंडक्टर के द्वारा दे दी जाती है।

कीमत में चवन्नी की वृद्धि का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर किस रूप में पड़ता है यह तो आपको नहीं पता लेकिन आपके पर्स पर प्रतिकूल एवं प्राइवेट बस चालकों व मालिकों के आय पर अनुकूल प्रभाव देखने को मिल जाता है। हां, यदि आप जागरूक हैं, सशक्त हैं, और आपने चवन्नी से अठन्नी के वृद्धि पर किराये में होने वाली पांच से दस रुपए वृद्धि को लूट/डकैती आदि की संज्ञा दे दी तो फिर कंडक्टर आपको गाड़ी में पेट्रोल-डीजल की खपत के बारे में, चवन्नी की वृद्धि से गाड़ी में तेल भरवाने के दुष्प्रभाव पर इतनी लंबी थेसिस देने में लग जाएगा कि आप कीमत में चवन्नी एवं किराये में पंचटिकया वृद्धि के गणित को भूल जाएंगे। जिस प्रकार पत्नी के तेवर एवं पाकिस्तान का नेचर बदलने वाला नहीं, उसी प्रकार बस किराये पर पेट्रोल का प्रभाव (भले ही उसकी कीमत घट जाए) भी बदलने वाला नहीं। पेट्रोल-डीजल की कीमत में कमी पर यदि आप पुनः जागरूक और सशक्त उपभोक्ता की तरह कंडक्टर से पेट्रोल के घटे दाम पर किराये को कम देने की कोशिश करें तो कंडक्टर 'एकाध रुपये की मामूली कमी से क्या होता है सर' बोलकर बढ़ा हुआ किराया वसूल करने हेतु उसी प्रकार जबरन हील-हुज्जत करने लगता है, जिस प्रकार पत्नी ब्यूटी किट, पार्लर व शॉपिंग पर अतिरिक्त खर्च तथा पाकिस्तान पीओके और घुसपैठ के सवाल पर बहस करने में भिड़ जाता है। गीता के शाश्वत वचनों की तरह यह भी एक अटल सत्य है कि पेट्रोल-डीजल के कीमतों में मामूली वृद्धि प्राइवेट बस के किराए में भारी- भरकम वृद्धि के लिए जिम्मेदार तो होंगे किंतु बाद में पेट्रोल-डीजल के दाम में कमी कभी भी बढ़े हुए बस किराये को घटाने का कारण नहीं बनेगा। संभवतः श्री कृष्ण जी अर्जुन को यह ज्ञान देने में इसलिए चूक गए कि उस समय पेट्रोल-डीजल से रथ का परिचालन नहीं होता था। ■

पुस्तक समीक्षा राधेश्याम मंगोलपुरी

परदे से परदा उठाते किस्से

सिनेमा के जरिए स्वप्न और यथार्थ की दुनिया बनाने वाले लोगों की दुनिया और उनके जुनून को जानते-समझते यह लगा कि इस चमकीली दुनिया के भी अपने अंधेरे-उजाले हैं। उनकी कहानियां भी फिल्मों जैसी ही रोचक, अजूबा और मायावी हैं।'-अजय कुमार शर्मा (बॉलीवुड के अनकहे किस्से की 'भूमिका' से)।

बॉलीवुड के अनकहे किस्से किताब में तीन खंड हैं- 1. पुराने किस्से, 2. कैसे-कैसे किस्से, और 3. फिल्मों के किस्से। लेखक ने इन खंडों को 'अध्याय' कहा है-पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय। पहले अध्याय में कुल 35 किस्से हैं, दूसरे अध्याय में 18, और तीसरे अध्याय में किस्सों की कुल संख्या 12 है। इस तरह इस किताब में सब मिलाकर 65 किस्से हैं। हर किस्सा दो-दो पृष्ठों का है। हर किस्से के साथ दो-एक श्वेत-श्याम चित्र भी हैं। हर मूल किस्सा जैसे ही खत्म होता है, उसके साथ एक पुच्छला भी जुड़ा हुआ है जिसे नाम दिया गया है- चलते-चलते। इस 'चलते-चलते' में कोई चुटीली बात कुछ ही पंक्तियों में कही गई है, जो मूल किस्से को पाठक के मन में लंबे समय तक याद रखने में कुंजी का काम करती है।

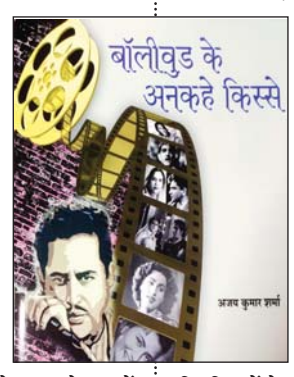

'कहानी चार महीने शादी की' शीर्षक के अंतर्गत प्रसिद्ध अभिनेता किशोर साहू के बारे में कई सारी सूचनाएं हैं। इसी के साथ यह भी कहा गया है कि स्नेहप्रभा प्रधान नई अभिनेत्री थीं। किशोर साहू और स्नेहप्रभा प्रधान ने 13 सितम्बर, 1940 को मुंबई के रजिस्टार ऑफिस में सिविल मैरिज कर ली। यह शादी सिर्फ4 महीने टिकी। तेरह जनवरी, 1941 को दोनों अलग हो गए। इस मूल किस्से के 'चलते.चलते' में अजय ने कुल इतना लिखा है- 'बाद में किशोर साहू का विवाह उनकी पूर्व प्रेमिका प्रीति कुमारी पांडे के साथ ही एक अक्टूबर, 1943 को हुआ। आर्य समाज विधि से संपन्न इस विवाह में प्रीति के परिवार से कोई शामिल नहीं हुआ था। दोनों के विवाह में मात्र 200 रुपये खर्च हुए थे। विवाह को अंजाम तक पहुंचाने में शांतिनिकेतन के अध्यापक गुरदयाल मलिक का महत्त्वपूर्ण योगदान था।'

पुराने किस्से के प्रसंग में अजय 'मदर इंडिया' की मां जद्दनबाई की बात की है। एक प्रोड्यूसर द्वारा पृथ्वीराज कपूर को चूना लगाने का किस्सा भी पुस्तक में है। यहां दहाड़ते सोहराब मोदी को याद किया गया है और बॉलीवुड की पहली पिनअप गर्ल बेगम पारा को भी। यहां केदार शर्मा को ईमानदारी पर कम पैसे की नौकरी की कहानी है तो दुर्गा खोटे की जिद में सीखी बांग्ला की भी चर्चा है। पहले भारतीय हॉलीवुड स्टार साबू का 'सौदा' (फिल्म) कैसे अधूरा रह गया, इसकी भी कथा लेखक ने लिखी है। जयराज के स्टंटमैन से सफल नायक और चरित्र अभिनेता तक के सफर का एक अलग ही किस्सा है। अजय कुमार शर्मा की किताब बॉलीवुड के अनकहे किस्से अपने अंदर हिन्दी सिनेमा के अनेकानेक राज समेटे हुए है।

पाठक जब इसके पन्नों से गुजरता है तो पता चलता है कि फिल्मों के मोहक दृश्यों में दिखने वाले अभिनेता-अभिनेत्रियां और परदे के पीछे काम करने वाले तमाम लोग-निर्देशक, कैमरामैन, गायक, गीतकार, संगीतकार आदि-भी साधारण जन की तरह ही अपनी जिंदगी में सफलता-असफलता से प्रभावित होते हैं। उनकी जिंदगी के भी प्रपंच हैं, बिडंबनाएं हैं, किंतु-परंतु हैं, आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उत्थान-पतन हैं।

किताब का नाम : बॉलीवुड के अनकहे किस्से।
मूल्य : 750/रुपये (हार्डबाउंड)
लेखक : अजय कुमार शर्मा
प्रकाशक : संघीस पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, लोनी (गाजियाबाद) ■

राग रंग आलोक पराड़कर

संगत के सम्मान का स्वाभिमान

देश भर के संगीत समारोहों में शिरकत करते हुए हमेशा यह बात महसूस की है कि इन समारोहों में मुख्यतः मुख्य कलाकारों की भूमिका ही महत्त्वपूर्ण होती है, आयोजक उन्हीं से पारिश्रमिक तय करते हैं, प्रायः उन्हीं के चित्र पोस्टर और निमंत्रण पत्र पर होते हैं, संगत के कलाकारों को लेकर आयोजकों का कोई विशेष आग्रह नहीं रहता है, इन्हें मुख्य कलाकारों की पसंद और सुविधा से ही तय किया जाता है, उनके पारिश्रमिक भी मुख्य कलाकारों के अनुपात में बहुत कम होते हैं जबकि किसी भी संगीत कार्यक्रम की सफलता में संगतकारों खासकर तबला वादक की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण होती है।

उस्ताद जाकिर हुसैन जैसे कुछ तबला वादकों को छोड़ दें तो ज्यादातर की प्रायः कोई शर्त भी नहीं होती और वे मुख्य कलाकारों द्वारा बनाई गईं शर्तों पर ही खुश हो लेते हैं। संगीत जगत के इस परिदृश्य में प्रख्यात तबला वादक पं. किशन महाराज की बहुत याद आती है, जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी इस वजह से विदेश के कार्यक्रमों के लिए मना कर दिया कि पोस्टर पर उनका चित्र मुख्य कलाकार से छोटा था, प्रख्यात सितार वादक पं. रविशंकर के साथ अपनी प्रसिद्ध जोड़ी इसलिए तोड़ ली कि वे विदेश के कार्यक्रमों में भी भारत के कार्यक्रमों के लिए तय पारिश्रमिक दे रहे थे, राजभवन के समारोह में इसलिए नाराज हो उठे कि वहां कलाकारों को जमीन पर बैठकर कार्यक्रम करना था और दर्शकों के लिए कुर्सियां लगी थीं। तीन सितम्बर को उनका 101वां जन्मदिवस है। इस मौके पर उनके शिष्य तबला वादक अरविंद आजाद अपनी संस्था 'तालायन म्यूजिक सर्किल' की ओर से पुणे में श्रद्धासुमन का आयोजन कर रहे हैं। महाराज की जन्मशताब्दी पर बनारस सहित देश में कई स्थानों पर समारोह आयोजित किए गए थे।

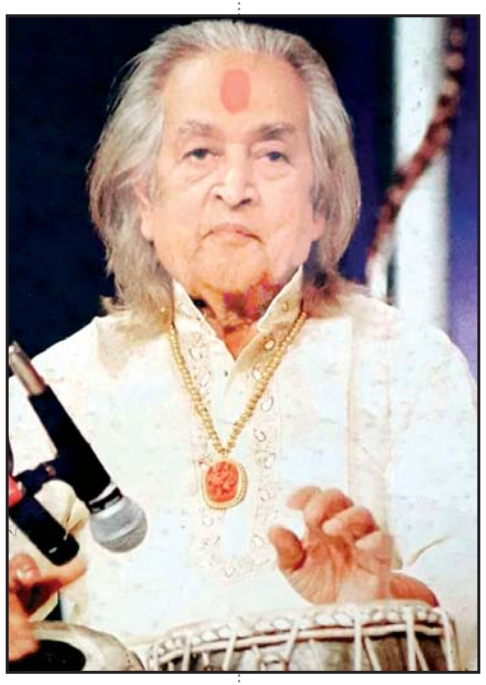

बताते हैं कि लखनऊ के गोलागंज में हैदरी खान नाम का कलाकार रहा करता था जिसने बादशाह गाजीउद्दीन हैदर को कह दिया था कि आपका क्या है, आप मर गए तो दूसरा तुरंत बादशाह बन जाएगा लेकिन अगर मैं मर गया तो फिर मुझ-सा हैदरी खान दूसरा पैदा नहीं होगा! बनारस कई रूपों में अपने संगीत कलाकारों में बसता है। बनारस के कई कलाकारों में जहां एक इत्मिनान, सुकून है, चैनदारी रही है, वहीं पं. किशन महाराज में एक बनारसी रौब और ठसक थी, पूरी दुनिया को ठेंगे पर समझने की फक्कड़ी थी। उन्होंने खूब बजाया, अपनी लयकारियों से दुनिया को अचरज में डाल दिया वहीं तबला वादक के सम्मान से समझौता नहीं किया, हमेशा तबला वादक को मुख्य कलाकार के बराबर का दर्जा दिए जाने की लड़ाई लड़ी, नुकसान भी उठाए लेकिन झुके नहीं।

महाराज जी ने खुद बताया था कि 1962-63 में राजस्थान के राजभवन में संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, महाराज ने देखा कि कलाकारों के कार्यक्रम के लिए जमीन पर कालीन बिछी हुई है, और दर्शकों के लिए कुर्सियां और सोफा सेट लगे हुए हैं। यह बात उन्हें बहुत नागवार गुजरी और राज्यपाल से शिकायत की गई जिसके बाद कुर्सियां और सोफे हटाकर लोगों के जमीन पर बैठने की व्यवस्था करने पर ही संगीत समारोह हो सका। ऐसी ही घटना बंगाल के राजभवन में भी हुई थी। पं. किशन महाराज और पं. रविशंकर की प्रसिद्ध जोड़ी के टूटने का कारण भी महाराज का स्वाभिमान ही था। येहूदी मेन्यूहिन के निमंत्रण पर दोनों कलाकारों को लंदन जाना था। इन कार्यक्रमों में ऐसी व्यवस्था थी कि मुख्य कलाकार के बराबर ही संगत कलाकार को भी पारिश्रमिक दिया जाना था लेकिन पं. रविशंकर ने किशन महाराज से कहा, 'देखो किशन हम तो भारत के हिसाब से ही पारिश्रमिक देंगे। किशन महाराज नाराज हो गए और यह जोड़ी टूट गई। पं. रविशंकर चतुर लाल को लेकर लंदन गए जो आकाशवाणी में काम करते थे। 1923 में कृष्ण जन्माष्टमी थी जब उनका जन्म हुआ। इसी कारण उनका नाम कृष्ण प्रसाद हुआ लेकिन मां के किशन बुलाने से वे किशन महाराज हो गए। बनारसी अक्खड़पन और स्वाभिमान उनमें हमेशा बना रहा, जिसे कई बार उनका अभिमान भी मान लिया जाता था। ललाट पर बड़ा-सा लाल टीका लगाए और अक्सर मंच पर बज़ासन में बैठने वाले महाराज के व्यक्तित्व से उनसे उम्र में छोटे कलाकार तो आक्रांत ही रहते थे।

कबीरचौरा की संकरी गलियों में वे जिस भव्यता से रहते थे, उस पर अक्सर लोगों को अचरज होता। उनके घर में लॉन था, कबूतरों और तमाम दूसरे पशु-पंछियों की जगहें थीं, तरह-तरह के फूल-पौधे थे और खूबसूरत ड्राइंगरूम था। नीचे विद्यार्थियों के अभ्यास की जगह थी तो ऊपर गणेश कक्ष था जहां गणेश की मृदंग बजाते हुए विशाल प्रतिमा है। इस कक्ष में संगीत की बैठकें होती रहीं। ■

कैनवस जय त्रिपाठी

रूपाकारों की संवेदनात्मक ध्वनि

जैसे-जैसे कला की दुनिया विकसित होती है, कलाकार, कला-चिंतक एवं कला से जुड़े व्यक्ति कला आलोचना-समालोचना अनुकूलन जारी रखते हैं। इससे समकालीन कला को गतिशील और बदलते स्वरूप में मूल्यवान अंतर्दृष्टि मिलती है। कला में आज पारंपरिक कला इतिहास के मानदंडों से मुक्त होने का प्रयास न केवल प्रत्येक तत्व के रूप का पता लगाते हैं, बल्कि मानव जाति के साथ उसके संबंध और प्रभाव को भी दर्शाते हैं। नई दिल्ली स्थित गैलरी एस्पेस में इन दिनों डॉ. पौला सेनगुप्ता की कलाकृतियों की प्रदर्शनी-'अ रिवर ऑफ अनरेस्ट...अ डेल्टा ऑफ ड्रीम्स'-प्रदर्शित है। पौला की एकल प्रदर्शनी को गैलरी स्पेस ने ही आयोजित किया है।

प्रदर्शनी में प्रवेश करते ही नजर उस ओर जाती है, जहां महिला कलाकार ने 'अ पैलेस ऑफ पोर्सलेन ऑन अ टॉवर ऑफ मड बाय द रीवर ऑफ अनरेस्ट' शीर्षक से अशांत नदी के बेचैन पानी का प्रतिबिंब रचते हुए आठ रेशम पैनलों की शृंखला प्रदर्शित की है। उनसे बात करने पर वह अपनी संवेदनात्मक सोच से नवाब की कहानी के बारे में विस्तार से क्रमबद्ध बताती हैं, जिसे उन्होंने प्रतीकात्मक और सपनों के विस्तृत डेल्टा के रूप में प्रदर्शित भी किया है। इसमें कलाकार ने नवाब वाजिद अली शाह और कोलकाता के पास हुगली तट पर मटियाबुर्ज ('मिट्टी का टॉवर') पर उनके चिड़ियाघर के साथ उनके दोहरे जुड़ाव से उत्पन्न कामों को एक समूह में दर्शाया है, जहां नवाब अपने जीवन के अंतिम तीन दशकों तक निर्वासन में रहे थे। इस बीच पौला की एक बात बहुत प्रासंगिक लगती है कि नवाब जानवरों के शौकीन थे, न कि उनसे प्यार करते थे।

कोलकाता में रह कर कलाकर्म करने वाली यह कलाकार कला के पारंपरिक दृश्य संदर्भ की तुलना में काफी स्वतंत्र भाव के साथ आकृतियां रचती हैं। समकालीन कलाकार के रेखांकन की सृजनात्मकता दृश्यमान जगत के रूप में मन से, मौन से, ध्यान से मूर्त को स्वरूप देती प्रतीत होती है। चित्रकार कागज की सतह पर जूट की रस्सी, चावल से बने कागज के गुदे और चावल के कागज पर स्याह आकृतियों को रूपों, रंगों और रेखाओं की दृश्य भाषा को मूर्त रूप में गढ़ती हैं। अपनी रेखाओं से मूर्तता की रचनाओं का जो निर्माण उन्होंने किया है, वे विविध हैं, बौद्धिकता को प्रतिबिंबित करते हैं। मूर्तता में चित्रण की वास्तविकता से प्रस्थान का संकेत देतीं रेखाओं की ध्वनि उनके मूक रेखाचित्रों में सुनी जा सकती है। जैव विविधता से समृद्ध सुंदरबन का डेल्टा परिदृश्य हो अथवा अलग-अलग कथाओं को जोड़ने वाले एनीमेशन, इंस्टॉलेशन, ड्राइंग आदि पौला के सोचने और विचारों को विकसित करने की रचनात्मक क्षमता को दर्शाते हैं एवं नये विचारों को विकसित करने की अनुमति देते हैं। उनकी एक कलाकृति के परिदृश्य में अवध से कलकत्ता तक नवाब की यात्रा की कहानी है, जो शाही लाल बजरे पर सवार होकर बहती नदी में तैरती है। नदी में बाघ, शेर, दरियाई घोड़ा, गैंडा, हिरण, मगरमच्छ, जिराफ, जेबरा आदि जानवर तैरते हैं। इसमें हुगली नदी के दो किनारों के अलग-अलग भूगोल का प्रतिनिधित्व करते नीचे सुंदरबन की भूरी, चिकनी मिट्टी से निकलने वाले मैंग्रोव वनों की जड़ों को रस्सी से दर्शाया गया है। कलाकार के दृश्यमूलक विचारों को ये केंद्रित करते हैं।

महिला रचनाकार की रचनात्मकता दूसरों से कुछ बेहतर करने के बारे में नहीं है, बल्कि सोचने, तलाशने, खोजने और कल्पना करने के बारे में है। एक छापा कलाकार (प्रिंट मेकर) होने के बावजूद पौला कलाकृति की रचना में गतिशील ऊर्जा को संचारित करने के लिए चित्रों आदि में विभिन्न माध्यमों और तकनीकों का उपयोग करती हैं, जिनमें कई मिली हुईं वस्तुएं, मलमल, वुडब्लॉक, रस्सी आदि के साथ-साथ चावल निर्मित कागज के गुदे और चावल के कागज का प्रयोग प्रेक्षक को खुले दिमाग और लीक से हटकर सोचने के लिए प्रेरित करता है। प्रतीत होता है कि इनकी कलात्मक सोच ने निस्संदेह दृश्य कला में सृजनात्मकता को संयोजन से गढ़ा है, जहां कला तत्व अपने आप को अनुमति दे रहे हैं कि किसे कहां रखना है कला में समकालीनता के प्रभाव को जानने-समझने वाली डॉ. पौला सेनगुप्ता कलाकार के साथ-साथ शिक्षाविद् भी हैं। विधिवत जानती-समझती हैं कि रचनाओं के अनगिनत रूप होते हैं। अपनी कृतियों में पौला ने अपने संवेदनशील विचारों को अधिक महत्त्व दिया है। इस लिहाज से वह कलाकृतियों की कलाकार ही नहीं, बल्कि सूत्रधार लगती हैं। 30 सितम्बर तक गैलरी एस्पेस में प्रदर्शनी का अवलोकन किया जा सकता है। प्रदर्शनी देखने पर पता चलता है कि पौला अपने विचारों एवं संवेदनाओं को रचनात्मक रेखांकन, शिल्प, एनीमेशन, इंस्टॉलेशन आदि के माध्यम से कलात्मकता के साथ गढ़ती हैं, और गढ़ते चलती हैं...। ■

https://t.me/AllNewsStonePaid

यूपी को मिली एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ और लखनऊ के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी

● सीएम योगी ने जताया पीएम का आभार, कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने तीन नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, जिसमें एक मेरठ से लखनऊ (चारबाग) के बीच चलेगी। प्रधानमंत्री के द्वारा यूपी के लोगों को दी गई इस सौगात पर सीएम योगी ने खुशी जाहिर की है। इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रदेशवासियों को इस उपहार के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया।

अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सीएम योगी ने लिखा, 'मेक इन इंडिया' एवं 'आत्मनिर्भर भारत' के स्वप्नद्रष्टा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी मार्गदर्शन में देश की आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास-यात्रा सतत जारी है। इस यात्रा को और गति देते हुए प्रधानमंत्री जी ने आज देशवासियों को 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने मेरठ-लखनऊ सहित मदुरै-बेंगलुरु, चेन्नई-नागरकोइल के मध्य अत्याधुनिक-विश्वस्तरीय वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया है। बेहतर कनेक्टिविटी के साथ ही पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देते इस उपहार के लिए आपका हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी। उल्लेखनीय है कि मेरठ और लखनऊ के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत से उत्तर प्रदेश की राजधानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ हाईस्पीड कनेक्टिविटी से जुड़ गई है। इससे माध्यम से प्रदेशवासियों को सुखद, सुगम और आरामदायक यात्रा का लाभ मिलेगा। प्रदेश में इससे पहले 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें संचालित की जा रही हैं। ये ट्रेनें दिल्ली-वाराणसी, रांची-वाराणसी, लखनऊ-देहरादून, पटना-लखनऊ, आनंद विहार-अयोध्या और गोरखपुर-प्रयागराज के बीच संचालित हो रही हैं। इसमें अब मेरठ-लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन भी जुड़ गई है। ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने से पूर्व पीएम मोदी ने कहा कि आज उत्तर से दक्षिण तक देश की विकास यात्रा में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज से मेरठ-लखनऊ के बीच वंदे भारत ट्रेन की सेवा शुरू हो रही है। इस विस्तार के साथ हमारा देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर कदम दर कदम बढ़ रहा है। आज जो तीन वंदे भारत ट्रेनें शुरू हुई हैं इनमें तीन महत्वपूर्ण शहरों की कनेक्टिविटी मिली है। इसमें मेरठ-लखनऊ रूट पर भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन संचालित की जा रही है। यह पश्चिम यूपी के लिए बड़ी खुशखबरी है। मेरठ और पश्चिमी यूपी क्रांति की धरती है। आज यह क्षेत्र विकास की नई क्रांति का साक्षी बन रहा है। मेरठ एक ओर आरआरटीएस के जरिए राजधानी दिल्ली से जुड़ रहा है दूसरी ओर इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से प्रदेश की राजधानी लखनऊ की दूरी भी कम हो गई है। आधुनिक ट्रेनें,एक्सप्रेसवे का नेटवर्क, हवाई सेवाओं का विस्तार, पीएम गति शक्ति का विजन कैसे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल रहा है, एनसीआर इसका उदाहरण बन रहा है।

सीएम योगी करेंगे एशिया के पहले राजगिद्ध संरक्षण केंद्र का उद्घाटन

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/ गोरखपुर

● गोरखपुर वन प्रभाग के कैम्पियरगंज रेंज में बना है जटायु संरक्षण व प्रजनन केंद्र

देश ही नहीं एशिया में राजगिद्ध (रेड हेडेड वल्चर) के संरक्षण के लिए गोरखपुर वन प्रभाग के कैम्पियरगंज रेंज में स्थापित 'जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र' का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इसके लिए 6 सितंबर की तिथि प्रस्तावित है। इस जटायु संरक्षण केंद्र का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री ने 7 अक्टूबर 2020 को किया था। जटायु संरक्षण केंद्र का उद्घाटन करने के बाद 6 सितंबर को ही मुख्यमंत्री स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित मानीराम क्षेत्र के सोनबरसा गांव में 634.66 करोड़ रुपये की पांच विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे।

राजगिद्ध जटायु की गाथा तो रामायण काल से ही सभी जानते हैं लेकिन पर्यावरणीय खतरे के चलते जटायु के वंशजों के अस्तित्व पर ही संकट आ गया। योगी सरकार ने इस संकट को दूर करने का संकल्प लिया है। राजगिद्ध के संरक्षण व संवर्धन के लिए गोरखपुर वन प्रभाग के कैम्पियरगंज (भारीवैसी) में जटायु संरक्षण व संवर्धन केंद्र बनाया गया है। इस केंद्र के जरिये राजगिद्धों की संख्या बढ़ेगी ही, विलुप्त होती प्रजातियों में शामिल इन जीवों को देखने के लिए सैलानियों की आमद बढ़ने से ईको टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना पर कुल 2 करोड़ 80 लाख 54 हजार रुपये की लागत आई है। इसमें ब्रीडिंग एवरी, होल्डिंग एवरी, हॉस्पिटल एवरी, नर्सरी एवरी, वेटनरी सेक्शन, प्रशासनिक भवन, रिकवरी एवरी, गार्डरूम, जेनरेटर रूम, पाथवे का निर्माण किया गया है। इस केंद्र में कुल 8 स्टाफ कार्यरत हैं। जटायु संरक्षण केंद्र में कुल 6 राजगिद्धों (नर एवं मादा) को लाया जा चुका है। यहां राजगिद्ध गिद्धों की निगरानी की सीसी कैमरों से की जाएगी। गोरखपुर के प्रभागीय वनाधिकारी (डीएफओ) विकास यादव के मुताबिक पांच हेक्टेयर जमीन पर बनाए गए इस केंद्र के लिए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी और प्रदेश सरकार के बीच में समझौता हुआ है। गोरखपुर वन प्रभाग द्वारा बनाई गई कार्ययोजना के अनुसार इस जटायु संरक्षण केंद्र से आगामी आठ-दस साल में 40 जोड़े राजगिद्ध छोड़े जाने का लक्ष्य है।

उपराष्ट्रपति करेंगे पूर्वी यूपी के पहले सैनिक स्कूल का लोकार्पण

● 7 सितंबर को प्रस्तावित है कार्यक्रम, राज्यपाल व मुख्यमंत्री भी रहेंगे उपस्थित

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/ गोरखपुर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक और पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले सैनिक स्कूल का लोकार्पण उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे। सैनिक स्कूल गोरखपुर के लोकार्पण के लिए 7 सितंबर की तारीख संभावित है। इस अवसर पर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल भी उपस्थित रहेंगी। लोकार्पण को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं।

गोरखपुर का सैनिक स्कूल खाद कारखाना परिसर में आवंटित 49 एकड़ भूमि पर बना है। 176 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले इस स्कूल का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 23 जुलाई 2021 को किया था। 'युवाओं को शिक्षा, देश की रक्षा' के ध्येय से इस शैक्षिक

प्रकल्प में कक्षा 6 से 12 तक बालक-बालिकाओं को आवासीय व्यवस्था के तहत शिक्षा प्रदान की जाने की व्यवस्था है। प्रवेश परीक्षा के जरिये कक्षा 6 और 9 में दाखिला लेने के बाद इस सैनिक स्कूल में पहली जुलाई से पढ़ाई शुरू हो चुकी है। प्रथम चरण में इस स्कूल में कक्षा 6 और 9 में 84-84 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है। इनमें कुल मिलाकर 40 छात्राएं और 128 छात्र हैं। यहां छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग कैंपस हैं। स्कूल का प्रशासनिक भवन प्राचीन भारतीय संस्कृति व परंपरा का दर्शन कराते है। सैनिक स्कूल के विद्यार्थियों के खेलकूद की गतिविधियों के लिए खेलों के कई कोर्ट व मैदान भी विकसित किए गए हैं।

गोरखपुर का सैनिक स्कूल सीएम योगी के दिल के बहुत करीब है। इसके शिलान्यास के बाद भी वह कई बार इसके निर्माण कार्यों का भौतिक निरीक्षण करने आते रहे हैं। उन्होंने सैनिक स्कूल का उपहार देकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के मेधावियों को सैन्य सेवाओं में जाने के लिए एक सशक्त प्लेटफार्म उपलब्ध कराया है। पूर्वी उत्तर के इस सैनिक स्कूल से सैन्य सेवाओं में अवसर के लिए क्षेत्रीय संतुलन को भी बढ़ावा मिलेगा।

सैनिक स्कूल का उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास कर उन्हें भारतीय सशस्त्र सेनाओं के अधिकारी वर्ग में चयन के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) के लिए तैयार करना होता है। सामान्य विद्यालयों से अलग संकल्पना वाले इस स्कूल में प्रवेश हेतु चयन प्रक्रिया में बच्चों की बौद्धिक क्षमता के साथ-साथ शारीरिक, मानसिक और चिकित्सकीय क्षमता का भी विशिष्ट रूप से आकलन किया जाता है। इसका पूरा पैटर्न सैन्योन्मुखी शिक्षा पर आधारित है। सैनिक स्कूल की समय सारिणी सेना में होने वाले प्रशिक्षण के अनुरूप होती है।

लापरवाही और भ्रष्टाचार में 28 चकबंदी अधिकारियों पर गिरी गाज

आठ मंडलों के अधिकारियों के खिलाफ की गई निलंबन, पद से हटाने, जवाब तलब और अनुशासनात्मक कार्रवाई

● बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी उप संचालक चकबंदी, सहायक चकबंदी, चकबंदीकर्ता और चकबंदी लेखपाल पर लिया गया एक्शन

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

पद के दुरुपयोग, काम में लापरवाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार का चाबुक लगातार जारी है। सीएम योगी के कड़े रुख के बाद चकबंदी विभाग में एक के बाद एक लापरवाह अधिकारियों पर गाज गिरने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में सीएम योगी के निर्देश पर चकबंदी संबंधी मामलों के निपटारे में लेटलतीफी, लापरवाही, अनियमितता पर आठ मंडल के दो दर्जन से अधिक चकबंदी अधिकारियों पर गाज गिरी है। इसमें 13 बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के खिलाफ निलंबन, जवाब-तलब और अनुशासनिक कार्रवाई की गयी है। वहीं एक उप संचालक चकबंदी अधिकारी को पद से हटाने के निर्देश दिये गये हैं, जबकि एक उप संचालक चकबंदी अधिकारी से लापरवाही पर जवाब तलब किया है। इसी तरह एक चकबंदी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई, एक सहायक चकबंदी अधिकारी का वेतन रोकने के साथ स्पष्टीकरण तलब किया गया है। इसके अलावा तीन सहायक चकबंदी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गयी। इतना ही नहीं एक सेवानिवृत्त सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा सेवाकाल में अनियमितता पर पेंशन में 20 प्रतिशत की कटौती का प्रस्ताव शासन को भेजा गया। इसके अलावा कई अन्य के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की गई। चकबंदी आयुक्त जीएस नवीन ने बताया कि सीएम योगी की मंशा के अनुरूप समय-समय पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए विभाग की समीक्षा बैठक की जाती है। इसी क्रम में हाल ही में समीक्षा बैठक में कई अधिकारियों के काम में लापरवाही, अनियमितता और भ्रष्टाचार में लिप्त गतिविधियां पायी गई। इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजी गयी, जिस पर सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिये गये। इसी क्रम में आठ मंडल प्रयागराज, वाराणसी, मीरजापुर, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या और देवीपाटन के चकबंदी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इनमें बरेली, हरदोई, ललितपुर, उन्नाव, चित्रकूट और जौनपुर के बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी क्रमशः पवन कुमार सिंह, श्रीप्रकाश चंद्र उत्तम, राकेश कुमार, सुरेश कुमार सागर, मनोहर लाल और स्वतंत्र वीर सिंह यादव को चकबंदी कार्यों में अपेक्षित प्रगति न होने पर जवाब तलब किया गया है। वहीं प्रतापगढ़ के उप संचालक चकबन्दी/ मुख्य राजस्व अधिकारी राकेश कुमार गुप्ता को पर्यवेक्षणीय दायित्व का निर्वहन न करने पर स्पष्टीकरण तलब किया गया है जबकि गोरखपुर के उप संचालक चकबन्दी अधिकारी राज नारायण त्रिपाठी को कार्य की प्रगति संबंधी सूचना न देने पर पद से हटाने के लिए नियुक्ति विभाग को पत्र लिखा गया है। वहीं सेवानिवृत्त सहायक चकबंदी अधिकारी रमेश पाल सिंह राणा द्वारा सेवाकाल में अनियमितता पर पेंशन में 20 प्रतिशत कटौती करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। राहत आयुक्त ने बताया कि कुशीनगर के बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी संतोष कुमार को कार्य में लापरवाही पर निलंबित कर दिया गया। साथ ही विभागीय कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखा गया है। इसके अलावा वाराणसी के बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी पवन कुमार सिद्धू को धारा-52 में लक्षित ग्राम अजगरा का कार्य पूर्ण न करने तथा स्थानान्तरित चकबन्दी लेखपालों को अवमुक्त न करने के कारण वेतन करने के साथ अनुशासनिक कार्यवाही की गयी। इसके साथ ही कार्य में शिथिलता पर शाहजहांपुर, मीरजापुर, गोरखपुर और देवरिया के बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी क्रमशः मोहन लाल तत्कालीन, नरेंद्र सिंह, शशिकांत शुक्ला और पवन पांडेय के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही की गई। यही नहीं कनौज के बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी धर्मेंद्र सिंह, बाराबंकी के चकबंदी अधिकारी शिव नारायन गुप्ता, बाराबंकी के कनिष्ठ सहायक उमाशंकर को जांच में अनियमितता पर अनुशासनिक कार्यवाही की गई। फतेहपुर के ग्राम ललौती का कार्य लक्ष्य के अनुसार पूर्ण न होने पर सहायक चकबंदी अधिकारी महेन्द्र सिंह का वेतन रोक दिया गया। साथ ही स्पष्टीकरण तलब किया गया है। इसी तरह बलरामपुर के सहायक चकबंदी अधिकारी संदीप यादव द्वारा ग्राम मस्जीदिया का कार्य पूर्ण न करने पर अनुशासनिक कार्यवाही की गयी। प्रयागराज के ग्राम राजेपुर सराय अरजानी और प्रतापगढ़ के ग्राम धीमी का कार्य लक्ष्य के अनुसार पूर्ण न होने पर संबंधित सहायक चकबन्दी अधिकारी को चिन्हित कर अनुशासनिक कार्यवाही की गयी।

नमामि गंगे के तहत यूपी के लिए 5 परियोजनाओं को मिली मंजूरी

● राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की 56वीं कार्यकारी समिति की बैठक में 73.39 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं को दी गई हरी झंडी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/ नई दिल्ली

उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के संरक्षण और सफाई के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही योगी सरकार के प्रयासों को एक और कामयाबी मिली है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की 56वीं कार्यकारी समिति की बैठक में उत्तर प्रदेश के लिए 73.39 करोड़ रुपए की लागत वाली 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण और सफाई के लिए कदम उठाना है। ये परियोजनाएं गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने और उसके इको-सिस्टम को सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। नमामि गंगे और आईआईटी बीएचयू के बीच संस्थागत ढांचे के तहत वाराणसी में स्मार्ट लैबोरेटरी फॉर क्लीन रिवर परियोजना के सचिवालय की स्थापना की जाएगी। यह परियोजना भारत में छोटी नदियों के कायाकल्प के लिए एक महत्वाकांक्षी और महत्त्वपूर्ण पहल है। इस तरह की परियोजना का उद्देश्य नदियों को उनके प्राकृतिक रूप में वापस लाना, जलस्रोतों की रक्षा करना और पर्यावरणीय संतुलन को बहाल करना है। इसमें विश्वव्यापी विशेषज्ञता और संधारणीय प्रथाओं का उपयोग करके पानी की गुणवत्ता में सुधार, जल प्रबंधन के स्थायी तरीके और स्थानीय समुदायों की भागीदारी जैसी गतिविधियां शामिल हैं। वहीं, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गुलावठी में एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य गंगा की सहायक पूर्वी काली नदी के प्रदूषण को रोकना है। इस परियोजना के अंतर्गत इंटरसेप्शन एवं डायवर्जन के साथ ही 10 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रति दिन) क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का भी निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 50.98 करोड़ रुपए है, जिसमें अगले 15 वर्षों के लिए रखरखाव और प्रबंधन भी शामिल है।

भाजपा लोकतंत्र को आघात पहुंचा रही: अखिलेश

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सत्ता का दुरुपयोग करके लोकतंत्र को आघात पहुंचा रही है। उपचुनाव में भी जनता को गुमराह कर रही है। सात साल की सरकार के दौरान मुख्यमंत्री ने जनहित में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया। जनता से किए वादों को पूरा नहीं किया। लोगों के साथ भेदभाव किया। विकास कार्य ठप्प है। भाजपा सरकार के पास जनता को बताने के लिए कोई काम नहीं है।

अखिलेश यादव शनिवार को समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय लखनऊ में डॉ. राममनोहर लोहिया सभागार में एकत्र कार्यकर्ताओं को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हार से भाजपा बौखलाई है। झूठ और लूट भाजपा का एजेण्डा है। सरकारी धन की लूट और झूठ बोलकर विरोधी दलों का बदनाम करने को भाजपा विकास समझती है। जनता भाजपा की चालों को समझ चुकी है। यादव ने कहा कि ख्यमंत्री जी और भाजपा के नेता बेतुकी बातें करते है। सभी राजनीतिक दलों के झंडे अलग-अलग रंगों के होते हैं। मुख्यमंत्री को लाल रंग से ऐतराज क्यों है? ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव में जनता ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में जिस तरह का भारी समर्थन जताया है और भाजपा की चुनाव में हार हुई है, इसलिए मुख्यमंत्री जी लाल रंग के प्रति दुर्भावना रखने लगे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की नीतियां पीडीए, किसान, नौजवान विरोधी है। पीडीए की एकजुटता से भाजपा घबराई हुई है। समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रही है। समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। समाजवादी पार्टी ने सरकार के समय गांव, गरीब, किसान और नौजवान के हित में तमाम फैसले लिए लेकिन भाजपा सरकार ने हर वर्ग को धोखा दिया है। भाजपा सरकार ने गांवों, किसानों की उपेक्षा की है। गांवों का विकास समाजवादी पार्टी ही कर सकती है। विकास भाजपा के बस की बात नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का सफाया करना एकमात्र लक्ष्य है। यह उत्तर प्रदेश की जनता के हित में हैं। भाजपा की नकारात्मक राजनीति ने प्रदेश का बहुत नुकसान किया है। इस नुकसान की भरपाई करने का काम समाजवादी सरकार की सकारात्मक नीतियां करेंगी।

सुशील पासी व शाहनवाज आलम बने एआईसीसी के सचिव

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सुशील पासी एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन शाहनवाज आलम को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सचिव बनाए जाने पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष प्रभारी प्रशासन दिनेश कुमार सिंह द्वारा उनका स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव सुशीला पासी एवं शाहनवाज आलम ने सर्वप्रथम कार्यालय प्रांगण में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न पं. जवाहर लाल नेहरू, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तथा चौराहे पर स्थित राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। तद्पश्चात प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष दिनेश सिंह ने नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव सुशील पासी तथा शाहनवाज आलम को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया तथा उन्हें मिठाई खिलाकर उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। स्वागत कार्यक्रम के उपरान्त नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव सुशील पासी तथा शाहनवाज आलम ने संयुक्त रूप से अपने सम्बोधन में कहा कि हम जैसे साधारण कार्यकर्ता की मेहनत एवं निष्ठा को देखते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हमें राष्ट्रीय सचिव बनाकर कार्य करने का अवसर प्रदान किया है इसके लिए हम मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी तथा राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का विशेष आभार व्यक्त करते हैं।

सीएम योगी ने पुलिस परीक्षा के सकुशल संपन्न होने पर दी अभ्यर्थियों को बधाई

लखनऊ। सीएम योगी ने यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के सकुशल संपन्न होने पर अभ्यर्थियों को बधाई दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,200 से अधिक पदों पर चयन के लिए आयोजित लिखित परीक्षा-2023 के निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने की सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई! परीक्षा में सहभागिता करने वाले सभी ऊर्जावान और अनुशासित युवाओं को मनोनुकूल परिणाम प्राप्त हों। सभी का भविष्य उज्ज्वल हो, इस हेतु अनंत मंगलकामनाएं! उन्होंने आगे लिखा कि विश्व की सबसे बड़ी सिविल पुलिस भर्ती परीक्षा को सफलतापूर्वक, सकुशल संपन्न कराने में सहयोगी सभी जनों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड और समस्त जनपदों के जिला प्रशासन को हृदय से धन्यवाद!

कड़ी सुरक्षा में सकुशल संपन्न हुई यूपी की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती परीक्षा

फूलप्रूफ प्लान को भेद नहीं पाया पेपर लीक और सॉल्वर गैंग

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उत्तर प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती परीक्षा आखिरकार शनिवार को सकुशल संपन्न हो गई। इस परीक्षा को संपन्न कराने के लिए योगी सरकार ने ऐसी पुख्ता तैयारी की, जो पूरे देश के लिए एक नजीर बन गई। परीक्षा को संपन्न कराने के लिए सरकार ने मैनपावर से लेकर एडवांस टेक्नोलॉजी तक का उपयोग किया।

परीक्षा केंद्र के अंदर और बाहर सुरक्षा के ऐसे कड़े इंतजाम रहे कि नकलची और सॉल्वर गैंग ने पूरी परीक्षा से ही दूरी बना ली। योगी सरकार ने पेपर लीक को लेकर परीक्षा से पहले जो कानून सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम-24 बनाया, उसका भी असर देखने को मिला। इसके अलावा यूपी पुलिस ने वॉट्सएप से लेकर सोशल मीडिया तक अपनी पैनी नजर बनाए रखी। खुफिया एजेंसियों को 24 घंटें अलर्ट मोड में रखा गया, ताकि कहीं कोई कमी न रह जाए। दो चरणों में 5 दिन तक चली इस परीक्षा में 32 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। इस दौरान योगी सरकार के अभूतपूर्व इंतजामों के बीच पारदर्शिता और शुचिता का भी पूरा ध्यान रखा गया। इसके लिए परीक्षा को सरकारी स्कूलों पर ही संपन्न कराया गया। परीक्षा के आयोजन में सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का पालन किया गया, जिससे परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा।

इसके लिए 2300 मजिस्ट्रेट और 1,97,859 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस सीसीटीवी का प्रयोग किया गया।

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का किया गया इस्तेमाल

सीएम योगी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए 1174 केंद्रों के 16,440 कमरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जो आर्टिफिशियल इंजेलिजेंस से आच्छादित थे। इससे हर परीक्षा कक्ष की गतिविधियां, जैसे कक्ष निरीक्षक का भ्रमण न करना आदि की सूचना रियल टाइम पर बोर्ड के कंट्रोल रूम में पहुंचती रही। वहीं कहीं कोई संदेह होने पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट को तत्काल जानकारी दी गयी। वहीं बोर्ड द्वारा परीक्षा से पहले ही 48 लाख से अधिक कैंडीडेट्स का आधार सत्यापन कराया गया। इसमें 85 प्रतिशत कैंडीडेट्स का आधार सत्यापित हुआ जबकि शेष 15 प्रतिशत कैंडीडेट्स का आधार सत्यापित न होने पर उन्हे ईकेवाईसी के लिए केंद्र पर परीक्षा से आधा घंटे पहले बुलाया गया।

परीक्षा केंद्रों पर तैनात किये गए 74 ऑब्जर्वर पुलिस अधिकारी

पुलिस भर्ती परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए 1,97,859 पुलिसकर्मियों और दो कंपनियों को तैनात किया गया। इसमें पीएसी की 25 और सीएपीएफ की 8 कंपनियों को तैनात किया गया। वहीं 137 अपर पुलिस अधीक्षक, 522 पुलिस उपाधीक्षक, 47,587 मुख्य आरक्षी, 86,844 आरक्षी और 26,582 महिला आरक्षी को तैनात किया गया। इसके अलावा 3876 निरीक्षक भी तैनात किये गये, जिसमें 3740 पुरुष और 136 महिला निरीक्षक शामिल हैं। इसके साथ ही 32,311 उपनिरीक्षक को तैनात किया गया। इसमें 30,220 पुरुष और 2091 महिला उपनिरीक्षक शामिल हैं। इतना ही नहीं परीक्षा केंद्रों पर 74 ऑब्जर्वर पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया।

इलेक्ट्रानिक गैजेट्स को निष्क्रिय करने के लिए लगाए गए जैमर

परीक्षा को पारदर्शी बनाने एवं सही अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के लिए तकनीक का प्रयोग किया गया। इसके लिए परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थियों की चैकिंग, फ्रिस्किंग एवं पर्यवेक्षण की उचित व्यवस्था की गई थी। केंद्र पर अभ्यर्थियों फिजिकल फ्रिस्किंग, एचएचएमडी द्वारा फ्रिस्किंग, बायोमैट्रिक फिंगर प्रिन्ट एवं फेशियल रिकॉग्निशन के बाद ही प्रवेश दिया गया। वहीं फेशियल रिकॉग्निशन न होने पर एफआरआईएस कैप्चर करने की भी व्यवस्था की गई। फेशियल रिकॉग्निशन में संशय होने पर अभ्यर्थी का आधार वेरिफिकेशन कराया गया। इसके अलावा सभी केन्द्रों पर इलेक्ट्रानिक डिवाइसेज जैसे मोबाइल, ब्लूटूथ को निष्क्रिय करने के लिये जैमर लगाए गए। परीक्षा कक्ष एवं केन्द्र में सीसीटीवी लगाकर निगरानी की गयी, जिसका लाइव फीड केन्द्र के कन्ट्रोल रूम, जनपद के कन्ट्रोल रूम एवं भर्ती बोर्ड मुख्यालय के कन्ट्रोल रूम में पहुंचता रहा। पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए 67 जिलों के जिन थाना क्षेत्रों में परीक्षा केन्द्र बनाये गये, वहां यूपी-112 पीआरवी के वाहनों के चार्ट में परीक्षा केन्द्र के आस-पास के महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया गया।

जनपदीय पर्यवेक्षक के रूप में डीएम को किया गया तैनात

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (यूपीपीआरपीबी) के अध्यक्ष राजीव कृष्णा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप परीक्षा के लिए विभिन्न प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों की तैनाती की गई। वहीं जनपद स्तर पर जिलाधिकारी जनपदीय पर्यवेक्षक (मजिस्ट्रेट) के रूप में तैनात रहे। उनके द्वारा परीक्षा केन्द्र ड्यूटी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती समेत अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाएं की गयीं। इसके तहत जिलाधिकारी द्वारा हर सेंटर पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ सहायक केंद्र पर्यवेक्षक की तैनाती की गई। इसके अलावा अपर जिलाधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी (प्रशासन) के रूप में नियुक्त किया गया जबकि 3 परीक्षा केंद्रों पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गयी। इतना ही नहीं नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए उड़ान दस्तों को मुस्तैद किया गया। वहीं केंद्र पर्यवेक्षक के रूप में पुलिस उपाधीक्षक से लेकर सब इंस्पेक्टर की तैनाती की गयी। प्रदेश के जिन सेंटर पर नौ सौ से अधिक अभ्यर्थी थे, वहां पुलिस उपाधीक्षक को तैनात किया गया। वहीं नौ सौ से कम अभ्यर्थी वाले सेंटर पर इंस्पेक्टर और सात सौ तक अभ्यर्थी वाले सेंटर पर सब इंस्पेक्टर को नियुक्त किया गया। परीक्षा की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा केन्द्र पर नियुक्त कर्मियों में से 50 प्रतिशत जिलाधिकारी और शेष 50 प्रतिशत केन्द्र व्यवस्थापक (प्रधानाचार्य) द्वारा नियुक्त किये गये।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

संयम संस्कृति का मूल है। विलासिता, निर्बलता और अनुकरण के वातावरण में संस्कृति का विकास नहीं होता।

– काका कालेलकर

दुविधा के दायरे

दूसरी नजर

पी चिदंबरम

केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी समेत सभी राजनीतिक दल और प्रदेशों के मुख्यमंत्री खुद को एक अजीब दुविधा की स्थिति में महसूस कर रहे हैं। यह दुविधा पेंशन के सवाल पर पैदा हुई है।

एक निश्चित आयु के बाद भारत के सभी नागरिकों को पेंशन नहीं मिलती। भारत में कोई भी सामाजिक सुरक्षा योजना नहीं है, जो नागरिकों को पेंशन प्रदान करती हो। निजी क्षेत्र में कार्यरत लाखों लोगों को सेवानिवृत्ति पर पेंशन नहीं मिलती। यहां तक कि भारतीय रक्षा बलों में 'शार्ट सर्विस कमीशन' अधिकारियों को भी पेंशन नहीं मिलती।

पेंशन पर बहस

जब तक जीवन प्रत्याशा कम थी, तब पेंशन का कोई महत्त्व नहीं था। कुछ लोगों को पेंशन मिलती थी, मगर सेवानिवृत्ति के बाद कम ही लोग लंबे समय तक जीवित रह पाते थे। 1947 में, जब भारत को आजादी मिली, तो जीवन प्रत्याशा 35 वर्ष से कम थी। आज, यह 70 वर्ष से थोड़ा अधिक है। इस तरह पेंशन की बाध्यता, सेवानिवृत्ति के बाद औसतन 10-12 वर्षों तक बनी रहेगी और अगर पारिवारिक पेंशन योजना लागू है, तो यह जीवनसाथी को भी जारी रह सकती है। यही कारण है कि अधिकतर नियोक्ता पेंशन को लेकर बहुत सावधान रहते हैं। मगर कर्मचारियों के पास एक जोरदार मुद्दा है: पेंशन लंबी और निष्ठावान सेवा के माध्यम से अर्जित एक 'अधिकार' है; या पेंशन एक 'विलंबित वेतन' है; या पेंशन सेवानिवृत्ति के बाद 'सम्मान के साथ जीने' के अधिकार का जरिया है।

सरकारी कर्मचारियों के मामले में, 'पेंशन के अधिकार' वाले तर्क ने बहस पर विजय हासिल कर ली, और यह फैसला उचित था। अब जिन्हें पेंशन का अधिकार प्राप्त नहीं है, उन्होंने उन वर्गों की ओर इशारा करते हुए मांग उठाई कि पेंशन का अधिकार उन्हें भी मिलना चाहिए। दरअसल, सभी वर्गों के लोगों के लिए एक सार्वभौमिक पेंशन योजना होनी चाहिए।

जैसे-जैसे सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना की जड़ें जमती गईं, एक सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन की अवधारणा ने भी जड़ें जमानी शुरू कर दी। यह विचार बना कि मूल वेतन और महंगाई भत्ते का पचास फीसद पेंशन के रूप में मिलना चाहिए।

अधिकतर राज्य सरकारों ने यूपीएस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। कांग्रेस सहित प्रमुख राजनीतिक दल यूपीएस पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। हालांकि, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के कई संघों और कई केंद्रीय कर्मचारी संघों ने पेंशन निधि में कर्मचारियों के अंशदान का विरोध किया है।

बदली हुई चाल

जनवरी 2004 में जब पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की जगह नई पेंशन योजना (एनपीएस) लागू हुई, तो उसने पेंशन के दोनों स्तंभों को हिलाकर रख दिया: इसने गैर-अंशदायी परिभाषित लाभ योजना को एक परिभाषित अंशदान योजना में बदल दिया और इसने चुपचाप न्यूनतम पेंशन की अवधारणा को परे कर दिया। विरोध शुरू हो गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस पर झुकना स्वीकार नहीं किया और उनके उत्तराधिकारी मनमोहन सिंह ने भी दस साल तक मैदान नहीं छोड़ा। इसी तरह, नरेंद्र मोदी ने दस साल तक वह जमीन नहीं छोड़ी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में आए नतीजों ने चाल को पूरी तरह से बदल दिया है।

तीन अगस्त, 2022 को पीआइबी की एक विज्ञप्ति के अनुसार, केंद्र सरकार के कुल पेंशनभोगियों की संख्या 69,76,240 थी। 2024-25 में पेंशन पर बजटीय व्यय 2,43,296 करोड़ रुपए है। मीडिया रपटों के अनुसार, मार्च 2023 तक, एनपीएस में केंद्र सरकार के 23.8 लाख लाभार्थी और राज्य सरकारों के 60.7 लाख लाभार्थी थे। 2024 में, यह संख्या थोड़ी अधिक या थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन हम इसके अनुमानित आंकड़े जानते हैं। यह भारत की जनसंख्या का एक अंश है।

एक अप्रदत्त पेंशन योजना- जिसे ओपीएस के रूप में जाना जाता है- अर्थव्यवस्था को वित्तीय रूप से बर्बाद कर देगी। सरकारें वर्तमान राजस्व से उसका 'भुगतान नहीं कर सकतीं'। किसी न किसी को इस योजना को वित्तपोषित करना पड़ेगा। यह काम या तो सरकार कर सकती है या कर्मचारी या फिर दोनों। एनपीएस एक ऐसी योजना है, जिसे सरकार (14 फीसद) और कर्मचारी (10 फीसद) दोनों द्वारा वित्तपोषित किया गया। 'वित्तपोषण' एक अच्छी आर्थिकी है।

सरकार द्वारा घोषित एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) एक ऐसी योजना है, जिसमें सरकार (18.5 फीसद) और कर्मचारी (10 फीसद) द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा। न्यूनतम दस हजार रुपए प्रतिमाह की पेंशन, जिसे महंगाई के अनुसार समायोजित किया जाएगा, का आश्वासन दिया गया है। इस पर विस्तृत जानकारी का इंतजार है।

इस लेख के लिखे जाने तक, अधिकतर राज्य सरकारों ने यूपीएस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। कांग्रेस सहित प्रमुख राजनीतिक दल यूपीएस पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। हालांकि, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के कई संघों और कई केंद्रीय कर्मचारी संघों ने पेंशन निधि में कर्मचारियों के अंशदान का विरोध किया है।

वित्तपोषण कौन और कैसे करेगा?

यह सरकारों, राजनीतिक दलों और कर्मचारी संघों के लिए बड़ी दुविधा का विषय है। विशुद्ध रूप से राजकोषीय स्वरूप पर सचेत दृष्टिकोण से बोलते हुए, यूपीएस को तुरंत खारिज नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, इस पर कुछ सवाल बने हुए हैं:

1. क्या कर्मचारी के अंशदान और सरकार के अंशदान के बीच का अंतर, जो अभी 8.5 फीसद है, भविष्य में और बढ़ जाएगा?
2. टीवी सोमनाथन ने कहा कि 'सरकार इस कमी को पूरा करेगी'। क्या यह 'अपनी क्षमता के मुताबिक भुगतान' से एक कदम दूर नहीं है?
3. जबकि 10+10 फीसद अंशदान स्वीकृत पेंशन निधि प्रबंधकों को सौंपा जाएगा। क्या 8.5 फीसद अंशदान का निवेश किया जाएगा और अगर हां, तो किसके द्वारा और कहां?
4. पहले वर्ष के लिए 6,250 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि कम बताई गई लगती है; क्या यह सच है?
5. क्या यूपीएस को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दिए जाने से पहले राज्य सरकारों से परामर्श किया गया था? क्या कर्मचारी संघ इसमें शामिल होंगे?

अब यह देखने की बात है कि हितधारक इस दुविधा से कैसे बाहर निकलते हैं।

सियासी शतरंज की चाल

वक्त की नब्ज

तवलीन सिंह

सियासी शतरंज में सफलता से चाल चलने के बारे में जितना नरेंद्र मोदी जानते हैं, शायद ही इस देश का कोई दूसरा राजनेता जानता होगा। इस बात को मानते हैं वे लोग भी जो मोदी के भक्त नहीं हैं। एक उदाहरण है वह हल्ला और हिंसा, जो कोलकाता में दिखा है पिछले दिनों। न्याय के लिए लड़ाई न रह कर अब पूरी तरह से पश्चिम बंगाल में राजनीतिक रोटियां सेंकने का काम हो रहा है। ये खेल खेला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के आला राजनेताओं के इशारे पर। कहने को तो पिछले हफ्ते वाला बंद स्थानीय नेताओं ने बुलाया था आरजी कर अस्पताल के उस डाक्टर के लिए न्याय दिलवाने के प्रयास में, लेकिन आपने भी देखा होगा कि बंद का नेतृत्व आम लोग नहीं, भाजपा के लोग कर रहे थे।

ऐसा नहीं है कि लोगों में उस बदनसीब डाक्टर के लिए हमदर्दी कम हुई है। ऐसा भी नहीं है कि लोग न्याय नहीं चाहते हैं। लेकिन यह भी जानते हैं हम कि न्याय की गाड़ी अब चल पड़ी है, इसलिए इसके बावजूद विरोध प्रदर्शन करना और बंद बुलाना सिर्फ ममता बनर्जी की सरकार को परेशान करने के लिए नहीं करवाए जा रहे हैं? असली मकसद जानना मुश्किल है, लेकिन एक बात साफ है और वह यह कि राष्ट्रीय स्तर पर इस घटना को उठाने में भाजपा का हाथ है। पिछले सप्ताह जब मैंने इस घटना पर राष्ट्रपति का बयान सुना कि 'बस बहुत हो गया है', तो जो शक था, यकीन में बदल गया! राष्ट्रपति के इस वक्तव्य को मैंने जब कोलकाता में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों से जोड़ा तो निष्कर्ष क्या यही निकला कि ममता की सरकार को गिराने के लिए आंदोलन शुरू हो गया है? भाजपा के कुछ प्रवक्ताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है। क्या इसलिए ही नहीं राष्ट्रपति को इस दर्दनाक हादसे में घसीटा गया है?

ममता दी या तो ये चाल समझी नहीं हैं या सोच-समझ कर इस चाल का जवाब दे रही हैं खुद हल्ला बोल कर। कह दिया है उन्होंने कि बंगाल में आग लगेगी तो उसका असर असम, ओड़ीशा, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों में भी दिखेगा। मैं उनके सलाहकारों में होती तो उनको सलाह जरूर देती कि इस तरह के भड़काऊ बयान देकर वे फंस रही हैं उस जाल में जो उनके लिए बिछाई जा रही है। ऐसे बयानों के बदले अगर शांति और संयम की बातें करतीं तो उनको ज्यादा लाभ मिलता। शायद उनकी सरकार बच जाती।

बंगाल में जो हो रहा है, अच्छा नहीं है, इसमें दो राय नहीं है। किसी सीमावर्ती राज्य में अशांति फैलाना भारत के हित में नहीं है। और इस वक्त जब बांग्लादेश में अराजकता फैली हुई है, तो ऐसा करने से अपने देश की सुरक्षा को सिर्फ नुकसान पहुंचाने का काम होगा। ममता बेशक उस किस्म की मुख्यमंत्री हैं, जो भाजपा के आला राजनेताओं को पसंद नहीं हैं।

बंगाल में जो हो रहा है, अच्छा नहीं है, इसमें दो राय नहीं है। किसी सीमावर्ती राज्य में अशांति फैलाना भारत के हित में नहीं है। और इस वक्त जब बांग्लादेश में अराजकता फैली हुई है तो ऐसा करने से अपने देश की सुरक्षा को सिर्फ नुकसान पहुंचाने का काम होगा। ममता बेशक उस किस्म की मुख्यमंत्री हैं, जो भाजपा के आला राजनेताओं को पसंद नहीं हैं। लेकिन बंगाल के लोगों ने कई बार साबित किया है कि उनको अपने मुख्यमंत्री में पूरा विश्वास है। लेकिन उनको क्यों नहीं याद रहता है कि ममता एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं? लोकसभा चुनावों में संदेशखाली को लेकर भाजपा ने खूब हल्ला मचाया था, इस उम्मीद से कि उनको ऐसा करने से चुनावी लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं हुआ। तृणमूल कांग्रेस को उनतीस सीटें मिलीं और भाजपा को केवल बारह। विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, तो अभी से अशांति फैला कर क्या हासिल होने वाला है?

सवाल मन में आया तो जवाब भी आ गया। नरेंद्र मोदी को हारने की आदत नहीं है। तो महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी का साथ 2019 वाले विधानसभा चुनावों के बाद छोड़ कर अपने आप को मुख्यमंत्री बनाया विपक्षी दलों के साथ मिलकर, तो मोदी और उनकी टीम फौरन हरकत में आ गई थी। याद कीजिए कैसे उन्होंने अजीत पवार को उप-मुख्यमंत्री बनाकर देवेंद्र फडणवीस को चालाकी से दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश की थी। आधी रात को राज्यपाल साहब को उठाकर शपथ दिलवाई गई। जब यह चाल नाकाम हुई तो उद्धव की सरकार गिराने की कोशिश शुरू हो गई थी। याद कीजिए किस नाटकीय तरीके से 2022 में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया था। उसके बाद पिछले साल एक चाल और चली गई और वह थी शरद पवार की पार्टी तोड़ने की।

महाराष्ट्र में भाजपा सरकार बन तो गई, लेकिन इसका खमियाजा पिछले लोकसभा चुनावों में भुगतना पड़ा था, जब भारतीय जनता पार्टी को चौदह सीटें खोनी पड़ी थीं। अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र में, लेकिन जो कभी मोदी का जादू यहां दिखता था, आज गायब है। जिस गांव में मैं रहती हूं, वहां कभी मोदी के नाम पर वोट पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती है महाराष्ट्र में, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा।

हमारे राजनेता अक्सर मतदाताओं को भोले और बेवकूफ समझते हैं। उनके सामने जब घुटने टेकते हैं या साष्टांग प्रणाम करने का नाटक करते हैं, तो जानते नहीं कि इस देश के आम आदमी को कितनी समझ है आजकल अपने वोट की शक्ति की। तो जब चुनी हुई राज्य सरकारें गिराई जाती हैं, दिल्ली में बैठे शासकों के इशारे पर लोगों को अच्छा नहीं लगता है इसलिए कि ऐसा करने से राज्य में कई विकास के काम रुक जाते हैं और अस्थिरता का माहौल बन जाता है, जिससे किसी को फायदा नहीं है। समस्या यह है कि हमारे राजनेता अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं और वही गलती करते रहते हैं जिनसे न सिर्फ उनका, बल्कि देश का नुकसान होता है। ऐसी गलती अब पश्चिम बंगाल में हो रही है।

हमारे समय में मिथक

संस्कृति

विनोद शाही

हमारे समय में सामान्य-जन के केंद्र में आ सकने की संभावनाएं जितनी गहरी होंगी, मिथकों में हमारी दिलचस्पी उतनी ही बढ़ती जाएगी। मिथक लोक-चित्त द्वारा देखे गए सामूहिक सपनों जैसे होते हैं। मिथकों में सामान्य समय के बजाय, युगबोधक समय का एक पूरा परिदृश्य दर्ज रहता है। किसी भी समय का सत्य, उस दौर की व्यवस्था द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व के दावों की छाया भर नहीं होता। वह बाहर हाशिये पर खड़े रह गए जनसमूहों की चेतना में निहित होता है, जो दमित होकर भी, मिथकों में अपनी अभिव्यक्ति को निरंतर खोजती रहती है।

व्यवस्थाएं इतिहास रचने का दावा करती हैं और अपने दावों को मजबूत करने के लिए 'व्यवस्थाओं की व्यवस्था' के रूप में संस्कृति के प्रतिनिधि रूपों को रचती-गढ़ती हैं। गोया, व्यवस्थाओं की पहुंच एक हद तक, इतिहास से लेकर संस्कृति तक देखी-आंकी जा सकती है; पर मिथक व्यवस्था की पहुंच से हमेशा परे रहते हैं। उन्हें रचने-गढ़ने का काम, सिवाय लोकचित्त के, और कोई नहीं करता। इसलिए मिथकों को समझने के लिए जरूरी होता है कि हम लोक और युग की संधि पर अपनी निगाह जमाएं।

मिथकों में युग-बोध को हिंसा-प्रतिहिंसा, आत्मरक्षा-अहिंसा के पैटर्न की तरह भी खोजा-पढ़ा जा सकता है। ऐसा करते हुए, दरअसल हम लोकचित्त की युगबोधक स्वप्न-कथाओं के रूबरू होते हैं। पर इनका मकसद दूसरा होता है। वे इशारों-इशारों में इतिहास और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने से जुड़े, सत्ता-व्यवस्थाओं के दावों का विखंडन भी किया करती हैं। मिथकों की अर्थ-बहुलता को आज हम इसलिए समझ पाने लायक हुए हैं, क्योंकि इस मामले पर स्वप्न-मनोविज्ञान और समाजशास्त्र की गहरी निगाह पड़ी है। जनेतिहास लिखने के आधे-अधूरे प्रयासों की इस संदर्भ में जो भूमिका है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसके अलावा गहराई में उतर गए कबीलाई समाजों के मानव वैज्ञानिक अध्ययनों ने भी हमारी बहुत मदद की है। मौजूदा उत्तर-आधुनिक विमर्शों ने अब इन अध्ययनों को 'ज्ञान के सत्ताविमर्श और सत्ता के ज्ञान विमर्श' की तरह ग्रहण कर, हमें एक नई दृष्टि दी है। इसने हमें 'सत्ता-व्यवस्थाओं' के दावों के निहितार्थों को समझने लायक बनाया है। इस तरह अब हम सत्ता के हाशियों पर छिटके पड़े रह गए लोकचित्त के सपनों और उसकी वैकल्पिक-व्यवस्था को भी कुछ-कुछ समझने लगे हैं।

दरअसल, ज्ञान और सत्य की खोज के असल हेतु, उस समय और समाज में होते हैं, जो उस खोज को प्रेरित करता है। किसी भी दौर में ज्ञान और सत्य को समझने-परखने की कसौटियां और जरूरतें वर्तमान से ही उपजती हैं। इसलिए पहला सवाल है कि हम हिंसा और प्रतिहिंसा के तौर-तरीकों, नक्शों की तलाश में, मिथकों तक का सफर क्यों करें? इसलिए कि हमारे समय के वैज्ञानिक कार्य-कारणवादी तर्क और उनसे उपजी विमर्श बहुलता, ठीक से इस बात की व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। वे हमें यह नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर क्यों हमारे समय में राज्य हिंसा के सांस्थानिक और रूपों को जायज बनाया जाता है। ऐसा करते-करते वे जनविरोधी और जनदमनकारी चरित्र वाले होते जाते हैं? ऐसी हिंसाओं को जायज करार दिए जाने वाले युद्धों का मुकाबला करने के लिए बहुत से जनसमूह आखिर क्यों आत्मघाती या आतंकी और फिदायीन प्रतिहिंसाओं की शरण में चले जाते हैं? और हिंसाओं- प्रतिहिंसाओं के तमाम आपसी तर्कपूर्ण रिश्तों को तोड़ते हुए, आखिर क्यों अनेक दफा जन-असंतोष, व्यापक विनाश करने वाले दंगों की तरह भड़क कर, अतार्किक-प्रतिहिंसाओं की हद तक चला जाता है?

आधुनिक काल में मिथकीय चेतना का अंतर्विकास, ज्यादातर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, भारत की आजादी के लिए जद्दोजहद करने के तहत हुआ। उस दौर के अनेक नौजवानों की ऐसी कथाएं हमें मालूम हैं, जिन्होंने अपनी जेबों में भगवद्गीता या कुरआन शरीफ की प्रतियां रखकर फांसी के फंदे चूमने में किसी तरह के खौफ को अपने नजदीक नहीं आने दिया। किसी मिथकीय स्वप्न-कथा के पात्रों की हैसियत से, जीवन जीने की कोशिश करते इस तरह के लोगों के मनोविज्ञान को समझना जरूरी है। वे लोकचित्त में पनप रही उस कुंठा या बीमारी से ग्रस्त दिखाई देते हैं, जिसके लिए सत्ता-व्यवस्था का दमन-चक्र, सीधे जिम्मेवार होता है।

इस तरह हम यह देख सकते हैं कि अलग-अलग समय में प्रकट होने

आधुनिक काल में मिथकीय चेतना का अंतर्विकास, ज्यादातर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, भारत की आजादी के लिए जद्दोजहद करने के तहत हुआ। उस दौर के अनेक नौजवानों की ऐसी कथाएं हमें मालूम हैं, जिन्होंने अपनी जेबों में भगवद्गीता या कुरआन शरीफ की प्रतियां रखकर फांसी के फंदे चूमने में किसी तरह के खौफ को अपने नजदीक नहीं आने दिया।

वाले अलग तरह के युगगत हालात, मनुष्यों के नए आचरणों के जरिए, अपने भीतर मौजूद मिथकीय चेतना का भी अंतर्विकास या विरूपन करते हैं। लोकचित्त द्वारा मिथक, हर दौर में, अपनी जरूरतों के मुताबिक, नई शक्लों और नई परिस्थितियों तक में ढलकर नए होते रहते हैं। पर यह काम सजग रूप में नहीं होता। न ही कोई साहित्यिक कृति अचानक लिखी जाकर किसी मिथक को नए सांचे में ढाल सकती है।

साहित्यिक कृतियां, केवल युगगत हालात की तब्दीलियों में नई शक्ल ले रहे मिथकों को जुबान और थोड़ी तराश भर दिया करती हैं। इस तरह वे मिथकों की विकसनशील जीवंतता को सजग रूप प्रदान कर, उनकी अंतर्रचना में हमसफर और सहभागी हो सकती हैं। पर, यह रचनाशीलता, हर युग-स्थिति में विधायक ही नहीं होती। कई दफा कुंठा, विकृति या बीमारी के लक्षण गहरा जाने पर मिथकीय रचनाशीलता भी गुमराह होकर उल्टे और भी विनाशकारी नतीजे लाने का हेतु हो सकती है। इससे स्पष्ट है कि आधुनिक-उत्तराधुनिक काल में हमारे लोक और जग के क्षेत्र का जितना विस्तार हो रहा है, उतना ही मिथकों के अधिकाधिक गहन अध्ययन की जरूरत बढ़ती जाती है। लगता है कि मिथक मानवजाति का जिस रूप में सभ्यताकरण करना चाहते हैं, वह प्रक्रिया अभी अधूरी है।

सुलगाने वाले, बुझाने वाले

बाखबर

सुधीश पचौरी

अपनी राजनीति का यही मजा है कि एक बोलता है, तो तुरंत दूसरा उसकी बोलती बंद करने के चक्कर में रहता है। एक चैनल ने जातियां गिनाईं कि भारत में कोई चार लाख और साठ हजार जातियां-उपजातियां हैं। यानी एक रोटी के चार लाख साठ हजार टुकड़े। अब सर जी ही बताएं कि किसका कितना पेट भरेगा, कितना रहेगा खाली और कैसे बताओगे कि किसकी कितनी हिस्सेदारी, किसकी कितनी संख्या भारी और कौन करेगा कमाई। बहसें भी बेशर्म हैं, जिनमें हरेक दूसरे से कहता रहा कि पहले तुम गणना कराओ कि तुम कराओ। फिर आई एक तुकबंद चेतावनी कि 'बटेंगे तो कटेंगे... एकता में टिकेंगे... एक रहोगे, सुरक्षित रहोगे... एक रहोगे तो नेक रहोगे... सनातन राष्ट्रीय धर्म है... बांग्लादेश को देख लो..!' यह वाणी गूंजी ही थी कि शुरू हुई चैनल पर एक ओर 'तौबा तौबा' तो दूसरी ओर कि ये तो राष्ट्र की एकता का आह्वान है।

एक शाम एक चैनल ने अपने सर्वे में प्रधानमंत्री की 'लोकप्रियता' को कुछ गिरता दिखाया, तो दूसरे ने अपने सर्वे में कुछ उठता दिखाया! चैनलों के भी अपने-अपने प्रधानमंत्री हो गए! फिर खबर आई कि महाराष्ट्र में आई तेज आंधी-बरसात के दौरान कुछ महीने पहले लगी शिवाजी की मूर्ति अचानक गिर गई और राजनीति गरम। एक कहिन कि शिवाजी का शाप लगेगा। फिर टूटने पर होने लगी माफी-माफी। प्रधानमंत्री तक ने मांगी माफी कि शिवाजी हमारे भगवान हैं। जांच करेंगे। दोषियों को सजा देंगे।

फिर खबर में आया कोलकाता में सामूहिक बलात्कार की शिकार मृतका डाक्टर के लिए 'हमें न्याय चाहिए' नारे के साथ 'नवान्न' तक 'विरोध प्रदर्शन' और बदले में मिलता पुलिस का दमन। 'डंडों', 'गैस गोलों' और 'पानी की बौछारों' वाला 'न्याय'। बहुत से घायल और बेहोश। फिर शाम की बहसों में प्रवक्ता बरक्स प्रवक्ताओं के बीच वैसे ही दोषारोपण... कि ये सरकार के खिलाफ साजिश, कि बंगाल की औरतों पर अत्याचार क्यों? राज्यपाल चिंतित! राष्ट्रपति चिंतित! कई चर्चक देते ज्ञान कि केंद्र कुछ करता क्यों नहीं, कि राष्ट्रपति शासन लागू हो..!

फिर आया बयान कि बंगाल को जलाने की साजिश हो रही है... बंगाल जलेगा तो ये राज्य जलेगा, वो जलेगा..! हम आपकी कुर्सी गिरा देंगे। फिर आया एक पूरक बयान कि ये लड़ाई उन्होंने शुरू की है, खत्म मैं करूंगा... मैं आंदोलन दिल्ली तक ले जाउंगा..! हम तो कहेंगे कि जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू... बोलो ओम शांतिः शांतिः शांतिः! एक एंकर बोला कि विचारों में हिंसा है। एक प्रवक्ता कहिन कि उन्होंने शासन करने का अधिकार खो दिया है, वे फासीवादी तरीके से लोगों का दमन कर रही हैं। बहरहाल, शाम की बहसों में 'आग' सुलगती रही, जिसे कुछ एंकर बुझाते रहे। कुछ 'अर्थविज्ञानी' कहते रहे कि 'जलाने' नहीं, 'जलेगा' कहा। फिर कई राज्यों के प्रवक्ता भी धमकी के जवाब में धमकी दिए कि हमारे राज्य के बारे में कैसे बोला कैसे बोला। लेकिन वाह रे योगी जी कि इतने घमासान के बीच भी एक नए डिजिटल मीडिया कानून का एलान कर दिए, जिसके अनुसार अब से सोशल मीडिया में आते अभद्र, अश्लील, राष्ट्रविरोधी, आपत्तिजनक टिप्पणियां आदि सब बंद! विपक्षी कहें कि ये फासीवाद है!

शाम की बहसों में 'आग' सुलगती रही, जिसे कुछ एंकर बुझाते रहे। कुछ 'अर्थविज्ञानी' कहते रहे कि 'जलाने' नहीं, 'जलेगा' कहा। फिर कई राज्यों के प्रवक्ता भी धमकी के जवाब में धमकी दिए कि हमारे राज्य के बारे में कैसे बोला कैसे बोला।

इसके बाद आया एक चैनल पर विपक्ष के एक बड़े नेता का 'जिउ-जित्सु' जैसी 'मार्शल आर्ट' सिखाने वाला 'डोजो प्लान'। साथ ही 'जिउ-जित्सु' के 'दर्शन' सहित 'डेमो वीडियो', जिसमें बताया गया कि वे इसके 'ब्लैक बेल्ट' हैं। वीडियो में वे दूसरे 'जिउ-जित्सु' लड़ाके को कई तरह से पटकते रहे। फिर बताया कि यह 'डोजो प्लान' युवाओं को 'जिउ-जित्सु मार्शल आर्ट' में 'प्रशिक्षित' करेगा। ये 'गेम' बड़ा 'ऊर्जादायक' है। एक एंकर बताती रही कि 'राष्ट्रीय खेल दिवस' के दिन इधर शुरू हुआ भाजपा का नया राष्ट्रीय सदस्यता अभियान तो उधर शुरू हुआ 'डोजो प्लान'! चर्चा में एक विपक्षी प्रवक्ता ने टिप्पणी की कि ये 'डोजो' नहीं 'डोज' प्लान है, जबकि भाजपा का सदस्यता अभियान अधिकाधिक सदस्य बनाने के लिए है। इसी क्रम में एक बहस में एक प्रवक्ता ने कटाक्ष किया कि भाजपा बूढ़ों की जमात है, जबकि 'कांग्रेस-इंडिया' युवाओं की जमात है।

एक दिन किसान आंदोलन को लेकर भाजपा सांसद कंगना का बयान आया और राजनीति गरमा गई। भाजपा ने तुरंत उससे अपना पल्ला झाड़ा। फिर आया पंजाब के एक बुजुर्ग सांसद का कंगना के खिलाफ विवादित बयान। इस गर्हित 'लैंगिक' और 'स्त्रीद्वेषी' कुंठा पर कई एंकर, चर्चक देर तक बरसते रहे कि कंगना के बारे में ऐसा कहने वाले पर कार्रवाई हो, लेकिन इस 'स्त्रीद्वेष' के भी कुछ पक्षधर मैदान में, कि न वे वैसा बोलतीं, न ऐसा सुनतीं।

https://t.me/Allnewspaperspdf

www.readwhere.com

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्

भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

संस्थापक: शहीद शिरोमणि लाला जगतनारायण जी, अमर शहीद रमेश चन्द्र जी एवं वरुण के योद्धा अश्विनी कुमार जी

धर्म परिवर्तन करने वालों के आरक्षण का मुद्दा

भारत देश में आरक्षण का मसला बहुत ही विवादित है। आरक्षण की आग में कई बार देश झुलस चुका है। इसके बावजूद आरक्षण के मसले पर जमकर सियासत होती रही है। आरक्षण ऐसा प्याला है जो हर जाति के लोग उसे होठों से छू लेना चाहते हैं जैसे उसमें अमृत भरा हो। इस आरक्षण के प्याले ने कई बार इतना जहर फैलाया है जिसने समाज को तोड़ने का काम किया है। यह देश आरक्षण की मांग को लेकर जबरदस्त हिंसक आंदोलनों का चश्मदीद रहा है। केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्यमंत्री तोखन साहू ने अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को लेकर बयान दिया है जिसको लेकर एक बार फिर चर्चा छिड़ गई है। तोखन साहू ने कहा है कि धर्म परिवर्तन करने वालों को एसटी कैटेगरी का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इससे पहले भी कई हिन्दू संगठन धर्म परिवर्तन के बावजूद आरक्षण का लाभ लेने वालों का मुद्दा उठाते रहे हैं। मंत्री महोदय का कहना है कि "हिंदू धर्म में कभी धर्म परिवर्तन की बात नहीं की जाती। हम सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हमने कभी किसी को धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं कहा लेकिन कांग्रेस ने हमेशा वोट बैंक की राजनीति के लिए धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दिया है। धर्म परिवर्तन करने वालों को उस (एसटी) समुदाय का लाभ क्यों मिलना चाहिए? जो लोग किसी विशेष समुदाय में हैं, उन्हें डॉ. बीआर अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के अनुसार उस समुदाय का लाभ मिलना चाहिए ताकि सभी वर्गों को लाभ मिल सके।"

धर्म परिवर्तन करने वालों को उस (एसटी) समुदाय का लाभ क्यों मिलना चाहिए? जो लोग किसी विशेष समुदाय में हैं, उन्हें डॉ. बीआर अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के अनुसार उस समुदाय का लाभ मिलना चाहिए ताकि सभी वर्गों को लाभ मिल सके।" उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस का नारा था न जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर लेकिन अब कांग्रेस ने इस नारे को नकार दिया है। अनुसूचित जाति के वह लोग हैं जो इस देश की सामाजिक व्यवस्था में पीड़ित रहे। उन्हें बरसों तक प्रताड़ित किया जाता रहा। उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण की कल्पना की गई थी।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस का नारा था न जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर लेकिन अब कांग्रेस ने इस नारे को नकार दिया है। अनुसूचित जाति के वह लोग हैं जो इस देश की सामाजिक व्यवस्था में पीड़ित रहे। उन्हें बरसों तक प्रताड़ित किया जाता रहा। उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण की कल्पना की गई थी। अनुसूचित जाति में आरक्षण इसलिए नहीं दिया जाता कि वह गरीब है या पिछड़े हैं बल्कि इसलिए दिया जाता है कि वह उच्च जातियों की प्रताड़ना का शिकार हुए। अंत: हमें हर वर्ग के आरक्षण का मूल उद्देश्य समझना होगा। मुस्लिम और ईसाइयों को इसमें आरक्षण नहीं है। क्योंकि इनमें जाति प्रथा और छुआछूत नहीं है। इनमें जातियां व्यावहारिक रूप से तो हो सकती हैं लेकिन सैद्धांतिक रूप से नहीं। इसमें केवल हिन्दू, सिख और बौद्ध ही शामिल हैं। ईसाई और मुस्लिम धर्मों में छुआछूत भी नहीं है।

अब सवाल यह है कि क्या धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम और ईसाई बनने वालों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए या नहीं। एक तरफ यह तर्क दिया जाता है कि ईसाई या इस्लामी समाज के लोगों को कभी भी इस तरह के पिछड़ेपन या उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ा है। वास्तव में अनुसूचित जाति के लोग ईसाई या इस्लाम धर्म में परिवर्तित ही इसलिए होते हैं ताकि वो छुआछूत जैसी दमनकारी व्यवस्था से बाहर आ सकें। वहीं बौद्ध और सिख धर्म को इसमें शामिल करने को इसलिए सही ठहराया जाता है क्योंकि धर्मांतरण की प्रकृति ईसाई और मुस्लिम धर्म से अलग है। अनुसूचित जनजाति यानि आदिवासियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है क्योंकि आदिवासी किसी भी धर्म का हो सकता है। इसलिए इसमें धर्म की दीवार नहीं है। ईसाई और मुस्लिम भी एसटी हो सकते हैं। इन दो वर्गों के अलावा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों को ओबीसी में लिया गया है। जहां भी धर्म बीच में नहीं आता यानि ओबीसी किसी भी धर्म का मुस्लिम और ईसाई भी हो सकता है। दूसरी तरफ तर्क यह है कि क्या ईसाई धर्म या इस्लाम धर्म में कोई ऐसा कैमिकल है कि सिर के ऊपर डालते ही सामाजिक कलंक खत्म हो जाएगा। क्या ऐसा सोचा जा रहा है कि जो हिन्दू है उसका समाज सिर्फ हिन्दुओं से मिलकर बना है, जो ईसाई है उसका समाज सिर्फ ईसाई धर्म के लोग हैं और मुसलमानों का समाज सिर्फ मुस्लिमों से है। भारत में अनेक तरह के धर्म और जातियां हैं जिनसे समाज बना हुआ है। भारत की विविधता में एकता ही मुख्य खासियत है।

सवाल यह भी है कि क्या दलितों के धर्म परिवर्तन करने के बाद मतांतरित व्यक्तियों का समाज फूल मालाएं डालकर स्वागत करने लगता है। जो लोग दलितों को छोटा समझते थे उनके ईसाई होते ही क्या उनसे यह कहा जाता है कि अब हम और तुम बराबर हो गए। धर्मांतरण के बाद भी सामाजिक कलंक बना ही रहता है। आरक्षण तो नव बौद्धों को भी दिया जाता है। यानि जो एससी थे और हिन्दू धर्म छोड़कर बौद्ध बन गए। उसी तरह सिखों में भी जो पहले एससी थे और बाद में सिख धर्म अपना लिया, उनको भी आरक्षण दिया जाता है। अब आरक्षण के मुद्दे पर राष्ट्रव्यापी बहस छिड़ गई है। आरक्षण के मसले पर बार-बार यही कहा जाता रहा है कि जातियों के नाम पर समाज को न बांटा जाए बल्कि आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए। जो लोग गरीब और पिछड़े हुए हैं उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। सवाल आदिवासियों का भी है जो अभी भी जल, जंगल और जमीन के सहारे रहते हैं। जिन आदिवासियों ने ईसाई धर्म स्वीकार किया है उनका क्या होगा। बेहतर यही होगा कि संविधान के अनुरूप आरक्षण की व्यवस्था की जाए या फिर आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए।

आदित्य नारायण चोपड़ा
Adityachopra@punjabkesari.com

तुच्छ लोगों ने बेटियों की आबरू को...

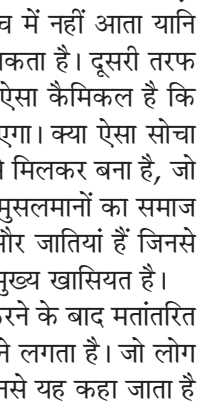

कैसे कहूं कि उस सितम ने किस हद तक उस पर कहर ढाया है,
दिखे हैं घाव हमें उसके शरीर पर,
पर उसकी आत्मा पर लगी चोट का दर्द कोई समझ नहीं पाया है,
किसी के गंदे हाथों ने उसके शरीर को दागदार बनाया है,
पर शर्मशार है हम ये देखकर कि कुछ तुच्छ लोगों ने बेटियों
की आबरू को भी राजनीतिक मुद्दा बनाया है।।

-गीता पाढा

चुनावी अखाड़े में उतरने को तैयार पहलवान

'सच मानो मेरी रफ्तार का यकीं शायद
हवाओं को भी न हो पाएगा
चल पड़ेंगे मेरे कदम जिस तरफ उस
ओर ही आंधियों का शोर होगा'

यूं तो खेलों का कोई एक रंग नहीं होता, बस राष्ट्रीयता की डोर में बंधा देश प्रेम के जज्बे का एक शर्तिया ऐलान होता है। दिल्ली के निज़ाम के नाको तले जब देश की बहादुर पहलवान बेटियों के साथ अन्याय हुआ तो उन्होंने जनतंत्र के विरोध प्रदर्शन के सबसे बड़े रिंग जंतर-मंतर को भी अपने हुंकार से चित्त कर दिया। अब कांग्रेस हरियाणा के इस हालिया विधानसभा चुनाव के चुनावी अखाड़े में कुछ सचमुच के पहलवानों को उतारने का इरादा रखती है। इसके लिए बाकायदा प्रदेश में कांग्रेस के सिरमौर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक रोड मैप तैयार किया है।

पहले कांग्रेस का इरादा विनेश फोगाट को भिवानी-महेंद्रगढ़ की किसी सीट से मैदान में उतारने का था पर विनेश से जुड़े विश्वस्त सूत्र खुलासा करते हैं कि विनेश अभी अपने पहलवानी कैरियर की इतिश्री नहीं चाहती, सो इस बार वह चुनाव लड़ने से हिचक रही है, चुनांचे देश का मान बढ़ाने वाली इस जीवट पहलवान से कहा गया है कि 'अगर वह चाहे तो पार्टी उन्हें राज्यसभा के रास्ते भी ऊपरी सदन में भेज सकती हैं।' भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध की पहली दुंदुभि फूंकने वाली साक्षी मलिक से कहा गया है कि 'अगले लोकसभा चुनाव में उन्हें सोनीपत लोकसभा सीट से चुनाव लड़वाया जा सकता है', वैसे भी सोनीपत एक ऐसी सीट है जहां मलिक वोटरों का दबदबा है, इस बार के चुनाव में ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया को झज्जर की बादली सीट से मैदान में उतारा जा सकता है, जो कि एक जाट बाहुल्य सीट है और पूनिया इसी क्षेत्र से आते हैं और स्वयं भी जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं।

बिन राहुल सब सून

बीआरएस प्रमुख व तेलांगना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव अपनी चुनावी हार से उबर कर विपक्षी एकता का नया अलख जगाने के लिए मेढ़क में एक बड़ी रैली प्लॉन कर रहे थे। इस रैली में शामिल होने के लिए उन्होंने बाकायदा ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, तेजस्वी यादव, शरद पवार जैसे विपक्षी धुरंधरों को मना भी लिया था। पर जैसे ही यह प्रस्ताव सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के पास पहुंचा उन्होंने इस आइडिया को सिरे से नकार दिया।

अखिलेश का तर्क था कि 'आज आपके प्रदेश यानी तेलांगना में कांग्रेस की सरकार है, सो कहीं न कहीं यह रैली भी कांग्रेस के खिलाफ अलख जगाने की शुरूआत होगी, हमें अपने उद्बोधनों में कांग्रेस पर भी निशाना साधना होगा, जबकि आज का सबसे बड़ा सच यही है कि कांग्रेस मौजूदा दौर में एक सशक्त विपक्ष की भूमिका मजबूती से निभा रही है और हमारी जैसी पार्टियां भी कंधे से कंधा मिला कर संसद व संसद के बाहर

कांग्रेस का साथ दे रही हैं, हमारे राज्यों में कांग्रेस हमारी गठबंधन साथी है, राहुल गांधी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं। ऐसे में हम राहुल जी के साथ दगा करने की सोच नहीं सकते। सो, बेहतर होगा आप ऐसी किसी रैली की प्लानिंग 2-3 साल बाद करें, फिलहाल इस रैली के आइडिया को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।

रंग चंपई में मुरझाते भगवा चेहरे

कोई चालीस साल तक आदिवासियों के हक की बात कहने वाले चंपई सोरेन भी आखिरकार अब भाजपाई हो गए हैं। हेमंत सोरेन व उनकी झारखंड मुक्ति मोर्चा को शायद चंपई के बेवफा हो जाने से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा हो, पर चंपई के नए घर में उनके आने से कोहराम मचा है। भाजपा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी चंपई की एंट्री से सबसे ज्यादा परेशान बताए जाते हैं। परेशान तो अर्जुन मुंडा भी हैं,

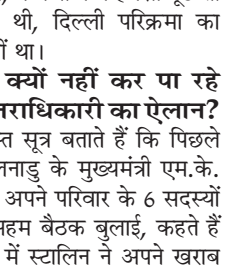

पर उनके लिए राहत की सांसें भी हैं क्योंकि अब तलक वे अकेले ही बाबूलाल के निशाने पर थे। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह अब भी आश्वस्त नज़र आता है कि 'झारखंड में अगली सरकार भगवा होगी।'

भाजपा ने इस चुनाव को भी एक तरह 'आदिवासी' बनाम 'गैर आदिवासी' मुद्दों पर केंद्रित कर दिया है। सो, सीएम पद पर अब तक सबसे बड़ा दावा बाबूलाल का ही माना जा रहा था पर अर्जुन मुंडा भी चुपचाप रिंग में उतर आए हैं। मुंडा 2024 का चुनाव खूंटी से हार गए थे, बावजूद इसके वे इस बार का विधानसभा चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। अब चंपई सोरेन के भाजपा ज्वॉइन कर लेने के बाद मरांडी करीबियों को लग रहा है कि उनकी छोटी सी पार्टी ही ठीक थी, कम से कम हमेशा पूछ तो बनी रहती थी, दिल्ली परिक्रमा का चक्कर नहीं था।

स्टालिन क्यों नहीं कर पा रहे अपने उत्तराधिकारी का ऐलान?

विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि पिछले दिनों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने अपने परिवार के 6 सदस्यों की एक अहम बैठक बुलाई, कहते हैं इस बैठक में स्टालिन ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए सरकार में

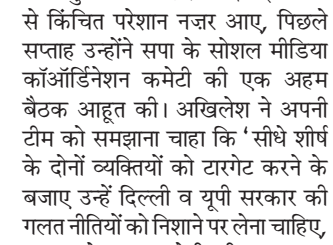

मंत्री अपने बेटे उदयानिधि स्टालिन को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने की इच्छा जताई। इस पर परिवार के बाकी सदस्यों की राय थी कि अभी उनका यह कदम उठाना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि उनके इस घोषणा से उनके भाई अझागिरी पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है और वे पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, इससे पार्टी का काफी नुकसान हो सकता है। स्टालिन ने इस विचार पर मंथन के लिए थोड़ा वक्त मांगा है।

मोदी-शाह के लिए नरम पड़ते अखिलेश

पिछले कुछ समय से सपा के सोशल मीडिया के निशाने पर सीधे पीएम मोदी व शाह आ गए हैं। खटाखट तीर छोड़े जा रहे हैं, तीखे निशाने साधे जा रहे हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव इस बात से किंचित परेशान नज़र आए, पिछले सप्ताह उन्होंने सपा के सोशल मीडिया कॉऑर्डिनेशन कमेटी की एक अहम बैठक आहूत की। अखिलेश ने अपनी टीम को समझाना चाहा कि 'सीधे शीर्ष के दोनों व्यक्तियों को टारगेट करने के बजाए उन्हें दिल्ली व यूपी सरकार की गलत नीतियों को निशाने पर लेना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा योगी जी पर हमला बोलना चाहिए'। इस पर अखिलेश की टीम का कहना था कि 'पर भाजपा की डिजिटल आर्मी तो सीधे उन्हें यानी अखिलेश को ही निशाने पर लेती है तो फिर वे क्यों उदारता दिखाएं'? इस पर अखिलेश ने अपनी टीम को समझाना चाहा कि 'यूपी चुनाव में अभी पूरे 2 साल का वक्त बाकी है, हमें पूरा यकीन है प्रदेश में अगली सरकार हमारी ही होगी, ऐसे में दिल्ली को ज्यादा छेड़ना ठीक नहीं रहेगा।' अखिलेश की सोशल मीडिया टीम ने एक गहरी चुप्पी साध ली, इसके निहितार्थ से सपा सुप्रीमो बखूबी वाकिफ थे।

...और अंत में

गांधी परिवार में काम का बंटवारा अघोषित तौर पर ही हो जाता है। राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका के सियासी खूबियों व महत्वाकांक्षाओं को बखूबी समझते हैं। सो, बिना कहे ही प्रियंका के लिए वे एक रोड मैप तैयार रखते हैं। जैसे इस दफे जम्मू-कश्मीर व हरियाणा में विधानसभा के चुनाव साथ-साथ हो रहे हैं, तो राहुल ने अपने कोर ग्रुप को

संकेत दे दिया है कि 'वे इस बार जम्मू-कश्मीर में ज्यादा सक्रिय रहेंगे तो प्रियंका हरियाणा के मसलों को हेंडल करेंगी'। ऐसा पहले भी हो चुका है जब प्रियंका ने राजस्थान के साथ हिमाचल में अपनी सक्रियता दिखाई थी, तो राहुल ने छत्तीसगढ़ और कुछ हद तक मध्य प्रदेश पर अपना फोकस रखा था। (एनटीआई)

रेप हत्याकांड : जिम्मेदारी तो लेनी होगी

यह समझ पाना कठिन है कि ममता बनर्जी कोलकाता के एक प्रमुख अस्पताल में एक युवा जूनियर डॉक्टर के साथ हुए जघन्य बलात्कार और हत्या के मामले में अपनी घोर लापरवाही के लिए भारी राजनीतिक कीमत चुकाने से कैसे बच सकती हैं। दिल्ली में 2012 के निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले की तरह ही, इस 9 अगस्त की रात को आरजी कर अस्पताल में हुए बर्बर अपराध पर जनता के आक्रोश को जितना अधिक ममता बनर्जी सरकार नियंत्रित करने की कोशिश करती है, उतना ही वह उनके खिलाफ पलटवार करती है।

निर्भया कांड के समय कांग्रेस पार्टी केंद्र और दिल्ली सरकार, दोनों में सत्ता में थी। दिल्ली की सड़कों पर चलती निजी बस में एक युवा पैरामेडिकल छात्रा के साथ हुए सामूहिक बलात्कार के बाद हुए सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन को ठीक से न संभाल पाने के कारण दोनों ने अपनी जबरदस्त राजनीतिक साख खो दी थी और इसके बाद हुए चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों में सत्ता भी गंवा दी। ममता की हताशा पिछले सप्ताह तब दिखी, जब उन्होंने धमकी दी कि यदि बंगाल जलेगा तो वे अन्य राज्यों में भी आग लगा देंगी।

इस जघन्य अत्याचार के खिलाफ जनता के गुस्से को नियंत्रित करना उनके लिए मुश्किल हो गया है, क्योंकि राज्य में चिकित्सा कर्मियों और आम नागरिकों द्वारा वास्तविक व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए हैं, हालांकि ये सभी विरोध प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित नहीं थे। कोलकाता में छात्र समूह 'छात्र समाज' द्वारा क्रूरतापूर्वक हत्या किए गए डॉक्टर के लिए न्याय की मांग को लेकर आयोजित रैली से वे काफी परेशान हो गईं। इससे पता चला कि राज्य सरकार लोकतांत्रिक राजनीति में विरोध की अभिव्यक्ति को अत्यधिक बल के प्रयोग से दबाने के लिए किस हद तक जा सकती है।

नबन्ना भवन के आसपास मीलों तक का पूरा क्षेत्र पुलिस किले में तब्दील हो गया था। फिर भी, दृढ़ निश्चयी और क्रोधित प्रदर्शनकारियों ने कई स्थानों पर पुलिस के साथ झड़प की, तथा अवरोधकों को तोड़कर राज्य सचिवालय भवन की ओर भागने का प्रयास किया। उनके पास कोई नेता नहीं था। न ही उन्हें किसी नेता की जरूरत थी, यह जघन्य अपराध के खिलाफ सार्वभौमिक आक्रोश था, और ममता सरकार द्वारा इसकी भयावहता को नकारने का

कायराना प्रयास था। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ पुलिस की सख्ती के कारण विपक्षी भाजपा ने एक दिन बाद कोलकाता में 12 घंटे के बंद का आह्वान किया।

लेकिन लोगों के आक्रोश को शांत करने के लिए कदम उठाने के बजाय ममता ने टकराव जारी रखा और कहा कि इस सबके पीछे भाजपा का हाथ है। ममता ने अपनी पार्टी की छात्र इकाई को संबोधित करते हुए धमकी भरे अंदाज में चेतावनी दी कि अगर बंगाल में आग लगेगी तो असम, बिहार, मणिपुर और ओडिशा भी इससे नहीं बचेगा और यह आग दिल्ली तक भी पहुंच जाएगी। शाफ्ट कार्ड खेलते हुए सीएम ममता ने दावा किया कि भाजपा अपराध का फायदा उठाकर उनकी सरकार को अस्थिर करना चाहती है। बता दें कि यह वही ममता हैं जिन्होंने इस साल की शुरुआत में मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की थी जब प्रदर्शनकारी किसानों को लुटियन दिल्ली पहुंचने से रोक दिया गया था। उन्होंने उस समय विरोध करने के लोकतांत्रिक अधिकार की बात की थी। लेकिन अपने मामले में वह कोलकाता के एक प्रमुख अस्पताल में अपनी निगरानी में हुए भयानक अपराध के बावजूद लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को कैसे भूल गई हैं। इससे जूनियर डॉक्टर के वीभत्स बलात्कार और हत्या से निपटने में उनका अहंकार और सत्तावाद साफ झलकता है।

हालात ये हैं कि मामले से निपटने की आलोचना करने वाली पूर्व टीएमसी सांसद मिमी चक्रवरी को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। ममता के भतीजे और चुने हुए राजनीतिक उत्तराधिकारी अभिषेक बनर्जी का प्रयास भी कम कायरतापूर्ण नहीं था, जिन्होंने अपराध को कम करके आंकने की कोशिश करते हुए कहा कि देश में प्रतिदिन लगभग 90 बलात्कार होते हैं। हालांकि इस मामले में जांच को गलत दिशा देने में सत्ताधारी पार्टी पर काफी आरोप भी लग रहे हैं।

उधर मामले में आरोपी संजय रॉय को भयावह अपराध के कुछ घंटों बाद ही पुलिस बैरक से गिरफ्तार कर लिया गया, जो एक वेतनभोगी स्वयंसेवक नागरिक है। वह लोगों से जबरन वसूली करने के लिए भी जाना जाता था और अक्सर अस्पताल आने वाली असहाय महिला मरीजों को इसका शिकार बनाता था। क्योंकि वह कोलकाता में शक्तिशाली टीएमसी नेताओं के साथ अच्छी तरह मिला हुआ था और ऐसे दिखावा करता था मानो वह वास्तव में पुलिस के लिए काम करता हो।

जेआर मीडिया इंस्टीट्यूट का ओरिएंटेशन डे

अभी दो दिन पहले की बात है कि हमारी पंजाब केसरी के अंतर्गत कार्यरत जे.आर. मीडिया इंस्टीट्यूट जो हमारे संस्थापक अमर शहीद लाला जगत नारायण और शहीद शिरोमणि सम्पादक श्री रमेश जी के नाम पर जगत नारायण, रमेश चन्द्र सोसाइटी के रूप में गठित है और पत्रकारिता को समर्पित है, के ओरिएंटेशन के मौके पर मैं भी उपस्थित थी। स्टूडेंट्स की पहले ही दिन हमारे इंस्टीट्यूट में एक-दूसरे से और स्टाफ से इंट्रोडक्शन हो जाए इसलिए यह समारोह आयोजित किया गया था। मेरे पुत्र अर्जुन चोपड़ा जो पंजाब केसरी के डायरेक्टर होने के साथ-साथ जे.आर. मीडिया इंस्टीट्यूट को भी संचालित करने की जिम्मेवारी निभा रहे हैं, भी उपस्थित थे। उन्होंने स्टूडेंट्स से सवाल किया और बातों ही बातों में पूछा कि आखिर वह क्या बात है जिसने उन्हें पत्रकारिता के इस कॉलेज में आने के लिए प्रेरित किया। उनकी सहजता भरे अंदाज पर और सवाल पर कई छात्र-छात्राओं ने बड़े भावुक होकर जवाब दिए लेकिन एक छात्र ने पूरे माहौल को भावुक बना दिया। उसने कहा कि वह यूपी से आया है और सिर्फ पत्रकार बनने के लिए ही आया है। उसकी आवाज, अंदाज और तेवर में पत्रकार बनने की ललक थी। उसने जवाब दिया कि मेरे पिताजी बहुत बीमार थे, अस्पताल में उनका ऑपरेशन होना था। डाक्टर इंकार कर रहे थे तो एक पत्रकार ने ही उनको अस्पताल में एडमिट करवाया और ऑपरेशन करवाया। इस छात्र के दिलो दिमाग में बैठ गया कि एक पत्रकार में वह ताकत है कि वह सब कुछ कर सकता है और कलम के दम पर सब कुछ करवा सकता है। हालांकि मैं जे.आर. मीडिया इंस्टीट्यूट की चेयरपर्सन हूं फिर भी मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि पत्रकारिता कोई ग्लैमर नहीं बल्कि कुछ कर दिखाने का जज्बा है।

हमारे यहां हर नए स्टूडैंट्स का स्वागत है क्योंकि हमारा अपना यूट्यूब चैनल सक्रिय है, जिसमें सैकड़ों युवा एंकरिंग व एडिटिंग तथा रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हमारा तो पत्रकारिता के मिशन में बलिदानों से भरा इतिहास रहा है। निष्काम पत्रकारिता करना एक ऐसा पेशा है जिसे चलाना बहुत कठिन है। बच्चों के अपने सपने हैं। पत्रकारिता के प्रति अपना-अपना दृष्टिकोण है। सब स्टूडेंट्स का अपना-अपना नजरिया था। कईयों का मस्ती भरा अंदाज भी था लेकिन मेरा यह मानना है कि पत्रकारिता के लिए, पत्रकार बनने के लिए एक जज्बा होना चाहिए और मुझे खुद उसकी यह बात बड़ी प्रेरणादायी लगी। क्योंकि मैं वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब जो बुजुर्गों के सम्मान के लिए गठित है तथा मैं स्वयं इसकी चेयरपर्सन हूं, इसलिए हम उनकी सेवा करते हैं। यह परोपकार है। स्टूडेंट्स में संस्कार देना व सेवा भाव बनाए रखना यह भी जरूरी है, इसलिए भी जेआर मीडिया एक आधुनिक इंस्टीट्यूट तथा संस्कार समर्पित मिशन भी है।

दरअसल हमारा जे.आर. मीडिया इंस्टीट्यूट इसलिए स्थापित हुआ कि हम अपने समाचार पत्र को चलाने के लिए एक ऐसी पीढ़ी तैयार करें जो पहले जर्नलिज्म की तकनीकी और बेसिक चीजें सीख लें इसीलिए इस इंस्टीट्यूट से जुड़े सभी लोग न सिर्फ प्रोफेशनल हैं बल्कि पंजाब केसरी की मजबूत कड़ी भी हैं। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि अर्जुन चोपड़ा ने बच्चों को इस मस्ती भरे माहौल के बीच उनके अंदर के जज्बात को बाहर निकालने के लिए प्रेरित किया। यह बात अलग है कि हमारी पंजाब केसरी और जे. आर. मीडिया इंस्टीट्यूट की टीम में नया और पुराना खून एक साथ मिलकर काम करता है। फिर भी मैं बारहवीं और ग्रेजुएशन पास करने वाले अगले कदम में कौन सी स्ट्रीम लें इसे लेकर हमारे पास बीजेएमसी, बीबीए जैसे डिग्री कोर्स हैं तो वहीं रिपोर्टिंग, एंकरिंग, एडीटिंग, फोटोग्राफी, डीजिटल मार्केटिंग जैसे अनेकों कोर्स हैं जो बेहद प्रोफेशनल हैं और करियर संवारने की दिशा में अग्रसर हैं। करियर को लेकर मेरा दावा है कि नए स्टूडेंट्स बेफिक्र रहें क्योंकि अनेक छात्र-छात्राएं डिग्री कोर्स पास करने के बाद देश के नामी-गिरामी चैनलों व मीडिया हाऊस में कार्यरत हैं। ये स्टूडेंट्स गाइड बनकर नई पीढ़ी का मार्गदर्शन कर रहे हैं तो यह देखकर अच्छा लगता है।

एडमिशन को लेकर बच्चे बहुत तनाव महसूस करते हैं। मेरा खुद का मानना है कि प्रोफेशनल कोर्स जो आगे चलकर करियर बनाते हों उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। बच्चों को भी इस मामले में अच्छा मार्गदर्शन लेना चाहिए जो आगे चलकर उनका करियर संवारें। सच बात यह है कि आज की तारीख में लोग इलेक्ट्रोनिक मीडिया के प्रति बहुत आकर्षण रखते हैं। उनमें पत्रकार बनने का क्रेज है। स्टूडेंट्स याद रखें वे जो भी बनना चाहते हों लेकिन उनमें कुछ कर दिखाने की ललक तो होनी ही चाहिए। इस स्टूडेंट्स जिसने पत्रकार बनने की राह चुनी उसको मैं बहुत बधाई देती हूं, अशीर्वाद देती हूं और सभी स्टूडेंट्स से उम्मीद रखती हूं कि दसवीं-बारहवीं या ग्रेजुएशन के बाद उनकी सिलेक्शन सही होनी चाहिए। हम सबको सही दिशा दिखाने की राह पर हैं और उनका मार्गदर्शन करने को तैयार हैं।

जब मायावती ने यू-टर्न लिया

नई दिल्ली, (एनटीआई): 2024 के आम चुनाव में बसपा की बुरी गत के बाद मायावती ने अपने हाथी की चाल बदलनी शुरू कर दी है। बहिन जी 'एक्टिव मोड' में आ गई हैं। सूत्रों की मानें तो पिछले सप्ताह उन्होंने पार्टी कोर कमेटी की बैठक बुलाई और उसमें ऐलान किया कि पार्टी अभी से 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं, इसके लिए 1 जनवरी 2025 को 100 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। इस पर कई क्षेत्रीय कॉआर्डिनेटर ने माया की इस राय का विरोध करते हुए कह दिया कि 'आज पार्टी इस हालत में है कि उसे अच्छे व मजबूत उम्मीदवारों का टोटा पड़ जाएगा।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com
स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

एक्स से

समय यूक्रेन के पक्ष में नहीं है, तो इसका सीधा कारण यह है कि वहां लोग हर रोज मर रहे हैं, जबकि व्हाइट हाउस और जर्मन चांसलरी के मास्टरमाइंड कूटनीतिक खेल खेल रहे हैं- गैरी कास्परोव/ पूर्व विश्व चैंपियन, शतरंज

हमें इस दौर से निकलना होगा

आत्ममुग्ध पश्चिम के मुल्कों को छोड़ दें, तो आधी से अधिक धरती की आबादी वीटो पावर में बड़े बदलाव के पक्ष में है। अगर हमें पिछले दशक तक जारी आर्थिक सुधारों को जारी रखना है, तो इन सुधारों के प्रति गंभीर नजरिया अपनाना ही होगा। अनैतिक विस्तारवाद और विकास के बीच झूलती दुनिया को बेहतर संतुलन की जरूरत है।

शशि शेखर

आजकल

कृपया 1991 से 2019 के बीच के दिन-रात याद कीजिए। आपको लगेगा कि हम इंसानियत के बेहतरीन दौर से गुजर रहे थे। कुछ अफ्रीकी मुल्कों को छोड़ दें, तो युद्ध उन दिनों बीते वक्त की निशानियां लगने लगे थे। इस दौरान चेकोस्लोवाकिया दो भागों में बंटा, सोवियत संघ में शामिल देश अलग हुए, पर वैसी हिंसा नहीं हुई, जैसी भारत अथवा इजरायल की आजादी के वक्त हुई थी।

इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि बर्लिन की दीवार गिरने से शुरू हुआ पश्चिम का प्रभुत्व सोवियत संघ के क्षरण के साथ वर्ष 1991 में परवान चढ़ चुका था। नव-पूंजीवाद विकास की नूतन बारहखड़ी के साथ हमारे दरवाजों पर दस्तक दे रहा था। अगले तीन दशक अति-निर्धनता के अभिशाप पर आघात के थे। इस दौरान समूची दुनिया में एक अरब से अधिक लोग गरीबी की रेखा से मुक्ति पाने में कामयाब हुए। यह अभूतपूर्व था।

इस बीच आतंकवाद की कुछ बड़ी वारदातों ने अवश्य आकार लिया। इसमें सबसे बड़ा न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला था, जिसमें तकरीबन तीन हजार लोग मारे गए और अरबों डॉलर की संपत्ति स्वाहा हो गई। उसी दिन अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय से भी दहशतगर्दों द्वारा कब्जाया हुआ एक जहाज टकराया। इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, पर अमेरिकी अभेद्यता की नाक अवश्य कट गई। बौखलाए अमेरिका और उसके दोस्तों ने अफगानिस्तान पर जवाबी हमला बोल दिया। वे मानते थे कि 'न्यूयॉर्क का हत्यारा' ओसामा बिन लादेन वहीं छिपा हुआ है। यह बात अलग है कि ओसामा अगले दस वर्ष उन्हें वहां नहीं मिला। बाद में उसे पाकिस्तान के अति-सुरक्षित एबटाबाद के सैन्य इलाके में मार गिराया गया। इससे पूर्व अमेरिका और उसके मित्र देशों ने इराक पर इस संगीन आरोप के साथ हमला बोला था कि वहां के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने घातक रासायनिक हथियार बना रखे हैं, जो मानवता के खिलाफ हैं।

इराक से पश्चिमी वैज्ञानिकों की भरमार वाली अंतरराष्ट्रीय जांच एजेंसी हाथ मलती लौटी थी। उस समय सवाल उठा था कि ऐसा अनर्थ क्यों? क्यों हजारों निरपराध लोगों के खून से हाथ रंगे गए? क्यों इराक जैसे खुशहाल मुल्क को यूं बर्बाद कर दिया गया? अमेरिका के पास जवाब न थे। यही वजह है कि जब उसने शक की बिना पर अफगानिस्तान पर धावा बोला, तो पश्चिमी मुल्कों के प्रति शेष दुनिया का भरोसा डगमगा गया। सयाने कहने लगे कि यह प्रवृत्ति बलशाली के लिए भली और निर्बलों के लिए घातक है।

वे गलत नहीं थे, क्योंकि इसी कालखंड में चीन और रूस ने भी आततायी रुख अपना लिया। रूस ने सीरिया पर बम बरसाए, क्रीमिया पर कब्जा किया और बाद में यूक्रेन के ऊपर धावा बोल दिया। चीन ने भारत के साथ गलवान में खूनी झड़प की। ताइवान की संप्रभुता को चुनौती दी और अब दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस का गुजर-बसर दूभर कर रखा है।

आज की दुनिया में जो तबाही फैल रही है, वह इसी बदनीयती की कोख से जन्मी है।

कोई आश्चर्य नहीं कि आज पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया में जारी जंग हर रोज नई आशंकाएं जन रही हैं। यूक्रेन-रूस के बीच युद्ध अपने तीसरे साल में है। इजरायल का गाजा पर सितम भी अगले महीने दूसरे साल में प्रवेश कर जाएगा। समूची दुनिया के पचास से अधिक मुल्क आंतरिक अथवा बाह्य संघर्षों से आक्रांत हैं। यही नहीं, ईरान अपने राष्ट्रपति की मौत के बाद सदमे से उबरा न था कि उसकी सरजमीं हमास के सदर इस्माइल हानियाह के खून से लाल हो गई। ईरान ने बदला चुकाने की कसम खाई है और उधर लेबनान व इजरायल के बीच जंग गरमाती जा रही है। आप इसे इस्लाम बनाम यहूदी का युद्ध मानने की गलती मत कर बैठिएगा। हम विरोधाभासों की नई दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं।

इस विरल वक्त में 'ऑर्थोडॉक्स' रशियन चर्च को मानने वाले मॉस्को और कीव को रोटी-बेटी, आचार-विचार और बरसों पुराने साथ की सौगंध तक नहीं रोक पा रही। वहां अब तक एक लाख से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और खरबों की संपत्ति स्वाहा हो चुकी है। यह जंग कब रुकेगी, इस सवाल का जवाब पुतिन और जेलेंस्की भी नहीं दे सकते। यही हाल इजरायल का है। नेतन्याहू जानते हैं कि वह जो कर रहे हैं, उसका हासिल सिर्फ आर्थिक तबाही है, पर वह तबाही की आग को हवा दिए जा रहे हैं। इजरायल के लिए आए दिन नए मोर्चे खुल रहे हैं और इससे समूचा भू-भाग थर्रा उठा है।

यह थर्राहट उन लोगों के मन में भी दहशत पैदा कर रही है, जो जानते हैं कि जंग आर्थिक विकास की राह में सबसे बड़ा रोड़ा साबित होती आई है। भारत जैसे तमाम देश इसी मत को मानते आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसीलिए पिछले हफ्ते कीव गए थे। वह इसके पहले मॉस्को की यात्रा कर चुके हैं। मोदी ने अनेक बार पुतिन, जेलेंस्की, बाइडन और अन्य बड़े नेताओं से इस संबंध में फोन पर चर्चा भी की, मगर युद्धग्रस्त भूमि के अधिपति कम जिद्दी नहीं हैं। जेलेंस्की ने मोदी के प्रस्थान के तत्काल बाद जैसी बचकानी बयानबाजी की, उससे जाहिर है कि वह शांति से ज्यादा अपनी छवि को तरजीह देते हैं। यही हाल नेतन्याहू का है। वह अमेरिकी सदर की चेतावनियों तक को दरकिनार कर चुके हैं। बढ़ते संघर्षों के इस दौर में राष्ट्राध्यक्षों की ऐसी सनक द्वितीय विश्वयुद्ध से पहले के महीनों की डरावनी याद दिलाती है।

इस पर अंकुश कैसे लगाया जाए?

सैद्धांतिक उत्तर तो यह है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद इसके लिए पूरी तरह अधिकृत है। उसे इस विनाश पर लगाम लगानी चाहिए, मगर परिषद कुछ मुल्कों की जागीर बनी हुई है। ऐसा न होता, तो इराक, अफगानिस्तान के बाद अब गाजा और यूक्रेन न सुलग रहे होते। स्लोवानिया की राष्ट्रपति नताशा पिर्क मुसर ने ठीक ही कहा है, 'आखिर संयुक्त राष्ट्र का गठन क्यों हुआ था? इसका गठन इस पूरे ग्रह पर शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए किया गया था। लेकिन इस संगठन के साथ एक बड़ी समस्या है। युद्ध न सिर्फ मैदानों में लड़े जाते रहे, बल्कि सुरक्षा परिषद (संयुक्त राष्ट्र) के भीतर वीटो शक्तियों के साथ भी जंग लड़ी जाती रही हैं। पिछले 25 वर्षों से हम संयुक्त राष्ट्र में सुधार को लेकर बहस कर रहे हैं। पर आज हम क्या देख रहे हैं? सुरक्षा परिषद निष्क्रिय है और जब भी हमारे हित की कोई बात होती है, कम से कम तीन देश वहां अपने वीटो के इस्तेमाल के लिए तत्पर होते हैं। मैं मानती हूं, अब वक्त आ गया है कि हम वीटो पावर में बड़े बदलाव के बारे में गंभीर विमर्श की शुरुआत करें।'

संयोग से नताशा अकेली नहीं हैं। आत्ममुग्ध पश्चिम के मुल्कों को छोड़ दें, तो आधी से अधिक धरती की आबादी इसके पक्ष में है। अगर हमें पिछले दशक तक जारी आर्थिक सुधारों को जारी रखना है, तो इन सुधारों के प्रति गंभीर नजरिया अपनाना ही होगा। अनैतिक विस्तारवाद और विकास के बीच झूलती दुनिया को बेहतर संतुलन की जरूरत है।

@shekharkahin
@shashishekhar.journalist

स्कैन करें
आजकल स्तंभ के तहत प्रकाशित आलेखों के लिए

जीना इसी का नाम है

ली किलेंगा
सामाजिक कार्यकर्ता

शरीर ही नहीं, रूह पर भी मरहम रखती किलेंगा

डॉक्टरों ने माता-पिता को आगाह कर दिया था कि किलेंगा भी बहुत ज्यादा वर्षों तक साथ उनका नहीं निभा पाएंगी। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा सात-आठ साल की मोहलत दी थी, मगर सबसे बड़ा कारसाज तो ऊपर कहीं बैठा है। उसने किलेंगा के लिए कुछ और लिख रखा था।

सहस्राब्दियों पहले धर्मराज युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा था, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने जो जवाब दिया, हममें से बहुत सारे लोगों को वह पता है। धर्मराज ने कहा था- यह जानते हुए कि सबको एक दिन मर जाना है, इंसान तमाम उम्र कभी न मरने की कामना करता रहता है। गालिब के यहां जो रात भर नींद न आने की बेचैनी है, वह वही युधिष्ठिर वाली हैरानी है- *मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती।* धर्मराज ने तो भौतिक काया के प्रति मनुष्य की आसक्ति को रेखांकित किया था, मगर जिसने भी उनके उत्तर का मर्म समझा, वह अपने कर्म से अमरत्व पाने में जुट गया। ली किलेंगा ने भले भारतीय साहित्य को न पढ़ा हो, मगर उनकी जिंदगी इस वैश्विक दर्शन से प्रेरित है।

पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या के तावेता शहर में आज से करीब 35 साल पहले किलेंगा पैदा हुईं। अपनी बहनों की तरह वह भी 'सिकल सेल एनीमिया' के साथ जन्मीं। इस वंशानुगत बीमारी से ग्रसित लोगों में लाल रक्त कोशिकाएं गलत आकार की होती हैं, जिसके कारण शरीर के अलग-अलग अंगों में रक्त का प्रवाह बाधित होता है और मरीज को भारी दर्द होता है। इसके शिकार लोगों को फेफड़े, आंख, गुर्दे आदि से जुड़ी कई तरह की जटिल समस्याएं हो सकती हैं। किलेंगा के चार भाई-बहनों में से तीन यह रोग लेकर इस दुनिया में आए। वह जब चार साल की थीं, तभी सबसे बड़ी बहन ने दम तोड़ दिया था।

इस नन्ही आयु में रोग और मौत जैसी बातें कहां समझ में आनी थीं, बस एक दिन बड़ी बहन का दिखना बंद हो गया। किलेंगा और उनकी दूसरी बहन के शरीर में भी रह-रहकर असह्य दर्द उठता था और उन्हें अक्सर अस्पताल ले जाना पड़ता। डॉक्टरों ने माता-पिता को आगाह कर दिया था कि ली किलेंगा भी बहुत ज्यादा वर्षों तक साथ उनका नहीं निभाएंगी। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा सात-आठ साल की मोहलत दी थी, मगर सबसे बड़ा कारसाज तो ऊपर बैठा है। उसने किलेंगा के लिए कुछ और लिख रखा था। सिकल सेल एनीमिया के मरीजों की तादाद अफ्रीकी देशों में बहुत ज्यादा है, बल्कि इसके 66 प्रतिशत मरीज अफ्रीका में ही हैं और इसको लेकर वहां पर सामाजिक वर्जनाएं भी कम नहीं।

किलेंगा व उनकी बहनों की रातें दर्द में कराहते, जागते कटतीं। उन्हें रोजाना दवा लेनी पड़ती थी और हर पखवाड़े खून की जांच के लिए अस्पताल जाना पड़ता था। इसे देखकर उन्हें यही लगता कि ऐसा सभी बच्चों के साथ होता है। लेकिन एक दिन स्कूल में तब धक्का लगा, जब किसी सहपाठी ने दूसरे बच्चों को उनके साथ बैठने से रोक दिया। उसने हिकारत भरी नजरों से देखते हुए सबको बताया कि किलेंगा को संक्रामक बीमारी है और जो भी उनके साथ बैठेगा, उसे यह

रोग हो जाएगा। उसके बाद उनके पास बैठना तो दूर, उनसे बात करना भी साथियों को गवारा न हुआ। इस बर्ताव से मन को गहरी चोट लगी। किलेंगा तीन महीने तक स्कूल नहीं गईं।

मगर माता-पिता ने अपनी बेटी के हृदय की इस चोट पर स्नेह और देखभाल का ऐसा लेप लगाया कि वह चोट कभी नासूर न बन सकी। उन्होंने इस रोग के बारे में न सिर्फ खुद को जागरूक किया, बल्कि अपने सभी बच्चों को पढ़ने-लिखने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टरों ने किलेंगा को बताया था कि सिकल सेल एनीमिया के पीड़ितों के शरीर का कोई अहम अंग 40 की उम्र के बाद पूरी तरह खराब हो सकता है, लिहाजा स्नातक करते ही उन्होंने फैसला किया कि वह केन्या भर में इस रोग से पीड़ित बच्चों व उनके परिवारों से मिलेंगी; अब जो भी जिंदगी है, उन्हें ही समर्पित करेंगी।

ली किलेंगा ने शुरुआत में देश के दस हजार रोगियों और उनके परिवार के अनुभव बटोरने का फैसला किया, मगर 400वें साक्षात्कार के दौरान उन्हें ऐसा दर्दनाक अनुभव हुआ कि उन्होंने अपनी वह मुहिम वहीं रोक दी। उन्होंने एक गांव में देखा कि इस रोग के कारण दर्द से रोते-तड़पते बच्चों को उनके परिवार ने एक कमरे में बंद कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि क्या किया जाए? एक तरह से परिजन अपनी संतानों की मौत की बाट जोह रहे थे। चार-चार साल के वे बच्चे उचित इलाज व देखभाल के अभाव में इतने अविकसित रह गए थे कि एक साल के दिखते थे। उनकी पीड़ा के आगे किलेंगा अपना सारा दर्द भूल गईं।

वह नैरोबी में स्वास्थ्य मंत्रालय के गैर-संक्रामक रोगों के निदेशक से मिलीं और उन्हें अपना अनुभव सुनाया, एकत्रित तस्वीरें भी दिखाईं। किलेंगा ने एक तरह से उन्हें बाध्य किया कि सिकल सेल एनीमिया के नियंत्रण व प्रबंधन के लिए अलग विभाग शुरू किए जाएं। जाहिर है, गरीब, अशिक्षित और स्वच्छ भोजन व पेयजल से वंचित परिवारों में इस रोग का प्रसार अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर किलेंगा ने 20,000 डॉलर दान से जुटाए। इस रोग से जुड़ी भ्रांतियों के खिलाफ जागरूकता अभियान शुरू हो गया।

केन्या में हर साल लगभग 14,000 बच्चे इस एनीमिया से पीड़ित पैदा होते हैं। वर्ष 2017 में ली किलेंगा ने अपने 'अफ्रीका सिकल सेल ऑर्गेनाइजेशन' की शुरुआत की। इसके तहत स्वास्थ्य बीमा से लोगों को जोड़ने के अलावा इस रोग के पीड़ितों के लिए विशेष क्लिनिक बनाने, विशेषज्ञ डॉक्टरों व चिकित्सा पेशेवरों की मदद से इलाज व देखभाल को लेकर लोगों को प्रशिक्षित करने का काम किया जा रहा है। अब तक पांच लाख लोग इस संगठन से लाभ उठा चुके हैं। एक किलेंगा की संवेदनशीलता ने लाखों बच्चों-वयस्कों को न सिर्फ दर्द से मुक्ति दिलाई है, बल्कि समाज को कई भ्रांतियों से बाहर निकाला है। *सीएनएन* ने ली किलेंगा को 'हीरो' माना है। सचमुच वह नायिका हैं। मरना तो एक दिन सबको है, क्यों न उससे पहले जीना सार्थक कर लिया जाए!

एक किलेंगा की संवेदनशीलता ने केन्या के लाखों लोगों को न सिर्फ दर्द से मुक्ति दिलाई, बल्कि समाज को कई तरह की भ्रांतियों से बाहर निकाला है। *सीएनएन* ने ली किलेंगा को 'हीरो' माना है। सचमुच वह नायिका हैं। मरना तो एक दिन सबको है, तो क्यों न उससे पहले जीना सार्थक कर लिया जाए!

प्रस्तुति : चंद्रकांत सिंह

वो लम्हा

अन्ना मणि
मौसम वैज्ञानिक

हीरे का उपहार नहीं मुझे किताब दीजिए

उसी महिला को कामयाब माना जाता है, जिसके पास खूब जेवर हों। जेवर ही महिलाओं की सुरक्षा बन जाता है और ऐसा हथियार भी, जिसका प्रयोग एक महिला दूसरी स्त्री के खिलाफ करती है। जहां चार-पांच महिलाएं जुट जाएं, वहां जेवर युद्ध का होना तय है।

अगर ताकत हो, तो आप सब कुछ न सही, पर बहुत कुछ जरूर हासिल कर सकते हैं। वेग जल का हो या किसी इच्छा का, जब ज्वार आता है, तो बड़ी-बड़ी बाधाएं भी मार्ग नहीं रोक पाती हैं। उस लड़की में भी पढ़ने की इच्छा का अथाह ज्वार था। गुड्डा-गुड़िया खेलने की उम्र थी, पर छह-सात की उम्र में ही पुस्तकों से मित्रता हो गई थी। पाठ्यक्रम को तो वह चंद महीनों में ही पूरा कर लेती थीं और उसके बाद अन्य पुस्तकों के पीछे लग जाती थीं। पास के सार्वजनिक पुस्तकालय में अपना दूसरा घर बना रखा था। आयु जब आठवें वर्ष में पहुंची, तब वह गंभीर मलयालम साहित्य में डूब गईं। अनमोल जीवन का आभास होने लगा, तो ज्ञान-विज्ञान की ताकत भी समझ में आने लगी।

हालांकि, तब परिवार के लोग अलग ही तैयारी में जुटे थे कि लड़की अब सयानी हो रही है। सबकी तमन्ना थी कि उसे उम्र के नौवें पड़ाव पर कुछ ऐसा दिया जाए कि वह खुशी से फूले न समाए। मां-पिता ने तय किया कि बेटी को हीरे की बालियां भेंट की जाएं। पिता बड़े अधिकारी थे, तो धन-संपदा की कोई कमी न थी। यही तो होता है ज्यादातर बच्चियों के साथ, जेवर के उपहार से शुरुआत होती है और धीरे-धीरे जेवरों का पिंजड़ा तैयार हो जाता है। एक जेवर, फिर दूसरा, तीसरा, पूरे जेवर सेट तक और उसके बाद दूसरे, तीसरे के आगे भी यात्रा सतत चलती है, मन ही नहीं भरता। उसी महिला को कामयाब माना जाता है, जिसके पास खूब सारे जेवर हों। जेवर ही महिलाओं की सुरक्षा बन जाता है और ऐसा हथियार भी, जिसका प्रयोग एक महिला दूसरी महिला के खिलाफ करती है। अचरज नहीं, जहां चार-पांच महिलाएं जुट जाएं, वहां जेवर युद्ध का होना तय है।

शायद ऐसे ही जेवर युद्ध के लिए उस पढ़ाकू लड़की को भी तैयार करने की बुनियाद रखी जानी थी, पर वह नन्ही विदूषी कमाल की थीं, उपहार की भनक लग गई। फिर क्या था, दोटूक सुना दिया कि मुझे कोई जेवर या बालियां नहीं चाहिए, कोई सोना-चांदी-हीरा नहीं। मुझे मत उलझाओ, बस पढ़ने दो। जेवर मिलेगा, तो भटका देगा। संभालकर रखने की चिंता में लगा देगा। जितना महंगा सामान, सुरक्षा की उतनी ही ज्यादा चिंता, तो कौन पाले फिजूल का बोझ?

अब तो माता-पिता चिंतित हो उठे और उन्हें उदासी भी घेरने लगी कि लड़की ने योजना पर पानी फेर दिया। पिता ने समझाया, 'बेटी, तुम्हारा जन्मदिन है, उपहार न देंगे, तो कैसा लगेगा?'

बेटी ने विनम्र दृढ़ता से आग्रह किया, 'पिताजी, आप जेवर नहीं, *एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका* का एक सेट दिला दीजिए।'

पढ़ाई का मोल जानने वाले सिविल इंजीनियर पिता का रोम-रोम हर्षित हो उठा। वह समझ गए कि अब बेटी को समझाना व्यर्थ है, उसने अपना रास्ता चुन लिया है। इतनी कम उम्र में ही उसमें पूरी दुनिया के बारे में जान लेने की इच्छा है।

पिता ने बेटी की मांग पूरी की। बेटी अद्भुत मितव्ययी थी। उन्हीं दिनों गांधी जी जब उसके शहर से गुजरे, तो बेटी ने उनसे सीखा और सादगी को स्वभाव बना लिया। वह भौतिकी में आगे बढ़ना चाहती थीं, पर ब्रिटेन में उन्हें मौसम विज्ञान पढ़ने का अवसर मिला और छात्रवृत्ति भी। पिता ने पूरे विश्वास व उत्साह से बेटी को विदेश जाने दिया। उन्हें पता था कि बेटी एक दिन कामयाब होकर घर लौटेगी। ऐसा ही हुआ। जल्दी ही भारत की इस बेटी का नाम दुनिया की विज्ञान पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगा, लोग उन्हें मौसम वैज्ञानिक अन्ना मणि के नाम से जानने लगे। वह मौसम विज्ञान के उपकरण बनाने में माहिर होकर स्वदेश लौटीं। वह उन चंद भारतीय वैज्ञानिकों में शामिल थीं, जिन्होंने साल 1960 के आते-आते देश को मौसम विज्ञान में आत्मनिर्भर बना दिया। जब भारत को अपना पहला रॉकेट छोड़ना था, पूरी दुनिया की निगाह उस पर टिकी थी, तब सबसे बड़े वैज्ञानिक विक्रम साराभाई ने आग्रह किया, 'अन्ना, तुम मौसम का मिजाज देखना कि कहीं कोई गड़बड़ न होने पाए।' अन्ना ने काम बखूबी किया और देश ने अंतरिक्ष में परचम लहरा दिया। अन्ना देश के लिए वाकई में मणि साबित हुईं, मौलिक खोज-अनुसंधान के अंबार लगा दिए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आज भी उनके काम की गाथा गाते थकता नहीं है।

जब दुनिया में बहुत कम जगह ओजोन पर अध्ययन हो रहा था, तब अन्ना (1918-2001) ने ओजोन मापने वाला यंत्र बनाया और दुनिया को आगाह किया कि पर्यावरण का ध्यान रखो, ओजोन परत में छेद का बढ़ना दुनिया के लिए ठीक नहीं है। ताउम्र ज्ञान की तलाश में लगी उस बेटी ने विवाह नहीं किया, वह हंसकर एहसास कराती थीं कि मैं खुद को संभाल लूं, तो बहुत है। पढ़ाई-लिखाई के लिए एक जीवन कितना कम है?

प्रस्तुति : ज्ञानेश उपाध्याय

मैं कहां-कहां से गुजर गया

तिरछी नजर

सुधीश पचौरी हिंदी साहित्यकार

कवि अज्ञेय की तरह एक दिन मुझ पर भी 'नए' की खोज का दौरा पड़ा और सुबह-सुबह नए की खोज में मैं अपनी जमीन से जुड़ने निकल पड़ा। गांव की जमीन तो एयरपोर्ट के लपेटे में आ गई थी, सोचा कि वह न रही, तो सामने यमुना-कछार के खेतों से ही जुड़कर देख लूं। क्या पता, ताजा हवा के साथ कोई नया आइडिया ही कुलबुला उठे और मेरी कलम से कोई महान कविता या उपन्यास टपक पड़े!

यूं मुझे कई बार कबीर भी समझा चुके थे कि देख बेटा, *जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ/ हों बौरी ढूंढन गई, रही किनारे बैठ!* यानी गहरा गोता लगाए बिना मोती नहीं मिलना, सो लगा दे गोता। कई बार मुक्तिबोध ने भी धिक्कारा था कि रे पचौरी, तूने *अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया?* कुछ रिव्यू किए, दो-चार कूड़ा किताबें लिख डालीं और खुद को आलोचना का मसीहा समझ बैठा? बात सच थी। मैं जैसे ही दिल्ली आया, वैसे ही अपनी जड़-जमीन भूल गया। कभी पलटकर भी नहीं देखा। फिर एक दिन समझ में आया कि असली लेखक तो वही रहा, जो अपनी जमीन से जुड़ा रहा, जमीनी यथार्थ लिखता रहा, लोगों की आंखें खोलता रहा, 'वोक' (जागृत) करता रहा, 'प्रवोक' करता रहा, तो मैं भी क्यों न 'वोक-प्रवोक' करने लगूं?

एक सुबह सामने के यमुना के कछार में निकल गया। कुछ दूर एक खेत में दो बच्चे पतंगें उड़ा रहे थे और चार किसान झोंपड़ी के आगे खाट पर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। कुछ दूर कई गाय-भैंसें घास चर रही थीं और कुछ औरतें भी घास काट रही थीं। इस दृश्य को देखते ही मुझे गुप्त जी की पंक्तियां याद आईं : *अहा ग्राम्य जीवन भी क्या है, क्यों न इसे सबका मन चाहे! थोड़े में निर्वाह यहां है, ऐसी सुविधा और कहां है!!*

उसी झोंके में मनोज कुमार का गीत मेरे बेसुरे गले से फूट पड़ा : *मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे-मोती/ मेरे देश की धरती...* इसे सुनते ही एक किसान बोला : अरे! कैसे हीरे-मोती? ये सब फिल्मी चोंचले हैं, उनमें से किसी ने कभी की भी है किसानी? किसानी के खेल में अब तो घाटा ही घाटा है, ये खेल तुम्हारे बस का नहीं।

मेरा हिंदी साहित्यकार जाग उठा और जोश में बोल पड़ा, ताऊ! मैं भी लेखक हूं। तू हल चलाता है, तो मैं कलम चलाता हूं। कुछ भी कर सकता हूं। राई को पर्वत कर सकता हूं और पर्वत को राई कर सकता हूं। ताऊ हो-हो कर हंसने लगे- 'हम सोच रहे हैं कि इस खेत को किसी तरह निपटाकर कनाडा निकल जाएं और तू आया है इस नरक में सड़ने! सड़ भई, मजे से सड़, कौन मना करे है? कभी-कभी भेड़िए भी आ जावे हैं। बस एक रात रुक के देख ले। वो क्या कहवे हैं, तेरा सारा आत्म-संघर्ष और वर्ग-संघर्ष-वंघर्ष, सब निकल जाएगा।'

पहली बार मुझे लगा कि अपने राष्ट्रकवि जी भी बहकाते रहे, जबकि यथार्थ तो एकदम विपरीत निकला। मैं अपना सा मुंह लेकर लौट आया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मुझ पर फिर गरीबी से जुड़ने का दौरा पड़ा और मैं अगली सुबह एक गरीब बस्ती में था- संकरी गली। दोनों ओर कच्ची-पक्की झुग्गियां। बदबूदार नालियां। मच्छर-मक्खियां। कहीं मोटरसाइकिल अड़ी थी, तो कहीं ई-रिक्शा पड़ा था। छोटे-छोटे बच्चे स्मार्टफोन में घुसे थे।

कुछ ही दूरी पर लुंगी-बनियान पहने एक तगड़े से आदमी ने मेरा रास्ता रोक लिया और पूछा कि कौन हो? मैंने कहा- लेखक हूं, यहां का यथार्थ जानने और कहने आया हूं। मेरे कुछ सवाल हैं। तब तक कुछ और लोग आ गए। उनमें से एक बोला- तुम हमारी कहानी लिखकर कमाओगे, हमें क्या दोगे? फ्री में यहां कुछ नहीं मिलता। मैंने पूछा, गरीबी? वह बोला, वह भी नहीं। यूं वह है ही कहां? अब तो सब कुछ फ्री है। समाजवाद आ चुका है। हमें तेरी मेहरबानी नहीं चाहिए। चल निकल और मैं चुपके से निकल आया।

मैं भी क्या चीज हूं, नए की तलाश में कहां-कहां से गुजर गया और नया भी 'फेक' निकला!

कटाक्ष

राजेंद्र धोड़पकर

https://t.me/AllNewsPaperPaid

www.jagran.com | राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
रविवार 1 सितंबर, 2024

दैनिक जागरण
भाषा विचार का वस्त्र है

महिलाओं के विरुद्ध अपराध

जिला अदालतों के राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की ओर ध्यान आकृष्ट कर बिल्कुल सही किया। ये अपराध इसलिए कहीं अधिक गंभीर चिंता का कारण हैं, क्योंकि अनेक प्रयासों के बाद भी उनमें कमी आती नहीं दिख रही है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कालेज अस्पताल में प्रशिक्षु महिला चिकित्सक की दुष्कर्म के बाद हत्या ने सारे देश को आक्रोशित करने का काम किया, लेकिन इसके बाद भी दुष्कर्म के मामले थमते नहीं दिख रहे हैं। कोलकाता की घटना को लेकर हर स्तर पर रोष और आक्रोश के बाद भी देश के हर हिस्से से दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही हैं। इन घटनाओं की गिनती करना भी कठिन है। स्थिति यह है कि दुष्कर्मी बच्चियों तक को निशाना बना रहे हैं। कोलकाता के साथ देश के अन्य क्षेत्रों में दुष्कर्म की घटनाओं को देखते हुए कानूनों को कठोर करने और अपराधियों को सख्त सजा देने की जो मांग की जा रही है, उसकी पूर्ति की ही जानी चाहिए, लेकिन इसी के साथ इसकी भी आवश्यकता है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध के मामलों में त्वरित न्याय हो। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री के इस विचार से असहमत नहीं हुआ जा सकता कि न्याय जितनी तेजी से मिलेगा, महिलाओं को अपनी सुरक्षा को लेकर उतना ही अधिक भरोसा होगा। इतना ही नहीं, इससे महिलाओं के खिलाफ अपराधों को अंजाम देने वाले तत्वों के मन में भय का संचार भी होगा।

यह एक तथ्य है कि जब अपराधियों को यथाशीघ्र कठोर दंड मिलता है, तब वे हतोत्साहित होते हैं। नारी अस्मिता को कुचलने वाले दुष्कर्म सरीखे गंभीर अपराध में लिप्त तत्वों को जितनी जल्दी संभव हो, कठोर दंड दिया जाना सुनिश्चित करने के साथ ही यह भी देखा जाना चाहिए कि उस दूषित मानसिकता का निदान कैसे हो, जिसके कारण महिलाओं को हेय दृष्टि से देखा जाता है और जिसके चलते दुष्कर्म सरीखे अपराध होते हैं। इस मानसिकता को दूर करने का काम समाज को करना होगा और इसकी शुरुआत घर-परिवार से करनी होगी। बच्चों और किशोरों को इसकी घुट्टी पिलानी होगी कि वे लड़कियों और महिलाओं का आदर करना सीखें। यह ठीक है कि लड़कियों को तरह-तरह की सीख दी जाती है, लेकिन ऐसी ही सीख लड़कों को भी दी जानी चाहिए। इसमें माता-पिता, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ शिक्षकों की भी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। समाज को उन तत्वों के प्रति भी सजगता बढ़ानी होगी, जो महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए संभावित खतरा बनते हुए दिखते हैं। ऐसे तत्वों के बारे में पुलिस को लगातार सूचना दी जानी चाहिए। समाज ऐसा करने के लिए तत्पर रहे, इसके लिए पुलिस को सहयोग करने के साथ ही संवेदनशील भी बनना होगा। समाज के हिस्से में एक आवश्यक काम यह भी है कि वह महिलाओं के सशक्तीकरण को लेकर और अधिक सक्रिय हो।

भूमि सर्वेक्षण और प्रमाण

बिहार के सभी जिलों में इन दिनों विशेष भूमि सर्वेक्षण चल रहा है। गांव और शहर, जिनके पास थोड़ी भी जमीन है, वे इसमें रुचि दिखा रहे हैं। विशेष सर्वेक्षण को लेकर आम लोगों में उत्सुकता है तो थोड़ा संशय भी है। संशय यह कि जिनके पास जमीन से जुड़े सभी कागजात नहीं हैं, उनका क्या होगा? कहीं उनकी जमीन सरकार तो नहीं ले लेगी। सर्वे से जुड़े अधिकारी और कर्मी शंकाओं का निवारण कर रहे हैं। लोगों को बता रहे हैं कि अगर आपकी जमीन पुश्तैनी है और उस पर आपका कब्जा भी है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। जमीन पर स्वामित्व के कई दस्तावेज होते हैं। उनमें कोई एक भी आपके या वंशजों के पास है तो उसके सहारे जमीन पर आपका स्वामित्व प्रमाणित हो जाएगा। सरकारी जमीन के बारे में भी स्पष्ट है कि इस पर अगर किसी का अवैध कब्जा है तो उसे छोड़ना होगा। यह कोई नई बात नहीं है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग लंबे समय से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के विरुद्ध अभियान चला रहा है। सरकारी विभागों को कहा गया है कि वह अपने हिस्से की जमीन की मापी कराए। विभाग के नाम से दाखिल-खारिज कराए। जमीन के किसी हिस्से पर अतिक्रमण है तो उसे अंचल और स्थानीय थाना की मदद से मुक्त कराए। विभागों ने इसमें रुचि दिखाई और बहुत हद तक सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटा भी। लेकिन, अब भी सरकारी जमीन पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग चाहे तो सर्वेक्षण के बारे में आम जनता के बीच से अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची बनाए और उसका उत्तर प्रचारित करे।

> कागजात नहीं है और अगर आपकी जमीन पुश्तैनी है तथा उस पर आपका कब्जा है तो डरने की जरूरत नहीं

नए औद्योगिक शहरों से उम्मीदें

संजय गुप्त

नए औद्योगिक शहरों की स्थापना करते समय उन कारणों पर ध्यान देना आवश्यक है, जिनके चलते स्मार्ट सिटी योजना उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने औद्योगिक कारिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 10 राज्यों में 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी विकसित करने की जिस योजना को हाल में मंजूरी दी, वह समय की मांग थी। इस फैसले के अनुसार उत्तराखंड में खुरपिया, पंजाब में राजपुरा, उत्तर प्रदेश में आगरा एवं प्रयागराज, बिहार में गया, महाराष्ट्र में दिघी, राजस्थान में जोधपुर-पाली, आंध्र प्रदेश में कोपर्थी एवं ओर्वाकल, तेलंगाना में जहीराबाद और केरल में पलक्कड़ में नए औद्योगिक शहर स्थापित किए जाएंगे। इसी तरह का एक शहर हरियाणा में स्थापित होगा। ये शहर बड़े औद्योगिक गलियारों के आसपास विकसित होंगे। ज्ञात हो कि आम बजट में इन औद्योगिक शहरों की स्थापना की घोषणा की गई थी। सरकार का मानना है कि इन औद्योगिक शहरों के विकास में 28,602 करोड़ रुपये का निवेश होगा और इन शहरों में 1.50 लाख करोड़ का औद्योगिक निवेश आएगा, जिससे 10 लाख प्रत्यक्ष जबकि 30 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी। फिलहाल कहना कठिन है कि ये शहर कब तक स्थापित हो सकेंगे और देश को उनसे कब तक लाभ मिलने लगेगा, क्योंकि सरकार की बड़ी योजनाएं तय समय में कठिनाई से ही पूरी होती हैं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अतीत में इस तरह की कुछ महत्वाकांक्षी घोषणाएं सही तरह आगे नहीं बढ़ सकीं और कुछ तो अपनी अहमियत खो बैठीं। उदाहरणस्वरूप विशेष आर्थिक जोन यानी एसईजेड उस तरह स्थापित नहीं हो सके, जैसी उम्मीद की जा रही थी। स्पष्ट है कि सरकार को इसके लिए विशेष प्रयास करने होंगे कि 12 नए औद्योगिक शहरों की स्थापना का लक्ष्य तय समय में सही तरह पूरा हो।

नए औद्योगिक शहरों को बसाने में तब कामयाबी मिलेगी, जब सरकार को निजी क्षेत्र का हरसंभव सहयोग मिलेगा। यह सहयोग तभी संभव है, जब निजी क्षेत्र को इनमें आकर्षण दिखेगा। ध्यान रहे कि कुछ प्रस्तावित औद्योगिक शहर बड़े शहरों से दूर हैं। इसके चलते कुशल कारीगर और प्रबंधन के दक्ष लोग वहां रहना चाहेंगे या नहीं, यह भविष्य ही बताएगा। निःसंदेह देश को ऐसे शहरों की आवश्यकता तो है, लेकिन जब तक उनमें अच्छी-खासी संख्या में उद्योग स्थापित नहीं हो जाते और नागरिक आबादी की बसाहट के लिए उपयुक्त आधारभूत ढांचे का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक वे लोगों के आकर्षण का केंद्र नहीं बनेंगे। यदि ये नए शहर अच्छी तरह बसाए जा सके तो उनके पास के बड़े शहरों में आबादी का बोझ कम किया जा सकता है। इन बड़े शहरों का आधारभूत ढांचा चरमरा रहा है। यह किस तरह चरमरा रहा है, इसका प्रमाण मानसून के इन दिनों में अच्छी तरह देखा जा सकता है। इन दिनों देश के कई बड़े शहर जलभराव से त्रस्त हैं। कुछ शहर तो बाढ़ के प्रकोप का सामना कर रहे हैं और इसके चलते उनका आधारभूत ढांचा और भी तेजी से खराब हो रहा है। कहने को तो देश के हर शहर के नगर निकायों ने मानसून से पहले जल निकासी का प्रबंध करने के दावे किए थे, लेकिन वे दो-चार बार की बारिश के बाद ही दम तोड़ गए। इस मामले में दिल्ली की स्थिति भी दयनीय है। शहरों में जल निकासी और खासकर वर्षा जल निकासी की जो व्यवस्था है, वह गई-बीती ही अधिक है। यह व्यवस्था अपर्याप्त तो है ही, खराब इंजीनियरिंग एवं अतिक्रमण के कारण और भी दुर्दशाग्रस्त हो गई है। कई शहर ऐसे हैं, जहां सीवरेज की व्यवस्था अधूरी है।

अवधेश राजपूत

अब जब केंद्र सरकार 12 नए औद्योगिक शहर विकसित करने जा रही है, तब उसे बड़े शहरों के आधारभूत ढांचे की भी सुध लेनी चाहिए। कायदे से छोटे शहरों के आधारभूत ढांचे को भी संवारा जाना चाहिए, लेकिन यह तो वह काम है, जिसे राज्य सरकारों को करना है। समस्या यह है कि राज्य सरकारें इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही हैं। इसके चलते नगर निगम जैसी संस्थाओं की कार्यप्रणाली सुधरने का नाम नहीं ले रही है। यह सही समय है कि नगर निगमों, नगर पालिकाओं के कामकाज को ठीक करने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। यह राज्य सरकारों की प्राथमिकता के अभाव का ही परिणाम रहा कि स्मार्ट सिटी योजना अपेक्षित नतीजे नहीं दे सकी। औद्योगिक शहरों की स्थापना करते समय उन कारणों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है, जिनके चलते स्मार्ट सिटी योजना उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी। स्मार्ट सिटी योजना के संचालन के बाद भी नगर निकायों और शहरी ढांचे संबंधी अन्य सरकारी एजेंसियों की कार्यप्रणाली में कोई उल्लेखनीय बदलाव नहीं आ सका है। यह इसीलिए नहीं आ सका, क्योंकि इन संस्थाओं का कामकाज बेहतर करने की जिम्मेदारी जिन जनप्रतिनिधियों और नौकरशाहों की थी, उन्हें जवाबदेह नहीं बनाया जा सका। इन्हें जिम्मेदार और जवाबदेह बनाए बिना शहरों के आधारभूत ढांचे को सुधारा नहीं जा सकता।

निःसंदेह नगर निकायों के साथ आम जनता को भी जिम्मेदार बनना होगा। उन्हें आधारभूत ढांचे संबंधी नियम-कानूनों के पालन के प्रति सजग रहना होगा। बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण इसीलिए होते हैं, क्योंकि आम लोग संबंधित नियम-कानूनों का पालन नहीं करते। जब कहीं एक-दो जगह अवैध निर्माण हो जाता है, तो बाकी के लिए वह नजीर बन जाता है। जब अवैध निर्माण या अतिक्रमण हो रहा होता है, तब उसे कोई रोकने-टोकने वाला नहीं होता। इसी के चलते झुग्गी बस्तियां स्थापित हो जाती हैं। जब उनमें आबादी बढ़ जाती है तो उन्हें वैध करार देने की पहल होने लगती है। वोट बैंक के लालच में सरकारें भी अवैध तरीके से बनाई गई बस्तियों और कालोनियों को नियमित कर देती हैं। जब ऐसा होता है तो अनियोजित विकास को बढ़ावा मिलता है और वह शहरों की सूरत बिगाड़ता है। यदि जनता आधारभूत ढांचे के सुनियोजित विकास को लेकर जागरूक नहीं होती तो शहरों की जो समस्याएं हर वर्ष बढ़ती जा रही हैं, वे विकराल होती जाएंगी और उनका समाधान अत्यंत कठिन हो जाएगा। शहरों का बिगड़ता आधारभूत ढांचा उनमें रहने वाले लोगों के समक्ष त्राहिमाम की स्थिति ही पैदा करेगा। हमारे नीति-नियंताओं को इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि शहर विकास के इंजन होते हैं और यदि उनके आधारभूत ढांचे को ठीक नहीं किया गया तो आर्थिक विकास के लक्ष्य को पाना कठिन ही होगा।

response@jagran.com

वफादार की वफादारी पर संदेह

हास्य-व्यंग्य

मेरे जिले के एक नामचीन नेता आजकल अपने कुत्ते को लेकर कुपित हैं। वह अक्सर उस मनहूस घड़ी को पानी पी-पी कर कोस रहे हैं, जब उनका राजनीति के स्वर्ण महल में प्रवेश नहीं हुआ था और उन्होंने इस नामाकूल कुत्ते को पाल लिया था। वैसे पानी पी-पी कर कोसना तो एक मुहावरा है। हकीकत यह है कि इस पानी में एक मादक द्रव्य भी मिला होता है, जिसमें गम को गलत करने और हर्ष का आनंद लेने की क्षमता समान रूप से देखी जाती है। इसे चुनाव के दौरान बांटकर अपनी जीत भी पक्की की जाती है और अपने कुछेक शौकीन कार्यकर्ताओं की थकान को भी मिटाया जाता है। नेताजी का कुत्ता भी कोई कम शौकीन नहीं है। वह भी अवसर का लाभ उठा लेता है। बचे हुए द्रव्य को चाटता है और मना करने पर अपने स्वामी के चरण चाट कर उनको मना भी लिया करता है। यूं भी राजनीति में अपने से बड़े लीडर के तलवे चाटने और चरण-चुंबन को अनिवार्य गुण कहा गया है।

नामचीन नेता ने सुन रखा था कि कुत्ता एक वफादार जानवर है। ऐसे कुत्ते अपने मालिक की मर्जी के बिना दुम नहीं हिलाते। कुत्ता अपनी गली का शेर भी होता है। इस कारण नेताजी ने उसे पाल लिया, लेकिन वही कुत्ता अब उनके ही काम नहीं आ रहा है। उसकी निष्ठा मौकापरस्त दलबदलुओं जैसी होती जा रही है। वह दौर ही और था, जब कुत्ते वफादारी का पर्याय समझे जाते थे। तब राजनीति में भी वफादारी को भली निगाहों से देखा जाता था। बड़े के सामने छोटा जुबान तक नहीं निकालता था।

सूर्यकुमार पांडेय

चोरों को देखकर भौंकने वाला कुत्ता अब नेताजी को देखकर भी गुर्रा उठता है, जिसकी उन्हें शिकायत है

कुत्ते का नाम आते ही नेताजी उस वक्त की यादों में उलझ जाते हैं, जब उनके साथ उनका एक अदद पिछलग्गू, जिसे आम बोलचाल की भाषा में चमचा कहा जाता था, हुआ करता था। मंत्री जी के पास तब यह कुत्ता नहीं था। इस नाते उनकी सारी बातें अपने चमचे के बारे में हुआ करती थीं। वह कहते थे, 'एक दिन के लिए भी इधर-उधर नहीं बहका। महत्वाकांक्षा उसे छू तक नहीं पाई। उसने अपनी तमाम जवानी, जिसे पोलिटिकल करियर कहा जाता है, नेता जी की चापलूसी में लगा दी। वह वफादारी का पट्टा अपने गले में डाले रैलियों के लिए भीड़ जुटाता रहा, चंदे की रसीदें झोले में भरकर दर-दर भटकता रहा। प्रदर्शनों, धरनों, जुलूसों में सबसे आगे रहकर पार्टी का झंडा थाम कर डंडे खाता रहा।' अपने चमचे की तारीफ के पुल बांधते नेता जी कह उठते, 'जब-तब मेरी रक्षा के लिए उसने मेरे राजनीतिक दुश्मनों पर भौंकने में भी कोर-कसर बाकी नहीं रखी और एक यह कुत्ता! इसने तो मेरी नाक कटा दी! नेता-नगरी में मुझे किसी को मुंह दिखलाने के काबिल नहीं छोड़ा। इतने दिनों का पुराना साथ और थोड़ा सा लगाव न होता तो मैं कब का दो लातें जमाकर भगा देता।'

नेता जी को शिकायत है कि जो कुत्ता पहले सिर्फ चोरों को देखकर भौंका करता था, अब खुद उन पर भी गुर्रा उठता है। सारी ट्रेनिंग बेकार गई। चोर का कुत्ता चोर पर ही भौंकने लगे तो उसे गोली मार देनी चाहिए। वह मार भी दें, मगर जब भी यह विचार उनके दिमाग में कौंधता है तो उन्हें चतुर्दिक कुत्ते ही कुत्ते नजर आने लगते हैं, किस-किस को मारेंगे। वह उस दिन को कोसते हैं, जब उन्होंने कुत्ता पाला था। यूं तो उनके पूर्ववर्ती और समकालीन नेता हाथी, बैल, गाय और बकरी वगैरह पालते रहे थे, किंतु उन्हें कुत्ता-पालन अपने स्वभाव के अनुरूप लगा था। कुत्ते को कहीं पर भी अपने साथ ले जा सकते हैं। यह छूट और जानवरों के साथ मुमकिन नहीं थी। कुत्ता सोते-जागते नेताजी के साथ रहता है। कहते हैं कि अगर किसी कुत्ते में महत्वाकांक्षा का बोध जाग जाए तो फिर वह कुत्ता नहीं रह जाता। वह अपनी अलग जमात बना लेता है। गली-मोहल्ले के तमाम कुत्ते उसके साथ हो लेते हैं। नेता जी आजकल कुत्ते से कुपित तो हैं, लेकिन उन्होंने उससे समझौता कर लिया है। उन्हें पता है कि जब तक कुत्ता रखवाला है, उनकी राजनीति सुरक्षित है।

response@jagran.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid

तथ्य-कथ्य | देश के सबसे धनी व्यक्ति

(संपत्ति करोड़ रुपये में)

स्रोत: हुरुन इंडिया रिच लिस्ट

व्यक्ति	संपत्ति (करोड़ रुपये)
नीरज बजाज	1,62,800
अजीम प्रेमजी	1,90,700
राधाकिशन दमानी	1,90,900
गोपीचंद हिंदुजा	1,92,700
कुमार मंगलम बिड़ला	2,35,200
दिलीप सांघवी	2,49,900
साइरस पूनावाला	2,89,800
शिव नादर	3,14,000
मुकेश अंबानी	10,14,700
गौतम अदाणी	11,61,800

ऊर्जा

सुख का सूत्र

हम सभी जीवन की दौड़ में भागते हुए भले ही अपने उद्देश्य पूर्ति से सुख की कामना करते हों, परंतु फिर भी कभी न कभी इस प्रश्न पर अटक जाते हैं कि सुख क्या है? हमें किस प्रकार का सुख चाहिए? क्या सुख की संकल्पना हमारे मन में पूरी तरह स्पष्टता के साथ आकार ले पाती है? कभी-कभी सुख का तात्पर्य हम तृप्ति या संतुष्टि को समझते हैं, कभी सफलता को और कभी मोक्ष को या कभी भौतिक संसाधनों के संग्रह एवं उनसे मिली सुविधाओं को। कुल मिलाकर हम जिस एक वस्तु की इच्छा लिए जीवन भर भागते रहते हैं, कई बार हमें उसका अर्थ ही स्पष्ट नहीं होता।

ऐसे में, यही श्रेयस्कर है कि हमें जीवन का उद्देश्य स्पष्ट रखते हुए उसकी तरफ बढ़ते रहना चाहिए। साथ ही साथ भूत या भविष्य की चिंता किए बिना उद्देश्य प्राप्ति की इस यात्रा में आने वाले हर एक पल का आनंद भी लेना चाहिए। तभी हमारे जीवन में उद्देश्य प्राप्ति की यह प्रक्रिया हमें निश्चित ही सुख की अनुभूति कराएगी, क्योंकि सुख का संबंध तो अंतर्मन से है। जब तक हमारा मन सुख का अनुभव न करे, तब तक कितने भी भौतिक साधन हमारे लिए सुख नहीं जुटा सकते। जो वास्तविक सुख हम इस बाहरी दुनिया में खोजते हैं, वह हमें कभी भौतिक साधनों के जरिये नहीं मिल सकता। हमें सच में सुख चाहिए तो मन के सुख की खोज करनी होगी।

हमारा उद्देश्य यदि हमारी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के साथ-साथ समाज कल्याण में भी सहायक है, तो ही वह हमें सुख प्रदान करेगा। सदैव मन को शांत रखते हुए अपने कार्य को प्रेमपूर्वक करते रहना चाहिए और हमेशा स्मरण रखना चाहिए जो है वह इसी पल में निहित है। न इससे पहले वाला पल हमारे वश में हो सकता है और न इस पल के बाद आने वाला पल हमारे वश में होगा। यह ध्यान रखते हुए जब हम आनंद लेने लगेंगे, तब ही हमें सुख की प्राप्ति होगी।

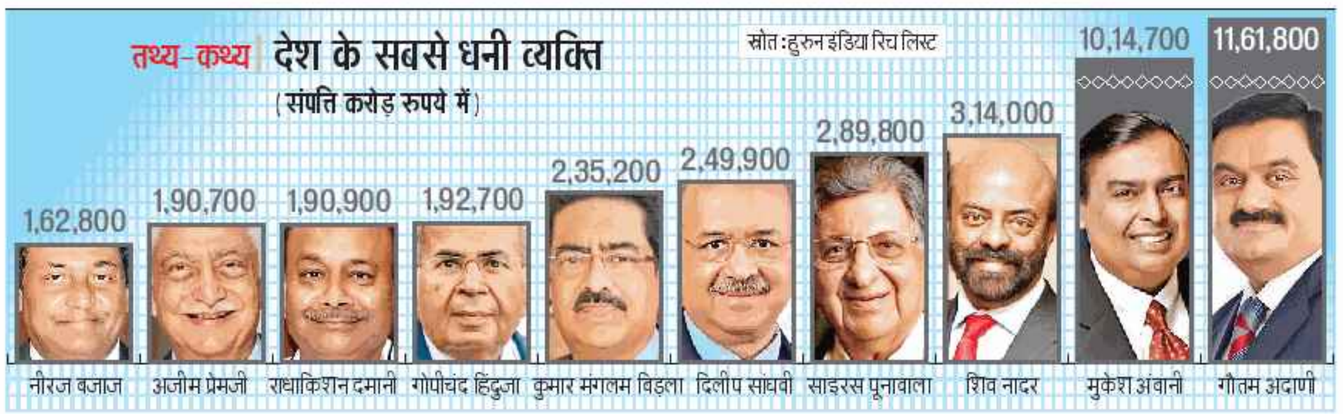

प्रियंका कटारे

पृथ्वी के आसपास विद्युत क्षेत्र की खोज

मुकुल व्यास

विज्ञानियों ने हमारी पृथ्वी के चारों ओर मौजूद एक अदृश्य विद्युत क्षेत्र का पता लगाया है

हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र है। विज्ञानियों ने पहली बार इस अदृश्य एवं कमजोर ऊर्जा क्षेत्र का पता लगाया है। इसे एंबीपोलर फील्ड कहा जाता है। इस विद्युत क्षेत्र की परिकल्पना सबसे पहले करीब 60 साल पहले की गई थी। विज्ञानियों का कहना है कि इसकी खोज हमारी निरंतर बदलती दुनिया के व्यवहार और विकास का अध्ययन करने और समझने के तरीके को बदल देगी। नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के एक खगोलशास्त्री का कहना है कि वायुमंडल वाले किसी भी ग्रह में एंबीपोलर फील्ड होनी चाहिए। अब हम यह पता लगा सकते हैं कि इसने समय के साथ हमारे ग्रह के साथ-साथ अन्य ग्रहों को कैसे आकार दिया है।

पृथ्वी अंतरिक्ष में मिट्टी का एक निष्क्रिय धब्बा मात्र नहीं है। यह सभी प्रकार के क्षेत्रों से घिरी हुई है जिनमें गुरुत्वाकर्षण भी है। हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में कम जानते हैं। यह वायुमंडल को सतह से सटाए रखने में भी मददगार है।

विज्ञानियों ने 1968 ने एक अनोखी घटना का वर्णन किया था। तब पृथ्वी के ध्रुवों पर उड़ने वाले अंतरिक्ष यान ने पृथ्वी के वायुमंडल से निकलने वाले कणों की एक सुपरसोनिक हवा का पता लगाया। विज्ञानियों ने उस समय सोचा कि यह एक तीसरा विद्युत ऊर्जा क्षेत्र हो सकता है।

कोलिनसन ने कहा कि हम पहले कभी इस विद्युत क्षेत्र को नहीं माप पाए, क्योंकि हमारे पास तकनीक नहीं थी। इसलिए, हमने इस अदृश्य शक्ति की तलाश करने के लिए 'एंड्यूरेंस' राकेट बनाया। यह एंबिपोलर फील्ड कैसे काम करती है? लगभग 250 किमी की ऊंचाई से शुरू होकर, आयनस्फीयर नामक वायुमंडल की एक परत में, अत्यधिक पराबैंगनी और सौर विकिरण वायुमंडलीय परमाणुओं को आयोनाइज करते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रानों को तोड़ते हैं और परमाणु को पाजिटिव चार्ज वाले आयन में बदल देते हैं। आयन एक परमाणु या अणु है जिसमें विद्युत आवेश होता है। इसमें इलेक्ट्रान और प्रोटान की संख्या असमान होती है। हल्के इलेक्ट्रान अंतरिक्ष में उड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि भारी आयन जमीन की ओर डूबने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्लाज्मा वातावरण चार्ज की तटस्थता बनाए रखने की कोशिश करता है, जिससे इलेक्ट्रानों और आयनों के बीच एक विद्युत क्षेत्र का उद्भव होता है जो उन्हें एक साथ बांधता है। प्लाज्मा वातावरण अंतरिक्ष या पृथ्वी के वायुमंडल का वह क्षेत्र है जिसमें प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा आयनों और इलेक्ट्रानों से बनी एक गैस है। विज्ञानी अभी विद्युत क्षेत्र के व्यापक निहितार्थों को नहीं जानते। उन्हें यह पता लगाना है कि यह कितने समय से है, यह क्या करता है और इसने हमारे ग्रह और उसके वायुमंडल के विकास को कैसे आकार दिया है। संभवतः पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति में भी इसकी भूमिका हो सकती है। **(लेखक विज्ञान के जानकार हैं)**

जनगणना पर संशय

जनगणना होनी है, लेकिन यह कब होगी, इसे लेकर अभी भी संशय कायम है। पहले ऐसी खबरें आईं कि सितंबर से जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। हालांकि जितनी तेजी से ऐसी अटकलें लगाई जाने लगीं, गृह मंत्रालय के शीर्ष अमले ने इसके खंडन में उतनी ही तत्परता दिखाई। ऐसे में यह सवाल जस का तस बना हुआ है कि जनगणना कब शुरू होगी, जो पहले से ही काफी समय से अटकी हुई है। पिछले दिनों रायपुर में अमित शाह से भी एक पत्रकार ने जनगणना को लेकर सवाल पूछा, लेकिन उन्होंने इसे यह कहते हुए टाल दिया कि जब भी शुरू होगी तो मीडिया को सबसे पहले बताया जाएगा। माना जा रहा है कि विपक्ष के साथ-साथ कुछ सहयोगी दलों की ओर से भी जनगणना के साथ ही जाति की गणना की मांग ने इस कवायद को राजनीतिक रूप से संवेदनशील बना दिया है। ऐसे में, सरकार इस पर फूंक-फूंक कर कदम रखते हुए किसी भी तरह के विवाद से बचना चाहती है।

राजभवन में बेचैनी

झारखंड में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, किंतु बेचैनी ओडिशा के राजभवन में महसूस की जा रही है। सुनने में आया है कि राज्यपाल रघुवर दास का मन भुवनेश्वर के राजभवन में नहीं लग रहा है। वह बार-बार रांची, जमशेदपुर और दिल्ली के दौरे कर रहे हैं। झामुमो नेता चम्पाई सोरेन के भाजपा में आने से पहले प्रधानमंत्री मोदी के साथ झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की मुलाकात ने रघुवर को कुछ ज्यादा ही बेचैन कर दिया। दिल्ली आकर उन्होंने भी आलाकमान को फीडबैक दे दिया। अहसास करा गए कि वह भी दावेदार हो सकते हैं। तर्क दिया कि लोकसभा चुनाव में राज्यपाल रहे दिग्गज भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। रघुवर की बेचैनी इसलिए भी बढ़ रही है कि झारखंड में चार पूर्व सीएम पहले से भाजपा का चेहरा बने हुए हैं। सिर्फ रघुवर का नाम छूट रहा है। उन पर समर्थकों का दबाव बढ़ रहा है कि वह भी अपनी दावेदारी को आगे करें।

राजरंग

व्यथित करते अनुरोध

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एक्स हैंडल पर पोस्ट चाहे कोई भी हो, उस पर कमेंट एक जैसे होते हैं। ये कमेंट कम गुजारिशों का सिलसिला अधिक होते हैं। मसलन, इनमें लिखा होता है-टैक्स कम कर दो मैडम, जीएसटी से नुकसान हो रहा है ताई, व्यापार डूब रहा है मैडम आदि। ऐसा ही एक वाकया 30 अगस्त को सामने आया जब इंडियन स्टील एसोसिएशन के पदाधिकारी सांसद एवं उद्यमी नवीन जिंदल के नेतृत्व में सीतारमण से मिलने आए, जिसे वित्त मंत्री ने एक्स पर पोस्ट भी किया। इस पोस्ट पर पहला कमेंट है-हेल्थ इंश्योरेंस पर 18 प्रतिशत जीएसटी हटा दो मैडम। वित्त मंत्री के हर पोस्ट पर टैक्स हटाने की मांग को लेकर कई कमेंट मिल जाएंगे। वित्त मंत्री लोगों की इन हरकतों से वाकिफ भी हैं और कुछ व्यथित भी। हाल में पत्रकारों के साथ एक अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने लोगों की इन हरकतों का जिक्र भी किया।

'घर की मुर्गी....'

कहावतों का किस्सा ही कुछ ऐसा है कि हर दौर में वे खरी उतरती हैं। जैसे कि घर की मुर्गी दाल बराबर वाली कहावत को ही लीजिए। यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर सटीक बैठती नजर आती है। एक तरफ इंग्लैंड का साउथैम्प्टन विश्वविद्यालय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देखते हुए भारत में कैंपस खोलने पहुंच गया है तो दूसरी ओर तमिलनाडु है, जिसने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विरोध को लेकर पीएम-श्री स्कीम पर शिक्षा मंत्रालय के साथ करार करने से ही इन्कार कर दिया। साउथैम्प्टन विश्वविद्यालय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत छात्रों को पढ़ाना चाहता है, तो तमिलनाडु और बंगाल जैसे राज्य इसे लागू करने के लिए कतई तैयार नहीं हैं। दुनिया में जिस नीति की तारीफ हो रही है, देश के भीतर उसके विरोध का तर्क शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों की समझ में नहीं आ रहा है। लगता है कि अपने ही देश के राज्य इसकी विशेषताओं को अनदेखा कर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर विदेशियों को इसकी आभा अपनी ओर खींच रही है।

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

भाषा विचार का वस्त्र है

नए औद्योगिक शहरों से उम्मीदें

महिलाओं के विरुद्ध अपराध

जिला अदालतों के राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की ओर ध्यान आकृष्ट कर बिल्कुल सही किया। ये अपराध इसलिए कहीं अधिक गंभीर चिंता का कारण हैं, क्योंकि अनेक प्रयासों के बाद भी उनमें कमी आती नहीं दिख रही है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कालेज के अस्पताल में प्रशिक्षु महिला चिकित्सक की दुष्कर्म के बाद हत्या ने सारे देश को आक्रोशित करने का काम किया, लेकिन इसके बाद भी दुष्कर्म के मामले थमते नहीं दिख रहे हैं। कोलकाता की घटना को लेकर हर स्तर पर रोष और आक्रोश के बाद भी देश के हर हिस्से से दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही हैं। इन घटनाओं की गिनती करना भी कठिन है। स्थिति यह है कि दुष्कर्मी बच्चियों तक को निशाना बना रहे हैं। कोलकाता के साथ देश के अन्य क्षेत्रों में दुष्कर्म की घटनाओं को देखते हुए कानूनों को कठोर करने और अपराधियों को सख्त सजा देने की जो मांग की जा रही है, उसकी पूर्ति की ही जानी चाहिए, लेकिन इसी के साथ इसकी भी आवश्यकता है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध के मामलों में त्वरित न्याय हो। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री के इस विचार से असहमत नहीं हुआ जा सकता कि न्याय जितनी तेजी से मिलेगा, महिलाओं को अपनी सुरक्षा को लेकर उतना ही अधिक भरोसा होगा। इतना ही नहीं, इससे महिलाओं के खिलाफ अपराधों को अंजाम देने वाले तत्वों के मन में भय का संचार भी होगा। यह एक तथ्य है कि जब अपराधियों को यथाशीघ्र कठोर दंड मिलता है, तब वे हतोत्साहित होते हैं। नारी अस्मिता को कुचलने वाले दुष्कर्म सरीखे गंभीर अपराध में लिप्त तत्वों को जितनी जल्दी संभव हो, कठोर दंड दिया जाना सुनिश्चित करने के साथ ही यह भी देखा जाना चाहिए कि उस दूषित मानसिकता का निदान कैसे हो, जिसके कारण महिलाओं को हेय दृष्टि से देखा जाता है और जिसके चलते दुष्कर्म सरीखे अपराध होते हैं। इस मानसिकता को दूर करने का काम समाज को करना होगा और इसकी शुरुआत घर-परिवार से करनी होगी। बच्चों और किशोरों को इसकी घुट्टी पिलानी होगी कि वे लड़कियों और महिलाओं का आदर करना सीखें। यह ठीक है कि लड़कियों को तरह-तरह की सीख दी जाती है, लेकिन ऐसी ही सीख लड़कों को भी दी जानी चाहिए। इसमें माता-पिता, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ शिक्षकों की भी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। समाज को उन तत्वों के प्रति भी सजगता बढ़ानी होगी, जो महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए संभावित खतरा बनते हुए दिखते हैं। ऐसे तत्वों के बारे में पुलिस को लगातार सूचना दी जानी चाहिए। समाज ऐसा करने के लिए तत्पर रहे, इसके लिए पुलिस को सहयोग करने के साथ ही संवेदनशील भी बनना होगा। समाज के हिस्से में एक आवश्यक काम यह भी है कि वह महिलाओं के सशक्तीकरण को लेकर और अधिक सक्रिय हो।

महिलाओं की सुरक्षा

बक्सर जिले में दो नाबालिग लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना बहुत ही शर्मनाक है। इन्हें आर्केस्ट्रा में बुलाया गया था, जहां कार्यक्रम समाप्त होने के बाद देर रात दरिंदों ने उनके साथ हैवानियत की। हालांकि, इस मामले में आरोपित गिरफ्तार कर लिए गए हैं, पर यह महिलाओं की सुरक्षा पर एक बड़ा प्रश्न है। इस तरह की घटनाएं नहीं हों, इसके लिए गंभीरता से प्रयास करने होंगे। प्रशासन के साथ समाज का भी यह दायित्व बनता है कि महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध सामाजिक स्तर पर मोर्चा खोलें। किसी के भी साथ इस तरह की घटना महिलाओं की अस्मिता पर प्रहार है, जिसे कोई भी सभ्य समाज कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। औरंगाबाद में भी एक नाबालिग का शादी की नीयत से अपहरण कर लिया गया, हालांकि पुलिस ने उसे बरामद करते हुए आरोपित को भी गिरफ्तार कर लिया। इस तरह की त्वरित कार्रवाई आवश्यक है, ताकि कानून के प्रति भय रहे। आज महिलाएं कार्यस्थलों पर जा रही हैं, बेटियां स्कूल-कालेज जा रही हैं और उनके साथ किसी तरह की घटना होती है तो असुरक्षा का भाव उनको मानसिक स्तर पर कमजोर कर देता है। इस तरह की कोई भी घटना पूरे समाज के लिए कलंक है, जिसे रोकना ही होगा। पुलिस को इसमें महती भूमिका अदा करनी होगी। इस प्रकार की घटनाओं को प्राथमिकता में रखते हुए दोषियों को शीघ्र से शीघ्र सजा दिलानी होगी, ताकि उसका एक संदेश जाए कि कानून से कोई बच नहीं सकता है। कई मामलों में देखा गया है कि कार्रवाई की धीमी गति के कारण आरोपित छूट जाते हैं और पीड़ित पक्ष उनके भय से दबाव में आ जाता है।

कार्रवाई की धीमी गति के कारण आरोपित छूट जाते हैं और पीड़ित पक्ष उनके भय से दबाव में आ जाता है

कह के रहेंगे

माधव जोशी

यह भी ठीक रहा...जल भराव से बदनाम होने वाली जगहों को हमने पहले ही 'जल संचय केंद्र' कहकर प्रचारित कर दिया!

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पाकिस्तान जाना चाहिए?

आज का सवाल

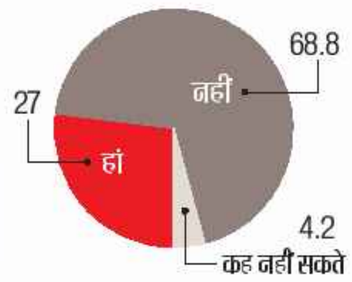

क्या चम्पाई सोरेन के भाजपा में शामिल होने से पार्टी को चुनावी लाभ मिलेगा?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

संजय गुप्त

नए औद्योगिक शहरों की स्थापना करते समय उन कारणों पर ध्यान देना आवश्यक है, जिनके चलते स्मार्ट सिटी योजना उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने औद्योगिक कारिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 10 राज्यों में 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी विकसित करने की जिस योजना को हाल में मंजूरी दी, वह समय की मांग थी। इस फैसले के अनुसार उत्तराखंड में खुरपिया, पंजाब में राजपुरा, उत्तर प्रदेश में आगरा एवं प्रयागराज, बिहार में गया, महाराष्ट्र में दिघी, राजस्थान में जोधपुर-पाली, आंध्र प्रदेश में कोपर्थी एवं ओर्वाकल, तेलंगाना में जहीराबाद और केरल में पलक्कड़ में नए औद्योगिक शहर स्थापित किए जाएंगे। इसी तरह का एक शहर हरियाणा में स्थापित होगा। ये शहर बड़े औद्योगिक गलियारों के आसपास विकसित होंगे। ज्ञात हो कि आम बजट में इन औद्योगिक शहरों की स्थापना की घोषणा की गई थी। सरकार का मानना है कि इन औद्योगिक शहरों के विकास में 28,602 करोड़ रुपये का निवेश होगा और इन शहरों में 1.50 लाख करोड़ का औद्योगिक निवेश आएगा, जिससे 10 लाख प्रत्यक्ष जबकि 30 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी। फिलहाल कहना कठिन है कि ये शहर कब तक स्थापित हो सकेंगे और देश को उनसे कब तक लाभ मिलने लगेगा, क्योंकि सरकार की बड़ी योजनाएं तय समय में कठिनाई से ही पूरी होती हैं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अतीत में इस तरह की कुछ महत्वाकांक्षी घोषणाएं सही तरह आगे नहीं बढ़ सकीं और कुछ तो अपनी अहमियत खो बैठीं। उदाहरणस्वरूप विशेष आर्थिक जोन यानी एसईजेड उस तरह स्थापित नहीं हो सके, जैसी उम्मीद की जा रही थी। स्पष्ट है कि सरकार को इसके लिए विशेष प्रयास करने होंगे कि 12 नए औद्योगिक शहरों की स्थापना का लक्ष्य तय समय में सही तरह पूरा हो।

नए औद्योगिक शहरों को बसाने में तब कामयाबी मिलेगी, जब सरकार को निजी क्षेत्र का हरसंभव सहयोग मिलेगा। यह सहयोग तभी संभव है, जब निजी क्षेत्र को इनमें आकर्षण दिखेगा। ध्यान रहे कि कुछ प्रस्तावित औद्योगिक शहर बड़े शहरों से दूर हैं। इसके चलते कुशल कारीगर और प्रबंधन के दक्ष लोग वहां रहना चाहेंगे या नहीं, यह भविष्य ही बताएगा। निःसंदेह देश को ऐसे शहरों की आवश्यकता तो है, लेकिन जब तक उनमें अच्छी-खासी संख्या में उद्योग स्थापित नहीं हो जाते और नागरिक आबादी की बसाहट के लिए उपयुक्त आधारभूत ढांचे का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक वे लोगों के आकर्षण का केंद्र नहीं बनेंगे। यदि ये नए शहर अच्छी तरह बसाए जा सके तो उनके पास के बड़े शहरों में आबादी का बोझ कम किया जा सकता है। इन बड़े शहरों का आधारभूत ढांचा चरमरा रहा है। यह किस तरह चरमरा रहा है, इसका प्रमाण मानसून के इन दिनों में अच्छी तरह देखा जा सकता है। इन दिनों देश के कई बड़े शहर जलभराव से त्रस्त हैं। कुछ शहर तो बाढ़ के प्रकोप का सामना कर रहे हैं और इसके चलते उनका आधारभूत ढांचा और भी तेजी से खराब हो रहा है। कहने को तो देश के हर शहर के नगर निकायों ने मानसून से पहले जल निकासी का प्रबंध करने के दावे किए थे, लेकिन वे दो-चार बार की बारिश के बाद ही दम तोड़ गए। इस मामले में राजधानी दिल्ली की स्थिति भी दयनीय है। शहरों में जल निकासी और खासकर वर्षा जल निकासी की जो व्यवस्था है, वह गई-बीती ही अधिक है। यह व्यवस्था अपर्याप्त तो है ही, खराब इंजीनियरिंग एवं अतिक्रमण के कारण और भी दुर्दशाग्रस्त हो गई है। हमारे कई शहर ऐसे हैं, जहां सीवरेज की व्यवस्था आधी-अधूरी है।

अवधेश राजपूत

अब जब केंद्र सरकार 12 नए औद्योगिक शहर विकसित करने जा रही है, तब उसे बड़े शहरों के आधारभूत ढांचे की भी सुध लेनी चाहिए। कायदे से छोटे शहरों के आधारभूत ढांचे को भी संवारा जाना चाहिए, लेकिन यह तो वह काम है, जिसे राज्य सरकारों को करना है। समस्या यह है कि राज्य सरकारें इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही हैं। इसके चलते नगर निगम जैसी संस्थाओं की कार्यप्रणाली सुधरने का नाम नहीं ले रही है। यह सही समय है कि नगर निगमों, नगर पालिकाओं के कामकाज को ठीक करने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। यह राज्य सरकारों की प्राथमिकता के अभाव का ही परिणाम रहा कि स्मार्ट सिटी योजना अपेक्षित नतीजे नहीं दे सकी। औद्योगिक शहरों की स्थापना करते समय उन कारणों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है, जिनके चलते स्मार्ट सिटी योजना उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी। स्मार्ट सिटी योजना के संचालन के बाद भी नगर निकायों और शहरी ढांचे संबंधी अन्य सरकारी एजेंसियों की कार्यप्रणाली में कोई उल्लेखनीय बदलाव नहीं आ सका है। यह इसीलिए नहीं आ सका, क्योंकि इन संस्थाओं का कामकाज बेहतर करने की जिम्मेदारी जिन जनप्रतिनिधियों और नौकरशाहों की थी, उन्हें जवाबदेह नहीं बनाया जा सका। इन्हें जिम्मेदार और जवाबदेह बनाए बिना शहरों के आधारभूत ढांचे को सुधारा नहीं जा सकता।

निःसंदेह नगर निकायों के साथ आम जनता को भी जिम्मेदार बनना होगा। उन्हें आधारभूत ढांचे संबंधी नियम-कानूनों के पालन के प्रति सजग रहना होगा। बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण इसीलिए होते हैं, क्योंकि आम लोग संबंधित नियम-कानूनों का पालन नहीं करते। जब कहीं एक-दो जगह अवैध निर्माण हो जाता है, तो बाकी के लिए वह नजीर बन जाता है। जब अवैध निर्माण या अतिक्रमण हो रहा होता है, तब उसे कोई रोकने-टोकने वाला नहीं होता। इसी के चलते झुग्गी बस्तियां स्थापित हो जाती हैं। जब उनमें आबादी बढ़ जाती है तो उन्हें वैध करार देने की पहल होने लगती है। वोट बैंक के लालच में सरकारें भी अवैध तरीके से बनाई गई बस्तियों और कालोनियों को नियमित कर देती है। जब ऐसा होता है तो अनियोजित विकास को बढ़ावा मिलता है और वह शहरों की सूरत बिगाड़ता है। यदि जनता आधारभूत ढांचे के सुनियोजित विकास को लेकर जागरूक नहीं होती तो शहरों की जो समस्याएं हर वर्ष बढ़ती जा रही हैं, वे विकराल होती जाएंगी और उनका समाधान अत्यंत कठिन हो जाएगा। शहरों का बिगड़ता आधारभूत ढांचा उनमें रहने वाले लोगों के समक्ष त्राहिमाम की स्थिति ही पैदा करेगा। हमारे नीति-नियंताओं को इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि शहर विकास के इंजन होते हैं और यदि उनके आधारभूत ढांचे को ठीक नहीं किया गया तो आर्थिक विकास के लक्ष्य को पाना कठिन ही होगा।

response@jagran.com

वफादार की वफादारी पर संदेह

हास्य-व्यंग्य

मेरे जिले के एक नामचीन नेता आजकल अपने कुत्ते को लेकर कुपित हैं। वह अक्सर उस मनहूस घड़ी को पानी पी-पी कर कोस रहे हैं, जब उनका राजनीति के स्वर्ण महल में प्रवेश नहीं हुआ था और उन्होंने इस नामाकूल कुत्ते को पाल लिया था। वैसे पानी पी-पी कर कोसना तो एक मुहावरा है। हकीकत यह है कि इस पानी में एक मादक द्रव्य भी मिला होता है, जिसमें गम को गलत करने और हर्ष का आनंद लेने की क्षमता समान रूप से देखी जाती है। इसे चुनाव के दौरान बांटकर अपनी जीत भी पक्की की जाती है और अपने कुछेक शौकीन कार्यकर्ताओं की थकान को भी मिटाया जाता है। नेताजी का कुत्ता भी कोई कम शौकीन नहीं है। वह भी अवसर का लाभ उठा लेता है। बचे हुए द्रव्य को चाटता है और मना करने पर अपने स्वामी के चरण चाट कर उनको मना भी लिया करता है। यूं भी राजनीति में अपने से बड़े लीडर के तलवे चाटने और चरण-चुंबन को अनिवार्य गुण कहा गया है।

नामचीन नेता ने यह सुन रखा था कि कुत्ता एक वफादार जानवर है। वफादार कुत्ते अपने मालिक की मर्जी के बिना दुम तक नहीं हिलाते। कुत्ता अपनी गली का शेर भी होता है। इस कारण नेताजी ने उसे पाल लिया, लेकिन वही कुत्ता अब उनके ही काम नहीं आ रहा है। उसकी निष्ठा मौकापरस्त दलबदलुओं जैसी होती जा रही है। वह दौर ही और था, जब कुत्ते वफादारी का पर्याय समझे जाते थे। तब राजनीति में भी वफादारी को भली निगाहों से देखा जाता था। बड़े के सामने छोटा जुबान तक नहीं निकालता था। ऐसों को पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता या निष्ठावान सिपाही कहा जाता था। आज आत्मसमर्पण भी गाजे-बाजे के साथ होता है।

सूर्यकुमार पांडेय

नेता जी को शिकायत है कि जो कुत्ता पहले सिर्फ चोरों को देखकर भौंका करता था, अब खुद उन पर भी गुर्रा उठता है

कुत्ते का नाम आते ही नेताजी उस वक्त की यादों में उलझ जाते हैं, जब उनके साथ उनका एक अदद पिछलग्गू, जिसे आम बोलचाल की भाषा में चमचा कहा जाता था, हुआ करता था। मंत्री जी के पास तब यह कुत्ता नहीं था। इस नाते उनकी सारी बातें अपने चमचे के बारे में हुआ करती थीं। वह कहते थे, 'एक दिन के लिए भी इधर-उधर नहीं बहका। महत्वाकांक्षा उसे छू तक नहीं पाई। उसने अपनी तमाम जवानी, जिसे पोलिटिकल करियर कहा जाता है, नेता जी की चापलूसी में लगा दी। वह वफादारी का पट्टा अपने गले में डाले रैलियों के लिए भीड़ जुटाता रहा, चंदे की रसीदें झोले में भरकर दर-दर भटकता रहा। प्रदर्शनों, धरनों, जुलूसों में सबसे आगे रहकर पार्टी का झंडा थाम कर डंडे खाता रहा।' अपने चमचे की तारीफ के पुल बांधते नेता जी कह उठते, 'जब-तब मेरी रक्षा के लिए उसने मेरे राजनीतिक दुश्मनों पर भौंकने में भी कोर-कसर बाकी नहीं रखी और एक यह कुत्ता! इसने तो मेरी नाक कटा दी! नेता-नगरी में मुझे किसी को मुंह दिखलाने के काबिल नहीं छोड़ा। इतने दिनों का पुराना साथ और थोड़ा सा लगाव न होता तो मैं कब का दो लातें जमाकर भगा देता।'

नेता जी को शिकायत है कि जो कुत्ता पहले सिर्फ चोरों को देखकर भौंका करता था, अब खुद उन पर भी गुर्रा उठता है। सारी ट्रेनिंग बेकार गई। चोर का कुत्ता चोर पर ही भौंकने लगे तो उसे गोली मार देनी चाहिए। वह मार भी दें, मगर जब भी यह विचार उनके दिमाग में कौंधता है तो उन्हें चतुर्दिक कुत्ते ही कुत्ते नजर आने लगते हैं, किस-किस को मारेंगे। वह उस दिन को कोसते हैं, जब उन्होंने कुत्ता पाला था। यूं तो उनके पूर्ववर्ती और समकालीन नेता हाथी, बैल, गाय और बकरी वगैरह पालते रहे थे, किंतु उन्हें कुत्ता-पालन अपने स्वभाव के अनुरूप लगा था। कुत्ते को कहीं पर भी अपने साथ ले जा सकते हैं। यह छूट और जानवरों के साथ मुमकिन नहीं थी। कुत्ता सोते-जागते नेताजी के साथ रहता है। कहते हैं कि अगर किसी कुत्ते में महत्वाकांक्षा का बोध जाग जाए तो फिर वह कुत्ता नहीं रह जाता। वह अपनी अलग जमात बना लेता है। गली-मोहल्ले के तमाम कुत्ते उसके साथ हो लेते हैं। नेता जी आजकल कुत्ते से कुपित तो हैं, लेकिन उन्होंने उससे समझौता कर लिया है। उन्हें पता है कि जब तक कुत्ता रखवाला है, उनकी राजनीति सुरक्षित है।

response@jagran.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid

तथ्य-कथ्य देश के सबसे धनी व्यक्ति

(संपत्ति करोड़ रुपये में)

स्रोत : हुरुन इंडिया रिच लिस्ट

ऊर्जा

सुख का सूत्र

हम सभी जीवन की दौड़ में भागते हुए भले ही अपने उद्देश्य पूर्ति से सुख की कामना करते हों, परंतु फिर भी कभी न कभी इस प्रश्न पर अटक जाते हैं कि सुख क्या है? हमें किस प्रकार का सुख चाहिए? क्या सुख की संकल्पना हमारे मन में पूरी तरह स्पष्टता के साथ आकार ले पाती है? कभी-कभी सुख का तात्पर्य हम तृप्ति या संतुष्टि को समझते हैं, कभी सफलता को और कभी मोक्ष को या कभी भौतिक संसाधनों के संग्रह एवं उनसे मिली सुविधाओं को। कुल मिलाकर हम जिस एक वस्तु की इच्छा लिए जीवन भर भागते रहते हैं, कई बार हमें उसका अर्थ ही स्पष्ट नहीं होता।

ऐसे में, यही श्रेयस्कर है कि हमें जीवन का उद्देश्य स्पष्ट रखते हुए उसकी तरफ बढ़ते रहना चाहिए। साथ ही साथ भूत या भविष्य की चिंता किए बिना उद्देश्य प्राप्ति की इस यात्रा में आने वाले हर एक पल का आनंद भी लेना चाहिए। तभी हमारे जीवन में उद्देश्य प्राप्ति की यह प्रक्रिया हमें निश्चित ही सुख की अनुभूति कराएगी, क्योंकि सुख का संबंध तो अंतर्मन से है। जब तक हमारा मन सुख का अनुभव न करे, तब तक कितने भी भौतिक साधन हमारे लिए सुख नहीं जुटा सकते। जो वास्तविक सुख हम इस बाहरी दुनिया में खोजते हैं, वह हमें कभी भौतिक साधनों के जरिये नहीं मिल सकता। हमें सच में सुख चाहिए तो मन के सुख की खोज करनी होगी।

हमारा उद्देश्य यदि हमारी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के साथ-साथ समाज कल्याण में भी सहायक है, तो अवश्य ही वह हमें सुख प्रदान करेगा। इसलिए, सदैव मन को शांत रखते हुए अपने कार्य को प्रेमपूर्वक करते रहना चाहिए और हमेशा यह स्मरण रखना चाहिए जो है वह इसी पल में निहित है। न इससे पहले वाला पल हमारे वश में हो सकता है और न इस पल के बाद आने वाला पल हमारे वश में होगा। यह ध्यान रखते हुए जब हम हर पल का आनंद लेने लगेंगे, तब अवश्य ही हमें सुख की प्राप्ति होगी।

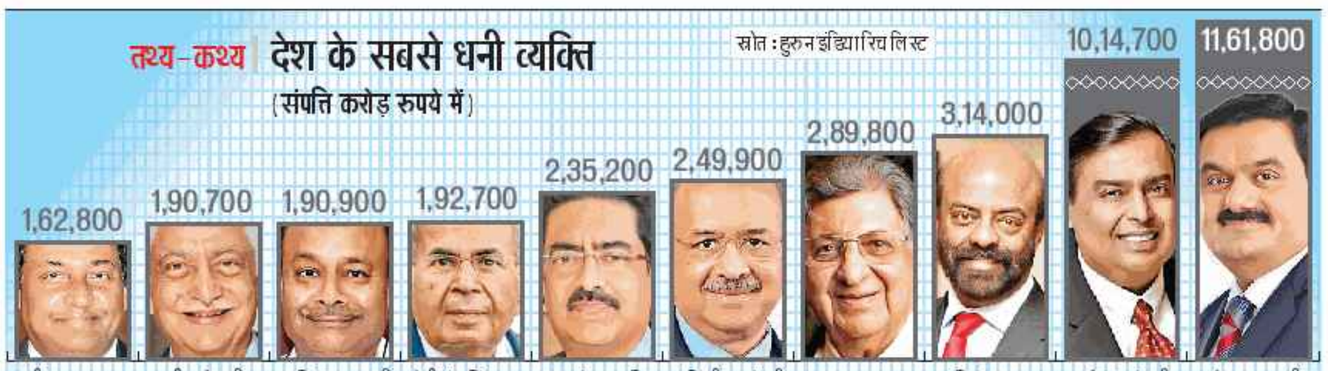

प्रियंका कटारे

जनगणना पर संशय

जनगणना होनी है, लेकिन यह कब होगी, इसे लेकर अभी भी संशय कायम है। पहले ऐसी खबरें आईं कि सितंबर से जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। हालांकि जितनी तेजी से ऐसी अटकलें लगाई जाने लगीं, गृह मंत्रालय के शीर्ष अमले ने इसके खंडन में उतनी ही तत्परता दिखाई। ऐसे में यह सवाल जस का तस बना हुआ है कि जनगणना कब शुरू होगी, जो पहले से ही काफी समय से अटकी हुई है। पिछले दिनों रायपुर में अमित शाह से भी एक पत्रकार ने जनगणना को लेकर सवाल पूछा, लेकिन उन्होंने इसे यह कहते हुए टाल दिया कि जब भी शुरू होगी तो मीडिया को सबसे पहले बताया जाएगा। माना जा रहा है कि विपक्ष के साथ-साथ कुछ सहयोगी दलों की ओर से भी जनगणना के साथ ही जाति की गणना की मांग ने इस कवायद को राजनीतिक रूप से संवेदनशील बना दिया है। ऐसे में, सरकार इस पर फूंक-फूंक कर कदम रखते हुए किसी भी तरह के विवाद से बचना चाहती है।

राजभवन में बेचैनी

झारखंड में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, किंतु बेचैनी ओडिशा के राजभवन में महसूस की जा रही है। सुनने में आया है कि राज्यपाल रघुवर दास का मन भुवनेश्वर के राजभवन में नहीं लग रहा है। वह बार-बार रांची, जमशेदपुर और दिल्ली के दौरे कर रहे हैं। झामुमो नेता चम्पाई सोरेन के भाजपा में आने से पहले प्रधानमंत्री मोदी के साथ झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की मुलाकात ने रघुवर को कुछ ज्यादा ही बेचैन कर दिया। भागे-भागे दिल्ली आकर उन्होंने भी बिन मांगे आलाकमान को फीडबैक दे दिया। अहसास करा गए कि वह भी दावेदार हो सकते हैं। तर्क दिया कि लोकसभा चुनाव में राज्यपाल रहे दिग्गज

राजरंग

भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। रघुवर की बेचैनी इसलिए भी बढ़ रही है कि झारखंड में चार पूर्व मुख्यमंत्री पहले से भाजपा का चेहरा बने हुए हैं। सिर्फ रघुवर का नाम छूट रहा है। इसलिए उन पर समर्थकों का दबाव बढ़ रहा है कि वह भी अपनी दावेदारी को आगे करें।

व्यथित करते अनुरोध

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एक्स हैंडल पर पोस्ट चाहे कोई भी हो, उस पर कमेंट एक जैसे होते हैं। ये कमेंट कम गुजारिशों का सिलसिला अधिक होते हैं। मसलन, इनमें लिखा होता है-टैक्स कम कर दो मैडम, जीएसटी से नुकसान हो रहा है ताई, व्यापार डूब रहा है मैडम आदि-आदि। ऐसा ही एक वाकया 30 अगस्त को सामने आया जब इंडियन स्टील एसोसिएशन के पदाधिकारी सांसद एवं उद्यमी नवीन जिंदल के नेतृत्व में सीतारमण से मिलने आए, जिसे वित्त मंत्री ने एक्स पर पोस्ट भी किया। इस पोस्ट पर पहला कमेंट है-हेल्थ इंश्योरेंस पर 18 प्रतिशत जीएसटी हटा दो मैडम। वित्त मंत्री के हर पोस्ट पर टैक्स हटाने की मांग को लेकर कई कमेंट मिल जाएंगे। कई कमेंट में निर्मला ताई और निर्मला आंटी के रूप में वित्त मंत्री को संबोधित किया जाता है। वित्त मंत्री लोगों की इन हरकतों से वाकिफ भी हैं और कुछ व्यथित भी। हाल में पत्रकारों के साथ एक अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने लोगों की परेशान करने वाली इन हरकतों का जिक्र भी किया।

'घर की मुर्गी....'

कहावतों का किस्सा ही कुछ ऐसा है कि हर दौर में वे खरी उतरती हैं। जैसे कि घर की मुर्गी दाल बराबर वाली कहावत को ही लीजिए। यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर सटीक बैठती नजर आती है। एक तरफ इंग्लैंड का साउथैम्प्टन विश्वविद्यालय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देखते हुए भारत में कैंपस खोलने पहुंच गया है तो दूसरी ओर तमिलनाडु है, जिसने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विरोध को लेकर पीएम-श्री स्कीम पर शिक्षा मंत्रालय के साथ करार करने से ही इन्कार कर दिया। साउथैम्प्टन विश्वविद्यालय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत छात्रों को पढ़ाना चाहता है, तो तमिलनाडु और बंगाल जैसे राज्य इसे लागू करने के लिए कतई तैयार नहीं हैं। दुनिया में जिस नीति की तारीफ हो रही है, देश के भीतर उसके विरोध का तर्क शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों की समझ में नहीं आ रहा है। लगता है कि अपने ही देश के राज्य इसकी खासियतों को अनदेखा कर रहे हैं, जबकि विदेशियों को इसकी आभा अपनी ओर खींच रही है।

पोस्ट

वेब सीरीज आइसी-814 में अनुभव सिन्हा ने आतंकियों को भले मानुस के रूप में दर्शाया है। इसके बावजूद वामपंथी कहते हैं कि वे कला का राजनीतीकरण नहीं करते। मोनिका वर्मा@TrulyMonica

मैंने बहुत सोचने का प्रयास किया, लेकिन यह समझ नहीं आया कि आखिर मीडिया को अपराधियों के नाम और फोटो क्यों नहीं प्रकाशित करने चाहिए? वह भी तब जब उन्होंने बेहद जघन्य अपराध किया हुआ हो? सिंधुवासिनी त्रिपाठी@Sindhuvasini

यूएस ओपन में जोकोविक और अलकराज दोनों हार गए। अब फेडरर, नडाल और जोकोविक की तिकड़ी की अंतिम कड़ी की आभा भी घट रही है। उम्र आखिर पकड़ ही लेती है। एक वक्त के बाद कला एवं अनुभव पर ताकत और युवावस्था की फिटनेस हावी हो जाती है। सुशील दोशी@RealSushilDoshi

कितनी बड़ी विडंबना है कि 'वी डेम' जैसे संस्थान तमाम देशों में लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मापने का दावा करते हैं, लेकिन जब उनसे कोई सवाल पूछ लिया जाए तो वे सवाल करने वाले को ही ब्लाक कर देते हैं। असल में ये दोहरे चरित्र और संदिग्ध रवैये वाले संस्थान हैं। सुशांत सरीन@sushantsareen

जनपथ

छक्के पर छक्का जड़ा बने सुपर स्टार,
अबकी युवा प्रियांश पर होगी आरम्पार।
होगी आरम्पार चढ़ेगी जमकर बोली,
पक्का है इस बार भरेगी उनकी झोली।
बन बैठे हो आप तुरुप का अब तो इक्का,
झूम उठे मैदान लगे छक्के पर छक्का!

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त
जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प. बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 25 अंक 141

****

“ जो किसी देश के संपूर्ण धन को नियंत्रित करता है, वह सभी उद्योग और वाणिज्य का मालिक है। -जेम्स ए गारफील्ड

अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति जेफरसन ने केंद्रीय बैंक का विरोध कर दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका का संविधान, फेडरल सरकार को बैंक बनाने और मुद्रा जारी करने का अधिकार नहीं देता है। यह काम तो राज्यों को मिलेगा। वह कह रहे हैं, 'केंद्रीय बैंक आम लोगों की आजादियों के लिए किसी हथियारबंद सेना से ज्यादा खतरनाक है।'

फेडरल रिजर्व

अमेरिकी अर्थव्यवस्था का नायक और खलनायक

जब अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने केंद्रीय बैंक को मार दिया

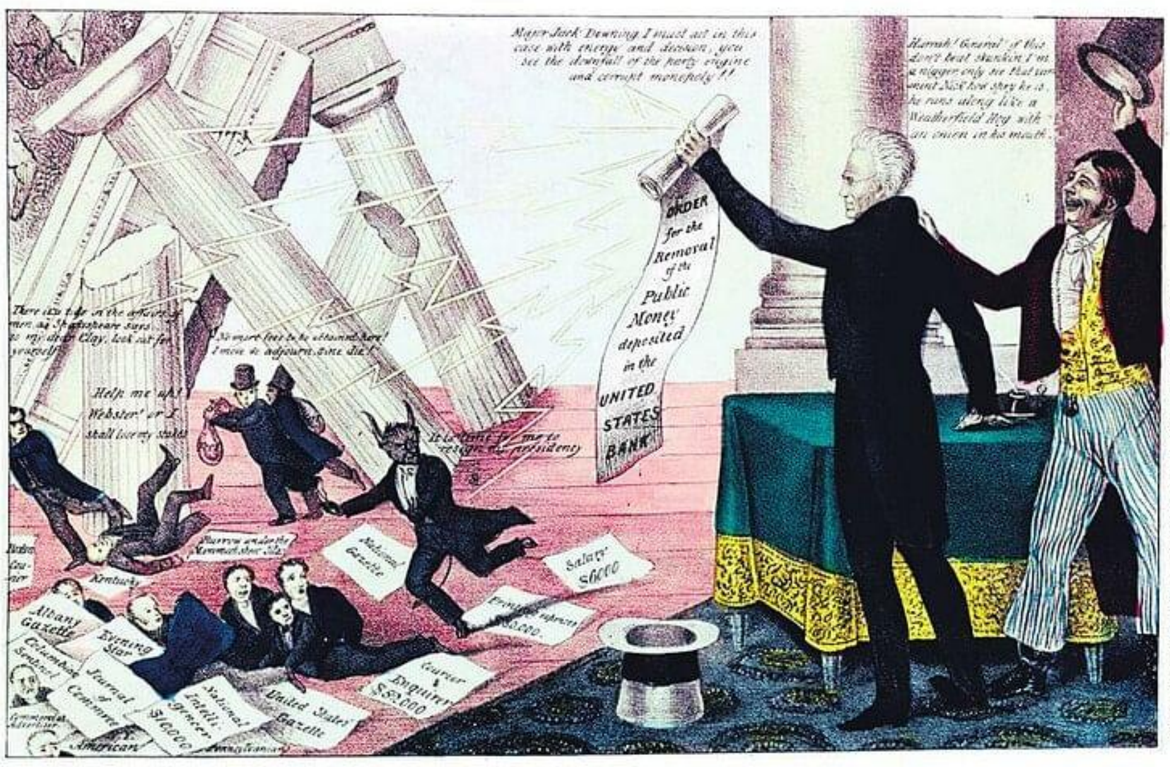

"Downfall of Mother Bank" by Henry R. Robinson, 1833. © Collection of the New York Historical Society / Bridgeman Art Library

एंड्र्यू जैक्सन और थॉमस जेफरसन, दोनों राष्ट्रपति केंद्रीय बैंकों के जानी दुश्मन थे। लेकिन वक्त इनसे ज्यादा ताकतवर निकला। वर्ष 1913 में फेडरल रिजर्व की स्थापना हुई, जो महंगाई को लेकर सख्त है। अमेरिकियों को लग रहा है कि फेडरल रिजर्व मंदी को बुलाकर ही मानेगा।

अंशुमान तिवारी
वरिष्ठ लेखक-पत्रकार

अगस्त की शुरुआत में जब दुनिया में मंदी का हल्ला हुआ, शेयर बाजार नई गर्त में जा धंसे, तो इस मुसीबत का खलनायक किसे माना गया? वही अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व। अमेरिका के शेयर कारोबारी अब फेडरल रिजर्व को रह-रहकर कोसते हैं। बार-बार शेयर बाजार गिराकर वे यह साबित करना चाहते हैं कि अगर ब्याज दरें नहीं घटीं, तो मंदी आई समझो।

अमेरिका में चुनाव का मौसम है, गिरते बाजार और मंदी की खबरें सरकारों को नहीं सुहातीं। फेडरल रिजर्व अमेरिकी अर्थव्यवस्था का पुराना नायक भी है और खलनायक भी। पूंजीवाद की महापीठ अमेरिका में महंगी पूंजी यानी ऊंची ब्याज दर को बिसूरने वाले बहुतेरे हैं। कोविड के बाद महंगाई बढ़ी, तो फेडरल रिजर्व ने कर्ज महंगा किया। बाजार में कम पूंजी आई और यह दवा चाटकर महंगाई का बढ़ना रुक गया। अलबत्ता महंगाई गई नहीं।

फेडरल रिजर्व सख्त है। उसकी सख्ती कुछ इस कदर बढ़ी है कि अमेरिकियों को लग रहा है कि फेडरल रिजर्व मंदी बुलाकर ही मानेगा। अमेरिकी सियासत का अतीत फेडरल रिजर्व को लेकर बड़ा ही रोमांचक रहा है। अगर आपको लगता है कि अमेरिकी सियासत में सबसे ज्यादा विवादित नेता डोनाल्ड ट्रंप हैं, तो आइए बैठिए टाइम मशीन में, हम आपको मिलवाते हैं ऐसे राष्ट्रपतियों से, जिन्होंने केंद्रीय बैंक को मार दिया।

यह 1836 का अमेरिका है। हम सीधे वाशिंगटन पहुंचे हैं। खबर है कि सातवें राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन ने बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की कानूनी मान्यता बढ़ाने यानी रि-चार्टर के प्रस्ताव पर वीटो ठोक दिया...और अमेरिका का केंद्रीय बैंक यानी फेडरल रिजर्व का पूर्वज बंद (1836) कर दिया गया।

हम जिस दौर में हैं, अमेरिका के सातवें राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन और तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन लोगों के नूरे-नजर हैं। ये दोनों राष्ट्रपति केंद्रीय बैंकों के जानी दुश्मन हैं। इन्होंने तय कर दिया कि आगे अमेरिका में कोई केंद्रीय बैंक नहीं होगा। अलबत्ता वक्त इनसे ज्यादा ताकतवर निकलेगा।

आइए, हम थोड़ा और पीछे चलते हैं। टाइम मशीन हमें उस काल खंड में ले आई है, जहां अमेरिकी आजादी की लड़ाई खत्म हो गई है। आजादी की लड़ाई ने अमेरिका को आर्थिक तौर पर तोड़ दिया है। अमेरिकी संविधान को मंजूरी (1789) मिल गई है। पहले वित्तमंत्री अलेक्जेंडर हैमिल्टन देश में कर्ज और पूंजी की समस्या दूर करने के लिए फेडरल बैंकिंग का प्रस्ताव लेकर आए हैं। अमेरिकी कारोबारियों के बीच बहस जारी है। हैमिल्टन की तैयारी एक ऐसा बैंक बनाने की है, जो ब्रिटेन की उपनिवेशवादी मौद्रिक प्रणाली समाप्त कर नेशनल करेंसी लागू करेगा। अमेरिकी मुद्रा डॉलर होने वाली है। सियासत गर्म है। अमेरिका के पश्चिम हिस्से के कारोबारी इस बैंक का विरोध कर रहे हैं। राजनीतिज्ञ विभाजित हैं। अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित संस्थापक नेता, आजादी के प्रबल समर्थक और जॉर्ज वाशिंगटन की कैबिनेट में विदेश मंत्री थॉमस जेफरसन ने भी इस केंद्रीय बैंक का विरोध कर दिया है। वह कह रहे हैं कि अमेरिका का संविधान, फेडरल सरकार को बैंक बनाने और मुद्रा जारी करने का अधिकार नहीं देता है। यह काम तो राज्यों को मिलेगा। वह कह रहे हैं, 'केंद्रीय बैंक आम लोगों की आजादियों के लिए किसी हथियारबंद सेना से ज्यादा खतरनाक है।' और यह लीजिए, अमेरिकी कांग्रेस में बखेड़ा हो गया। जेफरसन, जॉर्ज वाशिंगटन सरकार में विदेश मंत्री हैं और हैमिल्टन वित्तमंत्री। हैमिल्टन और जेफरसन के बीच तीखा विवाद हुआ है। अलबत्ता फेडरलिस्ट पार्टी की मदद से 1791 में अमेरिका के केंद्रीय बैंक का प्रस्ताव मंजूर हो गया। बुरी तरह खफा थॉमस जेफरसन ने (1793) कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है।

आगे बढ़ते हैं। यह 19वीं सदी की शुरुआत है। थॉमस जेफरसन व्हाइट हाउस में विराज रहे हैं। केंद्रीय बैंक को वह चलने नहीं देंगे। हैमिल्टन का केंद्रीय बैंक बीस साल तक चला। इसके बाद अमेरिकी संसद ने इसे मंजूरी नहीं दी। अब अमेरिका का केंद्रीय कर्ज और मौद्रिक ढांचा खत्म हो गया। विभिन्न राज्य उपनिवेश युग की तरह मुद्राएं जारी करने लगे हैं।

अब हम 19वीं सदी के पहले दशक में हैं। थॉमस जेफरसन का कार्यकाल 1809 में खत्म हो रहा है। केंद्रीय बैंक का विरोध ठंडा पड़ रहा है। अमेरिकी कांग्रेस ने आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए नए बैंक का प्रस्ताव मंजूर (1816) किया। यह अमेरिका का दूसरा केंद्रीय बैंक है। उम्रदराज होगा कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। यह 1836 का दौर है और एंड्रयू जैक्सन राष्ट्रपति बने हैं। अमेरिकी राजनीति में बैंक वार शुरू हो गया है। अखबार चीख रहे हैं कि राष्ट्रपति जैक्सन और बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के अध्यक्ष निकोलस बिडेल के बीच सीधी लड़ाई हो रही है। राष्ट्रपति जैक्सन केंद्रीय बैंक को भ्रष्टाचार का गढ़ मानते हैं। उन्होंने अपने वीटो का इस्तेमाल कर केंद्रीय बैंक को खत्म कर दिया। अमेरिकी सरकार का पैसा अब केंद्रीय बैंक में नहीं जमा होगा। यह अमेरिका में फ्री बैंकिंग का दौर है। राज्यों में करीब 8,000 बैंक हैं, जो अगले 25 साल तक अपनी करेंसी चलाएंगे। इस बीच अमेरिका में सिविल वार शुरू हो गया है। लड़ते-जूझते अमेरिकियों को लग रहा है कि मुद्राओं की अराजकता अब बंद होनी चाहिए।

अब हम 19वीं सदी के मध्य में हैं। अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान (1863) नेशनल बैंकिंग ऐक्ट फिर आया है। इसके जरिये एकल मुद्रा प्रणाली स्थापित हो रही है। अलबत्ता कोई सेंट्रल या फेडरल बैंक नहीं बनाया गया है। नए कानून में अनुमति प्राप्त बैंकों को ही करेंसी जारी करने की छूट दी गई है। मुद्राओं की अराजकता बैंकिंग संकट लेकर आई है। यह बीसवीं सदी की शुरुआत है और विकेंद्रित सरकारी बैंक पूंजी की कमी से डूबने लगे हैं।

इन्हें पहचानते हैं आप...यह हैं जॉन पियरपांट मॉर्गन यानी जेपी मॉर्गन। तब के अमेरिका के धनाढ्य बैंकर और फाइनेंसर। अमेरिकी सरकार इनकी शरण में है। इनकी पूंजी से बैंक उबारे जा रहे हैं। मॉर्गन 19वीं सदी के अंत में सोना देकर सरकार को संकट उबार चुके थे। 21वीं सदी में लौट कर आप जेपी मॉर्गन चेज समूह से मिलेंगे, जो पुराने मॉर्गन का उत्तराधिकारी है।

अब हम वापसी की उड़ान पर हैं। अमेरिका में 1907 के बैंकिंग संकट से सबक सीखे जा रहे हैं। सियासत में लंबी चर्चा चली है। 1913 में फेडरल रिजर्व की स्थापना हुई। इसके बाद 1935 में अमेरिकी कांग्रेस बैंकिंग कानून के तहत फेडरल ओपन मार्केट कमेटी बनाएगी, जो 21वीं सदी में पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाली बैंकिंग नीतियां तय करेगी। टाइम मशीन का सफर न्यूयॉर्क में खत्म होगा, जहां शेयर बाजार फेडरल रिजर्व को उसी तरह कोस रहे हैं, जैसे जेफरसन-जैक्सन कोसते थे। हम फिर मिलेंगे अगले सफर पर...

https://t.me/AllNewsPaperPaid

जीवन का उद्देश्य ढूंढें, नहीं तो बिल चुकाते रहेंगे

जैक निकास
द न्यूयॉर्क टाइम्स

सब पर हावी बाजार ने ऐसी लालची संस्कृति पैदा की है, जो हमारी सहज प्रवृत्ति पर हावी है।

एक दशक पहले दुनिया जोस मुजिका की दीवानी थी। वह उरुग्वे के मिलनसार राष्ट्रपति थे, जिन्होंने राष्ट्रपति भवन को त्यागकर अपनी पत्नी और तीन पैरों वाले कुत्ते के साथ टीन की छत वाले एक छोटे से घर में रहना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने जीवन की ऐसी अनगिनत कहानियां साझा कीं, जिस पर फिल्म बन सकती है। वामपंथी शहरी गुरिल्ला के रूप में उन्होंने बैंक लूटा था और 15 साल तक जेल में रहे और जमीन के एक छोटे से छेद में रहने वाले मेंढक से दोस्ती की।

इन कहानियों से परे उन्होंने अपने छोटे से दक्षिण अमेरिकी देश को दुनिया के सबसे स्वस्थ और सामाजिक रूप से सबसे उदार लोकतंत्रों में से एक बनाया। लेकिन उनकी विरासत उनके जीवन के रंगीन इतिहास और मितव्ययिता के प्रति प्रतिबद्धता से ज्यादा है। बेहतर समाज और खुशहाल जीवन को लेकर उनके विचार ने उन्हें लैटिन अमेरिका के सबसे प्रभावशाली और महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक बना दिया। अब वह मौत से लड़ रहे हैं। अप्रैल में उन्होंने घोषणा की कि वह ग्रासनली में हुए ट्यूमर की विकिरण चिकित्सा करवाएंगे। पिछले हफ्ते जब मैं उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो के बाहरी इलाके में उनसे मिलने गया, तो देखा कि बीमारी ने उन्हें बहुत कमजोर बना दिया है और वह मुश्किल से खा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम एक विचित्र बूढ़े से बात करने आए हो, आज की दुनिया के लिए मैं बिल्कुल फिट नहीं हूं। मानवता जिस तरह चल रही है, उससे लगता है कि सब नष्ट हो चुका है। उरुग्वे में 35 लाख लोग रहते हैं, जबकि देश 27 लाख जोड़ी जूते का आयात करता है। हम कचरा पैदा करते हैं और जीवन का कीमती समय इच्छाओं की पूर्ति में बिताते हैं। इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं और बाजार हम पर हावी हो गया है। इसने एक अचेतन संस्कृति पैदा की है, जो हमारी सहज प्रवृत्ति पर हावी है। हम खरीदारी करने और उसका भुगतान करने के लिए जीते और काम करते हैं। फिर भी वह कहते हैं कि इसके बावजूद जीवन सुंदर है। लेकिन हम इसे खो रहे हैं। मनुष्य अपने जीवन का उद्देश्य तलाश सकता है। लेकिन अगर आप जीवन का उद्देश्य नहीं तलाश पाते हैं, तो बाजार आपको जीवन भर बिलों का भुगतान करने के लिए मजबूर करेगा। अगर जीवन के उद्देश्य को पा लेते हैं, तो आपके पास जीने के लिए कुछ होगा। कुछ ऐसा, जो जीवन को खुशियों से भर दे।

©The New York Times 2024

अयोग्यवस्तुभरणात्
भजेद्योग्योऽपि दुष्टताम्।
रक्षणायेन्द्रदत्तासिं वहन्
व्याधोऽभवन्मुनिः।।

अवांछनीय (अनुपयोगी) वस्तु का समर्थन करने से योग्य व्यक्ति भी दुष्ट बन सकता है। जैसे-देवराज इंद्र द्वारा सुरक्षा के लिए दी गई तलवार को धारण करने से एक ऋषि शिकारी बन गए थे। -पुराणार्थसंग्रह

प्रस्तुति : शास्त्री कोसलेंद्रदास

जानना जरूरी है
संस्कृति के पन्नों से

आशुतोष गर्ग
लेखक एवं अनुवादक

इंद्र द्वारा वर्षा रोक दिए जाने से अन्न की भारी कमी हो गई। इससे महर्षि अगस्त्य और अन्य सभी ऋषि-मुनि चिंतित हो गए। अगस्त्य को इंद्र की चाल समझ में आ गई।

महर्षि अगस्त्य जब खुद बन बैठे इंद्र

महर्षि अगस्त्य के तपोबल की शक्ति से तीनों लोक भली-भांति परिचित थे। फिर भी देवराज इंद्र ने अगस्त्य को चुनौती देने की भूल कर दी। एक बार अगस्त्य ने बारह वर्ष का अखंड यज्ञ करने का संकल्प किया। इसके लिए बहुत से ब्राह्मणों और पुरोहितों की आवश्यकता थी। यज्ञ के सफल आयोजन के लिए समुचित मात्रा में अन्न आदि की भी आवश्यकता थी। इसलिए अगस्त्य ने सब वस्तुओं का प्रबंध कर लिया था। मगर संगृहीत अनाज के अतिरिक्त और भी अन्न चाहिए था। महर्षि को विश्वास था कि बीच में यदि अन्न की आवश्यकता पड़ी, तो उसकी व्यवस्था भी हो जाएगी।

बड़ी संख्या में ऋषि-मुनि व पुरोहितों की देख-रेख में यज्ञ आरंभ हुआ। पर इस महान यज्ञ की सूचना जैसे ही देवराज इंद्र को मिली, उन्हें महर्षि पर संदेह हुआ। स्वभाव से संशयी इंद्र को लगा कि महर्षि अगस्त्य शक्तियां बढ़ाने और देवलोक पर कब्जा करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। इंद्र ने यज्ञ को विफल करने का निश्चय किया और मेघों को उस क्षेत्र में वर्षा न करने की आज्ञा दे डाली।

धूप आने दो }

इंद्र द्वारा वर्षा रोक दिए जाने से अन्न की भारी कमी हो गई। इससे महर्षि अगस्त्य और अन्य ऋषि-मुनि चिंतित हो गए। अगस्त्य को इंद्र की चाल समझ में आ गई। उन्होंने ऋषियों से कहा, 'आप चिंता न करें। मैं जानता हूं कि देवराज इंद्र भय के कारण वर्षा नहीं होने दे रहे हैं। इसलिए मैं स्वयं इंद्र का कार्यभार संभालूंगा, लेकिन यह यज्ञ नहीं रुकेगा!'

अगस्त्य बोले, 'मैं चिंतन मात्र से इस यज्ञ को संपन्न कर सकता हूं। इसके अलावा मुझे स्पर्श-यज्ञ की विधि भी ज्ञात है, जिसमें संचित अन्न का स्पर्श कर लेने मात्र से देवता तृप्त हो जाते हैं। इसी भावना से यज्ञ भी संपन्न हो जाता है।' यह सुनकर ऋषि बहुत प्रसन्न हुए।

● अगस्त्य ने आगे कहा, 'देवराज इंद्र ने यदि वर्षा नहीं की, तो भी मेरे पास पर्याप्त अन्न और भोजन-सामग्री उपलब्ध है, जिससे मैं आपका बारह वर्ष तक भरण-पोषण कर सकता हूं। मैं अपने तपोबल से प्रत्येक व्यक्ति को उसकी पसंद का आहार उपलब्ध करवा दूंगा, परंतु यह यज्ञ अब किसी के रोके नहीं रुकेगा।'

ऋषियों ने यह सुना, तो वे बोले, 'महर्षि, आप भोजन की व्यवस्था तो कर देंगे, लेकिन यज्ञ पूर्ण करने के लिए धन, सुवर्ण, देवताओं आदि की उपस्थिति भी तो चाहिए। इन सबका क्या होगा?'

यह सुनकर महर्षि अगस्त्य बोले, 'यदि ऐसा है, तो मैं स्वयं इंद्र बन जाता हूं।' 'इंद्र! वह कैसे?' एक पुरोहित ने आश्चर्य से पूछा। अगस्त्य बोले, 'मैं अपने तपोबल से इंद्र की भूमिका अर्जित कर रहा हूं और यह आदेश देता हूं कि तीनों लोकों में जितना भी सुवर्ण और धन है, वह सब यहां मेरे सामने आ जाए। अप्सराओं के समूह, गंधर्व, किन्नर, देवी-देवता, विश्वावसु आदि समस्त प्रमुख जन तत्काल मेरे यज्ञ में उपस्थित हो जाएं।'

इंद्र ने अपनी पराजय स्वीकार की और बादलों को वर्षा का आदेश दे दिया। यह देख अगस्त्य मुस्कराए। अगस्त्य स्वभाव से दयालु थे, इसलिए उन्होंने इंद्र को क्षमा कर दिया और उनका वैभव भी लौटा दिया।

अगस्त्य के ऐसा कहते ही उनकी तपस्या के प्रभाव से सारी वस्तुएं प्रकट हो गईं। अगले ही क्षण, अगस्त्य ने इंद्र का समस्त वैभव अपने अधिकार में ले लिया।

देवलोक में बैठे इंद्र ने यह दृश्य देखा, तो वह भयभीत हो गए। वह समझ गए कि अगस्त्य की शक्ति को आंकने में उनसे भूल हो गई थी। इंद्र ने तत्काल अपनी पराजय स्वीकार की और बादलों को वर्षा का आदेश दे दिया। इसके तुरंत बाद उस क्षेत्र में वर्षा होने लगी। यह देखकर अगस्त्य मन ही मन मुस्कराए। अगस्त्य स्वभाव से दयालु थे, इसलिए उन्होंने इंद्र को क्षमा कर दिया और उनका वैभव भी लौटा दिया। इस तरह अगस्त्य ने इंद्र बनकर अपना यज्ञ संपन्न किया।

अध्ययन कक्ष

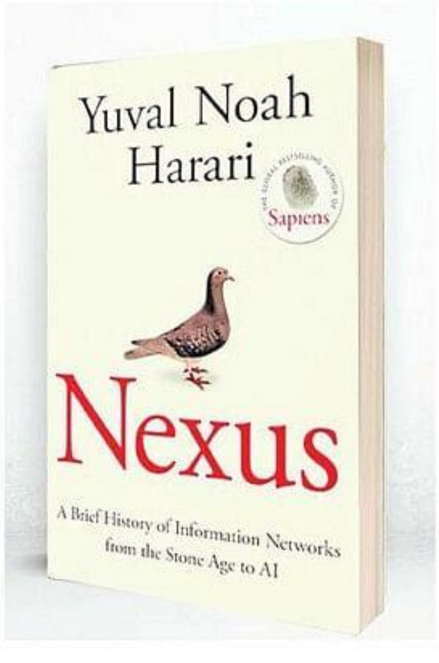

नेक्सस: ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इन्फोर्मेशन नेटवर्क्स फ्रॉम द स्टोन एज टू एआई

लेखक : युवाल नोआ हरारी

प्रकाशक : विंटेज डिजिटल
मूल्य : 2,299 रुपये
हार्डकवर

सत्ता, पूंजी और एआई, सब कहानियां हैं

इसी महीने लॉन्च हो रही युवाल नोआ हरारी की पुस्तक *नेक्सस* उनकी पिछली पुस्तक सेपियंस की तार्किक परिणति या यों कहें कि उसका अपडेटेड वर्जन है। *नेक्सस* नौकरशाही के इतिहास, लोकतंत्र और अधिनायकवाद के बीच के फर्क को बताने के साथ यह भी बताती है कि वर्तमान सूचना के युग में एआई हमें कहां तक ले जाएगा।

युवाल नोआ हरारी की पुस्तक *सेपियंस* हर किसी के पढ़ने लायक है, हालांकि इस विशाल गैर-कथेतर पुस्तक में हरारी द्वारा कही गई हर बात से सहमत नहीं हुआ जा सकता, लेकिन उसमें मानव इतिहास के बारे में आंखें खोलने वाले शोध हैं। हरारी की पुस्तकों की खास बात यह है कि उनमें यह नहीं बताया गया है कि इतिहास में क्या हुआ, बल्कि यह बताया गया है कि ऐसा क्यों हुआ और उससे हम आधुनिक युग में क्या प्रेरणा ले सकते हैं। इसी महीने जारी होने वाली उनकी अगली पुस्तक *नेक्सस सेपियंस* की तार्किक परिणति है। मनुष्य की चेतना संबंधी क्रांति के बारे में प्रस्तुत विचारों से आगे बढ़ते हुए, हरारी सूचना के प्रसार और वे मानव जीवन और समाजों को कैसे आकार देते हैं, इस पर गहराई से विचार करते हैं।

यह पुस्तक इसलिए भी दिलचस्प है, क्योंकि यह कहानी कहने की अवधारणा को एक विशिष्ट मानवीय गुण के रूप में विस्तारित करती है। पृथ्वी पर अन्य प्रजातियों के विपरीत हम मनुष्य कहानियों के माध्यम से सरकार, कानून, कंपनियां और धन जैसी अमूर्त चीजों का आविष्कार कर सकते हैं। *सेपियंस* की तरह, *नेक्सस* भी एक लंबी और चुनौतीपूर्ण किताब है। यह नौकरशाही के इतिहास, लोकतंत्र और अधिनायकवाद के बीच के अंतर के बारे में विस्तार से बताती है। उनके तर्कों और उन तर्कों का समर्थन करने वाले तथ्यों का कायल हुए बिना नहीं रहा जा सकता। *नेक्सस* मौजूदा समय के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दो प्रमुख वैश्विक रुझानों को संबोधित करती है- लोकलुभावन सत्तावादी व्यक्तित्वों का उदय और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उदय। हरारी ऐतिहासिक सबक का उपयोग करके यह बताना चाहते हैं कि हम इन दो संभावित खतरों से कैसे निपट सकते हैं। याद रखिए कि *सेपियंस* 2011 में लिखी गई थी - डोनाल्ड ट्रंप, कोविड-19 या चैटजीपीटी से पहले। तब से 13 वर्षों में दुनिया आश्चर्यजनक रूप से बदल गई है और *नेक्सस* इन बदलावों को ध्यान में रखते हुए एक त्वरित अपडेट की तरह लगती है।

नेक्सस हरारी के भविष्य-उन्मुख दृष्टिकोण का एक अधिक जमीनी संस्करण है। कोई नहीं जानता कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (या एलियन इंटेलिजेंस, जैसा कि हरारी का तर्क है कि हमें कहना चाहिए) के साथ वास्तव में क्या होगा। बहुत से लोग सटीकता और आत्मविश्वास के साथ अनुमान लगाने को तैयार हैं। लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता की यह खासियत सराहना करने लायक है कि यह अलग-अलग सूचनाओं को एक साथ जोड़कर मानवीय सूचनाओं के नेटवर्क पर एक परस्पर जुड़ी हुई नजर डालती है। *नेक्सस* ने मानव नेटवर्क के इतिहास पर एक दिलचस्प परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है, जो यह अनुमान लगाने का एक तरीका है कि एआई के साथ क्या हो सकता है। यह शुद्ध रूप से हरारी की पुस्तक है, यानी इसके अच्छे और बुरे, दोनों पहलू हैं।

अभियान

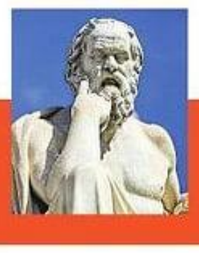

ऐसा काम चुनें, जिसे आप प्यार करते हैं और फिर आपको जीवन में एक दिन भी काम नहीं करना पड़ेगा। -सुकरात

amarujala.com
अमर उजाला

Hindi@mithelesh
■ मिथिलेश बारिया

गोल चबूतरा

डामर नहीं है उस पुरानी सड़क पर,
पर किसी नेता का नाम आज भी है,
ताले लगे अपने घर की
मैं जेबों में चाबियां टटोलता हूं...

पहले अमेरिकी ने जीती विश्व शतरंज चैंपियनशिप

आज के ही दिन सन 1972 में आइसलैंड के रेकजाविक में हुई विश्व शतरंज चैंपियनशिप में ग्रैंडमास्टर बॉबी फिशर ने रूसी खिलाड़ी बोरिस स्पैस्की को हराकर यह खिताब अपने नाम किया था। इस मैच को 'मैच ऑफ द सेंचुरी' भी कहा जाता है। बॉबी फिशर ऐसा करने वाले पहले अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी थे। बॉबी फिशर ने मात्र 8 साल की उम्र में पेशेवर तौर पर शतरंज खेलना शुरू किया था और महज 14 साल की उम्र में उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ओपन चैंपियनशिप जीती थी। इस तरह से वे 15 साल की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र के अंतरराष्ट्रीय ग्रैंडमास्टर बन गए थे। फिशर अपने खेल कौशल की वजह से किताबों और फिल्मों के विषय बन गए थे। उनकी खेल भावना को देखते हुए 'द बैलाड ऑफ बॉबी फिशर' गीत भी लिखा गया। आइसलैंड के रेकजाविक में खेले गई विश्व शतरंज चैंपियनशिप के समय शीत युद्ध चल रहा था, ऐसे में इस मैच में राजनीतिक रंग भी थे। फिशर ने सोवियत संघ पर टूर्नामेंट प्रणाली में धांधली करने का आरोप भी लगाया था। काफी झगड़े के बाद शुरू हुए मैच में फिशर की जीत हुई। फिशर को जीत की पुरस्कार राशि के रूप में 1,56,250 डॉलर मिले, जबकि 35 वर्षीय सोवियत ग्रैंडमास्टर स्पैस्की को 93,750 डॉलर मिले थे।

झरोखा
1 सितंबर

■ हिसार से हीनल पटेल

देश की बेटियां प्रगति कर रही हैं। दुनिया में परचम लहरा रही हैं। फिर भी कई बार उनके प्रति संकीर्ण मानसिकता देखने को मिलती है। अब एक राज्य में उनके विवाह की आयु के लिए कानून तो बना है, मगर हमारी सोच का क्या होगा?

कानून के साथ जागरूकता भी जरूरी

बेटियों के लिए हितैषी फैसला

चिट्ठी 1

देश में हिमाचल प्रदेश एक ऐसा पहला राज्य बन गया है, जहां अब बेटियों की शादी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष हो गई है। इसके लिए हिमाचल विधानसभा में बिल पारित हो गया और उम्मीद है कि राज्यपाल भी इस पर सहमति जता देंगे। हिमाचल सरकार ने बेटियों को भी उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करने और लैंगिक समानता के उद्देश्य से यह फैसला लिया है।

सरकार का यह फैसला देशहित और लड़कियों के हित के लिए है। कम उम्र में लड़कियों की शादी देश में जनसंख्या बढ़ाने का काम करती है और उनकी सेहत भी प्रभावित होती है। लेकिन अफसोस है कि 21वीं सदी में भी बहुत से लोगों की संकीर्ण मानसिकता लड़कियों के प्रति नहीं बदली है। इस कारण देश सामाजिक बुराइयां, जैसे-दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, बेमेल विवाह के मकड़जाल से मुक्त नहीं हो पाया है। सरकारें लड़कियों की सुरक्षा के लिए कानून तो बनाती हैं, लेकिन लोग कानून को ठेंगा दिखाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे देश के कुछ राज्यों में लिंगानुपात कम न होता। हमारे देश में कानून के अनुसार कोई नहीं चलना चाहता है और लड़कियों को कुछ लोग संकीर्ण मानसिकता के कारण बोझ समझते हुए उनकी जल्दी शादी करने की योजना बनाने लगते हैं। जो महिलाएं लड़कियों के प्रति संकीर्ण सोच रखती हैं, वे यह क्यों नहीं सोचतीं कि उनके माता-पिता ने उनके प्रति संकीर्ण सोच रखी होती तो क्या वे दुनिया में आकर, पढ़-लिखकर अपना कॅरिअर बना पातीं? भारत में महिला सशक्तीकरण तब तक संभव नहीं है, जब तक हर वर्ग के लोग लड़का-लड़की के बीच भेदभाव की संकीर्ण मानसिकता नहीं त्यागते और 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' पर अमल नहीं करते।

■ राजेश कुमार चौहान, जालंधर

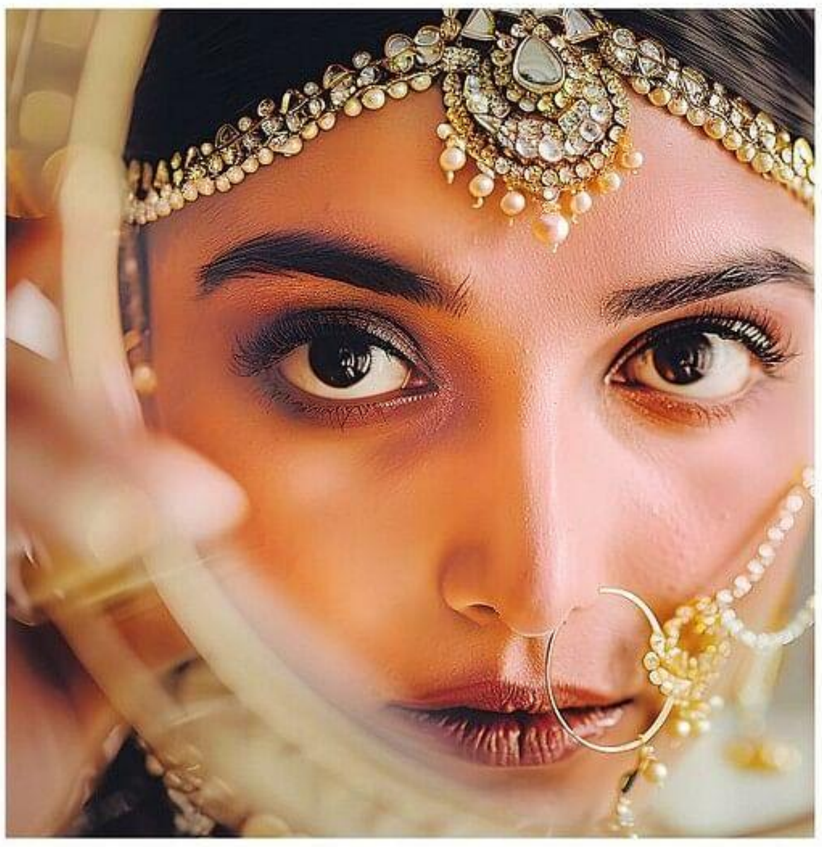

भोज में वैभव दिखाना उचित नहीं

हिंदू समाज में कुछ परंपराएं ऐसी हैं, जिनको सामर्थ्य न होने के बावजूद लोग निभाते हैं और कभी-कभी तो कर्ज में भी दब जाते हैं। मृत्यु भोज भी ऐसी ही परंपरा है। यह हमारे समाज में पीढ़ियों से व्याप्त है, इसलिए इसका सम्मान तो किया जाना चाहिए, लेकिन इसके बहाने आडंबर दिखाने की प्रवृत्ति अब खत्म होनी चाहिए।

आत्मा की शांति के लिए तर्पण, हवन और ब्राह्मण भोज किया जाना उचित है, लेकिन सामूहिक मृत्यु भोज के बहाने वैभव का प्रदर्शन उचित नहीं। कहीं-कहीं तो मृत्यु भोज का इतना भव्य आयोजन देखने को मिलता है, जैसे कोई सामाजिक समारोह हो। आजादी के बाद हिंदू समाज की जागरूकता से ही कुप्रथाओं का खात्मा हुआ है। बाल विवाह कभी सबसे बड़ा सामाजिक अभिशाप था, जो अब लगभग खत्म हो चुका है। दहेज को लेकर भी सामाजिक चेतना लगातार बढ़ी है। अस्पृश्यता भी खत्म हो रही है। ऐसे में मृत्यु भोज को लेकर भी सामाजिक विमर्श देखने को मिलेगा। जिस दिन लोग समाज के तानों के भय से मुक्त हो जाएंगे, उसी दिन से सामर्थ्य के हिसाब से परंपराओं का निर्वहन भी करने लगेंगे। पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जब लोगों ने मृत्यु भोज न कर उसमें खर्च होने वाली राशि को निर्बलों के कल्याण पर खर्च कर दिया। अच्छा हो, गांव-देहात में भी इस तरह के आयोजनों में खर्च कम कर गरीब बच्चों की शिक्षा और लड़कियों के विवाह पर खर्च किया जाए।

चिट्ठी 2

■ शैलेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, फिरोजाबाद

विदेशों में बसने की प्रवृत्ति क्यों

भारतीयों में विदेशों में बसने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में पिछले पांच वर्षों में 8 लाख 34 हजार भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी। इससे सवाल उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग भारत छोड़कर विदेश क्यों जा रहे हैं?

विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने पिछले पांच वर्षों में नागरिकता छोड़ने वाले भारतीय नागरिकों से संबंधित सवालों के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2023 में नागरिकता छोड़ने वाले भारतीयों की संख्या 2 लाख 16 हजार 219 थी। 2022 में यह संख्या 2 लाख 25 हजार थी, जबकि 2021 में यह संख्या 1 लाख 63 हजार थी। 2020 में 85 हजार 256 और 2019 में यह संख्या 1 लाख 44 हजार 17 थी। उन्होंने 2011-18 का डेटा भी साझा किया।

ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू, 2020 के अनुसार, लोग बेहतर जीवनशैली के लिए नई नागरिकता चाहते हैं। साथ ही, बढ़ती अपराध दर या व्यवसाय के अवसरों की कमी भी इसका कारण हो सकता है। इसके अलावा विदेशों में अच्छी सैलरी और बेहतर कामकाजी माहौल भी लोगों के भारत छोड़ने का एक बड़ा कारण है। 2018 से 2023 तक भारतीयों ने 114 देशों की नागरिकता हासिल की है। इनमें से अधिकांश लोग अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और जर्मनी में बस गए। आज आवश्यकता इस बात की है कि इस गंभीर मुद्दे पर गहनता से अध्ययन किया जाए, अन्यथा यहां की प्रतिभाएं पलायन करती रहेंगी।

चिट्ठी 3

■ डॉ. महताब अमरोहवी, अमरोहा

इनकी चिट्ठियां भी सराहनीय रहीं

मेरठ से अहमद खान, फर्रुखाबाद से डॉ. विनोद कुमार तिवारी, मोहाली से अभिलाषा गुप्ता, मेरठ से डॉ. सुधाकर आशावादी, फिरोजाबाद से शैलेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, बरेली से दिलीप कुमार गुप्ता, अंबाला से मनीषा पांडे, फिरोजाबाद से नितिन रावत, मिर्जापुर से सलिल पांडेय, मेरठ से डॉ. नरेन्द्र टोंक, अमरोहा से मुजाहिद चौधरी, वाराणसी से अमित श्रीवास्तव, पटना से मुकेश कुमार मनन।

हमें लिखें
abhiyan@amarujala.com

कुछ अलग

लगता है, गाड़ियां अब उड़ान भरेंगी

लद्दाख का मैग्नेटिक हिल एक ऑप्टिकल भ्रम पैदा करता है, जहां वाहन गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध आसानी से ऊपर की ओर चलते प्रतीत होते हैं।

लद्दाख का मैग्नेटिक हिल अपनी हैरान करने वाली घटना के लिए दुनियाभर में जाना जाता है। आमतौर पर सामान्य चढ़ाई वाले रास्तों पर भी वाहनों को ऊपर चढ़ने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है, लेकिन लद्दाख के मैग्नेटिक हिल पर वाहन आसानी से ऊपर की ओर चलते जाते हैं।

लेह-कारगिल राष्ट्रीय राजमार्ग से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित यह स्थान पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहता है। सही मायनों में देखा जाए तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से यहां वाहन ऊपर की ओर चढ़ते हुए मालूम पड़ते हैं। वैज्ञानिकों की मानें तो इस जगह के आसपास का परिदृश्य और ले-आउट ऐसा है, जिससे ऑप्टिकल भ्रम पैदा होता है और ढलान ऊपर की ओर मालूम पड़ती है। वास्तविकता तो यही है कि वह ढलान नीचे की ओर ही है। इसी ऑप्टिकल भ्रम की वजह से ऐसा लगता है कि वाहन ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। वास्तव में, वे गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर लुढ़क रहे होते हैं। इस घटना को देखने के लिए पर्यटकों को अक्सर वाहन का इंजन बंद या उसे न्यूट्रल में रखना पड़ता है। ऐसा करने से वाहन ऊपर की ओर बढ़ता प्रतीत होता है, जिससे गुरुत्वाकर्षण का विरोध करने का आभास होता है। कुछ वैज्ञानिक पहाड़ी में शक्तिशाली चुंबकीय बल होने की बात भी कहते हैं, जिसके कारण वह आसपास के वाहनों को खींचती है। यही वजह है कि इस क्षेत्र से गुजरने वाले विमान या तो ऊंचाई बढ़ा लेते हैं या रास्ता बदल देते हैं। इसके बावजूद लद्दाख के मैग्नेटिक हिल में वाहनों को ऊपर की ओर चढ़ते देखना एक पेचीदा और यादगार अनुभव है।

■ परमानंद मिश्रा, भदोही

गांधीवादी शास्त्री जी

महात्मा गांधी के विचार में आजादी के लिए स्वदेशी को अपनाना जरूरी था और इसीलिए उन्होंने चरखे को स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में लोकप्रिय बनाया। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने आजादी के बाद भी गांधी जी के इस विचार को जीवित रखा।

■ देहरादून से हृदय नाथ सिंह

ग्रामोफोन

'शाम से आंख में नमी सी है' की दिलचस्प कहानी

1968 में संगीतकार सलिल चौधरी के छोटे भाई समीर चौधरी एक फिल्म बना रहे थे- 'मिट्टी का देव'। सलिल चौधरी, मुकेश से 'मोन माताल, सांझ साकाल' जैसा अद्भुत बांग्ला गीत गवा चुके थे। फिल्म 'मिट्टी का देव' के लिए भी उन्होंने इसी गीत की धुन पर शायर-गीतकार गुलजार के लिखे गीत 'शाम से आंख में नमी नमी सी है' को लयबद्ध कर इसे भी मुकेश से ही गवाया। गुलजार के इस गीत को बाद में राहुल देव बर्मन ने आशा भोसले से गवाया और 2002 में रिलीज अपनी एलबम में जगजीत सिंह ने भी गाया, लेकिन वो बात, जो सलिल और मुकेश लेकर आए थे, फिर नहीं आ पाई। दुर्भाग्य यह रहा कि रिलीज से पहले ही स्टूडियो में हुए भीषण अग्निकांड में फिल्म 'मिट्टी का देव' की रिकॉर्डिड रील और साउंडट्रैक पूरी तरह नष्ट हो गए, जिससे यह फिल्म कभी सामने ही नहीं आ पाई। खास यह भी है कि सलिल और मुकेश के लाजवाब गीत को कभी किसी म्यूजिक कंपनी ने पुन: रिलीज करने के बारे में भी नहीं सोचा।

■ सारिका शर्मा, बरेली

पेंशन के सवाल पर कई सवाल

तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी ने घुटने नहीं टेके और उनके बाद मनमोहन सिंह ने भी 10 सालों तक इसके लिए कोई माहौल तैयार नहीं होने दिया। नरेंद्र मोदी भी 10 सालों तक आगे नहीं बढ़े, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम ने पूरी स्थिति को ही बदल डाला।

केंद्र में सत्ता पर काबिज राजनीतिक दल, अन्य पार्टियां और राज्यों के मुख्यमंत्री पेंशन के सवाल पर खुद को दुविधा की स्थिति में पाते हैं। भारत में एक निश्चित आयु वर्ग के लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है। यहां इस तरह की कोई भी सामाजिक सुरक्षा योजना नहीं है, जो नागरिकों को पेंशन दिला सके। निजी क्षेत्र में लाखों की संख्या में लोग काम कर रहे हैं, जिन्हें सेवानिवृत्ति पर कोई पेंशन नहीं मिलती है। यहां तक कि भारतीय सेना के शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले अधिकारियों को भी पेंशन नहीं मिलती है।

पेंशन पर बहस

जब तक लोगों में जीवन प्रत्याशा कम थी, पेंशन का कोई खास महत्व नहीं था। उस समय कुछ ही लोगों को पेंशन मिलती थी, लेकिन ऐसे कुछ ही लोग थे, जो सेवानिवृत्ति के बाद अधिक समय तक जीते थे। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब जीवन प्रत्याशा 35 वर्ष से कम थी। आज यह 70 वर्ष से थोड़ा अधिक है। औसत रूप से पेंशन की बाध्यता तो रिटायरमेंट के 10 से 12 सालों तक बनी रहेगी, लेकिन अगर पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था है तो यह जीवनसाथी को भी जारी रह सकती है। यही वजह है कि ज्यादातर नियोक्ता पेंशन को लेकर सतर्क रहते हैं। लेकिन कर्मचारियों के लिए यह मामला काफी महत्वपूर्ण है। उनका मानना है कि पेंशन उनकी लंबी वफादारी के साथ पूर्ण सेवा द्वारा प्राप्त किया गया अधिकार है या पेंशन ही सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानपूर्वक जीने के अधिकार का रास्ता है।

सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के अधिकार पर हुई बहस में जीत हासिल हुई और यह बिल्कुल सही फैसला था। जिन लोगों ने पेंशन से वंचित लोगों की तरफ इशारा किया, उन तक भी पेंशन की सुविधा पहुंचनी चाहिए। सही मायनों में सभी वर्गों के लोगों के लिए एक सार्वभौमिक पेंशन योजना होनी चाहिए। जैसे-जैसे सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन की शुरुआत हुई, एक सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन की अवधारणा ने भी जड़ें जमा लीं। यह अवधारणा अंतिम प्राप्त मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 50 प्रतिशत पर टिकी।

कैसे बदलीं परिस्थितियां

जब जनवरी 2004 में नई पेंशन योजना (एनपीएस) ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की जगह ली तो इसने पेंशन के दो स्तंभों को हिलाकर रख दिया। इसने गैर अंशदायी परिभाषित लाभ योजना को मौलिक रूप से परिभाषित अंशदान योजना में बदल दिया और चुपचाप न्यूनतम पेंशन की अवधारणा को छोड़ दिया। इसका विरोध शुरू हो गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने घुटने नहीं टेके और उनके बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी 10 सालों तक इसके लिए कोई माहौल तैयार नहीं होने दिया। इसी तरह नरेंद्र मोदी भी 10 सालों तक आगे नहीं बढ़े, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम ने पूरी स्थिति को ही बदल डाला।

3 अगस्त, 2022 को जारी पीआईबी की एक विज्ञप्ति के अनुसार, केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की कुल

पी चिदंबरम
पूर्व केंद्रीय मंत्री

संख्या 69,76,240 थी। 2024-25 में पेंशन पर बजटीय व्यय 2,43,296 करोड़ रुपये है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, मार्च 2023 तक एनपीएस में 23.8 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 60.7 लाख राज्य सरकार के पात्र कर्मचारी हैं। 2024 में संख्या थोड़ी अधिक या थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन हम अनुमानित आंकड़े पर बात करते हैं। यह भारत की जनसंख्या का एक अंश है। एक अप्रदत्त पेंशन योजना, जो कि ओपीएस थी, अर्थव्यवस्था को वित्तीय रूप से बर्बाद कर देगी। सरकारें वर्तमान राजस्व से भुगतान नहीं कर सकतीं। किसी को इस योजना को वित्तपोषित करना होगा। यह या तो सरकार है या कर्मचारी या दोनों। एनपीएस एक ऐसी योजना थी, जिसे सरकार (14 प्रतिशत) और कर्मचारी (10 प्रतिशत), दोनों द्वारा वित्तपोषित किया गया था।

एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) सरकार द्वारा घोषित एक वित्तपोषित योजना है, जिसमें सरकार की भागीदारी 18.5 प्रतिशत और कर्मचारी की भागीदारी 10 प्रतिशत रहेगी। एकीकृत पेंशन योजना कम से कम 25 सालों की सेवा पूरी करने वालों को सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत न्यूनतम पेंशन की गारंटी भी देता है। इसमें हर महीने 10 हजार रुपये की न्यूनतम पेंशन देने का आश्वासन दिया गया है, जिसे मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित किया जाएगा। हालांकि इसकी अंतिम रूपरेखा का अभी इंतजार करना होगा।

अभी तक किसी राज्य ने यूपीएस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। कांग्रेस समेत बड़ी राजनीतिक पार्टियां, यूपीएस पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों के कई संगठनों और कई केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने पेंशन फंड में कर्मचारी के योगदान का विरोध किया है।

फंडिंग पर संशय

यह सरकार, राजनीतिक दलों और कर्मचारी संगठनों के लिए एक संशय की स्थिति है। अगर राजकोषीय दृष्टिकोण से बात की जाए तो यूपीएस को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। हालांकि कुछ सवाल अभी भी बने हुए हैं-

1. क्या कर्मचारी के योगदान और सरकार के योगदान के बीच का अंतर, जो अब 8.5 प्रतिशत है, भविष्य में बढ़ेगा?
2. टीवी सोमनाथन ने कहा कि "सरकार इस कमी को पूरा करेगी।" क्या यह 'पे ऐज यू गो' से एक कदम दूर नहीं है?
3. अगर योगदान का 10+10 प्रतिशत अनुमोदित पेंशन फंड प्रबंधकों को सौंपा जाएगा, तो क्या 8.5 प्रतिशत योगदान का निवेश किया जाएगा और यदि हां, तो किसके द्वारा और कहां?
4. पहले वर्ष के लिए 6,250 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि को कम करके आंका गया प्रतीत होता है, क्या यह सच है?
5. क्या कैबिनेट द्वारा यूपीएस को मंजूरी दिए जाने से पहले राज्य सरकारों से परामर्श किया गया था? क्या कर्मचारी संघ इसमें शामिल होंगे? अब यह देखना भी दिलचस्प है कि हितधारक इस दुविधा से कैसे बाहर निकलते हैं?

Licensed by The Indian Express Limited

समझ और साहस के साथ संगीत दुनिया में

दिल्ली में पत्रकार वार्ता हो रही थी और प्रख्यात शास्त्रीय गायक पंडित कुमार गंधर्व हाथ में अखबार की प्रति लिए पत्रकारों के सामने लहराते हुए कह रहे थे, "हिंदी को छोड़िए, क्या किसी अन्य भाषा में भी कभी किसी ने मेरे ऊपर ऐसा लिखा है?" कुमार जी जिस आलेख की प्रशंसा करते हुए यह कह रहे थे, वह उनसे बातचीत के बाद उनके संगीत का विश्लेषण करते हुए लिखा गया था और उसके लेखक थे डॉ. मुकेश गर्ग। इस आलेख की एक बानगी देखिए, "कुमार गंधर्व यानी हिंदुस्तानी संगीत का नया सौंदर्यशास्त्र। कुमार गंधर्व यानी बगावत। घरानों के खिलाफ बगावत। ऐसी बगावत, जिसने घरानों के नाम पर चली आ रही श्रेष्ठता का पर्दाफाश किया। बताया कि नकल कर लेने से कोई बड़ा नहीं होता। बड़ा होता है सृजन से, कुछ नया रचने से। मैं तोताराम नहीं हूं, कहना है उनका।"

आलोक पराड़कर

स्मृति शेष

संगीत में समझ और साहस के साथ की गई समीक्षा कम ही दिखती है। मुकेश गर्ग इसके उदाहरण बन पाए क्योंकि वे जहां संगीत के मर्मज्ञ थे, वहीं हिंदी के अध्यापक भी थे।

मुकेश गर्ग
(1950-2024)

हम संगीत में समीक्षा की बात करते हैं, लेकिन संगीत में समझ और साहस के साथ की गई समीक्षा कम ही दिखती है, खासकर हिंदी में। जिन्हें संगीत के गुण-दोष की जानकारी होती है, उनके पास उसे लिखकर व्यक्त करने के लिए अच्छी भाषा नहीं होती और जो अच्छी भाषा के साथ इस क्षेत्र में आते हैं, वे संगीत की गहराइयों में नहीं जा पाते हैं। मुकेश गर्ग इसके उदाहरण बन पाए, क्योंकि कि वे जहां संगीत के मर्मज्ञ थे, वहीं हिंदी के अध्यापक भी थे। करीब 43 वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया और ब्रजभाषा एवं रीतिकाल के विशेषज्ञ माने गए। दिल्ली विश्वविद्यालय की अच्छी नौकरी थी। शायद तभी ठहरकर, सोच-समझकर लिखने का अवकाश भी बना सके। शास्त्रीय संगीत पर लिखा तो फिल्म संगीत का विश्लेषण भी किया।

8 अक्तूबर, 1950 को हाथरस में जन्मे मुकेश गर्ग प्रसिद्ध हास्य कवि काका हाथरसी के भतीजे थे। काका खुद संगीत के मर्मज्ञ थे। मुकेश गर्ग की प्रतिभा को उन्होंने ही सबसे पहले पहचाना। 16 वर्ष की उम्र में मुकेश गर्ग स्वरलिपि विशेषज्ञ बन गए और 23 साल की उम्र में काका द्वारा शुरू की गई 'संगीत' पत्रिका के संपादक, जिसका 2011 तक संपादन करते रहे। उनकी 200 से अधिक समीक्षाएं, 30 से अधिक शोध लेख, संगीत और साहित्य पर कई पुस्तकें प्रकाशित हैं। कुछ फिल्मों और धारावाहिकों में संगीत से जुड़े। खुद 'संगीत संकल्प' नामक संस्था भी बनाई। संगीत पर शोध करने वालों के लिए अनिवार्य मार्गदर्शक थे। बीमार होने के पहले तक लगातार सक्रिय बने रहे, घूमते रहे, व्याख्यान देते रहे। उनका होना हिंदी में सार्थक और गंभीर संगीत समीक्षा का होना था। उसमें साहस का बना होना था!

https://t.me/AllNewsPaperPdf

आजकल विपक्ष खासकर कांग्रेस पीएम मोदी की राजग सरकार पर यूटर्न सरकार का आरोप लगा रही है। हाल के एक दो महीनों में कुछेक फैसलों पर सरकार ने तर्कसंगत निर्णय किया है, तो विपक्ष ने सरकार पर अटैक का बहाना ढूंढ लिया है। प्रधानमंत्री के साथ विमर्श के बाद आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री एवं तेलुगूदेशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने अपने राज्य में 'जाति जनगणना' के बजाय 'कौशल जनगणना' कराने का फैसला लिया है। लिहाजा टीडीपी ने विपक्ष के एक 'राजनीतिक हथियार' को कुंद कर दिया है। कैबिनेट ने 10 राज्यों में 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी बनाने की परियोजना को स्वीकृति दे दी है। इस तरह लगातार काम करने, योजनाएं बनाने, रोजगार के अवसर पैदा करने के मद्देनजर सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री दबाव में यह सब कर रहे हैं? दलित, आदिवासी, ओबीसी का प्रलाप ऐसा रहा कि राहुल गांधी ने हास्यास्पद बयान दिया कि मिस इंडिया, बॉलीवुड, ओलंपिक खिलाड़ी और क्रिकेटर, उद्योगपति, मीडिया और न्यायपालिका आदि में इन जातियों के लिए कोई आरक्षण ही नहीं है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी आजकल बयान दे रहे हैं कि मोदी जी 'जाति जनगणना' करा दीजिए। नहीं तो ऐसी स्थिति आने वाली है कि आप नये प्रधानमंत्री को यह काम करते देखेंगे। दरअसल विपक्ष मुगालते में है कि इससे प्रधानमंत्री मोदी दबाव में आ जाएंगे और 'जाति जनगणना' करवा सकते हैं। यह विचार ही बेमानी है, क्योंकि डॉ. मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार के दौरान 'जातीय जनगणना' करवाई गई थी, लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। बेटियों और महिलाओं के खिलाफ राष्ट्रपति ने मार्मिक और अभूतपूर्व प्रतिक्रिया दी है। यह सब दबावमुक्त सरकार ही कर सकती है। जनधन योजना को भी दस वर्ष पूरे हुए हैं। इन्हीं मुद्दों पर पेश है आजकल का यह अंक...

किसी दबाव में नहीं प्रधानमंत्री मोदी

विश्लेषण
सुशील राजेश
वरिष्ठ स्तंभकार

मोदी सरकार पांच साल का यह कार्यकाल भी आराम से पूरा करेगी। बिहार में भाजपा, जद-यू, लोजपा (रामविलास) और हम आदि पार्टियां एनडीए के बैनर तले ही 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगी, यह तय हो चुका है। टीडीपी सांसदों के साथ प्रधानमंत्री और भाजपा अध्यक्ष की 2-3 बैठकें हो चुकी हैं और समर्थन में कोई दरारें भी नहीं हैं, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी दबाव में क्यों होंगे? यदि प्रधानमंत्री मोदी दबाव महसूस कर रहे होते और अपनी सरकार को कमज़ोर, अस्थिर स्थिति में पाते, तो राष्ट्रपति का ऐसा पत्र कभी भी जारी न किया जाता, लेकिन दुष्कर्म और हत्याओं की नृशंसताओं पर खुद प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के जरिए, यह संदेश देश को देना चाहते थे।

क्या प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में दबाव में हैं? यह आकलन विपक्षी दलों का है। विपक्ष ने मोदी सरकार की उम्र 6 माह आंकी है, लेकिन मेरा आकलन है कि सरकार पर कोई भी संकट नहीं है। चूंकि कुछ मामलों में प्रधानमंत्री को अपने निर्णय से पीछे हटना पड़ा है या वक्फ़ बोर्ड संशोधन बिल को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को सौंपना पड़ा है अथवा मीडिया से जुड़े एक बिल को भी फिलहाल ठंडे बस्ते के हवाले करना पड़ा है, लिहाजा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी दबाव में हैं।

'कौशल जनगणना' कराने का फैसला

दूसरी तरफ, प्रधानमंत्री के साथ विमर्श के बाद आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री एवं तेलुगूदेशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने अपने राज्य में 'जाति जनगणना' के बजाय 'कौशल जनगणना' कराने का फैसला लिया है। लिहाजा टीडीपी ने विपक्ष के एक 'राजनीतिक हथियार' को कुंद कर दिया है। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को निर्देश दिया है कि जिस रफ्तार से हमने 10 साल में काम किया है, वह आगामी पांच साल भी बरकरार रहनी चाहिए। कैबिनेट ने 10 राज्यों में 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी बनाने की परियोजना को स्वीकृति दे दी है। इसे ग्रेटर नोएडा और धोलेरा की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इससे 40 लाख प्रत्यक्ष-परोक्ष नौकरियां पैदा होंगी और 1.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश मिलेगा। 2030 तक 2 लाख करोड़ रुपये के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में 76,000 करोड़ रुपये की वाधवन बंदरगाह योजना की आधार-शिला रखी है। भारत सरकार ने रेलवे कॉरिडोर के विस्तार की घोषणा भी की है। जाहिर है कि रोज़गार के नये अवसर बनेंगे। इस तरह लगातार काम करने, योजनाएं बनाने, रोज़गार के अवसर पैदा करने के मद्देनजर सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री दबाव में यह सब कर रहे हैं?

बहुमत भाजपा-एनडीए के पक्ष में

आम चुनाव का जनादेश जून, 2024 में सार्वजनिक किया गया था। जनादेश आधा-अधूरा था, क्योंकि किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, लेकिन 240 सीट जीत कर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी रही और उसके एनडीए गठबंधन के पक्ष में 293 सीटें आईं। कांग्रेस 99 सीट पर ही अटक कर रह गई और 'इंडिया' गठबंधन 234 सीट ही हासिल कर सका। आईने और सत्य की तरह स्पष्ट है कि निर्णायक बहुमत भाजपा-एनडीए के पक्ष में रहा, तो फिर विपक्ष किस मुग़ालते में है कि वह ज्यादा ताकतवर है और उसकी वैकल्पिक सरकार बन सकती है। बेशक आंध्र की टीडीपी के 16 सांसद और बिहार के जद-यू के 12 सांसद महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जिन पर सरकार स्थित है। गौरतलब यह है कि आंध्र में औसतन हर परिवार पर 7 लाख रुपये और प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपये का कर्ज है। राज्य को नई राजधानी अमरावती में बनाने और अन्य परियोजनाओं के लिए कमोबेश 3-4 लाख करोड़ रुपये की जरूरत है। आर्थिक विकास के मद्देनजर बिहार देश में सबसे पिछड़ा और विपन्न राज्य है। दोनों राज्यों को मोदी सरकार ने करीब 75,000 करोड़ रुपये की शुरुआती मदद दी है।

कांग्रेस की राज्य सरकारें 'दिवालिया'

क्या कांग्रेस और विपक्ष दोनों राज्यों की अपेक्षित आर्थिक मदद कर सकते हैं? कांग्रेस की राज्य सरकारें खुद ही 'दिवालिया' स्थिति में हैं। तो टीडीपी और जद-यू एनडीए से अलग क्यों होंगे? यदि एनडीए में ऐसा सहयोग बना रहता है, तो मोदी सरकार पांच साल का यह कार्यकाल भी आराम से पूरा कर सकती है। बिहार में भाजपा, जद-यू, लोजपा (रामविलास) और हम आदि पार्टियां एनडीए के बैनर तले ही 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगी, यह तय हो चुका है। टीडीपी सांसदों के साथ प्रधानमंत्री और भाजपा अध्यक्ष की 2-3 बैठकें हो चुकी हैं और समर्थन में कोई दरारें भी नहीं हैं, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी दबाव में क्यों होंगे? आंध्र में 'कौशल जनगणना' के पायलट प्रोजेक्ट में करीब 33 लाख छोटी-बड़ी, मध्यम कंपनियों में सर्वेक्षण किए जाएंगे कि आखिर कंपनियां किस शिक्षा और हुनर के कामगार को नौकरी दे सकती हैं? आंध्र में करीब 3.5 करोड़ लोग 15-59 आयु-वर्ग के हैं। उनकी शिक्षा और हुनर क्या हैं, इसका भी सर्वेक्षण कराया जाएगा। दरअसल, भारत सरकार की प्राथमिकता है कि कौशल विकास को इतना बढ़ाया जाए कि विश्व में भारत का स्थान संवर सके। अभी भारत 109 देशों की सूची में 87वें स्थान पर है, जबकि चीन 36वें स्थान पर है। ये दो देश ही दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं। माना जा रहा है कि जाति के आधार पर नौकरी लेने के बजाय कौशल के आधार पर रोज़गार मिले, मोदी सरकार और आंध्र सरकार का यह नज़रिया है। अलबत्ता वे आरक्षण के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हैं। इस प्रोजेक्ट से रोज़गार और नौकरियों के अवसर स्पष्ट और व्यापक होंगे। यदि यह प्रोजेक्ट सफल रहा, तो फिर भाजपा शासित राज्यों में भी ऐसे ही सर्वेक्षण कराए जाएंगे। बेशक मोदी सरकार के सामने बेरोज़गारी सबसे बड़ी और चिन्ताजनक चुनौती है। देश में सबसे अधिक बेरोज़गारी आंध्र और हरियाणा में है। आईएमएफ की उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ ने हाल ही में कहा है कि 2030 तक भारत को कमोबेश 6 करोड़ अतिरिक्त रोज़गार पैदा करने ही होंगे। कुछ अर्थशास्त्री तो यह संख्या 10 करोड़ तक आंक रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह चिंतित सरोकार तो हो सकता है, लेकिन इस संदर्भ में प्रधानमंत्री को दबाव में माना जाए, यह पूर्वाग्रही आकलन है। दरअसल, आम चुनाव में कांग्रेस, सपा, राजद आदि ने एक 'छद्म नेरेटिव' गढ़ा था कि यदि भाजपा को 400 सीट मिल गईं, तो वे संविधान बदल देंगे। संविधान नहीं रहा, तो आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। आरक्षण नहीं रहा, तो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की नौकरियों का क्या होगा? वह नेरेटिव सफल रहा और भाजपा को 272 सीट वाला बहुमत भी नहीं मिल पाया। उसी को आधार बनाकर ये विपक्षी दल आजकल भी राजनीति कर रहे हैं और 'जाति जनगणना' का अनर्गल अलाप कर रहे हैं। अक्तूबर-नवम्बर में हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र आदि राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। उप्र में भी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं।

'जाति जनगणना' बेमानी, विपक्ष मुगालते में

लिहाजा राहुल गांधी व अखिलेश यादव का सोचना है कि 'जाति जनगणना' के मुद्दे पर हिन्दुओं को बांटा जा सकता है और वे जातियां मोदी-भाजपा को चुनाव हरा सकती हैं। दलित, आदिवासी, ओबीसी का प्रलाप ऐसा रहा कि राहुल गांधी ने हास्यास्पद बयान दिया कि मिस इंडिया, बॉलीवुड, ओलंपिक खिलाड़ी और क्रिकेटर, उद्योगपति, मीडिया और न्यायपालिका आदि में इन जातियों के लिए कोई आरक्षण ही नहीं है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी आजकल बयान दे रहे हैं कि मोदी जी 'जाति जनगणना' करा दीजिए। नहीं तो ऐसी स्थिति आने वाली है कि आप नये प्रधानमंत्री को यह काम करते देखेंगे। दरअसल विपक्ष मुग़ालते में है कि इससे प्रधानमंत्री मोदी दबाव में आ जाएंगे और 'जाति जनगणना' करवा सकते हैं। मैं इसे बेमानी मानता हूं, क्योंकि डॉ. मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार के दौरान 'जातीय जनगणना' करवाई गई थी, लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। इस सवाल का जवाब कांग्रेस और उसके सहयोगी दल ही दे सकते हैं।

प्रभावशाली नेता रणनीति पर कर रहे मंथन

उस जनगणना के आंकड़े भारत सरकार में हैं, जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने वे देखे होंगे। प्रधानमंत्री यह काम तब करा सकते हैं, जब वह नौकरशाही में 'सीधी भर्तियां' करने की माकूल स्थिति में होंगे। सरकार में विशेषज्ञों को शीर्ष स्थानों पर जरूर रखा जाएगा, लेकिन उनमें आरक्षण की गुंज़ाइश के साथ ऐसा किया जाएगा। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री और भाजपा के अन्य बड़े नेता इस रणनीति पर मंथन कर रहे हैं कि अधिकतर हिन्दू, जिनमें दलित, आदिवासी, ओबीसी भी शामिल हों, भाजपा के पक्ष में मतदान करें। आरक्षण पर पीएम ऐसा जवाब देने की फिराक़ में हैं कि 'जाति जनगणना' प्रासंगिक और प्रभावशाली मुद्दा ही न रहे। एक और मुद्दा देश के सामने आया है, जिससे साबित होता है कि प्रधानमंत्री मोदी दबाव में नहीं हैं। वह है-राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का तीन पन्नों का पत्र, जो उन्होंने पीटीआई के संपादकों को लिखा था। बेटियों और महिलाओं के खिलाफ राष्ट्रपति ने विस्फोटक, मार्मिक और अभूतपूर्व प्रतिक्रिया दी है। भारत में राष्ट्रपति सार्वजनिक बयान नहीं देते। वह केंद्रीय कैबिनेट की सलाह से ही काम करते हैं। यह पत्र जारी करने से पूर्व प्रधानमंत्री दफ्तर भेजा गया होगा। फिर कैबिनेट की संस्तुति के बाद ही पत्र देश के सामने आया होगा! यह भी संभव है कि यह पत्र सरकार के स्तर पर लिखवाया गया हो और फिर 'राष्ट्रपति भवन' ने उसे जारी किया हो! राष्ट्रपति ने यहां तक कहा था कि बस, अब बहुत हो गया।' राष्ट्रपति छोटी बच्चियों के साथ दरिंदगी से बहुत आहत लगीं। उन्होंने समाज के सामने एक मुश्किल सवाल रख दिया कि क्या कोई सभ्य समाज ऐसे बर्बर, जघन्य अपराधों को बर्दाश्त कर सकता है? मेरा मानना है कि यदि प्रधानमंत्री मोदी दबाव महसूस कर रहे होते और अपनी सरकार को कमज़ोर, अस्थिर स्थिति में पाते, तो राष्ट्रपति का ऐसा पत्र कभी भी जारी न किया जाता, लेकिन दुष्कर्म और हत्याओं की नृशंसताओं पर खुद प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के जरिए, यह संदेश देश को देना चाहते थे। प्रधानमंत्री फांसी तक की बात कह चुके हैं। बहरहाल, कई और मुद्दे हैं, जिन्हें सोशल मीडिया पर कुकुरमुत्तों की तरह उग रही विचारकों की जमात ने उठाए हैं और वे प्रधानमंत्री मोदी को दबाव में पाते हैं, लेकिन मैं देश की स्थिति और उसके निरंतर आर्थिक विकास से संतुष्ट हूं।

जनधन खाता लाया आर्थिक-सामाजिक बदलाव

अर्थव्यवस्था
सतीश सिंह
एजीएम एसबीआई और स्तंभकार

अठाईस अगस्त 2014 को शुरू किए गए प्रधानमंत्री जनधन योजना यानि पीएमजेडीवाई के 28 अगस्त 2024 को 10 साल पूरे हो गए। अपने 10 सालों के सफर के दौरान इस योजना ने कई उपलब्धियां हासिल की। यह योजना वित्तीय समावेशन की संकल्पना को साकार करने, महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने, डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया को गांव-गांव व घर-घर तक पहुंचाने, ग्रामीण क्षेत्र में बिचौलिए व सूदखोरों या महाजनों की भूमिका को कम करने, चोरी-चकारी की घटनाओं में कमी लाने, भ्रष्टाचार कम करने, सामाजिक बदलाव लाने, जमा और खर्च आदि में तेजी को सुनिश्चित करने में सफल रही है। चालू वित्त वर्ष में 16 अगस्त तक इस योज़ना के तहत 3 करोड़ नए खाते खोले गए हैं।

खातों की संख्या 53.13 करोड़

मार्च 2015 में जनधन खातों की संख्या 14.72 करोड़ थी, जो 16 अगस्त 2024 में बढ़कर 53.13 करोड़ हो गई, जो खाता खोलने के मामले लगभग 4 गुणा वृद्धि को दर्शाता है। खोले गए खातों में से 66.6 प्रतिशत खाते ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि 53.13 करोड़ खाते चालू या सक्रिय हैं और उनमें 2.3 लाख करोड़ रूपये का अधिशेष है, जबकि मार्च 2015 तक महज 14.7करोड़ खाते खोले जा सके थे और उनमें 15,670 करोड़ रुपए जमा थे। अगस्त 2024 में जनधन खातों में औसत अधिशेष 4,352 रूपये रहा,जो मार्च 2015 में 1,065 रूपये था। उल्लेखनीय है कि 16 अगग्स्त 2024 तक सिर्फ 8.4 प्रतिशत जनधन खातों में ही शून्य अधिशेष था। 53.13 करोड़ खातों में से 29.56 करोड़ खाते महिलाओं के हैं, जो प्रतिशत में 55.6 है। जनधन खाता खोलने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने सकारात्मक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकारी बैंकों ने कुल खोले गए जनधन खातों में से 78 प्रतिशत खाते खोले हैं। उत्तरप्रदेश में सबसे अधिक 9.4 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं, जबकि बिहार 6 करोड़ जनधन खाते खोलकर मामले में दूसरे स्थान पर है।

कोरोना काल में रही खास भूमिका

जनधन खाते, मोबाइल और आधार कार्ड ने कोरोना महामारी में आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से किसान सम्मान निधि का वितरण छोटे एवं सीमांत किसानों के बीच करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी वजह से कोरोना महामारी के दौरान बड़ी संख्या में वंचित तबके के लोग असमय काल-कवलित होने से बच गए। आज जनधन खातों की वजह से गांवों के 5 किलोमीटर के दायरे के 99.95 प्रतिशत लोगों की पहुंच बैंकिंग सुविधाओं तक हो गई है।

ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा

गांव के लोग बैंक की शाखाओं, बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट और भारतीय पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई बैंकिंग सुविधाओं का लाभ किसी न किसी रूप में ले रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा शुरू किए गए फोन आधारित गैर वितीय सेवाओं का लाभ भी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के

लोग बिना बैंक शाखा गए ले रहे हैं, जिससे उनका कीमती समय व्यर्थ में बर्बाद नहीं हो रहा है। जनधन खाता खोलने, खातों के रखरखाव और न्यूनतम अधिशेष राशि के नहीं रहने या खाता अधिशेष शून्य रहने पर भी बैंक द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाता है और ग्राहकों को 10,000 रुपये तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी दी जा रही है। बैंक रुपे कार्ड भी निःशुल्क जारी कर रहे हैं, जिसके साथ ग्राहकों को 2 लाख रुपये तक का मुफ्त दुर्घटना बीमा भी दिया जा रहा है।

प्रधानमंत्री जनधन योजना की वजह से आज 80 प्रतिशत व्यस्क के पास औपचारिक बैंक खाता है, जबकि 2011 में यह प्रतिशत महज 50 थी। इस योजना ने वैश्विक स्तर पर वित्तीय समावेशन के संदर्भ में भारत का मान बढ़ाया है, साथ ही इसके कारण परिवार की जगह व्यक्तिगत स्तर पर आमजन की पहुंच बैंक सुविधाओं तक हुई है। वितीय समावेशन के लिए समुचित परिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए जरूरी है कि आमजन की भागीदारी के साथ-साथ सरकार की भी मामले में सक्रिय हिस्सेदारी हो। इस संदर्भ में सरकार और आमजन बढ़चढ़ कर काम कर रहे हैं और निजी स्तर पर भी इसे बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है। हालांकि, अभी भी जनधन खातों के साथ-साथ लोगों को वित्तीय रूप से साक्षर करने और उन्हें ऑनलाइन धोखाधड़ी के खतरों से अवगत कराने की आवश्यकता है, जिसे निजी और सरकारी दोनों इकाइयों द्वारा लगातार किए जाने की जरूरत है,तभी प्रभावी तरीके से इन लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। जनधन खातों से आज रुपे कार्ड ने ग्रामीणों की पहुंच दुनिया-जहान के बाजारों तक कर दी है। अब गांव के घरों में भी अमेज़न, फ्लिपकार्ट आदि देश-विदेश में बने उत्पादों की डिलीवरी कर रहे हैं।

बचत करने की प्रवृति विकसित

इतना ही नहीं, जनधन खातों ने लोगों के बीच बचत करने की प्रवृति विकसित की है साथ ही साथ खर्च करने की प्रवृति में भी इजाफा किया है, जिसका मुख्य कारण ग्रामीणों की ऑनलाइन बाजार तक पहुँच का होना है। इन बदलावों से आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आ रही है। जनधन खाते सामाजिक बदलाव के भी वाहक हैं। इनकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं में कमी आ रही है और लोगों की जुआ खेलने और शराब पीने की लत में भी कमी देखी जा रही है। जनधन खातों ने डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने, ई-कॉमर्स के कारोबार को बढ़ाने और यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम (यूपीआई) के जरिये डिजिटल भुगतान के मामले में दुनिया में भारत को शीर्ष पर पहुंचाने में भी मदद की है। जुलाई 2024 तक भारत में यूपीआई के जरिये 5570 करोड़ लेनदेन किए गए थे।

सरकारी योजनाओं से जोड़ें खाते

सामाजिक और आर्थिक मोर्चों पर और भी बेहतरी लाने के लिए जनधन खातों के साथ-साथ अब सरकार और बैंकों को ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में सूक्ष्म और लघु स्तर पर ऋण की सुविधा किफ़ायती दर पर उपलब्ध कराने की भी जरूरत है, ताकि ग्रामीण भारत आत्मनिर्भर बन सके और ग्रामीण क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में हिस्सेदारी बढ़ सके। साथ ही साथ देश में समावेशी विकास की संकल्पना भी शत-प्रतिशत साकार हो सके। मौजूदा डिजिटलाइजेशन के दौर में यह भी जरूरी है कि शहरी व ग्रामीण आमजन को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने और उन्हें साक्षर करने की दिशा में निरंतर काम करते रहा जाये। साथ ही, सरकार को चाहिए कि वह जनधन खातों के साथ अन्य सरकारी योजनाओं को आपस में जोड़ने की व्यवस्था करे ताकि अधिक से अधिक संख्या में वंचित तबके को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।

वित्तीय समावेशन के 10 स्वर्णिम वर्ष

जनधन योजना
शंभू भद्र
वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार

एक समय था जब देश में बैंक में खाता खोलना जग जीतने जैसा काम था। पीएसयू बैंकों में खाता खोलने के लिए इतने कागजी दस्तावेजों की अनिवार्यता थी कि अपना ही पैसा जमा करने के लिए लोगों को पापड़ बेलने पड़ते थे। नब्बे के दशक में पीएसयू बैंकों के सरकारी बाबूइज्म को निजी क्षेत्र के बैंकों ने पहचान कर खूब फायदा उठाया और केवल खाता खोलने के लिए मिनिमम बैलेंस के नाम पर नौकरीपेशा मध्यवर्ग और छोटे व मध्यम कारोबारियों को जमकर चूना लगाया। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक आदि जैसे निजी बैंकों का उदय पीएसयू बैंकों के बाबूइज्म के स्याहकाल में ही हुआ। उसके बाद तो अनेक निजी बैंक आए, दबाब में सरकारी बैंक भी लचीले हुए, इसके बावजूद देश की करीब चालीस करोड़ से अधिक आबादी बैंकिंग सिस्टम से दूर थी। 21 वीं सदी में इतनी बड़ी आबादी का बैंकिंग सिस्टम से दूर रहना सरकार के वित्तीय समावेशन के लक्ष्य में बड़ी बाधा था। सरकार की डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) स्कीम की सफलता में भी बैंकों में खाता नहीं होने से दिक्कत आ रही थी। सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने में मुश्किल आ रही थी। इस दौर में ही बांग्लादेश में वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में एक बड़ा प्रयोग हो रहा था। ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनुस बैंकिंग क्षेत्र में क्रांति ला रहे थे। मोहम्मद यूनुस बिना दस्तावेज खाता खोलकर व बिना गारंटी छोटे लोन देकर बांग्लादेश की बड़ी आबादी को बैंकिंग सिस्टम में लेकर आए। उनके इस भागीरथ प्रयास के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। भारत में भी ऐसे प्रयोग की जरूरत थी। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था पूंजीगत तरलता की समस्या से जूढ रहे थे। यूपीए सरकार ने आधार योजना से नागरिकों के बायो फिजिकल पहचान के क्षेत्र में व्यापक आधार तैयार कर दिया था। वर्ष 2014 में पीएम नरेन्द्र मोदी की सरकार आई। पीएम मोदी इन सब स्थितियों पर अच्छे से गौर किया और उन्होंने देश की बड़ी आबादी को बैंकिंग सिस्टम में लाने के लिए जनधन खाता योजना लांच की, जिसमें जीरो बैलेंस पर खाता खोलने का अभियान शुरू हुआ। प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में 28 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई। वर्ष 2024 के 28 अगस्त को जनधन योजना के दस साल पूरे हुए। इस योजना ने देश में बैंकिंग सिस्टम व वित्तीय समावेशन की तस्वीर बदल दी। पीएमजेडीवाई के बुधवार (28 अगस्त) को 10 साल पूरे होने पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की महत्वपूर्ण उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि यह वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और करोड़ों लोगों को सम्मान देने में सर्वोपरि योजना रही है। विशेष रूप से महिलाएं, युवा और हाशिए पर रहने वाले समुदाय। पीएमजेडीवाई के दस वर्ष के दरम्यान में 53.13 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं, जिनमें 29.56 करोड़ महिला लाभार्थी हैं, जो क्रमशः यूरोपीय संघ की जनसंख्या से अधिक और अमेरिका की जनसंख्या के लगभग बराबर हैं।

जनधन खाते धारकों को रूपे कार्ड दिया जाता है, तो वर्ष 2015 में 15.74 करोड़ रूपे कार्ड धारक थे, आज वर्ष 2024 के अगस्त माह तक 36.14 करोड़ हो गए हैं। दस वर्ष में जनधन खातों में जमा दो लाख करोड़ रुपये पार कर गए हैं। वर्ष 2015 अगस्त में जनधन खातों 22 हजार 900 करोड़ रुपये जमा हुए थे, साल दर साल बढ़ते गए। वर्ष 2016 में 42 हजार करोड़ रुपये, वर्ष 2017 में 65 हजार 799 करोड़ रुपये, वर्ष 2018 में 82 हजार करोड़ रुपये जमा हुए थे। वर्ष 2019 में जनधन खातों में जमा एक लाख करोड़ रुपये पार कर गया। वर्ष 2020 में 1.30 लाख करोड़ रुपये, वर्ष 2021 में 1.45 लाख करोड़ रुपये, वर्ष 2022 में 1.72 लाख करोड़ रुपये, वर्ष 2023 में 2.02 लाख करोड़ रुपये और वर्ष 2024 में अगस्त तक 2.34 लाख करोड़ रुपये जनधन खातों में जमा हैं। ये वो पैसे हैं, जो हाशिये पर जीवन जी रहे लोगों के पास खाते नहीं होने से नकदी के रूप में गुल्लक में रहते थे। गरीबों के इन पैसों ने पब्लिक सेक्टर के बैंकों की तरलता की समस्या को कम किया। हालांकि जनधन की सफलता को देखते हुए पीएसयू बैंकों को अपनी उस रणनीति पर विचार करना चाहिए जिसमें विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे लोग व कॉरपोरेट बैंकों को सिस्टम का फायदा उठाकर चूना लगाते हैं। माइक्रो लोन व बैंकिंग से बैंक अधिक फायदा उठा सकते हैं बनिस्पत मैक्रो लोन व बैंकिंग से।

जनधन योजना की खासियतें

जब यह योजना शुरू की गई थी, तब बैंकों ने देश भर में 77,892 शिविर आयोजित किए और लगभग 1.8 करोड़ खाते खोले। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इस उपलब्धि को मान्यता दी। वित्तीय समावेशन अभियान के हिस्से के रूप में 1 सप्ताह में खोले गए सबसे अधिक बैंक खाते 18,096,130 हैं और यह उपलब्धि भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा 23 से 29 अगस्त 2014 तक हासिल की गई थी। पिछली सरकारों ने भी वित्तीय समावेशन के लिए पहल की थी, उदाहरण के लिए, पिछली यूपीए सरकार ने उन लोगों के लिए नो-फ्रिल्स बैंक खातों की योजना शुरू की थी जिनके पास खाता नहीं था, लेकिन वे लोकप्रियता हासिल करने में विफल रही थीं। पीएमजेडीवाई का सबसे प्रमुख उद्देश्य बैंक रहित व्यक्तियों के लिए एक बुनियादी बचत बैंक खाता खोलना था। पीएमजेडीवाई खातों में कोई न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की आवश्यकता नहीं थी, और इन खातों में नियमित खातों की तरह जमा पर ब्याज मिलता था। पीएमजेडीवाई खाताधारकों को रुपे डेबिट कार्ड दिए गए। पीएमजेडीवाई खाताधारकों को जारी किए गए रुपे कार्ड पर 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध था। 28 अगस्त, 2018 के बाद खोले गए नए पीएमजेडीवाई खातों के लिए कवर को बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया। पात्र पीएमजेडीवाई खाताधारक 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट (ओडी) सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

योजना की प्रगति : पीएमजेडीवाई खातों का सबसे बड़ा हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (14 अगस्त तक 41.42 करोड़ खाते) के साथ है, इसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (9.89 करोड़ खाते), निजी क्षेत्र के बैंकों (1.64 करोड़) और ग्रामीण सहकारी बैंकों (0.19 करोड़) का स्थान है। पीएमजेडीवाई खातों के राज्यवार विश्लेषण से पता चलता है कि सबसे अधिक खाते उत्तर प्रदेश में खोले गए हैं, सबसे अधिक आबादी वाला राज्य (9.45 करोड़), और सबसे कम लक्षद्वीप में (केवल 9,256 खाते)। यूपी के अलावा 15 राज्य हैं जहां 1 करोड़ से अधिक पीएमजेडीवाई बैंक खाते हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, असम, ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हरियाणा। जनधन योजना ने अर्थव्यवस्था के वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्रों पर परिवर्तनकारी प्रभाव डाला है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid